हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

# पड़ोसियों की चिंता

ईरान से अमेरिका तक हालात तेजी से बदल रहे हैं और उसमें भी एशिया व दक्षिण एशिया तो निर्णायक दौर से गुजर रहा है। भारत की नीतियों में भी कुछ बदलाव के संकेत हैं और यह जरूरी भी है। बांग्लादेश में एक ऐसा बदलाव दिखा है, जिसकी चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। साल के आखिरी दिन भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने वह किया, जो भारत की पुरुष, महिला और अंडर-19 क्रिकेट टीमों ने कुछ समय पहले तक करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक पाकिस्तानी नेता या प्रतिनिधि से हाथ मिलाया। जयशंकर और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक बांग्लादेश में जब आमने-सामने आए, तो हाथ मिलाने का मौका आया। इस मौके के फोटो को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनूस ने भी साझा किया है और खुद अयाज सादिक ने भी। हाथ मिलाने का मतलब मोहम्मद युनूस को भी पता है और पाकिस्तान में तो इसी से खुशी का माहौल बन गया है। मई के महीने से ही पाकिस्तान के साथ तनाव जारी है। क्या अब इस तनाव में अब कमी आने वाली है?

बहरहाल, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार का मौका रिश्ते सुधार के मौके में बदल गया लगता है। वक्त के मुताबिक, कूटनीति के तेवर-कलेवर बदलना गलत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तानी नेता को ऐसी उम्मीद नहीं थी। भारतीय विदेश मंत्री ने उनकी एक उम्मीद को पूरा कर दिखाया है, तो अब उम्मीद है कि पाकिस्तान के रुख में कुछ अनुकूल बदलाव आए। बहरहाल, पाकिस्तान के साथ ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी भारत को अपना बुनियादी कूटनीतिक तालमेल बनाए रखना चाहिए। जरूरत से ज्यादा दूरियां कई बार महंगी पड़ती हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि अनेक शक्तियां ऐसी हैं, जो भारत को उसके निकट पड़ोसियों से दूर करना चाहती हैं। विगत दिनों से बांग्लादेश का रुख भले बहुत बुरा रहा हो, पर भारत उसे मित्र देश ही मानता है। भारतीय विदेश मंत्री ने चेन्नई में स्पष्ट कहा है कि 'यदि पड़ोसी को कोई समस्या है, तो आप किसी न किसी तरह से योगदान देना चाहेंगे। कम से कम आप नमस्कार करेंगे ही, मित्रता व संबंध बनाने के प्रयास करेंगे, और एक देश के रूप में हम यही कर रहे हैं।' वाकई, हमें अपनी व्यवहार कुशलता को बचाए रखना होगा। इसी कड़ी में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक पहल को भी देखना चाहिए। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास जाकर उन्होंने शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते हुए शोक व्यक्त किया है। खालिदा जिया के परिवार और बांग्लादेशियों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस सामान्य, किंतु आवश्यक पहल की प्रशंसा होनी चाहिए।

**यह प्रश्न उन प्रतिकूल पड़ोसियों के दिलो-दिमाग तक जरूर पहुंचना चाहिए कि वे हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हम भारत के लोग उनके साथ कैसे पेश आ रहे हैं?**

यह बात हमारे पड़ोसियों के दिल तक पहुंचनी चाहिए कि वे हमारे साथ क्या कर रहे हैं और भारत किस तरह से पेश आ रहा है। जो देश हमें तोड़ देना चाहते हैं, जो हमारे यहां आतंकी भेजते रहे हैं, उन देशों के प्रति भी संतुलित व्यवहार रखना भारत की भलमनसाहत है। हालांकि, हमें भलमनसाहत की भावुकता में कोई जल्दबाजी करने से बचना होगा। जयशंकर ने उचित ही कहा है, हमने अपनी सद्भावना का परिचय देते हुए कई साल पहले सिंधु जल संधि की थी। जब उस सद्भावना का अनुकूल उत्तर नहीं मिला, तब भारत को अच्छे व बुरे पड़ोसी के बीच भेद करने को मजबूर होना पड़ा। अगर कोई देश लगातार आतंकवाद दे रहा है, तो वह हमसे पानी की उम्मीद क्यों करता है? बेशक, कूटनीति लचीली रहे, पर हमें अपने हितों से समझौता नहीं करना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 03 जनवरी, 1951

## शाश्वत पथ

वर्ष-परिवर्तन के समय कई ऐसे उद्‌गार हमारे सामने आये हैं, जिन पर ध्यान देकर लाभ उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, 'आओ, हम सब नये वर्ष को अपने राष्ट्रीय जीवन में कायापलट करने वाला बनायें। हम सब अपने दिलों में उस पुरानी रोशनी को पुनः प्रज्वलित कर नई शुरुआत करें, जो भयंकर संघर्ष के दिनों में हमारे दिलों को प्रकाशमान करती थी। और, हम सब मिलकर भारत की सेवा में जुट जायें।' नेहरूजी ने खाली यह आह्वान ही नहीं किया है, बल्कि तत्व की कुछ बातें भी कही हैं।

विश्व-समस्याओं को शांतिपूर्वक हल करने की प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस बात की उपेक्षा नहीं की है कि 'आज यदि हम शांति की बात करते हैं, तो कभी-कभी लोग उसे गलती से आत्म-समर्पण या तुष्टीकरण समझ लेते हैं।' और 'बहुतों को आत्म-समर्पण या तुष्टीकरण का एकमात्र विकल्प युद्ध दिखाई देता है, चाहे उसके कितने ही भयंकर परिणाम क्यों न हों।' लेकिन, उन्होंने स्पष्ट किया है कि शांति का उनका प्रतिपादन आत्म-समर्पण या बुराई के साथ समझौते का प्रतिपादन नहीं है; इसके विपरीत, उनकी दृढ़ धारणा है कि 'शांति को बुराई के साथ समझौता करके नहीं खरीदा जा सकता और न उसकी उन तरीकों से रक्षा हो सकती है, जो स्वयं शांति के लिए घातक हैं।' बल्कि युद्ध के सिवा और भी विकल्प या रास्ते हैं 'जिनमें आत्म-समर्पण नहीं करना पड़ता, फिर भी उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है।' इसी भावना में विश्व-समस्याओं के हल का प्रतिपादन करके वह लंदन-सम्मेलन का जिक्र करते हुए, जिसमें भाग लेने वह जा रहे हैं, कहते हैं कि 'अगर हम सही दिशा में एक छोटा-सा कदम भी उठा सके, तो (लंदन) सम्मेलन का होना सार्थक हो जायेगा।'

अपने एक दूसरे भाषण में, जो मैसूर सेवादल के स्वयंसेवकों के समक्ष उन्होंने दिया, पूर्ण अनुशासन पर नेहरूजी ने जोर दिया है। देश-सेवा के लिए पूर्ण अनुशासन को अत्यावश्यक बताते हुए नेहरूजी कहते हैं: 'हर एक देश-सेवा की बात करता है, लेकिन ठीक तरह देश-सेवा करने के लिए पूर्ण अनुशासन अत्यावश्यक है। अगर हर व्यक्ति अपनी मनमानी करे, तो कोई अनुशासन नहीं रह सकता, न कोई सेवा ही संभव है।' दूसरे बड़े देशों का हवाला देते हुए वह कहते हैं, वे अच्छा और बड़ा काम करते हैं।

**दूषित जल की आपूर्ति से इंदौर में अनेक लोगों की मौत हुई है। भारत में दूषित जलापूर्ति हमेशा से चिंता का विषय रही है। यह एक ऐसी बड़ी कमी है, जिस पर संसद में अनेक बार चर्चा हुई है, फिर भी अक्सर लापरवाही सामने आ जाती है। ऐसी ही एक चर्चा लोकसभा में 24 सितंबर, 1964 को हुई थी। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सत्ता पक्ष ने अपनी सरकार व जिम्मेदार अधिकारियों का पूरा बचाव किया था।**

## आमने-सामने

# लोगों तक कैसे पहुंचा मल मिश्रित पानी

यहां स्कैन करें

हरि विष्णु कामत | तत्कालीन वरिष्ठ सांसद

- ऐसी शिकायत पहले भी सामने आई थी, पर आठ साल बाद भी सुधार न हुआ।
- साल 1956 में भी सड़कों पर सैकड़ों लोग पीलिया से मर गए थे।
- दूषित जल की आपूर्ति करने वालों को मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 18 वर्ष व्यतीत हो चुके मैं और दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, उसकी जनता अभी भी पीड़ित है। यहां पर अन्न नहीं मिलता है। जो अन्य वस्तुएं मिलती हैं, उनमें मिलावट होती है।

मुझे 1955 की एक घटना अच्छी तरह याद है। उस वर्ष भारत में रूस से दो मेहमान सर्वश्री ख्रुश्चेव तथा बुल्गानिन भारत आए थे। जब वह लौटकर रूस गए, तो ऐसी अफवाह फैली कि उनको पीलिया रोग भारत आने के कारण हो गया, क्योंकि वह रूस पहुंचने के तुरंत बाद ही अस्पताल में दाखिल हो गए थे। इस समय की हमारी स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली की मंत्री थीं। उस समय 1955 में गंदे पानी के बारे में लोकसभा में चर्चा हुई थी, तथा उस समय की स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने सभा में पूरा आश्वासन दिया था कि सभी संभव उपाय किए जाएंगे, जिससे भविष्य में गंदा पानी दिल्ली में पीने के लिए न मिले। परंतु आज आठ साल के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार जल-मल बोर्ड अभी भी जल-मल मिश्रित पानी का संभरण दिल्ली में कर रहा है।

मुझे मालूम हुआ है कि पीलिया रोग से एक बालक की मृत्यु हो चुकी है तथा कई बालक अस्पताल में पड़े हैं। मैंने यह भी सुना है कि अस्पतालों में तथा गैर-सरकारी डॉक्टरों के पास भी इतने रोगी हैं कि वे सभी रोगियों की ओर उचित ध्यान देने में असमर्थ हैं। इसी आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री को उसी प्रकार इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस प्रकार श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अरियालूर रेल दुर्घटना होने पर इस्तीफा दे दिया था। मैंने 1956 में भी पीने के गंदे पानी के कारण फैले पीलिया रोग के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर से इस्तीफा देने की मांग की थी।

हाल में ही पीने के पानी के बारे में सभा में एक प्रश्न था। उसके संबंध में मैंने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि आज जो यह स्थिति है, वह 1955 की तुलना में किस प्रकार की है? अच्छी है अथवा बुरी है? मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि यह स्थिति उस समय से भिन्न है। ...उन्होंने कहा है कि उसकी तुलना में स्थिति अच्छी है। मैं चाहता हूं कि कृपा करके वह इस बात को स्पष्ट करें कि स्थिति अच्छी किस प्रकार है? इन आठ वर्षों में स्थिति सुधारने की परियोजना पर कितने करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं? अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी जांच के लिए एक संसदीय आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए, जो दोषी व्यक्तियों का पता लगाए और आवश्यक दंड दिलाए।

महोदय, 1955 में स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने एक बहुत बहादुरी भरा वादा किया था कि इन सभी मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है, और सदन को आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब यह सवाल पूछा गया कि कौन जिम्मेदार है और लापरवाही करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की जानी-पहचानी तकनीक अपनाई। उस समय, दिल्ली राज्य के मुख्य आयुक्त या मुख्यमंत्री संयुक्त जल और सीवेज बोर्ड के लिए जिम्मेदार थे। मैं सरकार को एक बात के लिए सलाम करता हूं कि सीवेज बोर्ड को खत्म करने के आठ साल बाद भी जल और सीवेज बोर्ड दिल्ली के नागरिकों को जल-मल देकर अपने नाम के अनुरूप काम कर रहा है।

यहां जल-मल का एक नमूना है, जिसे शायद मेरे माननीय मित्र ने मेज पर रखा है। अगर आप बस इसका ढक्कन खोलें और थोड़ी दूरी से ही इसे नाक के पास ले जाएं, बहुत करीब नहीं, तो आपको बदबू आएगी, उल्टी जैसा महसूस होगा। मुझे उम्मीद है कि उसके बाद और कुछ नहीं होगा।

यह हंसने की बात नहीं है। एक बच्चे की मौत हो गई है। मैंने अभी एक और दोस्त से सुना कि कई और बच्चे अस्पताल में बीमार हैं, और डॉक्टर- निजी डॉक्टर और कुछ सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर- पीलिया या संक्रामक हेपेटाइटिस से पीड़ित मरीजों की भीड़ को संभालने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। यह पीलिया का शुरुआती लक्षण हो सकता है, जैसे गैस्ट्रो-एंटेराइटिस। यह सरकार की तरफ से धोखा है कि लोग भूख से नहीं, बल्कि गैस्ट्रो-एंटेराइटिस से मरते हैं। आखिरकार, भूख से कोई बीमारी होती है? भूख से मौत नहीं हो सकती है, लेकिन इससे गैस्ट्रो-एंटेराइटिस या शायद हेपेटाइटिस और शायद टाइफाइड या हैजा या ऐसा कुछ हो सकता है। ...अगर तथ्यों को देखें, तो यह बड़ी शर्म की बात है। ...

अगर राजधानी में हालात ऐसे हैं, तो यह सोचकर ही रूह कांप जाती है कि दूर-दराज के गांवों में क्या हो रहा होगा? शायद वहां पटवारी और हेड-कांस्टेबल राज कर रहे हैं और जो मन में आता है, वही कर रहे हैं। चाहे वहां लोगों का पीने के लिए साफ पानी मिल रहा हो या कीचड़ या धूल या गंदगी, मैला और बदबूदार मलयुक्त जल मिल रहा हो, मुझे नहीं पता कि उन्हें वहां क्या मिल रहा है? इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि यह सदन मेरे इस प्रस्ताव को मंजूरी दे कि इस मामले की जांच के लिए एक संसदीय आयोग नियुक्त किया जाए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसे सजा दी जाए और उसे कानून के कठघरे में लाया जाए। साल 1956 में जो हुआ था, उसे दोहराया न जाए, जब एक इंजीनियर को सिर्फ मौखिक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था, जबकि सैकड़ों लोग सड़कों पर पीलिया से मर गए थे। ...

दूसरी ओर, अगर संसद इस मामले पर सख्त कार्रवाई नहीं करती है, तो देश की राजधानी में, और शायद भारत में भी कहीं, और बड़े पैमाने पर पीलिया जनित हत्या की इस त्रासदी को दोहराया जा सकता है। इससे पहले कि और बुरा घटित हो, मैं यह मांग करता हूं कि तुरंत कार्रवाई की जाए और अपराधियों को बिना देरी के कानून के कठघरे में लाया जाए और अगर जरूरी हो, तो उन्हें मौत की सजा दी जाए।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

# दूषित जल की आपूर्ति से हमें भी दुख हुआ

यहां स्कैन करें

सुशीला नायर | तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री

- दिल्ली में इस समय हर साल ऐसे हालात बनते हैं। इसमें बहुत चिंता की बात नहीं।
- मैं यह बता दूं कि ऐसे मामलों में सड़कों पर कोई भी नहीं मरता। यह आरोप गलत है।
- कुछ अफसरों को निलंबित कर देने से न्याय नहीं, अन्याय होगा।

श्रीमन्, मैंने बहुत ध्यान से माननीय सदस्यों के भाषण सुने। मैं सबसे पहले यह कहना चाहती हूं कि मुझे और मेरे साथियों को भी इस बात या प्रदूषित जल संबंधी शिकायत का दुख है। अगर दिल्ली में रहने वाले किसी भी छोटे या बड़े व्यक्ति को तकलीफ होती है, तो हमको दुख होता है और हम चाहते हैं कि किसी को तकलीफ न हो।

पानी के कारण और अन्य कारणों से जो बीमारियां इस मुल्क में सदियों से जनता की जान लेती रही हैं, उन बीमारियों की रोकथाम के लिए जितनी मेहनत हो सकती है, उतनी दिन और रात हम कर रहे हैं और उसमें बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। कहीं-कहीं उसमें असफलता भी हुई है। उस असफलता के लिए हमको दुख है। लेकिन उस असफलता को लेकर जब ऐसी-ऐसी बातें कही जाती हैं, जैसे किसी ने कुछ किया ही न हो, तो थोड़ा सा अफसोस होता है। लेकिन अधिकार है माननीय सदस्यों का, जो चाहे सो कहें, गालियां भी दे सकते हैं और जो डांट-डपट मुनासिब समझें, वह भी कर सकते हैं। चाहे परिस्थिति ईश्वर की तरफ से बनी हो या किसी की तरफ से, यह सच है कि यह पानी का कष्ट हमारे नागरिकों को हुआ है, कई सालों से हुआ है, कभी पानी की कमी के कारण हुआ है, कभी पानी में दोष आ जाने के कारण हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि इस वक्त पानी में जो दोष पाया गया है, अगर 1955 का एक हादसा न हो गया होता, तो हम आज शायद किसी को पानी उबालने के लिए भी न कह रहे होते। ...

हम ज्यादा क्लोरीन डालकर पानी जनता को दे रहे हैं। इसमें कोई कारण नहीं है, यह मानने के लिए कि इस पानी को पीने से चारों तरफ भय का वातावरण हो जाना चाहिए, जैसे कि कहा जा रहा है। आप कह सकते हैं कि अगर ऐसा ही था, तो आपने पानी उबालने के लिए क्यों कहा? हमने पहले ही दिन से जो पानी उबालने के लिए कहा था, वह दोहरी सुरक्षा के बयान से कहा था। पानी ऐसा भी नहीं है कि जिससे घबराने की कोई बात हो, लेकिन यहां कोई कह रहा है कि हम नहा नहीं सकते, कोई कह रहा है कि हम इससे कुल्ला नहीं कर सकते।

कोई-कोई डॉक्टर भी माननीय सदस्यों की तरह भड़क सकते हैं। भड़कने का अधिकार माननीय सदस्यों को है, डॉक्टरों को नहीं है, यह बात नहीं है। यह स्वतंत्र देश है। उन्होंने भी कुछ भड़ककर कह दिया होगा, लेकिन वैज्ञानिक सच क्या है? यही मैं निवेदन करने की कोशिश कर रही हूं। ...बीमारों की संख्या नहीं बढ़ी है। यही एक खुशी की बात है, संतोषजनक बात है। चाहे हमारे भाई श्री फ्रैंक एंथनी इसको बाजीगरी कहें, यह उनकी मर्जी है, लेकिन यह संख्या किसी की बनाई हुई नहीं है। वह कहते हैं कि उनके कुत्ते भी हमारे अस्पतालों में नहीं जाते हैं। मैं बड़े अदब से कहना चाहती हूं कि उनके कुत्तों के इलाज के लिए तो हमारे अस्पतालों में आम तौर पर कुछ प्रबंध नहीं किया गया है, उनके लिए तो वेटरनरी अस्पताल होते हैं। लेकिन जो हमारे अस्पताल हैं, उनमें हर रोज हजारों, लाखों लोग जा रहे हैं और मेरे पास उनके महीने-दर-महीने और साल-दर-साल के आंकड़े मौजूद हैं...। दूषित जल से जुड़े तुलनात्मक आंकड़े अगस्त और सितंबर के महीनों में बढ़ जाते हैं। ...पिछले साल बड़ी मेहनत की गई और पानी का इतना अच्छा क्लोरिनेशन किया कि कुल 67 मामले हुए और उनमें दो लोगों की मृत्यु हुई। इस साल भी अगस्त में इस दूषित जल प्रकरण से बहुत पहले 104 मामले दर्ज हुए और तीन मौतें हुईं।

अब मैं सितंबर महीने के आंकड़े आपके सामने रखती हूं। सन् 1961 के सितंबर में 61 मामले आए, 1962 के सितंबर में 44, 1963 के सितंबर में 37 और 1964 के सितंबर में 40 मामले सामने आए, तो उनमें कोई विशेष बढ़ोतरी हुई हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री कामथ ने कहा कि ये सरकारी आंकड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग सड़कों पर या अपने घरों में मरे हैं, उनके आंकड़े इनमें नहीं हैं। मैं बता दूं कि ऐसे मामलों में सड़क पर कोई नहीं मरता। ...अगर कोई डॉक्टर भी किसी को देखता है, तो उसको इसकी खबर देनी होती है। अगर यह भी मान लिया जाए कि कुछ अंडर रिपोर्टिंग है, तो ऐसी बात नहीं है कि इसी साल में यह अंडर रिपोर्टिंग हुई हो। मैंने आपके सामने 1961, 1962, 1963 और 1964 के आंकड़े रख दिए हैं और इनमें कोई बड़ा फर्क नहीं है, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है। ...

इसी प्रकार मैं अर्ज कर दूं कि 'इन-फैक्टिव हेपेटाइटिस' कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जो इस साल हुई हो...। मैं बड़े अदब से कहना चाहती हूं कि यह केवल पानी की वजह से ही हुई हो, यह बात भी नहीं है। इस मुल्क में हम लोगों की आदत भी बहुत ज्यादा साफ-सुथरी नहीं हैं। आप जानते हैं कि यहां किस तरह से खुली खाने की चीजें बिकती हैं, जिन पर मक्खियां बैठती हैं, जिनमें धूल पड़ती है, इनसे भी चीजों में संक्रमण होता है। ...

अगर मुझ पर आप स्वास्थ्य की रक्षा की जिम्मेदारी डालते हैं, तो मैं आपका उसमें सहयोग मांगती हूं कि जो चीज स्वास्थ्य की रक्षा के लिए करनी आवश्यक है, उसमें आप मेरा हाथ मजबूत करें और उसमें आप पीछे से मेरी चुटिया को न खींचने लगें। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, तो पीछे से मुझे खींच लें और अगर आगे नहीं बढ़ती हूं, तो फिर मुझे चाबुक लगाएं। यह एक बड़ी आफत की बात है।

...अगर आप सब रचनात्मक टीका-टिप्पणी करें, सकारात्मक आलोचना करें और सुझाव दें, तो मैं उसका स्वागत करती हूं, लेकिन खाली 'इमोशन' से तो काम चलने वाला नहीं है। ... आपके सुझाव अगर अच्छे होंगे, तो उन पर निश्चित ही काम किया जाएगा।

श्रीमन्, मैं कोई विवाद नहीं उठाना चाहती हूं। मेरा तो इतना ही कहना है कि इस वक्त जो जल-दूषण हुआ, उसमें किसी मनुष्य का हाथ था या नहीं, कहा जा सकता है। यह बात मैं साफ कर देना चाहती हूं कि खाली सदन को खुश करने के लिए मैं कह दूं कि ... किन्हीं अफसरों को मुअत्तिल कर दो या सस्पेंड कर दो, तो यह चीज मैं नहीं करने वाली हूं, क्योंकि वह अन्याय की बात होगी...।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

## मनसा वाचा कर्मणा

# प्रसन्नता की लालसा

प्रसन्नता की चाह तुम्हें दुखी करती है। जब तुम अप्रसन्न अथवा दुखी हो, तो उसके पीछे तुम्हारी प्रसन्नता की आकांक्षा ही है। प्रसन्नता की लालसा दुख ले आती है। यदि तुम प्रसन्नता के लिए लालायित नहीं होते, तब तुम प्रसन्न होते हो। मगर जब तुम प्रसन्नता की परवाह नहीं करते, तब मुक्त हो जाते हो और जब मुक्ति की भी परवाह नहीं करते, तब तुम प्रेम को प्राप्त होते हो। प्रसन्नता के लिए परवाह न करना पहला कदम है। दूसरा कदम है, परम वैराग्य। जब तुम मुक्ति की भी परवाह नहीं करते, तब तुम मुक्त होते हो।

प्रसन्नता मन की एक अवधारणा मात्र है। तुम्हें लगता है कि जो तुम चाहते हो, यदि वह सब तुम्हारे पास आ जाए, तो तुम प्रसन्न हो जाओगे। जो भी तुम चाहते हो, वह सब तुम्हारे पास हो, तो क्या तुम सचमुच प्रसन्न हो जाओगे? प्रसन्नता की इस लालसा को विराम देना ही वैराग्य है।

इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि तुम्हें दुखी होना चाहिए। इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम्हें आनंद नहीं उठाना चाहिए, पर प्रसन्नता की लालसा से जब मन मुक्त होता है, तभी तुम ध्यान में उतरते हो। तब ही योग संभव है।

अपने कपोल सपनों और कल्पनाओं को नष्ट कर दो। तुम कौन सी बड़ी प्रसन्नता चाहते हो और उसे कितने दिनों तक बनाकर रख पाओगे? यह सब कुछ तो समाप्त होने वाला है। क्या ऐसा ही नहीं है? इसलिए इससे पहले कि यह जमीन तुम्हें खा जाए, लालसा से मुक्त हो जाओ। इस ज्वरता से मुक्त हो जाओ, जिसने तुम्हारे मन को जकड़ रखा है। इस प्रसन्नता की लालसा से मुक्त हो जाओ।

श्री श्री रविशंकर

फ्रेडरिक मर्ज | चांसलर, जर्मनी

**जर्मनी एक ऐसा देश है, जहां हम सब आजादी से और बराबर अधिकारों के साथ जीते हैं। हम एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं। यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है कि इस खूबसूरत और रहने लायक देश को संभालकर रखें।**

## अनुलोम-विलोम
### खुदरा दुकानदारी

# दुकानदार पहले खुद को बदलें तो सही

किराने वाले से रेजर खरीदने गया। साफ-साफ लिखा था, 3 पर 1 फ्री। अगले ने नहीं दिया। पूछने पर बोला, भैया, अभी स्कीम खत्म हो गई है, इसलिए नहीं दे पा रहा। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अगली बार से उस दुकान पर जाना बंद। कल बेटा बोला, पापा बर्गर खाना है। ले गया उसे पास के ही एक आउटलेट पर। मैंने 2 बर्गर ऑर्डर कर दिए, अगले ने एक पर्ची फाड़कर दे दी। इतने में ही बेटा बोला, पापा पिज्जा। मैंने भी आउटलेट वाले को बोला, भाई, एक बर्गर और एक पिज्जा कर दे। बोला, भैया बिल तो कट किया, ये चेंज नहीं हो सकता, पिज्जा आपको अलग से ही लेना पड़ेगा।

कहीं ऊंघते दुकानदार ग्राहक को सामान दिखाना ही नहीं चाहते, तो कहीं जरा सी बात पर झुंझला जाते हैं, कहीं-कहीं तो ऊंची आवाज में भी मैंने उनको बात करते देखा है। कस्टमर आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन खुदरा दुकानदारों के कर्म ही ऐसे हैं कि वे उनको छोड़कर कोई दूसरी दुकान देखने को मजबूर हैं, और आप बदनाम करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कि उसने आपका धंधा चौपट कर दिया। अरे भैया, आपने खुद ऐसा किया है, अपने कर्मों से, छोटे-मोटे मुनाफे में आपका काम चलता नहीं, ग्राहक से बात आपको ढंग से करनी नहीं, स्कीम आपको देनी नहीं, 10 बजे दुकान खोलनी है, ऐसे में भला कैसे चलेगा? अगर वे होम डिलीवरी दे रहे हैं, तो आप भी दो। अपना व्यवहार सुधारो, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, दुकान को कंप्यूटराइज्ड करो, सातों दिन चौबीसों घंटे लगो काम पर, आदमी बढ़ाओ, मुनाफा ज्यादा लेने की मत सोचो। झक मारेंगे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके आगे। सुधरो तो सही, बदलाव तो करो अपने आप में।

आपके पास रोने के 20 बहाने हो सकते हैं- हमारे पास तो आदमी नहीं हैं, दुकान छोड़कर कैसे जाएंगे, अकेले आदमी हैं, ऐसे ही किसी को कैश काउंटर पर कैसे बिठा देंगे, लेकिन काम करने के लिए बहाने नहीं, अपग्रेडेशन चाहिए। करिए तो सही, नहीं तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, किसी बड़े कॉरपोरेट को गरियाना बंद कीजिए, और मस्त रहिए अपनी घटती बिक्री के साथ। कितने ही खुदरा कारोबार हैं, जिनके धंधे में साल-दर-साल ग्रोथ है, क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने को अपग्रेड किया है। वैसे भी ऑनलाइन सेल्स या प्लेटफॉर्म एक सुविधा मात्र है उन लोगों के लिए, जिनके पास समय नहीं है और जो ज्यादा कीमत देकर घर बैठे ही काम करवाना चाहते हैं। खुदरा व स्थानीय व्यापार का भारत जैसे देश में आज भी कोई तोड़ नहीं है। जरूरत है तो बस इनमें बदलाव लाने की।

दीपक गोयल, टिप्पणीकार

# खुदरा दुकानदारी अब घाटे का सौदा

परिवर्तन का शाश्वत नियम भारतीय बाजार पर पूरी तरह प्रभावी है। खुदरा दुकानदार इसी कोशिश में रहते हैं कि अपने माल को उपभोक्ताओं के घरों तक हर हाल में पहुंचा सकें, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ऐसा असर पड़ा है कि लोग स्थानीय दुकानदार को महत्व ही नहीं दे रहे। वे छोटे-छोटे घरेलू सामान भी ऑनलाइन मंगवाना पसंद करते हैं। ऑनलाइन वाले महज पांच या दस मिनट में घर बैठे सामान मंगवाने की सुविधा देने लगे हैं। इससे स्थानीय दुकानदारों की दुकानदारी चौपट होने लगी है, जबकि वे ग्राहकों से यह वायदा भी करने लगे हैं कि उनको बस सामान की लिस्ट दे दी जाए, वे भी सामान घर भिजवा देंगे।

असल में, अब हर माल डाक या कूरियर के माध्यम से उपभोक्ताओं के घर तक उचित और किफायती दामों में आराम से पहुंच रहा है। ऐसे में, वे बाजार जाकर घंटों का समय बर्बाद क्यों करें? किराने के सामान ही नहीं, कपड़े, जूते-चप्पल, फ्रीज-मशीन तक, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। ये सब नजदीक के दुकानदारों के पास मिलना मुश्किल होता है। फलस्वरूप, उपभोक्ताओं की पहली पसंद ऑनलाइन खरीदारी बनती जा रही है। फुटकर दुकानदार चिरौरी करके भी ऑनलाइन बाजार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और प्रतिस्पर्द्धा में बुरी तरह पिछड़ते जा रहे हैं। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा कुछ बड़ी कंपनियां निगल ले रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में खुदरा दुकानें बंद होने लगी हैं। छोटे-मझोले दुकानदारों की चमक काफी फीकी पड़ गई है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वे अब क्या करें? वे इस समय का मुकाबला आखिर कैसे करें? कुछ दुकानदारों को तो मैंने छोटी-मोटी अन्य नौकरी करके अपना गुजर-बसर करते भी देखा है।

उपभोक्ताओं को रास आने वाली ऑनलाइन खरीदारी सिर्फ खुदरा दुकानदारों को प्रभावित नहीं कर रही, बल्कि इससे अब थोक व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनका पूरा बाजार इन्हीं फुटकर व्यापारियों पर निर्भर होता है। इस तरह देखें, तो लगता यही है कि एक न एक दिन ऑनलाइन कारोबार स्थानीय दुकानदारी को खत्म कर देगा। हालांकि, खुदरा दुकानदार लगातार खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वे भी कुछ फीसदी की छूट देने लगे हैं। यह सही है कि कोई भी नई व्यवस्था आती है, तो तय मार्ग पर चलने के आदी लोगों पर प्रहार करती है, उनकी जड़ता तोड़ती है, मगर अपनी जड़ता को खत्म करने के बावजूद यदि इन दुकानदारों को लाभ नहीं मिलेगा, तो वे क्या करेंगे? खुदरा दुकानदारों के सामने आज यही यक्ष प्रश्न है।

दिनेश सिंह, चिकित्सक

# सस्ते ई-वाहनों का सबको इंतजार

**इस साल कई बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक कारें पेश होंगी। थोड़ी महंगी होने के कारण अभी तक इलेक्ट्रिक कारें खास वर्ग की पसंद रही हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये बजट कीमतों में पेश होंगी। दरअसल, इलेक्ट्रिक बैटरियों की नई केमिस्ट्री इन वाहनों को आम लोगों की गाड़ी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। ई-वाहनों की दुनिया को किन क्षेत्रों से है उम्मीद? कौन सी हैं आने वाली इलेक्ट्रिक कारें? विशेषज्ञ की क्या है राय? एक लेखा-जोखा**

आने वाले वक्त में खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों में कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बीते साल कारों में कई लोकप्रिय मॉडलों के इलेक्ट्रिक अवतार हम देख चुके हैं। इस साल यह ट्रेंड और तेजी पकड़ेगा। साल 2025 में लगभग 17-20 नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च हुए थे। 2026 में यह संख्या 25% से 30% तक बढ़ने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर आने वाला दौर भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के मामले में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। आइए जानें क्या-क्या तैयारी हो रही है ई-वाहनों की दुनिया में:

### बदलेगी बैटरी केमिस्ट्री

- **एलएफपी बैटरियां:** भारत में फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम-आयन बैटरियों का वर्चस्व है, जिनमें एलएफपी (लिथियम आयरन/फेरो फॉस्फेट) बैटरियां अधिक भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभर रही हैं। टाटा नेक्सन, पंच, टिआगो, एमजी विंडसर आदि गाड़ियों में इस तरह की बैटरियां देखने को मिली हैं। अधिकांश इलेक्ट्रिक बसों में इनका इस्तेमाल होता है। गर्म जलवायु के लिए सुरक्षित, लंबी उम्र वाली और कोबाल्ट-मुक्त होने के कारण एलएफपी बैटरियां अपेक्षाकृत सस्ती भी पड़ती हैं।
- **एनएमसी बैटरियां :** बैटरियों की यह तकनीक अपनी उच्च ऊर्जा घनत्व के लिए जानी जाती हैं, जो कम वजन में अधिक रेंज और बेहतर परफॉरमेंस देती है। इनका उपयोग मुख्य रूप से प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों, जैसे हुंडई आयोनिक और हाई-स्पीड परफॉरमेंस स्कूटरों में किया जा रहा है।
- **सोडियम आयन बैटरी :** सोडियम-आयन बैटरी पर भी काफी काम हो रहा है। ये सस्ती होंगी और अधिक तापमान में सुरक्षित रहती हैं। एलएफपी बैटरी जहां रेंज ज्यादा देती हैं, वहीं सोडियम बैटरी फास्ट चार्जिंग में बेहतर होती हैं। शुरुआती तौर पर इन्हें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में उपयोग करने की संभावना है।

#### सावधान करेंगी ई-कारें

1 अक्तूबर 2026 से नई ई-पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों में अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम (एवीएएस) अनिवार्य होगा। ईवी लगभग न के बराबर आवाज करते हैं, इसलिए पैदल यात्रियों और नेत्रहीन लोगों की सुरक्षा हेतु ये वाहन कम गति पर कृत्रिम आवाज निकालेंगे, ताकि उनकी मौजूदगी का पता चले।

माना जा रहा है कि जल्दी ही भारत में रिलायंस और टाटा जैसी कंपनियां स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी गिगाफैक्ट्रियों की पूर्ण व्यावसायिक शुरुआत कर सकती हैं। ऐसे में बैटरी सेल्स का आयात कम होगा और बैटरी की लागत में 20-30% की कमी आ सकती है। इसका सीधा असर ईवी की कुल कीमत घटने के रूप में दिख सकता है।

बैटरी की बेहतर तकनीक फास्ट चार्जिंग का नया ट्रेंड लेकर आएगी। वैसे इंडियन ऑयल और टाटा पावर जैसे ऑपरेटर देशभर में 12,000 से अधिक सार्वजनिक फास्ट चार्जर और हाईवे चार्जिंग कॉरिडोर्स विकसित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। सरकार की फ्लैगशिप योजना पीएम ई-ड्राइव के तहत एक नई पहल के साथ ही 50 नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक चार्जिंग कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जा रहा है। फिलहाल चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 29,000 के पार पहुंच चुकी है। कंपनियां फास्ट चार्जिंग पर भी तेजी से काम कर रही हैं।

इस संदर्भ में ऑटोमोटिव एक्सपर्ट अविक चट्टोपाध्याय के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रेंज एंग्जायटी का मुद्दा बड़ा है। इसीलिए बैटरी केमिस्ट्री पर पुराने समय से शोध हो ही रहे हैं। ये देखना होगा कि पायलट प्रोजेक्ट्स के शोध प्रोडक्शन के स्तर पर कब पहुंचेंगे। ज्यादा जरूरत अपने देश में ही जलवायु और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों को देखकर शोध किए जाने की है। इस खास मुद्दे के लिए शोध और डेवलपमेंट पर सरकारी सहायता की जरूरत भी पड़ेगी। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय निवेशकर्ताओं को आकर्षित किया जा सकता है, ताकि और तेजी आए, क्योंकि सही बैटरी केमिस्ट्री की खोज के लिए एक नहीं, कई परीक्षण चरणों की जरूरत होगी।

पर्यावरण संरक्षण और ई-वाहनों को अपनाने में तेजी के लिए वह दो बड़े बदलावों की बात करते हैं, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूरी तरह इलेक्ट्रिफाई किया जाना। छोटी मोहल्ला बसों यानी 9 मीटर वाली और इंटरस्टेट बसों तक में इलेक्ट्रिक बसों को लाया जाना चाहिए। सभी थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिफाई होने चाहिए। इसके लिए तेज मैन्यूफैक्चरिंग चाहिए होगी। नतीजतन, सरकार की ओर से इंडस्ट्री के लिए इन्सेन्टिव योजनाएं मिलें, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी निर्माण प्रक्रिया तेज की जा सकेगी। वह कहते हैं, 'मेरा मानना है कि ईकॉमर्स, गिग वर्किंग के क्षेत्र में ई-दोपहिया को सबसे तेजी से अपनाया जाएगा। लेगेसी ब्रांड जैसे बजाज, टीवीएस आदि के कारण निजी उपयोग में भी तेजी आएगी।'

वह मानते हैं कि फोर-व्हीलर के संदर्भ में एडॉप्शन रेट उतना अहम नहीं है, जितना यह बात कि इलेक्ट्रिक सप्लाई की निरंतरता पर काम करना होगा। चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी होगा। **-फीचर डेस्क**

## आने वाली ई-कारें

**यह साल भारत में इलेक्ट्रिक कारों के लिए अहम होगा। देश की कई बड़ी कार निर्माता कंपनियां अपने लोकप्रिय कारों के ई-अवतार पेश करेंगी और कई नए ई-कार मॉडल भी आएंगे**

### मारुति सुजुकी ई-विटारा

जनवरी की सबसे बड़ी लॉन्चिंग मानी जा रही ई-विटारा। यह मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसमें 49 केडब्ल्यूएच और 61 डब्ल्यूएच बैटरी विकल्प मिलेंगे, जिनमें बड़ा पैक करीब 543 किमी (एआरएआई) रेंज देगा। ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी हो सकता है और इसे ग्लोबल मार्केट के लिए भारत में ही बनाया जा रहा है।

### टाटा सिएरा ईवी

टाटा मोटर्स अपने जाने माने सिएरा ब्रांड को इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रही है। इसे जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में पेश किया जा सकता है।

### टाटा अविन्या

भारतीय इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में यह संभवतः सबसे बड़ी लॉन्चिंग होगी। अविन्या टाटा का नया प्रीमियम ब्रांड शुरू करेगी और इसका प्रोडक्शन मॉडल कॉन्सेप्ट डिजाइन के आसपास रहेगा। यह टाटा के जेनरेशन 3 ईवी आर्किटेक्चर पर आधारित होगी।

### किया साइरोस

किया साइरोस का इलेक्ट्रिक वर्जन 2026 की दूसरी तिमाही में लॉन्च होने की संभावना है। इसे बजट इलेक्ट्रिक कार के रूप में पेश किया जाएगा। टाटा नेक्सन ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 400 जैसी कारों को टक्कर देगी।

### टोयोटा अर्बन क्रूजर

मार्च 2026 में टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी अर्बन क्रूजर पेश होगी। वहीं, फरवरी 2026 में विनफास्ट की तीसरी इलेक्ट्रिक कार, सात-सीटर एमपीवी लिमो ग्रीन, 60.1 केडब्ल्यूएच बैटरी के साथ आएगी। पूरी तरह चार्ज होने पर 450 किमी तक की रेंज देगी।

# कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए 5 अहम बातें

टिप्स

**घना कोहरा सड़क पर गंभीर खतरे की आशंका बढ़ा देता है। दृश्यता कम होने से हर साल हादसे भी होते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी और समझदारी भरी ड्राइविंग की ये आदतें अपनाकर आप इन खतरों से खुद को बचा सकते हैं।**

**सर्दियों** में कोहरा और कम दृश्यता, खासकर सुबह और रात में, ड्राइविंग को कठिन बना देते हैं। कभी-कभी सामने वाला वाहन आखिरी पल में दिखता है, जिससे अचानक ब्रेक या मोड़ लेना पड़ सकता है। कुछ बुनियादी सावधानियां अपनाकर सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है-

**लो बीम और फॉग लाइट:** घने कोहरे में हाई बीम की तेज रोशनी नमी से टकराकर दृश्यता कम कर देती है। इसके बजाय लो बीम और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, जो सड़क और सामने का मार्ग साफ दिखाती हैं। पीली रोशनी कोहरे में अधिक प्रभावी होती है, जबकि तेज सफेद लाइट देखने की क्षमता प्रभावित कर सकती है।

**सही ड्राइविंग के लिए हॉर्न और इंडिकेटर :** कोहरे में दृश्यता कम होने के कारण हॉर्न और टर्न इंडिकेटर और भी जरूरी हो जाते हैं। हॉर्न केवल जरूरत पड़ने पर बजाएं। मोड़ या लेन बदलते समय टर्न इंडिकेटर जरूर ऑन करें, ताकि अन्य ड्राइवर या पैदल यात्री आपके अगले कदम को समझ सकें और संभावित टकराव से बच सकें। चलते वाहन में हैजर्ड लाइट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे भ्रम पैदा होता है और टर्न सिग्नल सही समय पर काम नहीं करते।

**धीमी रफ्तार रखें :** कोहरे में वाहन हमेशा कम गति से चलाएं, क्योंकि कम दृश्यता में रुके हुए वाहन या पैदल यात्री अचानक सामने आ सकते हैं। लगभग 30 किमी/घंटा की रफ्तार सुरक्षित मानी जाती है। आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी रखें, ताकि आपात स्थिति में समय रहते ब्रेक लग सके।

**लेन में सुरक्षित रहने का तरीका :** घने कोहरे में ड्राइविंग के दौरान सड़क की सफेद लाइन पर ध्यान दें, बजाय इसके कि केवल आगे चलती गाड़ी की लाइट पर भरोसा करें। यह लाइन आपकी लेन बनाए रखने में मदद करती है और संकरी सड़कों पर सामने से आने वाले ट्रैफिक की ओर भटकने से बचाती है। अगर दृश्यता लगभग शून्य हो जाए, तो किसी सुरक्षित जगह जैसे पार्किंग या रेस्ट जोन में वाहन रोक दें और हैजर्ड लाइट ऑन करें।

**ट्रैफिक का अंदाज लगाएं :** घना कोहरा दृश्यता कम कर देता है, लेकिन सुनने की क्षमता बरकरार रहती है। खिड़कियां थोड़ी खोलें और म्यूजिक बंद करें, ताकि आसपास से आने वाले वाहन, सायरन या हॉर्न की आवाज आपको पहले सुनाई दे। यह ड्राइवर के लिए अतिरिक्त सतर्कता का एक महत्वपूर्ण साधन है। mint

# नए स्मार्टफोन से नई शुरुआत

गैजेट

**नए साल में नया और दमदार स्मार्टफोन खरीदने का विचार है तो जनवरी में लॉन्च होने वाले ये स्मार्टफोन आपको कीमत, कैमरा और परफॉर्मेंस में कुछ अच्छे विकल्प देंगे। अब बस कुछ ही दिनों में ये फोन भारत में उपलब्ध होने वाले हैं। आइए जानें, इन स्मार्टफोन की खासियतें**

### रिअलमी 16 प्रो सीरीज

जनवरी 6, 2026 को भारत में रिअलमी 16 प्रो सीरीज लॉन्च होगी। यह प्रीमियम फोन है। इसमें 200एमपी मुख्य कैमरा, बड़ा एमोलेड डिस्प्ले, लंबी बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। सीरीज में रिअलमी 16 प्रो और प्रो+ दोनों मॉडल होंगे। प्रो+ में पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ बेहतर जूम का विकल्प हो सकता है। ये फोन खासकर फोटोग्राफी और मल्टीमीडिया के लिए उपयुक्त हैं। भारत में रिअलमी 16 प्रो की शुरुआती कीमत 31,999 रुपये और प्रो+ की शुरुआती कीमत लगभग 39,999 रुपये हो सकती है।

### रेडमी नोट 15 5जी

भारत में 6 जनवरी को पेश होगा और अमेजन पर उपलब्ध रहेगा। स्नैपड्रैगन 6 जेन3 प्रोसेसर है, जो बैटरी की खपत भी कम करता है। फोन में 6.77 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 108 एमपी का कैमरा, 5,520 एमएएच की बैटरी और 45डब्ल्यू फास्ट चार्जिंग जैसे दमदार फीचर्स होंगे। कीमत 20,000 रुपये के आसपास या थोड़ा ऊपर हो सकती है। -रिया शर्मा

### पोको एम8 5जी

8 जनवरी 2026 को भारत में फ्लिपकार्ट पर लॉन्च होने वाला है। इसमें स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 प्रोसेसर मिलेगा, जो फोन को तेज चलाने के साथ बैटरी की खपत कम करता है। 6.77 इंच का एमोलेड डिस्प्ले वीडियो और कंटेंट देखने का अनुभव बेहतर बनाता है। 50 एमपी कैमरा, 5,520 एमएएच की बड़ी बैटरी और 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। अनुमानित कीमत 13,000 से 15,000 रुपये के बीच होगी, जिससे यह बजट में एक संतुलित 5जी विकल्प बनता है।

## रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

**मेष :** आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में सफल रहेंगे। लेखनादि बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। विदेश यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं।

**वृष :** वाणी में मधुरता रहेगी। कुटुंब-परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ वृद्धि भी हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा।

**मिथुन :** आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

**कर्क :** आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान हो सकता है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं।

**सिंह :** आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। कारोबार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यात्रा लाभप्रद रहेगी।

**कन्या :** मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। भवन सुख में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्य हो सकते हैं। वस्त्र आदि चीजों पर खर्च बढ़ सकते हैं।

**तुला :** मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। लेखन आदि बौद्धिक कार्यों में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार के लिए यात्रा पर जा सकते हैं।

**वृश्चिक :** मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। बातचीत में भी संतुलित रहें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है।

**धनु :** आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय वृद्धि।

**मकर :** आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, परंतु मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा।

**कुंभ :** मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। मान-सम्मान मिल सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे।

**मीन :** पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। परिवार का साथ भी मिलेगा। कारोबार के लिए यात्रा से लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे।

**स्कैन करें**
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

### व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

03 जनवरी, शनिवार, **शक संवत्:** 13, पौष, सौर शक 1947, **पंजाब पंचांग:** 20, पौष मास प्रविष्टे 2082 **इस्लाम:** 13, रज्जब, 1447 **विक्रमी संवत्** पौष शुक्ल पूर्णिमा तिथि दोपहर 01.33 मिनट तक पश्चात प्रतिपदा तिथि, आद्रा नक्षत्र सायं 05.28 मिनट तक, ब्रह्म योग प्रात: 09.05 मिनट तक पश्चात ऐन्द्र रात्रि 05.16 मिनट (सूर्योदय से पूर्व) तक। चन्द्रमा मिथुन राशि में (दिन रात)।

**सूर्य दक्षिणायन।** प्रात: 09 बजे से प्रात: 10.30 मिनट तक राहुकालम्। पौष पूर्णिमा। माघ स्नान प्रारंभ।

### वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

**घर के अंदर सब ठीक होने के बावजूद मेरी बेटी बहुत परेशान रहती है और डरती भी है। कृपया कोई समाधान बताएं। कौशांबी टोंक, अजमेर**

- आपने बेटी का कमरा वास्तु के अनुसार सही दिशा में बनवाया है, लेकिन उत्तर पश्चिम दिशा में उसके कमरे का उत्तर-पश्चिम कोना बढ़ा हुआ है, जो गलत है।
- साथ ही, उसके कमरे का द्वार भी दक्षिणी आग्नेय में है। यह भी सही नहीं है।
- आप उसके कमरे के चारों कोनों में डायरेक्शन एंगल्स लगा दीजिए।
- द्वार के ऊपर या नीचे तांबे का तार लगा दीजिए।
- उसके पैरों के नीचे सोते समय एक काला कपड़ा रखा करें, ताकि उसका डर खत्म हो।

### वर्ग पहेली : 8198

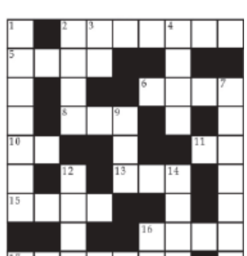

**बाएं से दाएं**
2. ढुंढवाना; खोज करवाना (3,4)
5. छटपटाना; दर्द से व्याकुल होना; गरजना (4)
6. आय पर लगने वाला कर (4)
8. असफल; विफल (3)
10. जगत; दुनिया; लोक; संसार (2)
11. उदार; दाता; दान देने वाला (2)
13. किवाड़; दरवाजा; द्वार; पट (3)
15. किसी के पूरे शरीर को खुले जल से तर करना; स्नान कराना (3)
16. पीड़ा के कारण मुंह से शब्द निकलना; कांखना (4)
17. क्रुद्ध होना; त्योरी चढ़ाना; नाराज होना (3,4)

**ऊपर से नीचे**
1. व्योम ज्ञान; वायुमंडल का विवेचक ज्ञान (4,3)
2. गरम करवाना; परिश्रम करवाना (4)
3. प्रस्तुत करना; लाकर देना (2)
4. तत्वों के योग से बना पदार्थ; रस द्रव्य (4)
7. युद्ध की नीति बनाना; रण की योजना बनाना (4,3)
9. भाल; माथा; ललाट; शीश; सिर (3)
12. चौंसठ कलाओं में से किसी भी कला को जानने वाला; चित्रकार; शिल्पकार (4)
14. भेंट होना; मिलना; उलझना; भिड़ना (4)
16. पुर्जा; मशीन; यंत्र; युक्ति; आने वाला दिन (2)

**हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली**
(उत्तर अगले अंक में)

### वर्ग पहेली : 8197

### सुडोकू : 8180

*मध्यम

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | 8 | | | | |
| | 8 | | | | | 5 | 9 | |
| | | 6 | 5 | | | 8 | | 7 |
| 2 | | 3 | | | | | 1 | |
| | | | 4 | 7 | 3 | | | |
| | 6 | | | | | 3 | | 4 |
| 5 | | 9 | | | 7 | 1 | | |
| | 7 | 8 | | | | | 2 | |
| | | | | 2 | | | | 9 |

**खेलने का तरीका :** दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

### सुडोकू : 8179

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 |
| 6 | 8 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 |

हमसे जुड़ने के लिए QR Code स्कैन करें

दैनिक नवज्योति
आपके लिए, आपके साथ
dainiknavajyoti.com
जोधपुर, शनिवार, 3 जनवरी, 2026

90 YEARS विश्वसनीयता के dainiknavajyoti.com


## गिग श्रमिकों के हितों की खातिर

गिग वर्कर्स ही हालिया 25 और 31 दिसंबर 2025 हुई राष्ट्रव्यापी हड़तालों ने देशभर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह हड़ताल उनके अस्थिर, अनिश्चित वेतन, अपारदर्शी वेतन संरचना, काम के लंबे घंटे, असुरक्षित स्थितियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर की गई थी। सर्वाधिक चिंता दस मिनट में सामान की डिलीवरी की शर्त उनके जीवन, विलंब से डिलिवरी से रेटिंग और पेनल्टी और रोजगार के लिए अलग चुनौती खड़ी कर रही है। ऐसे में यह जाहिर होता है कि पूरी गिग अर्थव्यवस्था में शोषणकारी तत्व मौजूद हैं। इन्हें समय रहते दूर कर सुधार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होने पर इन वर्कर्स का यह संघर्ष आने वाले समय में श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा और प्लेटफॉर्म कंपनियों के मॉडल को पुनर्परिभाषित करने को विवश कर सकता है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स की संख्या करीब 7.7 लाख थी। जो इस साल के अंत तक साढ़े तेईस लाख तक जा पहुंची है। अनुमान है कि यह संख्या वर्ष 2030 तक बढ़कर करीब ढाई करोड़ तक पहुंच जाएगी। आज देश में स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, जोप्टो, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्मों के डिलीवरी पार्टनर्स के अलावा लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी प्लेटफार्म भी हैं। हालांकि गैर कृषि क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में श्रमिक हैं। जो अस्थिर और अनिश्चित वेतन, वेतन संरचना में पारदर्शिता की कमी, लंबे घंटे और असुरक्षित काम करने की स्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने अपनी ओर से गिग वर्कर्स के कल्याण में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। नए श्रम कानूनों के तहत गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स को औपचारिक रूप से परिभाषित और मान्यता दी गई है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत एग्रीगेटर्स को अपने टर्नओवर का 1से 2 फीसदी सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान देने का प्रावधान किया गया है। जो इन श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को वित्त पोषित करेगा। ये श्रमिक अब सरकार द्वारा अधिसूचित दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ के भी पात्र हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की विशेषज्ञ समिति इनसे संबंधित मामलों पर सलाह देगी। लेकिन किसी विशिष्ट समस्या से निपटने के लिए सरकारी हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। उदाहरण के लिए गिग वर्कर्स के लिए डिलीवरी का समय। श्रम-बहुल अर्थव्यवस्था में वेतन वृद्धि पर दबाव पड़ने की संभावना है जिससे गैर-कृषि रोजगार के अवसर अभी भी पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि कंपनियों के लिए यह मानना जरूरी है कि गिग वर्कर उनके आॅपरेशन्स की रीढ़ है। भले ही वे शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वर्कर्स की चिंताओं को भी सुनना चाहिए। पेमेंट स्ट्रक्चर को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। डिलीवरी में थोड़ी सी देरी से उपभोक्ताओं और कंपनियों के मुनाफे से कहीं ज्यादा, गरीब वर्कर्स के वेतन हित को सोचें। ऐसे में अब दोनों पक्षों को सही और उचित हल निकालना चाहिए।

इस समस्या के समाधान के लिए जागरूकता पैदा हो

# बढ़ते शहरीकरण व ठोस कचरा प्रबंधन की समस्या

विश्लेषण

"बढ़ते शहरीकरण के फलस्वरुप बहुत सी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। शहरों पर बढ़ते जनसंख्या के दबाव के कारण पर्याप्त आवास परिवहन और अन्य सारी सेवाओं की कमी के साथ स्वच्छता के दृष्टिकोण से कचरा प्रबंधन भी एक बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आ रहा है।

आजादी के पश्चात भारत में हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ है, आज विकास के क्षेत्र में भारत विश्व में अहम स्थान रखता हैं। कृषि अंतरिक्ष विज्ञान चिकित्सा विज्ञान खनन व ई-कॉमर्स जैसे दर्जनों क्षेत्र हैं, जहां विश्व में भारत की अग्रणी भूमिका है। लेकिन तीव्र गति के विकास के साथ-साथ बहुत सी समस्याएं भी भारत के समक्ष खड़ी हैं, जिनका स्थाई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। जिनमें शहरों में से ठोस कचरे का प्रबंध 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी 30 प्रतिशत थी और यह 2030 तक 40 प्रतिशत तक पहुंचाने का अनुमान हैं। शहरी आबादी सालाना लगभग 2.3 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और इससे आर्थिक सामाजिक परिदृश्य में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। बढ़ते शहरीकरण के फलस्वरुप बहुत सी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। शहरों पर बढ़ते जनसंख्या के दबाव के कारण पर्याप्त आवास परिवहन और अन्य सारी सेवाओं की कमी के साथ स्वच्छता के दृष्टिकोण से कचरा प्रबंधन भी एक बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आ रहा है।

### कचरे के पहाड़

आज भारत के जितने बड़े शहर हैं उतनी ही व्यापक वहां कचरे के ढेर मिलेंगे। दिल्ली का गाजीपुर मुंबई का देवनार लैंडफिल कचरे के पहाड़ बन चुके हैं, जिससे मीथेन निवास करने वाले लोगों में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इससे न केवल मानवीय स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बल्कि वहां की मिट्टी और हवा भी बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि गाजीपुर और देवनार लैंडफिल के पास के क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मामलों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसके साथ ही श्वसन की अन्य बीमारियां भी त्वरित गति से बढ़ रही हैं। हम इस समय विकसित भारत 2047 के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कचरा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ा है वर्तमान में लगभग 145 मिलियन टन प्रति वर्ष की दर से यह पैदा हो रहा है और 2047 तक इसके 260 से 300 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक पहुंचाने की भी संभावना है।

### व्यावहारिक अनुपालन

यदि घरेलू स्तर पर ही उस कचरे का पृथक्करण प्रारंभ कर दिया जाए, तो नगर पालिकाओं के डंपिंग स्टेशनों पर दबाव कम पड़ेगा। नागरिकों में जागरूकता व्यावहारिक अनुपालन की कमी है, इसके साथ ही नगर पालिकाओं के पास में भी वित्त और तकनीकी संसाधनों की कमी भी है, जिससे इस समस्या के समाधान में कई व्यावहारिक समस्याएं आ रही हैं। इसका समाधान व्यक्तिगत स्तर से ही संभव हो सकता है। आज भारत के तमाम शहरों गांव मोहल्ले में हमें कचरे के ढेर देखने को मिलते हैं, जबकि वहां पर प्रतिदिन कचरा संग्रहण करने के लिए गाड़ियां आती हैं। शहरों में इधर-उधर फैल रही सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य कचरा मानव सभ्यता पर कलंक के समान है। उदाहरण के लिए देखें तो मुंबई शहर से प्रतिदिन 10000 मेट्रिक टन कचरा पैदा होता है और यह शहर ई-कचरा में भी अग्रणी है इस परिस्थिति में नगर पालिका कितना भी प्रयास कर ले नागरिक भागीदारी के बिना कचरा प्रबंधन नहीं कर सकती।

### स्वच्छ भारत मिशन

हालांकि स्वच्छ भारत मिशन गोबरधन जैसी पहलों से विभिन्न क्षेत्रों पर रचनात्मक काम किया जा रहा है, लेकिन जिस दर से ठोस कचरा पैदा हो रहा है उस दर से इसका निपटान नहीं हो पा रहा है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के द्वारा भी एक नियमावली तय की गई है, लेकिन उसका प्रभावशाली क्रियान्वयन होना आवश्यक है, ताकि व्यक्तिगत स्तर पर इस समस्या के समाधान हेतु जागरूकता पैदा हो सके। हालांकि नगर पालिकाओं के द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण एवं डंपिंग स्टेशनों पर ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं कि उसका कंपोस्ट रीसाइकलिंग इत्यादि में उपयोग किया जा सके, लेकिन घरेलू स्तर पर और संस्थागत स्तर पर कचरे का पृथक्करण नहीं किया जा रहा है सभी प्रकार के कचरे को एक ही डस्टबिन में डाल दिया जाता है और आगे जाकर वह एक बड़ी समस्या पैदा करता है।

### प्लास्टिक प्रदूषक

अध्ययन के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है, जहां से प्रति वर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट जो विश्व का लगभग 20 प्रतिशत है उत्पादित होता है, जिसमें अधिकांश भाग सिंगल यूज प्लास्टिक का है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमान अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में अपशिष्ट उत्पादन बढ़कर 165 मेट्रिक टन हो जाएगा। सेंटर फॉर शोध के अनुसार भारत में 3159 कचरे के पहाड़ हैं, जिनमें 80 करोड़ टन कचरा उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता भूमि पर जीवन भी दो प्रमुख लक्ष्य है, जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन की समस्या भी समाहित हैं। स्वच्छ सर्वेक्षणों में वर्ष 2016 से इंदौर शहर लगातार शीर्ष पर बना हुआ है और इसने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। इंदौर शहर में कचरा पृथक्करण डोर टू डोर कलेक्शन आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट जिम बायो एनर्जी और कंपोस्टिंग प्लास्टिक कचरे का प्रबंध इत्यादि बहुत सी तकनीकें हैं, जिनमें जन भागीदारी पर आधारित एक समग्र इंदौर मॉडल बनकर सामने आया है।

**अशोक चौधरी**
**यह लेखक के अपने विचार हैं।**

"

जीवन बोध

## प्रकृति एवं विज्ञान

जीवन का गूढ़ दर्शन क्या है, जीवन की गूढ़ता से उत्पन्न दर्शन दृष्टि में दो पक्ष उभरते हैं। एक, प्रकृति। दो, प्रायोगिक विज्ञान। व्योम, भूमि, वायु, जल, अग्नि जैसे अस्तित्व मौलिकता के साथ एक बृहद प्राकृतिक व्यवस्था हैं। जीवों में भी यही अस्तित्व है। ये मूल है। विशेषकर मानवीय जीवन का सर्वोच्च ध्येय इसी में निहित है। विज्ञान और इसके प्रयोग पंचतत्वों को मौलिकता से विहीन करते रहे हैं। मानव स्वरूप, जो पंचतत्वों का एक जैविक प्रतिनिधि है, वह भी अत्यधिक जैविकता विहीन हो चुका है। उसके विचार, भाव, कल्पनायें, भावनायें उसी के वश में नहीं हैं। वह वैज्ञानिक प्रयोगों के मध्य एक यंत्र हो चुका है। अरबों की संख्या में ऐसे यंत्र यहां-वहां घूम रहे हैं। ये सभी इस कठोर सत्य को विस्मृत कर- करके घूम रहे हैं कि मृत्यु ही संपूर्ण घुमाव का अंतिम लक्ष्य है। जब मानव जीवन जीने की प्रक्रिया में मृत्यु को भूलता जाता है, तो मानवीय विचारों, भावनाओं, इच्छाओं में निरंकुशता बढ़ती है। पंचतत्वों के अल्पांश के रूप में अपने तन-मन के साथ विद्यमान मानव जब अपने होने जीने के आधार प्रमुख व प्रतिनिधि तत्वों की अवहेलना, उपेक्षा व तिरस्कार में डूबा रहेगा, तो जीवन एवं जीने का महत्व क्या रहेगा ! कुछ भी तो नहीं। प्रकृति के विरुद्ध विज्ञान की यही दशा है।

**विकेश कुमार बडोला**

### हेल्थ इज वेल्थ

नए साल में हम सभी को जीवन बेहतर बनाने के लिए कुछ रेजोल्यूशन यानी संकल्प लेने चाहिए हैं, ताकि सेहत को बेहतर बनाया जा सके।

- स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैंए मौजूदा समय में हमारी सेहत के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं।
- जिन आदतों के कारण शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है उनमें शराब पीने की आदत प्रमुख है।
- अगर आप भी केवल ओकेजनल ड्रिंकर हैं, तो भी सावधान हो जाइए। इससे शरीर को इतना गंभीर नुकसान हो सकता है, जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी।
- विशेषज्ञ कहते हैं, शराब पीने की कोई भी सेफ लिमिट नहीं है।
- अल्कोहल को कई तरह के कैंसर का कारण माना जाता है। इससे लिवर के साथ मुंह के कैंसर का जोखिम भी बढ़ सकता है।
- अध्ययन में पाया गया है कि दिन में अगर आप एक ड्रिंक भी लेते हैं, तो इससे भी मुंह के कैंसर का खतरा 50 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

जल तरंग

## नमस्कार का सुख

सलाम के लिए मियांजी को क्यों नाराज किया जाये, इसे शिरोधार्य करके मैं सबको नमस्कार करता रहा, लेकिन किसी ने आगे से चलकर मुझे नमस्कार नहीं किया। इसका मुझे रंज भी कम न था। दफ्तर में कोई पोजीशन नहीं होने से वैसे ही कोई नमस्कार नहीं करता था, रही कॉलोनी की बात तो विपन्नता ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा आदमी होने के कारण नमस्कार करना आजकल वैसे ही जरूरी नहीं रह गया है। एक दिन पत्नी ने भी कुरेदा आप कब तक सबसे नमस्कार करते रहेंगे, क्या हमें नमस्कार करने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ क्या, मैंने कहा तुम बिल्कुल ठीक कहती हो ऐसा हमारा नसीब कहां, जो कोई हमें आकर नमस्कार करे। लेकिन हमें ऐसा कुछ करना ही होगा कि दस-बीस लोग हमें भी जब कभी मिलें तो नमस्कार करें। लेकिन हालात इतने विपरीत हैं कि नमस्कार करने वालों की जमात बनाना फिलहाल मुश्किल है। पत्नी बोली चमत्कार को नमस्कार है। हमारी माली हालत पतली होने से हम किसी प्रकार का चमत्कार भी नहीं कर सकते। वरना परचूनी वाले से नकद सामान उठाकर तथा मौहल्ले में कुछ दबे हुओं को उधार देकर हम नमस्कार के लिए बाध्य कर सकते हैं। गुप्ताजी को देखो कितने लोग नमस्कार करते हैं। उधार देकर ब्याज वसूलते हैं, परन्तु नमस्कार मुफ्त में लेते हैं। वरना आदमी तो एकदम लचर हैं। उन्हें नमस्कार करने की और कोई वजह नहीं है। बोलचाल में एकदम रूखे और बेहूदा है, परन्तु नमस्कार करने वालों का तांता लगा हुआ है। जब तुम जानती हो कि गुप्ताजी धनाढ्य हैं तो फिर और क्या वजह ढूंढ़नी है। हमने आर्थिक मोर्चे पर विफलता हासिल की है, इसी का परिणाम है कि नमस्कार करने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूं कि यदि हम प्रयास करें, तो दस-पांच लोग इसके लिए अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मैंने पत्नी को समझाया तो वह बोली, तो वह योजना छुपा क्यों रखी है। उसे अमल करो और नमस्कार सुख भी प्राप्त करो। दुखों की भरमार में एक सुख यह भी मिल जाये तो बहुत संतोष मिलेगा। मैं बोला हम यह कर सकते हैं कि पी.एफ से बचा-सुखा धन निकालकर उसे जरूरतमंदों को उधार दे दें। हो सकता है इस नवीन चमत्कार से नमस्कार का भाव पड़ोसियों में पैदा हो। कुछ पैसा मैं दफ्तर में फोर्थ क्लास में बांट दूंगा तो उधार भी मेरा आभामण्डल दमकाने लगेगा तथा चार-पांच जोड़ी ढ़ंग के कपड़े सिलवा लेता हूं, इससे भी फर्क पड़ेगा। यदि हमने ऐसा करके दस-पांच लोग भी जुटा लिये, तो अपना काम बन जायेगा। इधर मैं भी बात-बात पर टिटियाना बंद कर देता हूं। पत्नी बोली योजना तो सुखकारी है, लेकिन आपके पी.एफ में क्या है, यह मालूम करना जरूरी है। यदि पी. एफ ने धोखा दे दिया तो फिर कोई हमारा साथ नहीं देगा। मैं बोला घबराओं नहीं, अब मैं जुगाड़ कर लूंगा और नमस्कार सुख प्राप्त करके ही दम लूंगा। दिखावे का जमाना है। अभावों का रोना, बंद करो।

**पूरन सरमा**
**यह लेखक के अपने विचार हैं।**

### आज का विचार

यह चेतना को नया रूप देने का अवसर है। यह वह समय है, जब प्रकृति कहती है, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर सकते हो उसे कर दिखाओ।

**श्री चंद्रप्रभ जी।**

विंडो टू द वर्ल्ड

## भारत का सबसे ठंडा गांव

लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित द्रास गांव में भीषण सर्दी पड़ती है। इसे भारत का सबसे ठंडा गांव माना जाता है। यहां सर्दियों में तापमान कई डिग्री तक गिर जाता है,और गीले कपड़े टांगते ही कुछ ही देर में जम जाते हैं। द्रास को गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है। भारत में स्थित ये खूबसूरत जगह चारों तरफ से 16 हजार से 21 हजार फीट ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है।

अपनों से अपनी सी बात

## सांसारिक बन्धन

एक राजा ने कबीर साहब से प्रार्थना की कि आप दया करके मुझे सांसारिक बन्धनों से छुड़ा दो कबीर ने कहा, आप तो हर रोज पण्डित जी से कथा करवाते हो, सुनते भी हो। हां जी महाराज जी !कथा तो पण्डित जी रोज सुनाते हैं, विधि-विधान भी बताते हैं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, आप ही कृपा करें। अच्छा मैं कल कथा के वक्त आ जाऊंगा। अगले दिन कबीर वहां पहुंच गए, वहां राजा पण्डित जी से कथा सुन रहे थे। राजा उठकर श्रद्धा से खड़े हो गए। कबीर बोल राजन अगर आपको प्रभु का दर्शन करना है, तो मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। जी महाराज मैं आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूं जी ! राजन अपने वजीर को हुकुम दो कि वो मेरी हर आज्ञा का पालन करे। राजा ने वजीर को हुकुम दिया कि कबीर साब जैसा भी कहें वैसा ही करना। कबीर ने वजीर को कहा कि एक खम्बे के साथ राजा को बांध दो और दूसरे खम्बे के साथ पण्डित जी को बांध दो।राजा ने तुरन्त वजीर को इशारा किया कि आज्ञा का पालन हो। दोंनो को ही खम्बे से बांध दिया गया। कबीर साब ने पण्डित जी से कहा कि देखो राजा साब बंधे हुए हैं, उन्हें तुम खोल दो। पण्डित हैरान होकर बोला, महाराज मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूं। उन्हें कैसे खोल सकता हूं कबीर ने राजा से कहा, ये पण्डित जी तुम्हारे पुरोहित हैं, वे बंधे हुए हैं, उन्हें खोल दो। महाराज मैं भी बंधा हुआ हूं, भला इन्हें कैसे खोलूं। फिर कबीर ने सबको समझाया, जो पण्डित ही कर्मो के बन्धनों फंसा है, जनम मरण के बन्धन से छूटा नहीं, भला वो तुम्हें कैसे छुड़ा सकता है।अगर तुम सारे बन्धनों से छूटना चाहते हो, तो सतगुरू की शरण में जाओ, जो जन्म मरण के बन्धन से छूट चुका हो। केवल एक सन्त सद्गुरु ही सारे बन्धनों से आजाद होते हैं।

**ललित अकिंचन**

Feedback@dainiknavajyoti.com

नजरिया

"2026 में कदम रखना केवल कैलेंडर का पन्ना पलटना भर नहीं है, बल्कि यह आत्ममूल्यांकन और नव-आरंभ का अवसर है। वास्तव में सच तो यह है कि यह समय उन सपनों और लक्ष्यों को फिर से साधने का है, जो बीते वर्ष परिस्थितियों, सीमाओं या संकोच के कारण अधूरे रह गए।

आशा, संकल्प और सकारात्मक दृष्टि के साथ बढ़ने का संदेश

# नया वर्ष : अतीत से सीख लेकर भविष्य की ओर

साल 2025 से 2026 में कदम रखना केवल कैलेंडर का पन्ना पलटना भर नहीं है, बल्कि यह आत्ममूल्यांकन और नव-आरंभ का अवसर है। वास्तव में सच तो यह है कि यह समय उन सपनों और लक्ष्यों को फिर से साधने का है, जो बीते वर्ष परिस्थितियों, सीमाओं या संकोच के कारण अधूरे रह गए। साथ ही, यह आने वाली चुनौतियों को पहचानकर उनके लिए स्वयं को मानसिक, बौद्धिक और व्यवहारिक रूप से तैयार करने की प्रेरणा देता है। नया वर्ष हमें अतीत से सीख लेकर भविष्य की ओर आशा, संकल्प और सकारात्मक दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। कोई भी साल पूरी तरह आदर्श नहीं होता, और 2025 भी इसका अपवाद नहीं रहा। हालांकि, उससे मिली सीख नए वर्ष में दिशा दिखा सकती है। बीता साल आर्थिक लिहाज से भारी उतार-चढ़ाव से भरा रहा। लंबी तेजी के बाद शेयर बाजार में सुस्ती आई, वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के दोबारा सत्ता में आने के साथ टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। इन चुनौतियों के बीच भारत ने संतुलन और दृढ़ता का परिचय दिया।

### बड़े सुधार लागू किए

पिछले साल देश के भीतर जीएसटी 2.0 जैसे बड़े सुधार लागू किए गए, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अच्छी खासी मजबूती मिली। साल के अंत तक भारत ने जापान को पीछे छोड़कर लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान उसकी तेज और निरंतर आर्थिक वृद्धि पर आधारित है। कहना गलत नहीं होगा कि मजबूत घरेलू मांग, बढ़ता मध्यम वर्ग, सरकारी पूंजीगत खर्च, बुनियादी ढांचे में निवेश और जीएसटी जैसे संरचनात्मक सुधारों ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। साथ ही, वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव और भारत को वैकल्पिक उत्पादन केंद्र के रूप में मिल रहा भरोसा निवेश और निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। इसके विपरीत, जापान की अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि, घटती आबादी और सीमित घरेलू मांग से जूझ रही है।

### भारत की जीडीपी

इन सभी कारणों के चलते भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है और मौजूदा अनुमानों के अनुसार वह वर्ष के अंत तक जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच सकता है। इसके अलावा, अन्य देशों के साथ हुई व्यापार संधियां और अमेरिका के साथ होने वाला समझौता पूरा होने से आगे चलकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैश्विक स्तर पर आर्थिक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत बने रहने की संभावना है। इसका मुख्य कारण देश के भीतर मजबूत मांग, महंगाई का नियंत्रण में रहना और सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की संतुलित आर्थिक नीतियां हैं। अनुमान है कि भारत 2030 तक जर्मनी को भी पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा।

### रिपोर्ट के अनुसार

सरकार ने भरोसा जताया है कि मजबूत आर्थिक नींव के साथ, भारत की जीडीपी 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, देश के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अच्छी स्थिति में हैं, उनके पास पर्याप्त पूंजी और नकदी भंडार है, खराब कर्ज में कमी आई है और उनका मुनाफा भी मजबूत बना हुआ है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि केंद्रीय बैंक के दबाव परीक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ है कि प्रतिकूल हालात में भी बैंक संभावित नुकसान सहन कर सकते हैं और उनकी पूंजी नियामकीय न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर रहेगी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, समाशोधन निगम, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और बीमा क्षेत्र भी मजबूत स्थिति में हैं, जिनकी पूंजी पर्याप्त है और बहीखाते संतुलित हैं। हालांकि, निकट भविष्य में भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता से कुछ जोखिम बने हुए हैं,कुल मिलाकर भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर और सुरक्षित बनी हुई है।

### चुनौतियों का सामना

देश की अर्थव्यवस्था की तरह ही हमारे देश ने पिछले साल यानी कि वर्ष 2025 में सीमा से जुड़ी चुनौतियों का भी मजबूती से सामना किया। पड़ोसी देशों से रिश्तों की बात करें तो चीन के साथ लंबे समय से चला आ रहा तनाव कुछ हद तक कम हुआ। इसके साथ ही भारी बारिश, भूस्खलन, वायु प्रदूषण और अरावली से जुड़े मामलों के कारण पर्यावरण पूरे साल एक बड़ा मुद्दा बना रहा। एसआइआर को लेकर भी राजनीतिक विवाद देखने को मिला। राहत की बात यह रही कि इन सभी विषयों पर जनता पहले से ज्यादा जागरूक और सजग नजर आई। अंत में यही कहूंगा कि नये साल में यानी कि वर्ष 2026 में भारत से कई बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। सबसे बड़ी आशा यह है कि देश तेज और स्थिर आर्थिक वृद्धि के साथ दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आम लोगों की आय में सुधार आएगा। कुल मिलाकर, 2026 से अपेक्षा है कि भारत विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाते हुए नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएगा।

**सुनील महला**
**यह लेखक के अपने विचार हैं।**

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 03-01-2026 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH10 User: dilip.lal Time: 01-02-2026 22:08 Color:



# लीपापोती का प्रयास

## इंदौर में मौत के आंकड़ों पर बहस

**स्वच्छता रैंकिंग** में लगातार टॉप पर आने वाले इंदौर में दूषित पेयजल की वजह से हुई मौतें लापरवाही का नतीजा हैं। स्थानीय लोगों का यह आरोप बेहद गंभीर है कि पानी की क्वॉलिटी को लेकर लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। और दुर्भाग्य से इतनी बड़ी वारदात के बाद भी अदालत को दखल देकर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने का आदेश देना पड़ रहा है।

हाईकोर्ट में सुनवाई

**अलग-अलग आंकड़े।** मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान नगर निगम की तरफ से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में दूषित पेयजल की वजह से केवल चार मौतें बताई गई हैं, जबकि वहीं के मेयर का कहना है कि 10 लोगों की मौत हुई और दूसरे सोर्स संख्या 15 बता रहे हैं। मौत के आंकड़ों पर बहस साबित करती है कि अब भी इस घटना से सबक लेने के बजाय लीपापोती करने का प्रयास है। दूषित पेयजल की वजह से एक भी मौत होना शर्मनाक है और यहां तो 200 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा।

**कार्रवाई काफी नहीं।** राज्य सरकार ने नगर निगम के आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, अपर नगर आयुक्त को इंदौर से हटा दिया है और प्रभारी अधीक्षण अभियंता से जिम्मेदारी वापस ले ली है। लेकिन, क्या इतना काफी है? इस तरह की 'रूटीन' कार्रवाई जिम्मेदारों को सबक नहीं देतीं, बल्कि पीड़ितों का मजाक बनाती हैं। यहां ऊपर से नीचे तक, सभी की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

**सुधार की जरूरत।** इंदौर के भागीरथपुरा की घटना जरूरी नागरिक सुविधाओं की कमी की ओर भी इशारा करती है। आज भी देश में हर एक लाख आबादी पर औसतन लगभग 35 लोगों की दूषित पेयजल की वजह से जान जाती है। ग्लोबल एवरेज की तुलना में यह लगभग तीन गुना है। बेशक सरकार ने जल जीवन मिशन जैसे अभियान चलाए हैं, जिसकी बदौलत करीब 81% ग्रामीण घरों में टैप वॉटर पहुंचाने का दावा है, लेकिन अब भी सुधार की बहुत जरूरत है।

**चुनौती और बढ़ेगी।** भारत ने 2047 तक विकसित देशों की कतार में खड़े होने का लक्ष्य रखा है, लेकिन पहले आम लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा। 2050 तक भारत की आबादी 1.7 अरब तक होने का अनुमान है और तब पानी के संसाधनों पर और दबाव पड़ेगा। देश को बेहतर वॉटर मैनेजमेंट के साथ सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, तभी इस चुनौती का सामना किया जा सकता है।

## और सुनाओ

# पापा कहते हैं

**बहुत सारे** माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़ा नाम करें। IIT, NEET, IIM, UPSC... इस जैसे किसी भी इलीट क्लब का हिस्सा बनें। यह चाहत गलत नहीं है। लेकिन असली सवाल यह है कि वो खुद क्या बनकर जी रहे हैं? क्या आपने वो लोग देखे हैं, जो सुबह उठते हैं तो उनके सामने जीवन के लिए कोई उद्देश्य नहीं होता। मोबाइल फोन से दिन की शुरुआत होती है। घंटों रील्स देखते हैं। ऑफिस जाते हैं, वहां काम के अलावा सब कुछ करते हैं। टाइम पास, गुटबाजी और राजनीति। शाम को घर लौटते हैं तो फिर वही स्क्रीन। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम हो जाती है।

रमेश तिवारी

हाल ही में एक मित्र से मुलाकात हुई। बेहद मामूली बैकग्राउंड से निकलकर नॉलेज की दुनिया में काम कर रहे हैं।उनके बच्चे के जीवन में भी बेहतरी की जानकारी मिली। मैंने उनसे पूछा कि इस पूरी यात्रा से उन्होंने क्या सबक लिया। उनका जवाब था, अगर हम बच्चों को बेहतर जीवन देना चाहते हैं तो हमें खुद के भीतर भी बेहतरी की चाह रखनी होगी। कई लोग मिलेंगे, जिनके अंदर खुद कुछ स्किल सीखने की भूख नहीं होती। उन्होंने अपनी जो थोड़ी बहुत दुनिया बदली तो हो सकता है कि उसमें भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद का हाथ हो। इस बूते हालात फिलहाल ठीक-ठाक हो गए, अब इच्छा है कि समाज में पहचान दूसरों से 'अनमैचेबल' हो जाए।

पीढ़ियों के जीवन-स्तर में बदलाव इन्क्रीमेंटल होना चाहिए, धीरे-धीरे। लेकिन हम एकाएक बड़ा बदलाव चाहते हैं। और हां, यह जरूरी नहीं कि बच्चे को अच्छी सफलता दिलाने के लिए माता-पिता खुद बहुत सफल हों। लेकिन यह आवश्यक है कि बच्चे अपने माता-पिता को जूझते हुए, सीखते हुए देखें। घर में बेहतर बनने की एक संस्कृति होनी चाहिए।

खुद से आदर्श गढ़ने की जगह वो पैमाने खड़े कर दिए जाते हैं, जिनमें ज्यादातर नाकारा साबित कर दिए जाते हैं। कई बच्चे खरा उतरने के लिए खुद को गला देने वाली मेहनत भी करते हैं। इस बहुरंगी जीवन की ढेरों बुनियादी बातों से दूरी बना लेते हैं। वे एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, उसे देखकर भी घरवाले नजरअंदाज कर देते हैं। सबको पता है कि इन परीक्षाओं को पास करना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। दस-पंद्रह लाख बच्चों की भीड़ में से कुछ हजारों की जगह बनेगी। लेकिन लॉलीपॉप स्थापित करने के लिए यही तो चाहिए।

सबसे लुभावनी बात तो ये बताई जाती है कि अगर तुमने ये कर लिया तो लाइफ सेट हो जाएगी। ये कभी सेट नहीं होती। होनी भी नहीं चाहिए। एक संघर्ष जारी रहे। इसे पहले पैरंट्स ही लीड करें। जीवन में जहां हैं, उसी जगह से। अभिभावक एक रोल है, कोई अथॉरिटी नहीं। वो बस अपने रोल को ठीक से निभा ले जाए, यही काफी होगा।

## ऑफ़ दि ट्रैक

# सबसे पुराने क़दम

दिलीप लाल

**सऊदी अरब** के रेगिस्तान से इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी है, जो मनुष्य के पहले माइग्रेशन की कहानी को और स्पष्ट करती है। पश्चिमी नेफुद डेजर्ट में स्थित Alathar नामक स्थल पर वैज्ञानिकों को लगभग 1.15 लाख वर्ष पुराने मानव पदचिह्न मिले हैं। इन्हें अरब प्रायद्वीप में आधुनिक मानव (Homo sapiens) की अब तक की सबसे पुरानी प्रत्यक्ष मौजूदगी का प्रमाण माना जा रहा है। यह खोज उस धारणा को चुनौती देती है, जिसमें आज के सऊदी अरब को केवल सूखा, तपता और निर्जन क्षेत्र समझा जाता है। जांच से पुष्टि हुई कि ये किसी जानवर के नहीं, बल्कि इंसानों के हैं। इन पदचिह्नों की आयु Last Interglacial Period की बताई गई है, जब पृथ्वी की जलवायु अधिक नम और मानव जीवन के लिए अनुकूल थी। उस समय नेफुद डेजर्ट में मीठे पानी की झीलें, घास के मैदान और बड़े जानवर मौजूद थे। यहां पत्थर के औजार, आग या हड्डियों के प्रमाण नहीं मिलने से यह स्पष्ट होता है कि यह कोई स्थायी बस्ती नहीं, बल्कि मानव प्रवास के दौरान का अस्थायी पड़ाव था। यह खोज उस सिद्धांत को मजबूती देती है कि अरब प्रायद्वीप कभी अफ्रीका, लेवांत और दक्षिण एशिया को जोड़ने वाला एक 'ग्रीन कॉरिडोर' था, जिसके जरिए प्रारंभिक मानव अफ्रीका से निकलकर दुनिया के अन्य हिस्सों की ओर बढ़े।

## केंद्र ने नए साल में 4000 मंदिरों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई

# दक्षिण की ओर चला धर्म रथ

**प्रत्यक्षं किम् प्रमाणं** - जो सामने है, उसके लिए प्रमाण जरूरी नहीं होता। मेरे खयाल से सनातन धर्म के लिए यह बात एकदम सही है। किसी को शक नहीं है कि सनातन धर्म का ध्वज आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शीर्ष पर लहरा रहा है। भले ही आप इसे राजनीतिक चश्मे से देखें, लेकिन मानेंगे कि भारत में करीब एक दशक पहले बदले राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद सब इतना आसान नहीं था।

विश्वनाथ गोकर्ण

**दुर्लभ संयोग।** एक साल पहले महाकुंभ की गूंज अचानक से तेज हुई। 144 साल के दुर्लभ संयोग की चर्चा हर जगह होने लगी। लोगों को लगा कि अब नहीं गए, तो कभी नहीं जा पाएंगे। बड़ी संख्या में लोग तमाम मुश्किलें उठाकर और जमा-पूंजी लगाकर इस ऐतिहासिक मौके को अपने नाम करने पहुंचे।

**जेब खाली, मन भरा।** प्रयागराज पहुंचने वाला हर श्रद्धालु अपनी हैसियत से थोड़ा अधिक ही खर्च कर आया। नतीजतन, पंडित-पुरोहितों के साथ ई-रिक्शा, ऑटो, ठेला चालकों की भरपूर कमाई हुई। होटल, रेस्तरां वाले भी मालामाल हो गए।

**आज भी सिहरन।** महाकुंभ की यादों से लोग आज भी रोमांचित हो उठते हैं। वे याद करते हैं कि प्लेन टिकट महंगा था, ट्रेनों में जगह नहीं थी और रास्ते जाम थे, फिर भी लोग पहुंचे। जो होटल का खर्च नहीं उठा सकते थे, उन्होंने सड़क किनारे ही डेरा डाल दिया।

**इकॉनमी को बूस्ट।** केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के एक सर्वे के मुताबिक, महाकुंभ पहुंचे हर श्रद्धालु ने औसतन 5.8 हजार रुपये खर्च किए। मेले में लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। इस हिसाब से यूपी की इकॉनमी को करीब 3.88 लाख करोड़ का बूस्ट मिला। सर्वे से यह भी भी पता चलता है कि लोगों ने घूमने पर 41% से ज्यादा खर्च किया, जबकि रहने पर 16.64% और खाने पर केवल 11.24%।

**सभी को फायदा।** मेले में लोगों ने पुण्य ही नहीं कमाया, बड़े पैमाने पर रोजगार का मौका भी भुनाया। गंगाजल के लिए प्लास्टिक कैन और बोतल का कारोबार ही करोड़ों रुपये का हो गया। दक्षिण भारत में रहने वालों ने लाखों रुपये खर्च कर टैंकर से संगम का जल मंगाया। उन्होंने अपने इलाके के मंदिरों में जलाभिषेक किया और कई लोगों को निःशुल्क बांटा। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर और नागवासुकि मंदिर सहित कई कॉरिडोर का लोकार्पण किया जाना इन्हीं में से एक था। अब एक बार फिर प्रयागराज माघ मेले के लिए सज चुका है।

नए साल की आशा

**कॉरिडोर निर्माण।** महाकुंभ बीतते-बीतते लगा, सनातनी चर्चाएं कम होने लगेंगी, लेकिन उज्जैन के श्री महाकालेश्वर और मां विंध्याचल देवी कॉरिडोर निर्माण ने सनातनी उत्थान यज्ञ में आहुति दे दी। साल के आखिर तक प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर बहुप्रतीक्षित धर्म ध्वजा फहराया। इसे सनातन ध्वजा कहा गया, जिससे अयोध्या पर फिर विश्व भर में चर्चा होने लगी। आलम है कि अयोध्या, काशी और मथुरा में रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

**धार्मिक टूरिज्म।** पिछले साल इतने धार्मिक आयोजन हुए कि साल के अंत में लोग पहाड़ों और समुद्र किनारे छुट्टियां बिताने के बजाय धर्मस्थलों पर गए। पुराने साल को विदा करने वालों की भीड़ काशी, अयोध्या, मथुरा, वैष्णो देवी, कांची, मदुरै, तिरुपति और गोकर्ण जैसे स्थानों पर रही। कई पर्यटक द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर हैं, तो कई शक्तिपीठ पहुंच गए।

**अब दक्षिण की बारी।** केंद्र ने नए साल में तमिलनाडु में चार हजार मंदिरों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई है। ऐसा हुआ तो अब दक्षिण भारत में और भीड़ बढ़ेगी। इसके अलावा, 17 फरवरी को आंशिक सूर्य ग्रहण है। इसमें भी पवित्र नदियों वाले शहरों में लोग जाएंगे। इस दौरान कई अहम धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकते हैं। बहरहाल नए साल में भारत को तमाम मोर्चों पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, मगर संदेह नहीं है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सनातनी धर्म ध्वजा लहराता रहेगा।

*(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)*

**धार्मिक पर्यटन**

- काशी और अयोध्या में हर दिन आ रहे लाखों श्रद्धालु
- घूमने के लिए भी धार्मिक शहरों का रुख कर रहे लोग

# डेटिंग ऐप्स पर जॉब सर्च

**डेटिंग ऐप्स को प्यार तलाशने का जरिया माना जाता है। लेकिन, AI के जमाने में हालात बदल रहे हैं। एक सर्वे से पता चला है कि युवा अब इंटर्नशिप, जॉब इंटरव्यू और फ्रीलांसिंग के लिए भी डेटिंग ऐप्स का सहारा ले रहे हैं।**

5 पॉइंट

**1 2,200 लोगों का सर्वे**
सर्वे में शामिल एक तिहाई ने बताया कि नौकरी के लिए ही डेटिंग ऐप्स पर मैच ढूंढा। दो तिहाई ने अपनी पसंद की कंपनी के लोगों को राइट स्वाइप किया, जबकि आधे ने सीनियर पोजिशन वाले लोगों को चुना।

**2 मैनेजर तक पहुंच**
दरअसल, हायरिंग सिस्टम में AI के आने से योग्य उम्मीदवारों के रेज्यूमे ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। जॉब मार्केट और कठिन हो गया है। इसलिए, हायरिंग मैनेजर तक पहुंचने के लिए भी इनका सहारा लिया जा रहा है।

**3 पहचान में मददगार**
नेटवर्क बढ़ाने के लिए भी डेटिंग ऐप्स की मदद ली जा रही है, क्योंकि नौकरी तब ही मिलती है जब उस कंपनी में किसी से पहचान हो। ऐसे में युवा पहले ऐप्स से दोस्ती कर रहे और फिर उसी दोस्त से नौकरी मांग रहे।

**4 फ्रीलांस जैसा रिश्ता**
कई लोगों ने डेटिंग ऐप्स पर बनाए रिश्तों को फ्रीलांसिंग के लिए भुनाया। कुछ को रिश्ते में आने के बाद फ्रीलांस काम मिल गया, लेकिन उनका रिश्ता चला नहीं। हालांकि कुछ का रिश्ता नौकरी से आगे भी बढ़ा।

**5 कंपनियां कन्फ्यूज**
डेटिंग ऐप्स कंपनियों के लिए यह ट्रेंड नया है। उनके यूजर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता है कि अगर हायरिंग के लिए ऐप्स का इस्तेमाल होने लगा तो उन पर भरोसा घटेगा।

*प्रस्तुतिः अभिषेक मिश्र*

# राजशाही की वापसी का तो सवाल ही नहीं

*राजशाही का अंत कर गणतांत्रिक व्यवस्था अपनाने और एक प्रगतिशील संविधान हासिल कर लेने के बाद भी नेपाल लोकतंत्र की राह पर सहजता से आगे नहीं बढ़ पा रहा। एक के बाद दूसरी अनिश्चितता से उसका पाला पड़ता रहा है। इसी की ताजा कड़ी है गत सितंबर में हुआ Gen Z विद्रोह, जिसने तत्कालीन ओली सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की की अगुआई वाली अंतरिम सरकार ने मार्च में आम चुनाव करवाने का ऐलान किया है, लेकिन इस बीच पुरानी संसद को बहाल करने की मांग भी जारी है। ऐसे में पिछले दिनों दिल्ली आए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. बाबूराम भट्टराई से बातचीत कर NBT के* ***प्रणव प्रियदर्शी*** *ने यह समझने का प्रयास किया कि नेपाल इन हालात में कैसे फंसा और यहां से आगे की उसकी राह किस ओर जाती दिखती है। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंशः*

NBT सप्ताह का इंटरव्यू

डॉ. बाबूराम भट्टराई

> “असलियत यह है कि भारत और नेपाल के संबंध इतने पुराने और इतने गहरे हैं कि उसे किसी तरह से रिप्लेस करने की बात सोची भी नहीं जा सकती। फिर भी, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी मूर्खता करने की सोचता भी है तो खुद चीन उसे अस्वीकार कर देगा। ये बातें रेकॉर्ड पर हैं कि 19वीं और 20वीं सदी में जब भी ऐसी कोशिश की गई, चीन ने उसे हतोत्साहित किया।

■ **आप न केवल जनयुद्ध के दौर की अगुआई करने वाले प्रमुख नेताओं में रहे हैं, बल्कि संविधान समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं। जिस अनिश्चितता में नेपाल अभी फंसा है, उसे देखते हुए क्या चुनाव तय समय पर होने की आशा है?**

मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, इसलिए यह नहीं बता सकता कि चुनाव समय पर होंगे या नहीं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि चुनाव तय समय पर ही होने चाहिए। सबके लिए यही सही है, नेपाल की जरूरत यही है।

■ **सितंबर में नेपाल में सड़कों पर Gen Z का जो गुस्सा फूटा था, उसे आप किस तरह से देखते हैं?**

हमने नेपाल में लंबे संघर्षों के बाद संघीय गणतांत्रिक संविधान बनाया, उससे राजनीतिक तौर पर तो लोकतंत्र स्थापित हो गया, लेकिन उसके बाद जो बराबरी, समृद्धि, खुशहाली आनी चाहिए थी, वह नहीं लाई जा सकी। उसके खिलाफ नेपाल के युवाओं का असंतोष सामने आया, वही Gen Z विद्रोह था।

■ **पूर्व पीएम केपी ओली कहते हैं, उसके पीछे विदेशी हाथ था। उनका इशारा भारत की ओर है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं?**

देखिए, जो भी शासक वर्ग के लोग होते हैं वे इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह की कॉन्सपिरेसी थियरीज को मैं नहीं मानता। यह नेपाल के युवाओं का असंतोष था, जेनुइन विरोध था, इसमें कोई शक नहीं। हां, एक बार ऐसा विरोध फूट पड़ता है तो उसमें कुछ गलत तत्व भी प्रवेश कर जाते हैं। इसमें भी अगर ऐसा कुछ होगा, तो इसकी जांच चल ही रही है, उसमें सामने आ जाएगा, लेकिन मूलतः यह नेपाल के युवाओं का असंतोष था, उसके कारण भी आंतरिक थे।

■ **क्या थे वे आंतरिक कारण?**

दो तरह के फैक्टर रहे इसके पीछे। जनयुद्ध के लंबे दौर के बाद हमने राजशाही का अंत करके नया संविधान बनाया। उसके बाद अजेंडा बदल गया था। इसलिए हमारी जो माओवादी पार्टी थी, हमने कहा था कि उसका कार्यभार पूरा हो गया है। उसके बाद नई तरह की राजनीति की जरूरत थी, सुशासन के जरिए आर्थिक समृद्धि लाने की जरूरत थी। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। पुरानी पार्टी के पुराने नेता पुराने ही तौर-तरीके चलाते रहे। लिहाजा आर्थिक क्रांति नहीं हो पाई जिसका नतीजा इस विस्फोट के रूप में दिखा। दूसरा फैक्टर यह भी रहा कि टेक्नॉलजी के विकास, खासकर इंटरनेट की पहुंच से युवाओं की चेतना बढ़ी। उस लिहाज से उनकी आकांक्षाएं बढ़ीं। तो वस्तुगत और मनोगत ये दोनों कारण रहे।

■ **नेपाल में राजतंत्र की वापसी की मांग भी सुनने में आ रही है कई कोनों से। यह खतरा कितना वास्तविक है?**

देखिए, किसी भी समाज में एक छोटा सा हिस्सा तो होता ही है जो अतीतोन्मुख होता है। तो कभी ऐसा कोई स्वर कहीं से उठ जाए बात अलग है, वास्तव में ये फ्रिंज एलीमेंट्स ही हैं। राजशाही की वापसी का सवाल ही नहीं उठता। नेपाल उस दौर को पीछे छोड़ चुका है।

■ **केपी ओली के शासनकाल में खास तौर पर भारत विरोधी भावनाओं का उभार देखा गया। भारत के बरक्स चीन के करीब जाने का रुझान भी नजर आया...**

ऐसी बातें करने वाले जो भी लोग हों, वे हकीकत से अनजान हैं। कुछ लोग अपने किसी संकीर्ण स्वार्थ की वजह से भी ऐसी बातें प्रचारित करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि भारत और नेपाल के संबंध इतने पुराने और इतने गहरे हैं कि उसे किसी तरह से रिप्लेस करने की बात सोची भी नहीं जा सकती। फिर भी, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी मूर्खता करने की सोचता भी है तो खुद चीन भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये बातें रेकॉर्ड पर हैं कि 19वीं और 20वीं सदी में जब भी ऐसी कोशिश की गई, चीन ने उसे हतोत्साहित किया। चीन की तरफ से स्पष्ट बता दिया गया कि नेपाल का हित भारत से अच्छे संबंध बनाए रखने में है और सुरक्षित तथा स्थिर नेपाल चीन के भी हक में है।

■ **बीसवीं सदी में वामपंथी विचारों ने नेपाल और भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में गहरी छाप छोड़ी। लेकिन 21वीं सदी में उसका प्रभाव कमजोर होता जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि यह विचारधारा अप्रासंगिक होती जा रही है?**

कोई भी विचारधारा अपने समय और समाज से निरपेक्ष नहीं होती। आज तकनीकी विकास ने हमारे जीवन, सोच और जरूरतों को बदल दिया है। विचारधारा को भी उसी हिसाब से जरूरी बदलाव करने होंगे, तभी वह अपनी प्रासंगिकता बनाए रख पाएगी।

www.nbt.in

# ऐसी दुश्मनी पहले तो न थी!

**उत्तराखंड के** पर्वतीय जिलों में वन्यजीवों और इंसानों का आमना-सामना होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पहले भी इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष होता था, लेकिन कभी-कभार। और इसके बावजूद दोनों के बीच का रिश्ता सहज और समन्वय का था। यह रिश्ता कैसे बिगड़ा, इसे लेकर तमाम रिपोर्ट हैं - मुझे तो वे तीन कहानियां याद हैं, जो बता देती हैं कि पहाड़ों पर आखिर चल क्या रहा है।

चमोली के ज्योतिर्मठ की दया भिलगवाल को अब भी रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है। उनके सिर पर 22 और मुंह पर 12 टांके लगे हैं। घाव का निशान गहरा है। यह निशान उन्हें मिला था 4 नवंबर 2024 की सुबह। वह घर के पास खेतों में पशुओं के लिए घास लेने गई थीं। जब वह घास काट रही थीं, तभी भालू ने उन पर हमला कर दिया। दया ने कुछ देर तक मुकाबला किया, लेकिन फिर पस्त पड़ गईं। उनकी चीख सुनकर परिवार के लोग जब तक पहुंचते, भालू ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था।

दूसरी कहानी है उत्तरकाशी के मातली गांव की सुंदरी देवी की। उनकी उम्र 80 बरस है और उन्होंने पहाड़ को बदलते बहुत करीब से देखा है। उनसे जब इस बारे में बात हुई तो कहने लगीं, 'हमारे लिए जंगल सिर्फ पेड़-पौधों और हरियाली नहीं, हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। हम अपने आसपास के जंगल में बिना डर के जातेए थे। तब पता होता था कि कौन-सा इलाका हमारा है और कौन-सा वन्य जीवों का। दोनों ही इस सीमा को मानते। न हम उनके क्षेत्र में बिना जरूरत जाते और न ही वे इधर आते। आज जब इंसान पहले जैसा नहीं रहा, तो जंगल भी बदल गया है। हमने प्रकृति से दूरी बना ली है। जंगल और इंसान के बीच की समझ, उनके बीच का संतुलन टूट रहा है।' सुंदरी देवी ने अपने साथ घटी एक घटना बताई। वह रोज की तरह जंगल में चारा-पत्ती लेने गई थीं। एक पेड़ पर चढ़कर जब वह पत्तियां तोड़ रही थीं, तभी उनका गमछा गिर गया। उन्होंने नीचे देखा तो एक भालू आराम फरमा रहा था। वह न चीखीं और न घबराईं। पत्तियां तोड़ने के बाद वह धीरे से नीचे उतरीं और गमछा उठाकर घर चल पड़ीं। 'मुझे डर इसलिए नहीं लगा कि वह भी जंगल का हिस्सा है और मैं भी। तब तो कभी-कभी बाघ और तेंदुए भी गांव और घरों के आसपास दिखाई दे जाते थे। लेकिन, वे चुपचाप आते और चले जाते। अब आपस में दुश्मनी का भाव हो गया है, जो तब नहीं था।'

खुद अपनी आंख से

बृजेश सती

तीसरी कहानी है मिली कोट गांव के भरत सिंह चौधरी की। उनके साथ हाल ही में घटना हुई, 26 नवंबर को। वह पौधों में पानी दे रहे थे, जब अचानक भालू ने हमला कर दिया। उन्होंने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, पर भालू ने उन्हें खींच लिया। 55 साल के भरत सिंह ठीक हैं, लेकिन शायद पहले जितने भरोसे के साथ वह अब जंगल में कदम न रख पाएं।

## चलते-चलते...

**वैज्ञानिकों ने** गाजर के बेकार समझे जाने वाले कचरे को उच्च पोषण और स्वादिष्ट प्रोटीन स्रोत में बदलने का एक नया तरीका खोज लिया है। American Chemical Society की रिपोर्ट के अनुसार, इससे तैयार फंगल मायसेलियम का उपयोग पैटी और सॉसेज में किया गया। सोया या चने की तुलना में इस फंगल प्रोटीन से बने उत्पादों को लोगों ने अधिक पसंद किया।

## रीडर्स मेल

### नए दौर की हो रणनीति

**यह पत्र** 1 जनवरी के लेख 'जो वादा किया है, निभाना पड़ेगा' से संबंधित है। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है और हमें उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय वायु सेना के प्रमुख लड़ाकू विमानों की डिलिवरी में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की देरी पर कई बार चिंता जता चुके हैं। इसका सीधा असर हमारी सैन्य तैयारियों पर पड़ता है। ऐसे में अब जरूरी हो गया है कि निजी क्षेत्र भी अपना वादा पूरा करे और सेना की मांगों को समय पर पूरा करे। इतना ही नहीं, यह भी जरूरी है कि स्वदेशी सैन्य हथियारों में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए। आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। उसमें तकनीक और AI की भूमिका होगी। इसलिए, जरूरी है कि कार्यशैली भी उसी तरीके से बनाई जाए ताकि भारतीय सेना की तैयारी हमेशा समय से आगे रहे।

**बाल गोविंद, नोएडा**

### क्रांतिकारी बदलाव

**देश के** चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ताजा पहल ऐतिहासिक साबित हो सकती है। उनका यह कहना कि आपात स्थिति में अस्पतालों की तरह अदालतें भी 24 घंटे खुली रहे, काफी महत्त्वपूर्ण है। सूर्यकांत ने सीधे तौर पर कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आम लोगों की अदालत बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था जरूरी हो गई है कि अगर किसी शख्स को देर रात किसी जांच एजेंसी का समन मिले या उसकी स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा हो, तो वह आधी रात में भी अदालत का दरवाजा खटखटा सके। अदालतों को 24 घंटे खुले रखने का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर सूर्यकांत इसे व्यावहारिक रूप दे पाते हैं, तो यह न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकता है।

**अरविंद रावल, ईमेल से**

आर.एन.आई. नं. 510/57 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन: 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय: दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क: 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य: सोमवार से शनिवार: नेपाली 5 रु.; रविवार: नेपाली 6 रु. संपादक (दिल्ली मार्केट): आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

राष्ट्रीय सहारा
पटना। शनिवार • 3 जनवरी • 2026
www.rashtriyasahara.com



## नववर्ष के संकल्प

नववर्ष की शुरुआत में बस दो ही काम करने होते हैं। एक तो यारों-दोस्तों को नववर्ष की बधाई देनी होती हैं। नववर्ष पर दूसरा काम नववर्ष के संकल्प लेने का होता है। जैसे कि कुछ लोग धुम्रपान छोड़ने का संकल्प लेते हैं, तो कुछ लोग मॉर्निंग वॉक शुरू करने का। वैसे तो नफरत छोड़, प्रेम मोहब्बत से रहने का संकल्प लिया जाए, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। लेकिन इसका उल्टा होने की ही संभावना ज्यादा है कि भक्तजन और ज्यादा नफरत भरी पोस्ट शेयर करने का संकल्प ले सकते हैं। बहरहाल, कल्पना कीजिए कि हमारे नेताओं ने नववर्ष पर कोई संकल्प लिया होगा तो क्या संकल्प लिया होगा। क्या राहुल गांधी ने संकल्प लिया होगा कि अब से मैं भाजपा वालों की छाया से भी दूर रहूंगा। क्या पता क्या इल्जाम लगा दें। धक्का मारने और फ्लाइंग किस टाइप के इल्जाम तो लगा ही चुके।

भाजपा आइटी सेल वालों ने हो सकता है कि संकल्प लिया हो कि राहुल पर और गहराई से नजर रखनी होगी ताकि पता लगाया जा सके कि वे कब और कहां छुट्टी मनाने गए और जब छुट्टी पर गए तो उस वक्त देश में क्या हो रहा था, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा गैर-जिम्मेदार ठहराया जा सके। उनके वीडियोज की ज्यादा चतुराई से काट-छांट करनी होगी ताकि उन्हें पप्पू टाइप दिखाया जा सके। हालांकि बताते हैं कि लोगों ने उन्हें पप्पू मानना बंद कर दिया है। ऐसे में आइटी सेल की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अरविंद केजरीवाल भाजपा वालों की ज्यादा से ज्यादा पोल खोलने का संकल्प ले सकते हैं। यह संकल्प भी ले सकते हैं कि ऐसी और भविष्यवाणियां भी करेंगे कि उनकी पार्टी का और कौन-कौन नेता जेल जा सकता है। सच में केजरीवाल जी के सामने भाजपा की कल्पनाशीलता और संकल्पशीलता मंद पड़ जाती है और वो शीशमहल से आगे नहीं जा पाती। खैर, धनखड़ जी संकल्प ले सकते हैं कि मुझे अपने दिल में और दर्द पैदा करना होगा ताकि मैं ज्यादा पीड़ित दिख सकूं। मोदी जी और ज्यादा विदेश यात्राएं करने का संकल्प ले सकते हैं और यह संकल्प भी ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में उनके भाषणों में या तो वे होंगे या फिर नेहरू होंगे। दूसरे किसी को भी जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन यह सस्पेंस कैसे खत्म हो भैया कि नीतीश जी ने क्या सचमुच पलटने का संकल्प ले लिया है!

## राजनीति और परिवारवाद

गैरराजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के एक लाख नौजवानों को राजनीति में लाने का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा ये देश की राजनीति की दिशा बदलेंगे। उन्होंने 'परिवारवाद की राजनीति' को देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया। युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान करते हुए मोदी ने कहा, आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बनें। जो हम कहते हैं, डंके की चोट पर कर दिखाते हैं। मोदी ने ये बातें वाराणसी में कही। मोदी अपनी चुनावी रैलियों में भी वंशवाद पर करारा प्रहार करते रहे हैं। यह सच है कि उनके अपने परिवार से अब तक कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है। मगर यदि पूरे दल के लिहाज से देखा जाए तो यह भाजपा पर खुद भी पूरी तरह लागू होता नहीं नजर आ रहा। वंशवाद तथा परिवारवाद के खिलाफ तीखे तेवर रखने वाले मोदी भी इस सचाई से मुंह नहीं फेर सकते। भाजपा में ढेरों नेता परिवारवाद की ही देन हैं। तमाम खींचतान के बावजूद युवा नेताओं की बड़ी संख्या के पीछे वंशवाद ही है। भाजपा हमेशा खुद को परिवारवादी दल होने से इनकार करती रही है। मगर दल के कुछ वरिष्ठ नेता पार्टी पर परिवार के कब्जे का तर्क देते हुए नेताओं के बच्चों को राजनीति में आने का रास्ता प्रशस्त करने सरीखी बातें करते हैं। देश में कोई भी राजनीतिक दल परिवारवादी होने के आरोपों से बचा नहीं है। यह कहना गलत नहीं है कि कांग्रेस, सपा, राजद व एनसीपी जैसे तमाम क्षेत्रीय दल भी विरासत के तौर पर अपनी अगली पीढ़ी को मुखिया बनाने का काम बेधड़क करते हैं। वे तरह-तरह की दलीलों से तुष्टिकरण करना चाहते हैं। दरअसल, परिवारवाद से मुक्त रह पाना और राजनीतिक विरासत पर उचित उम्मीदवार या दावेदार को पदभार देने का जिगर रखना आसान नहीं है। नौजवानों को राजनीति में लाने का आह्वान सभी राजनीतिक दल समय-समय पर करते हैं। कुछ ही दिन पहले भाजपा में नये सदस्य बनाने का जो सिलसिला चालू हुआ है, उसमें जनता को बरगला कर सदस्यता देने की खबरें खूब आ रही हैं। राजनीति के प्रति आमजन को आकर्षित करने के लिए जरूरी है, इसे पारदर्शी बनाया जाए। अमूमन सफल राजनेताओं को नेतागिरी के इतर किसी अन्य पेशे में भी हाथ आजमाना पड़ता है। फिलहाल देश की आधे से अधिक आबादी जवानों की है। दीगर है कि राजनीति में युवा आएंगे तो जोश और बदलाव खुद-ब-खुद नजर आता दिख सकता है।

साफ-सफाई/अमित बैजनाथ गर्ग

## कचरे का निपटान जरूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वच्छता और कचरे के निपटान की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को जोड़ना है। यह अभियान एक दिन, एक साल का नहीं है। यह युगों-युगों तक निरंतर करने वाला काम है। जब तक स्वच्छता हमारा स्वभाव बन जाए, यह तब तक करने का काम है। असल में स्वच्छता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कचरे का निपटान है, जो पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। जनसंख्या बढ़ने से अपशिष्ट की मात्रा लगातार बढ़ी है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगभग सभी देश बढ़ते कचरे के कुशलतापूर्वक निपटान की चुनौती का सामना कर रहे हैं। असल में ठोस अपशिष्ट के निपटान की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सरकार की ओर से संचालित कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कूड़े-करकट से अधिकतम मात्रा में उपयोगी संसाधन प्राप्त करना और ऊर्जा का उत्पादन करना है, ताकि कम-से-कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को लैंडफिल क्षेत्र में फेंकना पड़े। इसका कारण यह है कि लैंडफिल में फेंके जाने वाले कूड़े का भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक तो इसके लिए काफी जमीन की आवश्यकता होती है। दूसरा कूड़ा वायु, मिट्टी और जल-प्रदूषण का संभावित कारण भी है। एक अनुमान के अनुसार, इस समय दुनिया में प्रतिवर्ष 201 करोड़ टन से ज्यादा ठोस कचरा पैदा हो रहा है। इसका एक तिहाई खतरनाक तरीके से वातावरण में फेंका जा रहा है, जो आने वाले समय में बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। भारत सहित दुनिया को कचरे से मुक्ति दिलाने के लिए विशेषज्ञ चार आर का सिद्धांत अपनाने की बात करते हैं। इसमें पहले आर का अर्थ रिफ्यूज यानी प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग से इनकार करना, दूसरे आर का अर्थ रिड्यूस यानी प्लास्टिक पदार्थों का कम से कम उपयोग करना, तीसरे आर का अर्थ रीयूज यानी नये की बजाय पुराने प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग करना और अंत में रिसाइकिल यानी पुराने प्लास्टिक पदार्थों को रिसाइकिल कर दोबारा उपयोग करना है। कुल मिलाकर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।

अनमोल वचन

*सकारात्मक रहना और आभारी रवैया रखना तय करेगा कि आप जिंदगी कैसे जीने जा रहे हैं।*
-जोएल ऑस्टिन

# भारत की कर संरचना में बदलाव

मनोज कुमार तिवारी
वरिष्ठ पत्रकार

**2025 : जब्ती करों से लोक-केंद्रित सुधार तक**

1930 में, महात्मा गांधी द्वारा नमक कर की अवज्ञा ने उजागर किया था कि कैसे दमनकारी कर प्रणाली नागरिक को राज्य से दूर कर सकती है। यह एक चेतावनी थी कि जब कर मनमाने या अत्यधिक होते है, तो वे विश्वास और सामाजिक सम्पर्क को कमजोर करते है। चार दशक बाद, भारत में एक और चरम स्थिति देखी गई, जब पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आयकर के स्तर को आश्चर्यजनक रूप से 97.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। इस परम्परा ने करदाताओं और राज्य के बीच गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। दशकों तक, भय के कारण अनुपालन होता रहा। इसने सक्रिय योगदान देने के बजाय टालमटोल को प्रोत्साहित किया। इसी पृष्ठभूमि में मोदी सरकार के कर सुधार, जो 8 वर्ष पहले आरंभ हुए और 2025 में निर्णायक रूप से आगे बढ़े, अतीत से एक स्पष्ट अंतर का प्रतीक है।

इस बदलाव में अंतर्निहित लाफ़र कर्व का तर्क यह है कि कम कर दरें राजस्व सृजन के लिए उप-इष्टतम है और कर आधार का विस्तार करती है। इस प्रकार भारत के 2025 के कर सुधार न केवल राजकोषीय परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते है, बल्कि एक दार्शनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते है, जो उत्पीड़न से सहयोग तक और अविश्वास से लेकर राज्य और नागरिक के बीच एक नया सामाजिक अनुबंध है।

जीएसटी से पहले की वास्तविकताः विखंडन, रिसाव और अविश्वास वैट शासन के दौरान, अप्रत्यक्ष करों की बहुलता ने व्यापक स्तर पर भ्रम पैदा किया , राज्यों ने 0 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत के एकसमान स्लैब को खत्म करते हुए बार-बार वैट दरों में बदलाव किया। वास्तव में, स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद, राज्यों ने अतिरिक्त शुल्क लगाने के विरूद्ध अपनी 2010 की रिपोर्ट में कैग की सुस्पष्ट सलाह की अनदेखी कर दी, फिर भी प्रवेश कर और स्थानीय अधिभार जारी रहे। इसने भ्रम और विखंडन पैदा किया और प्रत्येक राज्य ने अपने स्वयं के अनुपालन नियमों, दंड और प्रक्रियाओं को लागू किया। इसके गंभीर परिणाम हुए। कमजोर जांच और असंगत प्रवर्तन ने कर चोरी को प्रोत्साहित किया। हर दो डीलरों में से एक ने कर चोरी करने का प्रयास किया और सिर्फ एक मामले में ही, सात डीलरों को उचित दस्तावेज के बिना 1,026 करोड़ रूपये की छूट दे दी गई। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार (2025): कार्यनीति के रूप में सरलता वर्ष 2017 में जीएसटी की शुरुआत ऐतिहासिक थी। इसने भारत को एकल बाजार में समेकित किया, व्यापक करों को समाप्त कर दिया और एक पारदर्शी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की नींव रखी। यद्यपि, दरों और वर्गीकरण में अस्पष्टता के कारण विवाद पैदा हुए और निस्संदेह अनुपालन के साथ-साथ पंजीकरण में भी भारी समस्याएं रहीं। उदाहरण के लिए, वस्त्र क्षेत्र में धुलाई और रंगाई जैसी सेवाओं पर 'जॉब वर्क सर्विसेज' के हिस्से के रूप में 5 प्रतिशत कर लगाया गया था, जबकि ब्लीचिंग, प्रिंटिंग और रासायनिक उपचार जैसी प्रक्रियाओं पर 18 प्रतिशत का कर लगाया गया था। इससे वर्गीकरण को लेकर गंभीर भ्रम और कर विवाद पैदा हो गए।

इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मोदी सरकार ने 2025 में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की शुरुआत की, जो जीएसटी के लॉन्च के बाद से सबसे सार्थक सरलीकरण प्रदान करते है। इस प्रणाली को दो स्पष्ट स्लैब, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत में युक्तिसंगत बनाया गया था। साथ ही, वस्तुओं के वर्गीकरण को भी स्पष्ट किया गया, अनुपालन को सरल बनाया गया और पंजीकरण को सुगम बनाया गया। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने सक्रिय रूप से व्यवसायों और राज्यों की बात सुनी है और राज्यों को कार्यान्वयन में समान भागीदार माना है। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि सुधारों को सचारू रूप से लागू किया जाए। 2025 के जीएसटी सुधारों ने करों को सरल बनाने से कहीं अधिक काम किया; उन्होंने कई सेक्टरों में मांग को सीधे तौर पर प्रेरित किया। भारत में दीपावली के अवसर पर 6.05 ट्रिलियन रूपये की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक है। एक दशक से अधिक समय में यह इसकी सबसे मजबूत नवरात्रि बिक्री रही है। साथ ही, अक्टूबर 2025 में ऑटोमोबाइल खुदरा बिक्री 40.5 प्रतिशत बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। जिन आलोचकों ने यह तर्क दिया था कि जीएसटी को सरल बनाने और दरों को तर्कसंगत बनाने से कर राजस्व में कमी आएगी, वे भी गलत साबित हुए। अक्टूबर-नवंबर 2025 में, जीएसटी में महत्वपूर्ण कटौती के बावजूद, सकल जीएसटी संग्रह 2024 में इसी अवधि की तुलना में 2.8 प्रतिशत अधिक था।

जीएसटी दरों में कटौती और आयकर छूट की सीमा में वृद्धि से परिवारों को सालाना 2.5 लाख करोड़ रूपये की बचत करने में मदद मिलेगी। सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 0 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो 18 प्रतिशत से कम है। इसका अर्थ है कि 20,000 रूपये के बेस प्रीमियम पर पहले 3,600 रूपये जीएसटी (18 प्रतिशत) था, जिससे 23,600 रूपये देय था। छूट के बाद, 20,000 रूपये के भुगतान पर सीधे 3,600 रूपये की बचत है। जीएसटी में सुधार से किराने का सामान और दैनिक आवश्यक वस्तुओं के घरेलू बिलों में 13 प्रतिशत की बचत होगी, जबकि एक छोटी कार का खरीदार लगभग 70,000 रूपये बचा सकता है। एसी खरीद में 2,800 रूपये की बचत होगी क्योंकि इन वस्तुओं की जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।

जीएसटी स्लैब को तर्कसंगत बनाकर और आवश्यक एवं आकांक्षी दोनों वस्तुओं पर कर के बोझ को कम करके, सरकार ने आत्मविश्वास से व्यय करने और निरंतर मांग का वातावरण सृजित किया। मध्यम वर्ग के लिए कर में महत्वपूर्ण लाभ भारत की आयकर यात्रा इसके आर्थिक विकास को दर्शाती है। इंदिरा गांधी के युग में कर की दर 97.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी और कर चोरी और अविश्वास की जड़ें गहरी हो चुकी थीं। दशकों बाद, उदारीकरण के बावजूद, 2014 में राहत मामूली रही; आयकर छूट को 2 लाख रूपये तक सीमित कर दिया गया था, जो शहरीकरण की अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं था। मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग पर कर के बोझ को निरंतर कम किया है, प्रासंगिक उपायों पर नीतिगत स्थिरता को प्राथमिकता दी है। पिछले दशक में आयकर छूट की सीमा 2014 में 2 लाख रूपये से बढ़कर 2025 में 12 लाख रूपये हो गई है, जो 6 गुना राहत प्रदान करती है।

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, 75,000 रूपये की मानक कटौती के बाद, प्रभावी शून्य-कर सीमा अब 12.75 लाख रूपये प्रति वर्ष है। नई व्यवस्था में 12 लाख रूपये की आय वाले करदाताओं को 80,000 रूपये का कर लाभ मिलेगा जबकि 18 लाख रूपये की आय वाले व्यक्ति को टैक्स के रूप में 70,000 रूपये का लाभ मिलेगा। नमक कर से लेकर आयकर की जब्ती दरों तक, भारत का इतिहास बताता है कि त्रुटिपूर्ण कर प्रणाली विश्वास और विकास को कमजोर करती है। मोदी सरकार के 2025 के कर सुधार उस अतीत से एक स्पष्ट अंतर का प्रतीक हैं। सरलता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देकर, राज्य ने उपभोग में वृद्धि करते हुए अनुपालन को सुदृढ़ किया है। 2025 में, भारत में कर प्रणाली अब नियंत्रण का माध्यम नहीं रह गई है। यह एक साझेदारी है, जो यह मानती है कि जब नागरिकों पर भरोसा किया जाता है और प्रणालियां सरल होती है, तो अर्थव्यवस्था विकास के साथ मिलकर कदम बढ़ाती है।

**भारत में दीपावली के अवसर पर 6.05 ट्रिलियन रूपये की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक है। एक दशक से अधिक समय में यह इसकी सबसे मजबूत नवरात्रि बिक्री रही है। साथ ही, अक्टूबर 2025 में ऑटोमोबाइल खुदरा बिक्री 40.5 प्रतिशत बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। जिन आलोचकों ने यह तर्क दिया था कि जीएसटी को सरल बनाने और दरों को तर्कसंगत बनाने से कर राजस्व में कमी आएगी, वे भी गलत साबित हुए। अक्टूबर-नवंबर 2025 में, जीएसटी में महत्वपूर्ण कटौती के बावजूद, सकल जीएसटी संग्रह 2024 में इसी अवधि की तुलना में 2.8 प्रतिशत अधिक था**

### मच्छर-जनित बीमारियां और **मलेरिया** आज भी चिंता के सबब

- मलेरिया और मच्छर-जनित बीमारियों के बरक्स इंसान मजबूत तो हुआ है, लेकिन आज भी दुनिया के अनेक हिस्सों में ये बीमारियां चिंता का सबब बनी हुई हैं
- मलेरिया और मच्छर-जनित बीमारियों से आज भी विश्व भर में सालाना 10 लाख से ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु होती है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे होते हैं
- 20 अगस्त, 1897 को रोनाल्ड रॉस ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में मलेरिया के कारक एनोफिलीज मच्छर की पहचान की थी

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

एलेन मस्क की बहुत सारी बातें फालतू भी होती हैं पर EVMs V/S Ballot Paper System पर उन्होंने जो कुछ कहा है, वह सही और सटीक है। मस्क ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, EVMs सही और सटीक नहीं हैं क्योंकि उनमें गड़बड़ी की जा सकती है।

**उर्मिलेश, पत्रकार**
**@UrmileshJ**

# लाइक्स, शेयर व तनाव में उलझा युवा मन

ज्योति श्रीवास्तव
मनोवैज्ञानिक एवं परामर्शदाता

आप इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि युवा वर्ग वह वर्ग है, जिस पर न केवल पूरे परिवार का, बल्कि पूरे देश का भविष्य भी निर्भर करता है। अब ज़रा सोचिए, यदि कोई दानव इस युवा वर्ग की ऊर्जा, सोच और क्षमता को ही धीरे-धीरे खाने लग जाए, तो क्या होगा? निश्चय ही ऐसी स्थिति में युवा वर्ग, परिवार और हमारा देश सभी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ जिस दानव की बात की जा रही है, वह न तो दो सींगों वाला है और न ही बड़े-बड़े दाँतों वाला। यह वह अदृश्य दानव है, जो हमारी ज़िंदगी में तब प्रवेश करता है, जब हम बिना सोचे-समझे और बिना नियंत्रण के सोशल मीडिया का उपयोग करने लगते हैं।

आज के समय में सोशल मीडिया युवा वर्ग के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है और समय के साथ इसका प्रभाव और भी बढ़ता जा रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफ़ॉर्म जानकारी, संवाद और मनोरंजन का अच्छा माध्यम हो सकते है, लेकिन जब इनका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता, तो यह युवा वर्ग के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करने लगते है। सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है, परंतु बिना सतर्कता, बिना आत्मअनुशासन और बिना सीमा के इसका प्रयोग युवाओं में मानसिक समस्याओं को जन्म दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से किशोरों में अवसाद, चिंता और नींद से जुड़ी समस्याएँ तेज़ी से बढ़ रही है।

किशोर अक्सर अपने दोस्तों और अन्य लोगों के पोस्ट, लाइक और टिप्पणियों के आधार पर अपने जीवन की तुलना करने लगते है। इससे उनमें आत्म-सम्मान की कमी, तनाव और असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक उपयोग तुलना, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक दबाव को बढ़ाता है। किशोर दूसरों की संपूर्ण और चमकदार जीवनशैली जो वास्तव में वैसी नहीं होती को देखकर अपने जीवन से असंतष्ट हो जाते है। यही असंतोष धीरे-धीरे उनके मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर कर देता है और उदासी, अकेलापन तथा असुरक्षा की भावना बढ़ने लगती है। तुलना के अलावा, एक और गंभीर समस्या है साइबर बुलिंग। सोशल मीडिया पर संदेशों, टिप्पणियों या तस्वीरों के माध्यम से किया गया मानसिक उत्पीड़न किशोरों में अवसाद, आत्म-संकोच और कभी-कभी आत्महत्या जैसे खतरनाक विचारों को जन्म दे सकता है। कई बार किशोर डर या शर्म के कारण माता-पिता या शिक्षकों से मदद माँगने में भी हिचकिचाते है, जिससे समस्या और गहरी हो जाती है। अब यदि हम युवाओं की जीवनशैली की बात करें, तो यह स्पष्ट है कि एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से किशोर शारीरिक गतिविधियों से दूर हो जाते है। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से मोटापा, आँखों की समस्या और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ बढ़ सकती है। देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग करने से नींद की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे थकान, ध्यान की कमी और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब यह आवश्यक हो गया है कि सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु प्रभावी उपायों पर गंभीरता से विचार किया जाए। सर्वप्रथम, सोशल मीडिया का उपयोग जागरूकता और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण के साथ किया जाना चाहिए। युवा वर्ग को निरंतर आत्ममंथन करते रहना चाहिए कि वे सोशल मीडिया का उपयोग किस उद्देश्य से कर रहे है। यदि इसका प्रयोग उनके ज्ञान, दृष्टिकोण और जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक वृद्धि कर रहा है, तो इसे सार्थक माना जा सकता है। सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों के प्रति जागरूकता भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि युवा वर्ग डिजिटल माध्यमों पर होने वाली धोखाधड़ी, शोषण अथवा विभिन्न प्रकार की जालसाज़ी से स्वयं को सुरक्षित रख सके। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि सोने से पूर्व सोशल मीडिया के उपयोग को यथासंभव सीमित किया जाए, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मस्तिष्क की प्राकृतिक विश्राम प्रक्रिया को बाधित करती है और नींद के चक्र को प्रभावित करती है। इसके स्थान पर अध्ययनशील एवं उपयोगी पुस्तकों के पठन की आदत विकसित करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह अनजाने में सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग की ओर बढ़ रहा है, या उसमें उदासी, चिंता तथा आत्महीनता जैसे लक्षण दिखाई दे रहे है, तो उसे बिना किसी संकोच के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अपनी परेशानियों और संभावित खतरों को सही समय पर सही व्यक्ति के साथ साझा करना आपको सही दिशा दिखा सकता है, इसलिए स्वयं को सुरक्षित और उपयुक्त मंच पर खुलकर व्यक्त करें।

निष्कर्षतः, सोशल मीडिया आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए। यह ज्ञान, संवाद और आत्म-अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम हो सकता है, किंतु इसके असंतुलित और अनियंत्रित उपयोग से युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे है। तुलना, सामाजिक दबाव, साइबर बुलिंग, असंतुलित जीवनशैली और नींद की कमी जैसी समस्याएँ युवाओं को मानसिक रूप से कमजोर बना रही है। अतः यह आवश्यक है कि सोशल मीडिया के उपयोग को जागरूकता, आत्मअनुशासन और संतुलन के साथ अपनाया जाए। साथ ही, परिवार, शैक्षणिक संस्थान और समाज की सामूहिक भूमिका भी महत्वपूर्ण है, ताकि युवाओं को सही दिशा और सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान किया जा सके। यदि सोशल मीडिया का उपयोग उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक ढंग से किया जाए, तो यह युवाओं को सशक्त बना सकता है; अन्यथा, यही साधन उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए चनौती बन सकता है। इसलिए, सोशल मीडिया के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाना समय की अनिवार्य आवश्यकता है।

अन्नदाता | पीके चौधरी

बात 1965 की है । भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने " जय जवान जय किसान" का प्रसिद्ध नारा दिया । एक आश्रय का रक्षक और दूसरा आहार का पूरक। आधा दशक बीत चुका है। कुछ खास नहीं बदला है, कम से कम बिहार के किसान के लिए तो बिल्कुल नहीं। हमारे बहादुर जवान स्वेच्छा से देश के लिए गोली खाते थे और है और हमारे अन्नदाता किसान हतोत्साह हो कर जहर की गोली खा रहे है । ये कैसी विडंबना है कि जो सबका अन्नदाता है वही भूखा है ! ज्यादातर प्रदेशों में किसान की ये दशा नहीं है । पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी इत्यादि में किसान की हालत कहीं बेहतर है। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर राज्य सरकार की इच्छा और इच्छाशक्ति हो तो बिहार के किसान की दशा भी सुधर सकती है । मसला ये है कि जो मौजूदा बिहार सरकार, निर्वाचन के लिए अरबों रुपए पानी के तरह बहा सकती है, वही सरकार किसान की समस्या के लिए दीर्घकालिक निर्णय और नीति क्यों नहीं लाती है ? आइए इस मसले को कुछ आंकड़ों से समझते है । उदाहरण के लिए हम धान की खेती लेते है क्योंकि बिहार का किसान मूलतः इसी पर आश्रित है और जो आंकलन इस पर निकलेगा वही आकलन गेहूं या दूसरे किसानी फसलों पर भी उतना ही ठहरता है ।

**किसान की समस्या**

अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 20-21 के अनुसार, बिहार का किसान औसतन 0.5 हेक्टेयर का मालिक है। इसी की तुलना में केरल और पंजाब के किसान के पास औसतन 1.1 हेक्टेयर और 1.4 हेक्टेयर भूमि ही है। यहीं से गरीबी और मजबूरी की शुरुआत होती है। जब जमीन ही कम हो तो पैदावार कहाँ से ज़्यादा होगी? जाहिर है कि छोटी जमीन का मालिक ना तो बड़े या आधुनिक कृषि कदम उठा सकता है और ना ही बड़े स्तर पर की खेती का लाभ उठा सकता है।

अगर धान पर लागत बनाम आय की तुलना की जाय तो 15-16 के एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किसान की प्रति रुपए की लागत बनाम कमाई बाकी कई प्रदेशों जैसे कि केरल, पंजाब, हरियाणा इत्यादि से कम है । ध्यान दें कि बिहार के किसान के पास वैसे ही कृषि भूमि इनकी तुलना में काफी कम है। बात इतने तक भी सीमित नहीं है। मौसम की मार भी बिहार पर और प्रदेशों की तुलना में अत्यधिक है। सूखा और बाढ़ की बलयुग्म शक्ति पहले से ही अधमरे किसान का कमर ही तोड़ डालती है ।

**इस साल की समस्या**

इस बार धान की फसल काफी अच्छी हुई है । रॉयटर्स के अनुसार भारत के गोदामों में चावल के भंडार में 12 : वृद्धि हुई है। बाजार में दर लगातार गिर रहा है। किसान को अच्छी कीमत नहीं मिल रही है। उड़ीसा में सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीद में देरी के चलते किसान तंगी में अपना फसल औने पौने दाम में निकाल रहे है । बिहार में उत्पाद रखने की समस्या वैसे भी संगीन है। गोदाम है नहीं। बिहार सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता अत्यधिक है। अगर समय पर उचित कदम नहीं लिए गए तो स्थिति भयावह होगी। अगर समय पर किसान का फसल नहीं निकला तो उसके पास पैसे नहीं आयेंगे। पैसे नहीं आयेंगे तो रब्बी पर भी बहुत प्रतिकूल असर दिखेगा।

रोजगार और स्वरोजगार के लिए भी बिहार में अकाल की स्थिति पहले से ही है। बिहार सरकार को अति शीघ्र दो निर्णायक कदम लेने चाहिए। पहला ये की बिहार में धान और गेहूँ की एमएसपी बाकी राज्यों की तुलना में आनुपातिक ज्यादा हो । दूसरा ये कि इस दर की वृद्धि अति शीघ्र की जाए और किसान के फसल की खरीद हो। गोदामों की वृद्धि व्यवस्था पर द्रुत गति से निर्णय हो और उस का समापन हो।

बिहार के किसान के पास कृषि के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है । किसान करे तो क्या करे ? वो मजबूरी में या तो मजदूरी करता है या खुदकुशी कर लेता है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार के लिए यह एक और काला अध्याय होगा। जन सुराज की सरकार से मांग है कि सरकार तत्कालीन प्रभाव से किसानों की इस विषम समस्या का निवारण करे। अगर सरकार इस विषय की उपेक्षा करती है तो जन सुराज किसान के हित में किसान जागरूकता अभियान शुरू करेगी।

## रीडर्स मेल

### चेतना के कवि तुलसीदास

तुलसीदास जयंती केवल एक कवि की स्मृति नहीं है, अपितु यह भारतीय भक्ति परंपरा, लोक संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का भी पर्व है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। उन्होंने जिस प्रकार रामचरितमानस के माध्यम से प्रभु श्रीराम की कथा को जन-जन तक पहुंचाया, वह भारतीय साहित्य के इतिहास में अद्वितीय है। नई पीढ़ी को तुलसी की रचनाओं से जोड़ कर हम उनमें नैतिकता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक गौरव का भाव जगा सकते हैं।

**अशोक कुमार, लखनऊ।**

### एसआईआर की प्रासंगिकता

चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान एक ओर जहां मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर यह कई आलोचनाओं का भी केंद्र बन गया है-विशेषकर दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर खड़े समुदायों के संदर्भ में। विपक्ष की पार्टियों ने तो इसके खिलाफ बाकायदा एक अभियान ही छेड़ दिया है। कहना न होगा कि एक राष्ट्र तभी सशक्त होता है, जब उसका सबसे कमजोर नागरिक भी अपने मताधिकार को बिना डर, बाधा या भेदभाव के प्रयोग कर सके।

**राम प्रकाश शर्मा, लखनऊ**

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
वर्ष - 20, अंक 6879
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

इंडियन फ़ार्माकोपिया कमीशन के अंतर्गत आज दुनिया के 19 देश भारत से जुड़े हुए हैं। इंडियन फ़ार्माकोपिया कमीशन की वैश्विक रैंकिग अब 8 है, जो कि वर्ष-2009 से 2014 के बीच 123वीं थी।

-जगत प्रकाश नड्डा

भारत ने 2025 में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में प्रगति दर्ज की है। रिकॉर्ड 44.5 GW नई क्षमता जोड़ी गई है, जिसमें सोलर सबसे आगे रहा, जबकि विंड और हाइड्रो ने भी अहम योगदान दिया। यह प्रगति भारत को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सस्टेनेबल एनर्जी वाले भविष्य की ओर आगे ले जा रही है।

-गिरिराज सिंह

## संपादकीय

# उच्च शिक्षा में निवेश

भारत कभी पूरी दुनिया के लिए उच्च शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इतिहास में दर्ज हैं,जहां उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए देश-दुनिया से छात्र आया करते थे। तब भारत विश्व गुरु कहलाता था। लेकिन कालांतर में इसमें गिरावट आती गई और हम दुनिया के मानचित्र में हाशिए पर चले गए। देश के बहुतायत युवा आज बेहतर विकल्प एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विदेशों में जा रहे हैं। यही नहीं विदेशों में सर्वाधिक शिक्षा ग्रहण करने वालों में सबसे बड़ी तादात भारत के छात्रों की है। जो यह साबित करता है कि देश में उच्च शिक्षा का वातावरण बेहतर नहीं है। साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक,13.35 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है कि हम सक्षम हैं और विदेशों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा रहे हैं,लेकिन यह गर्व का विषय नहीं है। बल्कि यह एक सवाल है कि क्या कारण है कि इतनी बड़ा तादात में बच्चे उच्च शिक्षा के लिए भारत छोड़कर विदेश जा रहे हैं। सीधा सा जवाब है कि विकल्प के अभाव में यह बच्चे विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो भारतीय छात्रों का सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य कनाडा है। 2024 में वहां 4.27 लाख भारतीय छात्र थे। वहीं अमेरिका में 3.37 लाख,ब्रिटेन में 1.85 लाख,आस्ट्रेलिया में 1.22 लाख और जर्मनी में तकरीबन 43 हजार भारतीय छात्र थे। ध्यान देने वाली बात है कि इन आंकड़ों के पीछे केवल विश्वविद्यालयों की उच्च रैंकिंग नहीं है। बल्कि वीजा नीति,पोस्ट स्टडी वर्क परमिट और रोजगार के अवसर हैं। इनमें कनाडा भारतीयों का सर्वाधिक पंसदीदा देश है। जहां पढ़ाई करने के साथ ही काम करने और स्थायी निवास की राह अपेक्षाकृत आसान है। आंध्रप्रदेश और पंजाब के सर्वाधिक युवा कनाडा पहुंच रहे हैं। उनका सफर गांव से सीधे वैश्विक स्तर के विश्वविद्यालय तक तय हो रहा है। लेकिन इस यात्रा की भारी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। 2023-24 में केवल चार देशों कनाडा,अमेरिका,ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया में पढ़ने गए 8.5 लाख भारतीय छात्रों ने तकरीबन 2.9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। जो कि कई भारतीय राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। इस राशि को अगर देश के ही विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों पर खर्च किया जाता तो शायद आज देश की तस्वीर कुछ और होती। नीति आयोग की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है। इसमें इस असंतुलन को स्वीकार करते हुए 10 अरब डालर के भारत विद्याकोष का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें से 50 फीसदी राशि निजी क्षेत्र व प्रवासियों से आने की बात कही गई है। इसके माध्यम से अनुसंधान को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा देने की बात कही गई है। अनुसंधान की बात करें तो भारत इस क्षेत्र में विकसित देशों के मुकाबले काफी पीछे है। विकसित देश इस मद में जहां अपने जीडीपी का 2 से 3 फीसदी तक खर्च कर रहे हैं,वहीं भारत में महज 0.7 फीसदी राशि ही खर्च की जा रही है। इसलिए अगर भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है तो प्रयोगशालाओं में भारी-भरकम निवेश करना जरूरी है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 81 फीसदी छात्र राज्य-सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इनकी हालत अच्छी नहीं है। एक रिपोर्ट बताती है कि इन विश्वविद्यालयों में 40 फीसदी अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं और महज 10 फीसदी उच्च शिक्षण संस्थानों में ही पर्याप्त शोध की सुविधाएं हैं। यानी उच्चशिक्षा और शोध दोनों के हालात दयनीय हैं। इन्हें बेहतर बनाया जाना चाहिए। क्योंकि ये विश्वविद्यालय देश की शिक्षा की रीढ़ हैं। यहां मिशन मोड में शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए और इस दौरान संख्या ही नहीं गुणवत्ता का भी खयाल रखा जाना चाहिए। उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से संयुक्त नियुक्ति और विजटिंग प्रोफेसर मॉडल अपनाए जा सकते हैं। इससे ज्ञान का प्रवाह होगा और छात्रों को वैश्विक दृष्टि मिलेगी। साथ ही विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम तय करने व फीस संरचना में सीमित लेकिन स्वायत्त अधिकार देने होंगे। ताकि वे स्थानीय जरूरतों और वैश्विक मानकों के बीच जरूरी संतुलन बना सकें। शिक्षा को केवल सामाजिक सेवा नहीं  रणनीतिक निवेश माना जाना चाहिए और समझना चाहिए कि शिक्षा सुधारों का असर चुनावी चक्र से अलग होता है। इसे दीर्घकालिक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में देखा जाना चाहिए। तभी भारत में वैश्विक स्तर के प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा संस्थान या विश्वविद्यालय तैयार हो सकेंगे और विदेशी छात्र भी बड़ी तादात में भारत आकर शिक्षा ग्रहण के लिए आकर्षित होंगे।

# विकसित भारत जी राम जी, उत्तराखंड की नई राह

किरण कुमार शर्मा

पहाड़ में रोजगार की अनिश्चितता लंबे समय से सबसे बड़ी समस्या रही है। खेती मौसमी है, उत्पादन सीमित है और लागत अधिक। ऐसे में 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार केवल अतिरिक्त आमदनी नहीं, बल्कि भरोसे की नींव है। यह भरोसा ग्रामीण परिवारों को यह सोचने का अवसर देता है कि वे गांव में रहकर भी सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। कृषि और ग्रामीण श्रम के बीच संतुलन का प्रावधान भी उत्तराखंड के लिए विशेष महत्व रखता है। बुवाई और कटाई के दौरान 60 दिनों तक की समेकित विराम अवधि से यह सुनिश्चित होगा कि खेतों में श्रम की कमी न हो और किसान की उपज प्रभावित न हो। पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां खेती सामूहिक श्रम पर आधारित होती है, यह संतुलन ग्रामीण जीवन की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होगा।

उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में ग्रामीण रोज़गार केवल आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता, सांस्कृतिक निरंतरता और पहाड़ के अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न भी है। यहां की भौगोलिक विषमता, वर्षा आधारित खेती, सीमित औद्योगिक अवसर और मौसम की अनिश्चितता ने दशकों से गांवों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। इसी कमजोरी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है, लगातार होता पलायन। ऐसे समय में विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण), यानी 'जी राम जी' अधिनियम, 2025 का लागू होना उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत मोड़ के रूप में देखा जाना चाहिए। यह कानून केवल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम का स्थानापन्न नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास की सोच में एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत देता है। रोज़गार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना, समयबद्ध मज़दूरी भुगतान को अनिवार्य बनाना, पंचायतों को योजना निर्माण की केंद्रीय भूमिका देना और रोज़गार को टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण से जोड़ना। ये सभी प्रावधान उत्तराखंड की विशिष्ट परिस्थितियों में दूरगामी असर डाल सकते हैं। देखा जाए तो मनरेगा और जी राम जी में मूलभूत अंतर यह है कि मनरेगा गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से लागू कयिा गया कार्यक्रम था, जबकि जी राम जी विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम

## देवभूमि की दृष्टि से बड़ा कदम

है।उत्तराखंड में मनरेगा के तहत लगभग 16.12 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 9.34 लाख श्रमिक पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि राज्य की एक बड़ी ग्रामीण आबादी की आजीविका सीधे तौर पर ग्रामीण रोज़गार गारंटी व्यवस्था से जुड़ी हुई है। 125 दिनों की वैधानिक गारंटी का अर्थ है ग्रामीण परिवारों को पूरे वर्ष काम की बेहतर योजना बनाने का अवसर। इससे न केवल घरों में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय बाजार, छोटे व्यापार और सेवाओं को भी नई गति मिलेगी।पहाड़ में रोजगार की अनिश्चितता लंबे समय से सबसे बड़ी समस्या रही है। खेती मौसमी है, उत्पादन सीमित है और लागत अधिक। ऐसे में 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार केवल अतिरिक्त आमदनी नहीं, बल्कि भरोसे की नींव है। यह भरोसा ग्रामीण परिवारों को यह सोचने का अवसर देता है कि वे गांव में रहकर भी सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। कृषि और ग्रामीण श्रम के बीच संतुलन का प्रावधान भी उत्तराखंड के लिए विशेष महत्व रखता है। बुवाई और कटाई के दौरान 60 दिनों तक की समेकित विराम अवधि से यह सुनिश्चित होगा कि खेतों में श्रम की कमी न हो और किसान की उपज प्रभावित न हो।  इन गांवों में न स्कूलों की घंटी बजती है, न खेतों में हल की आवाज़ सुनाई देती है और न ही पर्व–त्योहारों की सामूहिक रौनक बची है। यह स्थिति केवल पहाड़ के खाली होने का संकेत नहीं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर चेतावनी है।'विकसित भारत-जी राम जी' कानून इस चिंताजनक परंपरा पर अंकुश लगाने की क्षमता रखता है। जब गांव में ही सुनिश्चित रोजगार, समय पर मज़दूरी और विकास से जुड़ी टिकाऊ परिसंपत्तियां बनेंगी, तो लोगों के पास गांव छोड़ने के बजाय गांव में टिके रहने का ठोस आधार होगा। 125 दिनों की वैधानिक रोज़गार गारंटी उन सीमांत परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो मजबूरी में महानगरों की ओर पलायन करते रहे हैं। यह कानून यह संदेश देता है कि गांव केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि आर्थिक संभावना का केंद्र भी हो सकता है। यदि रोजगार, जल, सड़क और आजीविका से जुड़ा ढांचा गांव में मजबूत होता है, तो जन–शून्य हो चुके या होने की कगार पर खड़े गांवों में भी पुनर्जीवन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इससे न केवल लोगों की वापसी संभव होगी, बल्कि नई पीढ़ी को गांव में भविष्य दिखाई देगा।इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह  है कि  रोज़गार को टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ना। जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी संरचनाएं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले कार्य, ये सभी क्षेत्र उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। पर्वतीय राज्य में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। चाल–खाल, जलस्रोत पुनर्जीवन, छोटी सिंचाई योजनाएं और वर्षा जल संचयन जैसे कार्य यदि योजनाबद्ध ढंग से किए जाते हैं, तो इससे खेती, पशुपालन और घरेलू जीवन को दीर्घकालिक सहारा मिलेगा। इसी तरह पैदल मार्ग, ग्रामीण सड़कें, गोशालाएं और सामुदायिक भवन न केवल रोजगार देंगे, बल्कि गांवों को रहने योग्य और आत्मनिर्भर बनाएंगे।पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 का वित्तीय साझेदारी मॉडल उत्तराखंड के लिए विशेष राहत लेकर आता है। इससे राज्य सरकार पर वित्तीय दबाव कम होगा और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की संभावना बढ़ेगी। प्रशासनिक व्यय की सीमा को छह से नौ प्रतिशत तक बढ़ाना भी व्यावहारिक कदम है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन और तकनीकी सहायता अनिवार्य होती है।नया कानून प्रौद्योगिकी को बाधा नहीं, बल्कि सहायक माध्यम के रूप में देखता है। जियो–टैगिंग, रियल–टाइम डैशबोर्ड और सोशल ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं पारदर्शिता बढ़ाएंगी। ग्राम सभा की भूमिका को सशक्त कर सामुदायिक निगरानी सुनिश्चित की गई है, जिससे योजना का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, 2025 उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का, पलायन की चुनौती से जूझने का और पहाड़ को फिर से जीवंत बनाने का। यह कानून श्रमिक को अधिकार देता है, गांव को संसाधन देता है और पंचायत को नेतृत्व की भूमिका सौंपता है। यदि 125 दिनों की रोज़गार गारंटी, टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण और पंचायत आधारित योजना निर्माण ईमानदारी से जमीन पर उतरता है, तो यह अधिनियम उत्तराखंड के गांवों को केवल श्रम का केंद्र नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर विकास की प्रयोगशाला बना सकता है। यही वह राह है, जिससे जन–शून्य होते गांवों की परंपरा पर अंकुश लगेगा, पलायन की गति थमेगी और पहाड़ में रहने का भरोसा एक बार फिर मजबूत होगा।

# ईरानी बहनें तोड़ रही बुर्का की जंजीरे

संजय सक्सेना

ईरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का साहसी विद्रोह पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है, जहां कुरान के नाम पर थोपी गई बुर्का और नकाब जैसी परंपराओं के खिलाफ सड़कों पर आवाज़ उठ रही है। खामेनेई की तानाशाही वाली सरकार के सामने ईरानी महिलाएं बिना नारे लगाए, बिना हिंसा किए, बस सिर से दुपट्टा उतारकर सड़कों पर उतर आई हैं, जो महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद 2022 से चला आ रहा आंदोलन अब 2025-2026 में और तेज हो गया है। यह बगावत न केवल ईरान तक सीमित है, बल्कि अरब और अन्य मुस्लिम देशों में भी बुर्का हटाने की हवा चल रही है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत जैसे स्थानों पर इसके पक्ष में कट्टरता बढ़ रही है।

ईरान को पूरी तरह इस्लामिक राष्ट्र कहा जाता है, जहां 1979 की क्रांति के बाद अयातुल्लाह खुमैनी ने कुरान आधारित शासन स्थापित किया और महिलाओं पर सख्त हिजाब अनिवार्य कर दिया। नैतिक पुलिस द्वारा सड़कों पर गश्त कर महिलाओं को पकड़ना और सजा देना आम हो गया, लेकिन 2022 में 22 वर्षीय महसा अमीनी की हिरासत में संदिग्ध मौत ने चिंगारी जला दी। उसके बाद लाखों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर दुपट्टा जलाया, बाल कटवाए और नारे लगाए, जिससे पूरे देश में आंदोलन फैल गया। हालिया समाचारों के अनुसार, दिसंबर 2025 में तेहरान और अन्य शहरों में महिलाएं खुलेआम बिना दुपट्टे के घूम रही हैं, जो सरकार को डरा रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने विवादास्पद हिजाब कानून को स्थगित कर दिया, लेकिन सर्वोच्च नेता खामेनेई के दबाव में सैन्य बल तैनात हैं। प्रदर्शनों में कम से कम छह मौतें हो चुकी हैं और दर्जनों गिरफ्तारियां हुई हैं, फिर भी महिलाओं का खामोश विरोध जारी है।

बहरहाल, यह आंदोलन सिर्फ ईरान का नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर इस्लाम के नाम पर थोपी गई कट्टरता के खिलाफ जागृति का प्रतीक है। अरब प्रायद्वीप से इस्लाम फैला, लेकिन अब सऊदी अरब जैसे देशों में महिलाओं को पहले से अधिक स्वतंत्रता मिल रही है, जहां अब पूर्ण बुर्का अनिवार्य नहीं। मध्य एशिया के मुस्लिम बहुल देशों में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। कजाकिस्तान, जहां 70 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है, ने 2025 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का-नकाब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जुर्माना 10 हजार से एक लाख रुपये तक। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने पहले ही चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर रोक लगा रखी है, ताकि धार्मिक कट्टरपंथ न फैले। कुल 16 से अधिक देशों ने बुर्का या नकाब पर कानूनी पाबंदी लगा दी है। यूरोपीय देशों में स्विट्जरलैंड ने 2021 के जनमत संग्रह में 51.21 प्रतिशत वोटों से 2025 में इसे लागू किया, जबकि फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑसट्रिया, नीदरलैंड, बुल्गारिया, इटली और जर्मनी ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर जुर्माना या जेल की सजा निर्धारित की। बेल्जियम में मात्र 300 महिलाएं ही बुर्का पहनती थीं, फिर भी 10 लाख मुसलमानों के बीच इसे प्रतिबंधित किया गया।

इसके विपरीत, दक्षिण एशिया में स्थिति उलटी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में, जहां इस्लाम स्थानीय रूप से फैला, वहां कट्टरता बढ़ रही है। भारत के बिहार में हाल ही में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला डॉक्टर का दुपट्टा हटाने पर विवाद हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान तक से विरोध के सुर उठे। बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि बुर्का पसंद है तो पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाएं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में महिलाएं दुपट्टा या बुर्का पहनने को धार्मिक अधिकार बताकर प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि वहां के सर्वेक्षणों में 60-70 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं इसे स्वैच्छिक बताती हैं, लेकिन कट्टर समूह दबाव बनाते हैं। भारत में कर्नाटक हिजाब विवाद के बाद स्कूल-कॉलेजों में बहस चली, जहां मुस्लिम छात्राओं ने पहनने पर जोर दिया। यह विरोधाभास दर्शाता है कि जहां मूल इस्लामिक केंद्रों में महिलाएं आजादी चाह रही हैं, वहीं यहां आयातित कट्टरता बुर्का को मजबूरी बना रही है।

## कविता

### जिंदगी कहती है

ये जिंदगी तो करती है बस अपनी मनमानी,
हर इंसान की अपनी है एक अलग कहानी,
कर्मों का हिसाब-किताब निरंतर चलता है,
कहीं है कारी बदरी तो कहीं धूप आसमानी ।

जो रूठ जाता है जिंदगी की समस्याओं से,
दूर हो जाता है वो तो सफ़ल संभावनाओं से,
वो जिंदगी को अपनी बोझिल बना लेता है,
टूट जाता है वो दर्दनाक भारी विपदाओं से ।

सीखों बाधाओं को नज़रिया बदल दूर करना ,
अपने 'आनंद' आत्मविश्वास को प्रबल रखना,
वर्तमान परिस्थितियों को बदला जा सकता है,
जिंदगी कहती हैं चाहते हो तुम यूँ प्यार करना ।

बड़े ही टेढ़े-मेढ़े दांव-पेंच है अलबेली जिंदगी के,
सुख-दुःख के मोल भाव प्रेम संतुष्टि सादगी के,
खोटे सिक्के को एक प्रभु तू ही सोना है बनाता,
कारण बहुत सारे है दीनानाथ तेरी बंदगी के ।

- मोनिका डागा 'आनंद'

## आपका मत

### अदालतों के दरवाज़े चौबीस घंटे खुले रखना

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का स्पष्ट कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को वास्तव में "आम लोगों की अदालत" बनाना चाहते हैं, ताकि कानून की आपात स्थिति में भी नागरिकों को तुरंत न्याय मिल सके । मुख्य न्यायाधीश के अनुसार, अदालतों को चौबीस घंटे खुले रखने का उद्देश्य देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रभावी रक्षा करना है । अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड की तरह अदालतों में भी "न्याय की इमरजेंसी" की व्यवस्था होना समय की आवश्यकता है। देश के आम गरीब और मध्यमवर्गीय नागरिकों के लिए यह सोच अत्यंत स्वागतयोग्य और जनहितार्थ है । यदि चीफ जस्टिस सूर्यकांत अपने इस विचार को व्यवहारिक निर्णय का रूप देते हैं, तो यह कदम न्याय व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकता है । अब तक जो आम नागरिक अपने अधिकारों के लिए जिला न्यायालयों तक ही सीमित रह जाते थे, वे इस व्यवस्था के लागू होने पर बड़ी अदालतों तक आसानी से पहुँच सकेंगे और समय पर न्याय पा सकेंगे ।

जब देश में प्रभावशाली नेताओं, अपराधियों और रसूखदारों के मामलों में अदालतें आधी रात को भी खुलकर कार्य कर सकती हैं, तो फिर आम नागरिकों के लिए अस्पतालों की इमरजेंसी की तरह अदालतों का चौबीस घंटे खुला रहना न केवल आवश्यक है, बल्कि पूरी तरह न्यायसंगत भी है ।

-अरविंद रावल

लोकसत्य

आप अपना मत व लेख हमें इस ई-मेल भेज सकते है।

loksatyaedit01@gmail.com

## Blogger

# मूल राष्ट्रवादी चेतना, लोकतंत्र और अधिनायकवाद के प्रति सतर्कता

संजीव ठाकुर

राष्ट्रवाद आधुनिक राष्ट्र-राज्य की वैचारिक आधारशिला है। यह केवल भौगोलिक सीमाओं या राजनीतिक सत्ता से संबद्ध अवधारणा नहीं है, बल्कि साझा इतिहास, सांस्कृतिक स्मृति, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक उत्तरदायित्वों का समन्वित स्वरूप है।

राष्ट्रवाद का मूल चरित्र सार्वभौमिक और समावेशी होता है, जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और मानवीय गरिमा जैसे मूल सिद्धांतों को पुष्ट करता है। ऐतिहासिक रूप से यह सिद्ध हुआ है कि राष्ट्र-निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया में राष्ट्रवादी चेतना की भूमिका निर्णायक रही है। किंतु जब यही चेतना सत्ता-केंद्रित राजनीति, संकीर्ण वैचारिक आग्रहों और तात्कालिक राजनीतिक लाभों से संचालित होने लगती है, तब यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है।

लोकतांत्रिक राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक का यह नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि वह राष्ट्र के प्रति निष्ठावान और सजग रहे। किंतु इस निष्ठा का आशय अंध-समर्थन या आलोचनात्मक विवेक का त्याग नहीं है। दुर्भाग्यवश, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रवाद को धर्म, जाति और संप्रदाय के साथ जोड़कर सत्ता-प्राप्ति का साधन बनाए जाने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ी है। ऐसी राजनीति न केवल राष्ट्रीय एकता को खंडित करती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता और निष्पक्षता को भी कमजोर करती है। इतिहास साक्षी है कि सत्ता के दीर्घकालिक केंद्रीकरण ने राजाओं, सम्राटों और शासकों को निरंकुश बनाया है। आधुनिक लोकतंत्र में भी यह खतरा कम नहीं हुआ है, बल्कि अधिक परिष्कृत रूप में उपस्थित है।

लोकतंत्र का मूल सिद्धांत सत्ता का निरंतर आवर्तन है। सत्ता का परिवर्तनशील होना शासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और जनोन्मुख बनाता

है। इसके विपरीत, जब सत्ता लंबे समय तक एक ही राजनीतिक शक्ति के अधीन रहती है, तो अधिनायकवादी प्रवृत्तियों का उदय स्वाभाविक हो जाता है। अवसरवादी राजनीति, पद-लोलुपता और जातिगत समीकरणों का अतिवादी प्रयोग लोकतांत्रिक संतुलन को बिगाड़ देता है। इस प्रक्रिया में जनता को दूरगामी राष्ट्रीय हितों के स्थान पर तात्कालिक लाभों के प्रलोभन में उलझाया जाता है, जिससे नीति-निर्माण की गुणवत्ता और राष्ट्रीय विकास की क्षमता दोनों प्रभावित होती हैं।

लोकतंत्र में राजनीति का उद्देश्य जनभावनाओं का शोषण नहीं, बल्कि उनका संरक्षण और संवर्द्धन होना चाहिए। किंतु जब राजनीति का केंद्र बिंदु सत्ता-प्राप्ति और सत्ता स्थायित्व बन जाता है, तब सिद्धांतों की प्रतिबद्धता कमजोर पड़ जाती है। अवतारवाद, सस्ती लोकप्रियता और भावनात्मक ध्रुवीकरण लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर देते हैं। भारतीय राजनीतिक परंपरा में 'शाम, दाम, दंड, भेद' को शासन के उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र में इनका अति प्रयोग अनुशासन, नैतिकता और संस्थागत विश्वास को क्षीण करता है।

लोकप्रियता को मापने के सुदृढ़ लोकतांत्रिक उपकरणों के अभाव में कई बार संगठित किंतु संख्यात्मक रूप से छोटे समूह नीति-निर्माण पर विपरीत प्रभाव डालने लगते हैं। यह स्थिति बहुमत के शासन के लोकतांत्रिक आदर्श के विपरीत है। दलबदल, अवसरवादी गठबंधन और सिद्धांतहीन राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण के प्रमुख कारण बन चुके हैं। भारतीय संविधान के भीतर विद्यमान कुछ प्रक्रियात्मक छिद्रों का उपयोग कर राजनीतिक दल सत्ता-संरक्षण के जटिल ताने-बाने बुनते हैं, जिनके दीर्घकालिक दुष्परिणाम समाज और राष्ट्र दोनों को भुगतने पड़ते हैं। जातिवादी राजनीति और लोकप्रियता की व्यावहारिक मजबूरियों ने खाप पंचायतों जैसी समानांतर संरचनाओं को जन्म दिया है। ये संरचनाएँ पंचायती राज व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती हैं, जिससे लोकतंत्र की जमीनी संस्थाएँ कमजोर होती हैं। इसी प्रकार, धर्म और धार्मिक प्रथाओं में समानता तथा स्वतंत्रता का हनन तुष्टीकरण-आधारित राजनीति का प्रतिफल है।

लोकतांत्रिक समाज में समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत किसी भी नीति-निर्णय के मूल में होने चाहिए। एकतरफा और भावनात्मक निर्णय इन मूल्यों के प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

अतिराष्ट्रवाद की अवधारणा, जब लोकतांत्रिक विवेक से विमुख हो जाती है, तब तानाशाही प्रवृत्तियों को वैधता प्रदान करने लगती है। सैनिक राष्ट्रवाद, भय की राजनीति और सस्ती लोकप्रियता ने बीसवीं शताब्दी में अनेक देशों में लोकतंत्र को क्षतिग्रस्त किया है।

जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। -स्वामी विवेकानंद

संपादकीय

# पड़ोसी नीति में भारत की परिपक्वता

बीते एक वर्ष में भारत-बांग्लादेश संबंधों में आई ठंडक केवल द्विपक्षीय असहमतियों का परिणाम नहीं है, ढाका की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते साम्प्रदायिक तनाव की भी देन है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश जिस तरह अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा और उग्र बयानबाजी का साक्षी बना, उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत को भी चिंता में डाला। इसके बावजूद भारत ने संयम, संवेदनशीलता और संवाद की नीति से पीछे हटने के बजाय 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत को व्यवहार में उतारने का प्रयास किया। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर का ढाका पहुंचना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश पत्र तारिक रहमान को सौंपना इसी नीति का प्रतीक है। यह महज औपचारिक संवेदना नहीं, भविष्य के लिए कूटनीतिक पुल बनाए रखने का संकेत भी है। ऐसे समय में, जब बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली व फरवरी 2026 में प्रस्तावित चुनावों को लेकर चर्चा तेज है, भारत का यह व्यवहार दूरदर्शिता को बताता है। रहमान को संभावित भावी प्रधानमंत्री माना जा रहा है, ऐसे में उनसे हुई मुलाकात भविष्य के संबंधों की आधारशिला लगती है। खालिदा का राजकीय अंतिम संस्कार केवल एक राजनीतिज्ञ को विदाई नहीं था, बांग्लादेश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अध्याय भी था। इसमें भारत, नेपाल और पाक सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने दक्षिण एशिया की जटिल कूटनीतिक संरचना को उजागर किया। विशेष रूप से 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारतीय और पाकिस्तानी वरिष्ठ नेताओं की अनौपचारिक मुलाकात ने यह संकेत दिया कि संवाद के द्वार पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, भले ही औपचारिक रिश्ते जमे हुए हों। आज जब बांग्लादेश आंतरिक उथल-पुथल से गुजर रहा है, तब भारत का संयमित रुख यह संदेश देता है कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते तात्कालिक कटुता से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और क्षेत्रीय शांति के दृष्टिकोण से संचालित होने चाहिए। संवेदना के इन कूटनीतिक संकेतों में भविष्य की संभावनाएं भी निहित हैं।

# 2026: पांच राज्यों में सियासी परीक्षा

नये साल 2026 की दस्तक के साथ ही देश की राजनीति निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्रशासित पुडुचेरी में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव न केवल क्षेत्रीय सत्ता-संतुलन तय करेंगे, 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी काफी हद तक स्पष्ट होगी। बिहार में एनडीए की जीत के बाद विपक्ष के हौसले जहां पस्त हैं, वहीं भाजपा के सामने अब हर राज्य में अलग-अलग राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का जटिल ताना-बाना है। यदि असम और पुडुचेरी को अपवाद मान लें, तो पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु भाजपा के लिए सबसे कठिन रणक्षेत्र साबित हो सकते हैं। इन तीनों राज्यों में भाजपा अब भी या तो हाशिये पर है या फिर सत्ताधारी दलों की मजबूत जड़ों से जूझ रही है। फिर भी, भाजपा की चुनावी शैली लगातार तैयारी, संसाधनों की प्रचुरता और मुद्दों को अवसर में बदलने की क्षमता उसे अन्य दलों से अलग खड़ा करती है।

सबसे दिलचस्प मुकाबला पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी और भाजपा के बीच यह सीधा संघर्ष बीते एक दशक से लगातार तीखा हुआ है। 2021 के चुनाव में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी व अपने वोट प्रतिशत में इजाफा भी किया था। लेकिन उसके बाद लोकसभा और उपचुनावों में भाजपा कमजोर पड़ती दिखी। तृणमूल ने न केवल अपना आधार मजबूत किया है, कांग्रेस और वाम दलों के कमजोर पड़ने का सीधा लाभ भी उठाया है। मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण तृणमूल को लाभ पहुंचा सकता है, जबकि पहले यह वोट कांग्रेस और वामपंथ में बंटता था। भाजपा ने बंगाल में कभी ध्रुवीकरण तो कभी सामाजिक गोलबंदी के जरिए रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास आंशिक ही सफल रहे। बंगाली समाज की ऐतिहासिक सुधारवादी परंपरा, भद्रलोक की भूमिका और जातिगत ध्रुवीकरण भाजपा की राह को जटिल बनाते हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष और संगठनात्मक प्रयोगों से संकेत जरूर दिए जा रहे हैं, पर जमीनी स्तर पर चुनौती अब भी बड़ी है। इसके बावजूद पड़ोसी बांग्लादेश में हुई राजनीतिक और सामाजिक

उथल-पुथल का मुद्दा भाजपा के लिए एक संभावित चुनावी हथियार बन सकता है।

असम में तस्वीर थोड़ी अलग है। यहां भाजपा सत्ता में है, पर कांग्रेस ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से दूरी बनाकर मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में कर लिया है। इससे भाजपा के लिए चुनावी ध्रुवीकरण उतना सहज नहीं रहा। नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी, जनगणना और मतदाता सर्वे जैसे मुद्दे भाजपा के लिए असहजता पैदा कर सकते हैं। फिर भी, असम में भाजपा की मजबूत पकड़ उसे अब भी मुकाबले में बनाए रखती है। तमिलनाडु में भाजपा के सामने सबसे कठिन चुनौती है। द्रविड़ राजनीति की मजबूत परंपरा, भाजपा की सीमित सामाजिक स्वीकार्यता और विपक्षी खेमे की बिखरी हुई स्थिति, ये सभी मिलकर यहां एकतरफा तस्वीर पेश करते हैं। अन्नाद्रमुक में टूट, छोटे सहयोगी दलों की अनिश्चितता और द्रमुक-कांग्रेस-वाम गठबंधन के चलते भाजपा के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करना आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव नतीजे भी यही संकेत देते हैं कि सीएम स्टालिन को चुनौती देना फिलहाल कठिन है। केरल में भाजपा अपेक्षाकृत अधिक उत्साहित नजर आती है। हालिया निकाय चुनावों में उसे कुछ सफलता मिली है और तिरुवनंतपुरम की स्थानीय सत्ता में हिस्सेदारी ने उसका मनोबल बढ़ाया है। लेकिन केरल का समाज स्पष्ट जातिगत और सांप्रदायिक रेखाओं में बंटा हुआ है, जहां भाजपा का प्रभाव मुख्यतः नायर समुदाय और कुछ शहरी युवाओं तक सीमित है। यहां भाजपा के वोट बढ़ने का सीधा असर वाम मोर्चा सरकार की मुश्किलें बढ़ाने में दिख सकता है, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ कांग्रेस को मिल सकता है।

पुडुचेरी में सामाजिक संतुलन नाजुक है। यहां भाजपा गठबंधन की सरकार है, लेकिन छोटे-से बदलाव भी सत्ता समीकरण को पलट सकते हैं। अतः यहां किसी भी दल के लिए परिणाम को लेकर पूर्ण आश्वस्ति संभव नहीं। कुल मिलाकर, 2026 के ये चुनाव केवल राज्यों की सत्ता का प्रश्न नहीं हैं, बल्कि यह भी तय करेंगे कि भाजपा की विस्तार रणनीति कहां तक सफल होती है और विपक्ष किस हद तक खुद को पुनर्गठित कर पाता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा और असम-केरल में कांग्रेस के पूरी ताकत झोंकने के संकेत साफ हैं। लेकिन भारतीय राजनीति का अनुभव यही कहता है कि यहां अंतिम फैसला अक्सर आखिरी दौर की रणनीति और मतदाता की मनोदशा तय करती है। यही अनिश्चितता इन चुनावों को असाधारण रूप से महत्वपूर्ण और रोचक बनाती है।

■ राममनोहर रायकवार

## पंचांग राशिफल

**3 जनवरी 2026 दिन शनिवार** पौष मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947। **राहुकाल-** प्रातः 9:00 बजे से 10:30 बजे तक। **सूर्य उदयकालीन ग्रह विचार:-** सूर्य धनु राशि में चंद्र मिथुन राशि में मंगल धनु राशि में बुध धनु राशि में गुरु मिथुन राशि में शुक्र धनु राशि में शनि मीन राशि में राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में रहेगा। **सूर्य उदयकालीन नक्षत्र विचार:-** सुबह प्रातःकाल मिथुन राशि का नक्षत्र आर्द्रा का द्वितीय चरण प्रारंभ होगा और इसका नक्षत्र पाया रजत रहेगा प्रातः 10:30 बजे मिथुन राशि का नक्षत्र आर्द्रा का तृतीय चरण प्रारंभ होगा और इसका नक्षत्र पाया रजत रहेगा दोपहर 4:30 मिथुन राशि का नक्षत्र आर्द्रा का चतुर्थ चरण प्रारंभ होगा और इसका नक्षत्र पाया रजत रहेगा रात्रि 10:30 बजे मिथुन राशि का नक्षत्र पुनर्वसु का प्रथम चरण प्रारंभ होगा और इसका नक्षत्र पाया रजत रहेगा। **योग:-** ब्रह्म। **करण:-** बब। **नक्षत्र के अनुसार राशि नाम अक्षर:-** घ ङ छ के। **आराधना का मंत्र:-** ॐ सूर्यात्मजाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सौरिः प्रचोदयात्॥

- **मेष राशि:-** ग्रहों की चाल मजबूती से आपकी मदद कर रही है इसका भरपूर लाभ उठाकर आने वाले एक-दो दिनों में अपने आवश्यक काम कर लें।
- **वृषभ राशि:-** समय आज बेहद शानदार स्थिति में है विरोधी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे कामकाज बेहद शानदार रहेगा।
- **मिथुन राशि:-** समय आज से ठीक हो रहा है तनाव में कमी आएगी कामकाज में रुचि बढ़ेगी जरूरी काम अभी सोच-समझकर करें।
- **कर्क राशि:-** समय आज बेहद कमजोर है कोई भी काम सही प्रकार से नहीं होने के चलते तनाव बढ़ सकता है।
- **सिंह राशि:-** शनि का सहयोग आज पूरी तरह से प्राप्त होगा मित्रों और परिजन के सहयोग से कार्य बन सकता है।
- **कन्या राशि:-** समय सामान्य है बिना वजह के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं वाद-विवाद से बचें।
- **वृश्चिक राशि:-** राशि स्वामी का असहयोग बढ़ने से मन अप्रसन्न रहेगा, कामकाज साधारण रहेगा।
- **धनु राशि:-** एकादश भाव में बनी शुभ ग्रह स्थिति आपके कार्यों को सफल बना सकती है प्रेम संबंध मधुर रहेंगे।
- **मकर राशि:-** शुक्र ग्रह का सहयोग आज आपको प्राप्त होने जा रहा है कार्यक्षेत्र शानदार रहेगा मन प्रसन्न होगा।
- **कुंभ राशि:-** सितारे आज से सामान्य हो रहे हैं, मानसिक तनाव में कमी आएगी कामकाज में रुचि बढ़ेगी संतान से जुड़ा कोई काम होगा।
- **मीन राशि:-** समय आज बेहद कमजोर है जरूरी काम बिल्कुल न करें यात्रा बहुत सोच-समझकर करें।
- **तुला राशि:-** सितारों की आज अनुकूलता आपके पक्ष में रहने जा रही है मन शांत होगा काम में रुचि बढ़ेगी।

# आत्मनिर्भर भारत की नई सामरिक उड़ान

भारत की बदलती सामरिक यात्रा आज केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति बन चुकी है। आर्थिक शक्ति, कूटनीतिक सक्रियता और स्वदेशी रक्षा तकनीक के समन्वय ने भारत को निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में उभारा है। प्रलय मिसाइल इसी परिवर्तनशील भारत की ठोस पहचान है।

पिछले एक दशक में भारत ने विकास की जिस तेज रफ्तार को अपनाया है, उसने देश की पहचान को केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे वैश्विक नेतृत्व की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। आर्थिक सशक्तिकरण, आधारभूत ढांचे का विस्तार और कूटनीतिक प्रभाव, इन तीनों मोर्चों पर भारत की प्रगति ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। आज भारतीय कूटनीति आत्मविश्वास से भरी हुई है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की निर्णायक भूमिका इसके प्रमाण के रूप में सामने आती है। इसी व्यापक प्रगति का सबसे ठोस और रणनीतिक रूप रक्षा क्षेत्र में दिखाई देता है। कभी हथियारों के आयात पर निर्भर रहने वाला भारत आज स्वदेशी तकनीक के बल पर रक्षा निर्यातक बन चुका है। कई मित्र देशों के साथ हुए रक्षा सौदे इस बदलाव की गवाही देते हैं। यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामरिक आत्मनिर्भरता का भी संकेत है।

**इसी** क्रम में भारत ने डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रलय मिसाइल का सफल सैल्वो लॉन्च कर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। ओडिशा तट के पास एक ही लॉन्चर से कम समय के अंतराल में दो प्रलय मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण न केवल तकनीकी दक्षता का प्रमाण है, भारत की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को भी रेखांकित करता है। इस परीक्षण का उद्देश्य मिसाइल प्रणाली की विश्वसनीयता और युद्धकालीन उपयोगिता को परखना था। दोनों मिसाइलों ने निर्धारित मार्ग का पूर्णतः पालन किया व सभी उड़ान लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। इस परीक्षण के दौरान आधुनिक निगरानी प्रणालियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज पर तैनात ट्रैकिंग सेंसरों ने पूरे प्रक्षेपवक्र की सटीक पुष्टि की, जबकि लक्ष्य क्षेत्र के निकट तैनात जहाजों पर लगे टेलीमेट्री सिस्टम ने अंतिम चरण की हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया। यह समन्वित निगरानी भारत की परीक्षण क्षमता की परिपक्वता को बताती है। प्रलय एक स्वदेशी, ठोस ईंधन से चलने वाली क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें अत्याधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम लगे हैं।

**इस** मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सटीकता और बहुउपयोगिता है। यह विभिन्न प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम है और अलग-अलग लक्ष्यों को भेद सकती है। यही कारण है कि प्रलय न केवल सामरिक संतुलन को मजबूत करती है, संभावित खतरों के प्रति भारत की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। इस मिसाइल का विकास हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत के नेतृत्व में किया गया, जिसमें डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकास-सह-उत्पादन भागीदार के रूप में सिस्टम इंटीग्रेशन का कार्य संभाला। यह सहयोग 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना का जीवंत उदाहरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस सफलता पर दी गई बधाई और डीआरडीओ प्रमुख का यह विश्वास कि यह मिसाइल शीघ्र ही सेना में शामिल होगी, यह संकेत देता है कि भारत अब केवल भविष्य की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि वर्तमान को भी सुरक्षित बना रहा है। प्रलय मिसाइल की यह उड़ान दरअसल भारत की उस सामरिक सोच की उड़ान है, जो आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय सुरक्षा के नए मानदंड स्थापित कर रही है।

■ जसवंत सिंह राजपूत

## जीवनशैली

भारत विविधताओं का देश है, जहां हर राज्य की अपनी पहचान, संस्कृति और विशेषताएं हैं। लेकिन इन सबके बीच एक राज्य ऐसा भी है, जिसकी तुलना यूरोप के सबसे विकसित और खुशहाल देशों में शुमार फिनलैंड से की जाने लगी है। न बर्फीली सर्दियां, न नॉर्डिक रातें फिर भी यह राज्य शिक्षा, सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में फिनलैंड की याद दिलाता है। यह राज्य है केरल, जिसे अब 'फिनलैंड ऑफ इंडिया' कहा जा रहा है। आखिर क्या हैं वे कारण, जो इस तुलना को सार्थक बनाते हैं?

# भारत में फिनलैंड की झलक

### शिक्षा बनी सबसे बड़ी ताकत

केरल की पहचान उसकी मजबूत शिक्षा व्यवस्था से शुरू होती है। यहां की साक्षरता दर 94 प्रतिशत से अधिक है, जो भारत में सबसे ऊंची मानी जाती है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, राज्य ने समान और सार्वभौमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि केरल की तुलना फिनलैंड से की जाती है, जो अपनी विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम जैसे वैश्विक आंकलनों में शीर्ष प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। दोनों ही जगह शिक्षा को केवल डिग्री नहीं, बल्कि सामाजिक विकास का आधार माना जाता है।

## केरल की अनोखी कहानी

### सामाजिक कल्याण और लैंगिक समानता

फिनलैंड की तरह केरल भी सामाजिक समानता और कल्याणकारी नीतियों के लिए जाना जाता है। यह भारत के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के मामले में केरल का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है। यह तस्वीर काफी हद तक फिनलैंड जैसे विकसित देशों से मेल खाती है, जहां सामाजिक सुरक्षा और लैंगिक समानता को शासन की रीढ़ माना जाता है।

### जीवन की गुणवत्ता में अग्रणी

केरल का मानव विकास सूचकांक देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी ऊंचा है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, लंबी जीवन प्रत्याशा और व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इसे अलग पहचान देती हैं। ठीक इसी तरह फिनलैंड भी अपने उच्च जीवन स्तर और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है।

### प्राकृतिक सौंदर्य और जल-संपदा

फिनलैंड को 'हजारों झीलों की भूमि' कहा जाता है, वहीं केरल अपने बैकवाटर्स, नदियों, झीलों और लैगून के लिए प्रसिद्ध है। भले ही जलवायु अलग हो, लेकिन पानी से जुड़ा जीवन दोनों जगहों की संस्कृति का अहम हिस्सा है।

### वास्तविक जुड़ाव

यह तुलना सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। हाल के वर्षों में केरल और फिनलैंड के बीच शिक्षा और सतत विकास को लेकर औपचारिक सहयोग भी हुआ है। 'फिनलैंड ऑफ इंडिया' का तमगा केरल की मानवीय उपलब्धियों और दूरदर्शी नीतियों को रेखांकित करता है। 'गॉड्स ओन कंट्री' केरल आज यह साबित करता है कि बेहतर शासन, सामाजिक मूल्यों और शिक्षा के बल पर विकास की नई परिभाषा गढ़ी जा सकती है।

# खुद की गुदगुदी पर क्यों नहीं आती हंसी?

गुदगुदी एक ऐसा अनुभव है, जिसे लगभग हर इंसान ने जीवन में कभी न कभी महसूस किया है।
पसलियों, पेट, गर्दन या पैरों के तलवों पर हल्का सा स्पर्श होते ही हंसी अपने आप फूट पड़ती है। यह हंसी अक्सर बेकाबू होती है, चाहे इंसान कितना ही गंभीर क्यों न बनने की कोशिश करे। लेकिन इस साधारण-सी अनुभूति में एक गहरा रहस्य छिपा है। हैरानी की बात यह है कि जब वही व्यक्ति खुद को गुदगुदी करने की कोशिश करता है, तो न हंसी आती है, न कोई खास प्रतिक्रिया होती है। आखिर ऐसा क्यों?

### वैज्ञानिक तर्क

वैज्ञानिकों के अनुसार, गुदगुदी सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि दिमाग और शरीर के बीच होने वाला जटिल संवाद है। विज्ञान गुदगुदी को दो प्रकारों में बांटता है। पहली है निस्कटिस, जो हल्के स्पर्श या खुजली जैसी अनुभूति से जुड़ी होती है। जैसे त्वचा पर किसी कीड़े का रेंगना। दूसरी और ज्यादा प्रभावशाली गुदगुदी को गार्गालेसिस कहा जाता है, जो तेज हंसी और शारीरिक प्रतिक्रिया पैदा करती है। आमतौर पर जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें गुदगुदी करता है।

### दिमाग देता है संकेत?

जब कोई दूसरा व्यक्ति गुदगुदी करता है, तो हमारा दिमाग उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं होता। यही अनिश्चितता मस्तिष्क को चौंका देती है। त्वचा में मौजूद संवेदी रिसेप्टर्स से संकेत मस्तिष्क के सोमैटोसेन्सरी कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं, जो स्पर्श को पहचानता है। साथ ही लिम्बिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जो भावनाओं और हंसी जैसी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस पूरी प्रक्रिया में एमिगडाला भी अहम भूमिका निभाता है।

## दिमाग में छिपा है राज

### खुद की गुदगुदी दिमाग के लिए नहीं बनती आश्चर्य

जब हम खुद अपने शरीर को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग पहले से जानता होता है कि अगला स्पर्श कहां और कब होने वाला है। इस का जिम्मा मस्तिष्क के सेरिबेलम नामक हिस्से पर होता है। सेरिबेलम हमारी हर स्वैच्छिक गतिविधि का अनुमान लगाकर दिमाग को पहले ही सतर्क कर देता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में सेंसरी कैंसलेशन कहा जाता है, जिसमें दिमाग स्पर्श की तीव्रता को कम कर देता है। यही कारण है कि खुद की गुदगुदी दिमाग के लिए कोई आश्चर्य नहीं बनती। वैज्ञानिक शोध यह भी बताते हैं कि गुदगुदी पर आने वाली हंसी हमेशा खुशी की अभिव्यक्ति नहीं होती। कई बार यह एक स्वचालित प्रतिक्रिया होती है, जो सामाजिक जुड़ाव और आपसी भरोसे से जुड़ी होती है। यही वजह है कि किसी अपने की गुदगुदी पर हंसी आसानी से निकल आती है, जबकि अजनबी की गुदगुदी असहज या परेशान करने वाली लग सकती है। कुल मिलाकर, गुदगुदी और हंसी का यह रहस्य हमारे दिमाग की भविष्यवाणी करने की क्षमता और अचानकपन के तत्व में छिपा है। जहां आश्चर्य होता है, वहां हंसी जन्म लेती है और जहां सब कुछ पहले से पता हो, वहां गुदगुदी भी बेअसर हो जाती है।

# 30 साल बाद गूंजी किलकारी

तीन दशक तक इटली के एक गांव में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। सिर्फ बिल्लियों की म्याऊं और बुजुर्गों की धीमी आवाजें ही इसकी पहचान बन चुकी थीं, लेकिन अब 30 साल बाद जब लारा ने जन्म लिया तो मानो गांव की हर गली ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब वहां सिर्फ बिल्लियों का नहीं, जीवन का भी राज लौट आया है।

### इंसानों से ज्यादा हैं बिल्लियां

इटली के अब्रूजो क्षेत्र में बसा छोटा-सा गांव पाग्लियारा देई मार्सी कभी रौनक से भरा रहता था। मगर वक्त के साथ युवा रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों की ओर चले गए। पीछे रह गए सिर्फ कुछ बुजुर्ग और बिल्लियां। अब इस गांव की आबादी घटकर सिर्फ 20 लोगों तक रह गई है, जबकि बिल्लियों की संख्या उनसे कई गुना ज्यादा है। तीन दशक से यहां किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था।

## बिल्लियों के गांव में लौटा जीवन

### लारा ने लौटाई खुशियां

फिर आई लारा बुसी त्राबुक्को, एक नन्ही बच्ची, जिसने गांव की खामोशी तोड़ दी। लारा कुछ ही महीने की है, लेकिन वह अब गांव की स्टार बन चुकी है। हाल ही में उसके बपतिस्मा (ईसाई दीक्षा समारोह) का आयोजन हुआ, जहां आसपास के ही नहीं, बल्कि दूर-दूर से लोग और पर्यटक भी पहुंचे, सिर्फ इस अद्भुत पल को देखने कि तीन दशक बाद इस गांव में जीवन ने फिर जन्म लिया।

### वक्त ने गांव किया खाली

कभी खेती-बाड़ी और पारिवारिक मेलजोल के लिए मशहूर रहा यह गांव अब लगभग वीरान हो चुका है। युवाओं का पलायन और घटती जन्म दर ने इसे बुजुर्गों का गांव बना दिया है। लेकिन लारा के जन्म के बाद उम्मीद की किरण लौटी है।

### एक गांव नहीं, पूरे इटली की कहानी

इटली इन दिनों जनसंख्या घटने के गंभीर संकट से गुजर रहा है। साल 2024 में यहां सिर्फ 3,69,944 बच्चे पैदा हुए, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। महिलाओं की औसत प्रजनन दर घटकर 1.18 प्रति महिला रह गई है, जो यूरोप में सबसे कम दरों में से एक है। आर्थिक अस्थिरता, नौकरी की कमी और बदलती जीवनशैली ने युवाओं को परिवार बढ़ाने से दूर कर दिया है।

### लारा बनी उम्मीद की किरण

तीन दशकों की खामोशी के बाद लारा की किलकारी ने पाग्लियारा देई मार्सी में नई जान फूंक दी है। अब लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारे गांव में अब सिर्फ बिल्लियां नहीं, एक नई पीढ़ी भी सांस ले रही है। लारा भले ही नन्ही है, लेकिन उसने साबित कर दिया कि जहां उम्मीद जिंदा रहती है, वहां जीवन लौट ही आता है।

जागरूक संपादकीय
जागरूक टाइम्स। मुंबई | शनिवार, 3 जनवरी 2026

## श्रीरामचरितमानस

**नामु राम को कलपतरु कलि कल्यान निवासु।**
**जो सुमिरत भयो भांग तें तुलसी तुलसीदासु॥26॥**

**भावार्थ :** कलियुग में राम का नाम कल्पतरु (मन चाहा पदार्थ देने वाला) और कल्याण का निवास (मुक्ति का घर) है, जिसको स्मरण करने से भांग सा (निकृष्ट) तुलसीदास तुलसी के समान (पवित्र) हो गया॥

# सपना होगा साकार

देश में बुलेट ट्रेन चलने का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए साल के पहले दिन देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। इसकी तारीख की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 2027 से देश में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अगले साल के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बुलेट ट्रेन की सवारी करने के लिए अभी से टिकट खरीद लीजिए। पहले चरण में सूरत से वापी के बीच 100 किलोमीटर दूरी में ये ट्रेन चलाई जाएगी। बुलेट ट्रेन में सफर का सपना संजोए हर भारतीय ट्रेन चलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यह ट्रेन न केवल गौरव का प्रतीक है, बल्कि बदलते भारत की तस्वीर भी बयां करेगी। बता दें कि देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाने की योजना है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दोनों मेट्रो शहरों के बीच 508 किमी का सफर दो घंटे 17 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। ट्रेन प्रोजेक्ट का लगभग 55 प्रतिशत काम पूरा हो जुका है। पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की थी। पूरे रूट में 352 किलोमीटर हिस्सा गुजरात और दादरा व नगर हवेली के बीच और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रोजेक्ट को नेशनल हाई-स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) जापान के सहयोग से तैयार करा रहा है। ये ट्रेन जापान की शिंकानसेन हाई-स्पीड ट्रेन की तर्ज पर चलेगी। इसकी अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 12 स्टेशन पड़ेंगे, जिसमें अहमदाबाद, वड़ोदरा, भरूच, सूरत, वापी, ठाणे और मुंबई प्रमुख हैं। प्रोजेक्ट का 85 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 465 किलोमीटर एलिवेटेड होगा, जिसमें से 326 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। चीन, जापान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इटली और ताइवान में बुलेट ट्रेनें चलती हैं। इनमें चीन के पास इसका सबसे लंबा नेटवर्क है। जापान ने 1964 में सबसे पहले बुलेट ट्रेन की शुरुआत की थी। वहीं फ्रांस और जर्मनी भी हाई-स्पीड रेल के मामले में प्रमुख देश हैं। अमेरिका, इंडोनेशिया और मोरक्को में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन पूरा कर लिया गया है। यह ट्रेन 18-19 जनवरी से गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलाई जा सकती है। ट्रायल रन के दौरान ट्रेन ने 16 कोचों के साथ अधिकतम 182 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। इसे जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। वैष्णव ने बताया कि गुवाहाटी-हावड़ा के बीच स्लीपर वंदे भारत के तृतीय एसी का किराया लगभग 2300 रुपए हो सकता है। उन्होंने कहा कि हवाई किराए की बात करें तो ये छह से आठ हजार के बीच होता है और कभी-कभी 10 हजार तक भी पहुंच जाता है।

स्वच्छता के पोस्टर के पीछे

# इंदौर में पानी के पाइपों में बहता जहर

**नरेंद्र शर्मा**

भारत के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा पिछले एक दशक से इंदौर के पास है, जो सिर्फ एक पुरस्कार नहीं बल्कि शहर की गर्वीली पहचान रहा है। लेकिन उसी इंदौर में इन दिनों पानी की लीकेज पाइप लाइनों के जरिये यहां के भागीरथपुरा इलाके में जिस तरह मौत का हाहाकार मचा हुआ है, उससे देश ही नहीं पूरी दुनिया स्तब्ध है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक इंदौर में दूषित पानी से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है और बीमार लोगों की संख्या करीब 1400 से ऊपर है। साल के पहले दिन तक शहर के भागीरथपुरा इलाके में पाइप लाइन में लीकेज से मिले सीवेज वाटर के कारण मरने वालों की संख्या जहां 14 थी, वहीं 2 जनवरी 2026 को 68 वर्षीय गीता बाई ने भी दम तोड़ दिया, इस तरह मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। अभी जितने लोग इस दूषित पानी के कारण बीमार हैं, उनमें 16 बच्चों के साथ 201 लोग, जो कि अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, उनकी हालत काफी नाजुक है।

इमेज

31 दिसंबर 2025 तक दूषित पानी को लेकर तरह-तरह की अटकलों और उनके खंडनों का जो बाजार गर्म था, उसे 1 जनवरी 2026 को महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी कि इस इलाके में पीने के पानी के साथ जानलेवा बैक्टीरिया की मिलावट पाइप लाइन में लीकेज के चलते सीवेज वाटर से हुई है।

इसके एक दिन पहले ही जिस तरह से बीजेपी के धाकड़ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक पत्रकार को इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर जिस तरह से हड़काने की कोशिश की थी और यह इम्प्रेशन दिया था कि मीडिया जानबूझकर शहर को बदनाम कर रही है, आज उन्हीं कैलाश विजयवर्गीय का वह वीडियो जिसमें वह एनडी टीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी के इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर कहा था कि फालतू का सवाल मत किया करो और यह भी कि 'घंटा' तुम्हें कुछ मालूम है। आज उस 60 सेकेंड के वीडियो के कारण न सिर्फ भाजपा की छवि तार-तार हो रही है बल्कि भारत के शहरी प्रशासन की सारी पोल खुलकर रह गई है। अब तक की मेडिकल जांच से यह भी पुष्टि हो गई है कि जिन 15 लोगों की मौत अभी तक हुई है, उन सभी लोगों की जान नलों में आ रहे जहरीले पानी से ही हुई है। मेडिकल कॉलेज के सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी ने सैंपल की जांच रिपोर्ट को पत्रकारों के सामने पेश करते हुए कहा है कि साफ तौरपर पुष्टि होती है कि जिस पानी को इलाके के लोगों ने पीया है, उसमें जहरीले बैक्टीरिया की मिलावट है। हालांकि इस मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा ने कुछ लीपापोती करने की कोशिश यह करके की कि अभी डिटेल में रिपोर्ट आने का इंतजार है और यह भी कि मेडिकल कॉलेज में 'कल्चर' टेस्ट भी किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ ठीक पता चलेगा। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि भागीरथपुरा इलाके में पेय जल में सीवेज का पानी प्रशासन की लापरवाही के कारण पीने वाले पानी में मिल गया है और इसकी पुष्टि उन्हीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी कर दी है, जो दो दिन पहले एनडी टीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी द्वारा इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर उखड़ गये थे। लेकिन अब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी खुद पत्रकारों के सामने आकर इस बात को स्वीकारा है और आशंका जताई है कि इलाके में स्थित चौकी के पास लीकेज वाली जगह है। दरअसल इस मामले में हर तरफ से आनन-फानन में जांच और कार्यवाईयों का दौर इसलिए भी चल पड़ा है, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करके दो सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने की बात कही है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक हालांकि हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरु नहीं हुई थी, लेकिन जबलपुर की दो सदस्यीय बेंच ने आज यानी 2 जनवरी 2026 को इस दूषित पानी के चलते हुई मौतों पर प्रशासन की लापरवाही को लेकर ऑनलाइन सुनवाई किए जाने का फैसला किया है और कोर्ट ने सरकार से स्टेट्स रिपोर्ट मांगा है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक दूषित पानी में बैक्टीरिया का होना तय हो चुका है, लेकिन कौन से बैक्टीरिया ने प्रभावित किया है, इसके लिए एक स्पेशल जांच होती है, जिसे 'कल्चर' कहते हैं, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। माना जाता है कि पानी की पाइप लाइन में जो सीवेज का पानी मिला है, उसमें कई तरह का गंदा पानी था। मसलन टॉयलेट में बहने वाला मल-मूत्र, बाथरूम में नहाने और कपड़े धोने के साबुन और पाउडर वाला पानी, साथ ही बर्तन धोने के साबुन, फर्श साफ करने वाले लीक्विड और केमिकल भी इस सीवेज पानी में बहते हैं यानी ये अलग-अलग तरह के दूषित जल ड्रेनेज में आकर मिलते हैं और यही पीने वाले पानी की पाइप लाइन में शामिल हो गया है। जानकारों का कहना है कि अगर इस पानी में कॉमर्शियल केमिकल संबंधी वेस्ट हैं, तो यह पानी इतना ज्यादा घातक हो गया है। इससे हैजा आदि के होने की गंभीर संभावनाएं होती हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पीने के पानी में गंदे पानी के मिलावट के कारण मौते हुईं, अब जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे पता चल रहा है कि स्थानीय बस्ती भागीरथपुरा के लोग पिछले एक साल से गंदले पानी की शिकायत कर रहे थे। फिर भी उनकी शिकायत प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने नहीं सुनी। सबसे बड़ा आरोप निगमायुक्त दिलीप यादव पर लग रहा है, जिन्होंने गंदे पानी की शिकायतों को अनदेखा किया और पाइप लाइन की टेंडर प्रक्रिया पर नजर नहीं रखी। वहीं अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया पर भी उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि अगस्त में टेंडर हुए थे, जिन्हें उन्होंने रोक रखा था, लेकिन शिकायतें नहीं सुनी। भागीरथपुरा इलाके जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं और 15 लोगों की जान गई है, उस इलाके के निगम पार्षद कमल वाघेला से चार महीनों से स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे। लेकिन वह इस संबंध में कोई त्वरित कार्यवाई कराने में असफल रहे। यही आरोप इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर भी लग रहा है, क्योंकि पार्षद कमल वाघेला का कहना है कि उन्होंने महापौर से कई बार शिकायतें की, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, न ही कोई कदम उठाया और अंतिम रूप से या व्यवहारिक रूप से जो प्रभावशाली व्यक्ति इस लापरवाही का प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हो सकता है, वो हैं बब्लू शर्मा, जो स्थानीय इलाके के जल कार्य प्रभारी हैं।

## गीता सार

**क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।**
**क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप॥3॥**

**भावार्थ :** हे पृथा-पुत्र! कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रु-तापन! हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर(युद्ध के लिए) खड़े हो जाओ॥

संभावना-2026/बड़ा पर्दा

# बड़े पर्दे पर सीक्वल व हॉरर कॉमेडी का होगा यह साल

**कैलाश सिंह**

'होमबाउंड', जोकि ऑस्कर के लिए भारत की एंट्री है, को 98वें अकादमी अवाड्र्स में इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में 14 अन्य फिल्मों के साथ शोर्टलिस्ट किया गया है। कोविड-19 के कारण जब 2020 में पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था तो बड़े शहरों से प्रवासी मज़दूर अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए थे, इनमें से दो युवा व्यक्तियों की वास्तविक आपबीती पर आधारित है फिल्म 'होमबाउंड' जिसका लेखन व निर्देशन नीरज घेवान ने किया है। इन दोनों युवाओं की दोस्ती को मूलतः पत्रकार बशारत पीर ने रिपोर्ट किया था, जो घेवान के लिए हमारे समाज की फाल्ट लाइंस, हाशिये पर पड़े युवाओं की महत्वाकांक्षाओं और किस तरह कठिन घड़ी में भी वह उम्मीद से भरे रहते हैं, की समीक्षा का आधार बना। अकादमी अवार्ड नामांकन 22 जनवरी 2026 को घोषित किये जाएंगे और उसके बाद ऑस्कर की दौड़ में पांच फिल्में रह जाएंगी। हालांकि नामांकन स्तर पर 'होमबाउंड' को जाफर पनाही की 'इट वाज़ जस्ट एन एक्सीडेंट', जोआकिम ट्राएर की 'सेंटीमेंटल वैल्यू' और पार्क चान-वुक की 'नो अदर चॉइस' से कड़ी चुनौती मिल रही है, लेकिन उम्मीद है कि उसे नामांकन मिलेगा और 16 मार्च 2026 को घेवान सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का ऑस्कर भी उठाएंगे। हालांकि साल 2026 हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की सैंकड़ों फिल्में रिलीज़ होने के लिए निर्धारित हैं, जिन सबके नाम तक देना यहां संभव नहीं है, लेकिन कुछ फिल्मों का दर्शक बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें पौराणिक कथाओं पर आधारित बड़े बजट की फिल्में भी हैं और एक्शन व थ्रिलर सीक्वल के अतिरिक्त हॉरर कॉमेडी, ड्रामा, प्रेम कहानियां आदि भी हैं। जो धारावाहिक टीवी पर अत्याधिक चर्चित हो जाते हैं उन पर फिल्म बनाने का सिलसिला पुराना है। ऐसी फिल्मों को अतीत में मिश्रित सफलता मिली है, लेकिन निर्माताओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। इसलिए जनवरी 2026 में टीवी के सफल कॉमेडी धारावाहिक 'भाभी जी घर पर हैं' के सितारों को लेकर इस नाम से बनाई गई फिल्म रिलीज़ होगी। जिन बड़े बजट की फिल्मों की अधिक प्रतीक्षा है, उनमें नितेश तिवारी के निर्देशन में 'रामायण पार्ट 1' है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। अनुमान यह है कि यह फिल्म सांस्कृतिक फेनोमेनन होगी, अपने विशाल बजट व विश्व-स्तरीय वीएफएक्स की वजह से।

तिथि विशेष

# सावित्रीबाई फुले

सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाचार्या और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका थीं। महात्मा ज्योतिबा को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जीया। जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछात मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवयित्री भी थीं। उन्हें 'मराठी की आदिकवयित्री' के रूप में भी जाना जाता था। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी, 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में ज्योतिबा फुले से हुआ था। 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की नौ छात्राओं के साथ उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले पांच नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन् 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ीं, बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया, वह भी पुणे जैसे शहर में। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर, 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की।

खेल-खिलाड़ी

# शेफाली के फॉर्म ने प्रतीका से मुकाबला बनाया दिलचस्प

**सारिम अन्ना**

नवंबर 2025 में भारत की शानदार ओडीआई विश्व कप (महिला) विजय का सबसे उदास पल सलामी बैटर प्रतीका रावल को पदक न मिलना रहा। वह बांग्लादेश के विरुद्ध लीग मैच में फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गईं थीं। उनकी जगह शेफाली वर्मा को अवसर दिया गया और इस 21-वर्षीय खिलाड़ी ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोनों बल्ले व गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ़ द मैच का खिताब हासिल किया। विश्व कप के बाद जो श्रीलंका के विरुद्ध टी-20 श्रृंखला हुई, उसमें भी शेफाली ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा, जिससे मालूम हुआ कि जब वह अपनी लय में होती हैं, तो कितनी खतरनाक हो जाती हैं। उनके वर्तमान फॉर्म को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह हर फॉर्मेट की प्लेयिंग 11 का अटूट हिस्सा होना चाहिए।

इमेज

लेकिन सवाल यह है कि प्रतीका टीम से बाहर क्यों बैठें, जबकि अब वह अपनी चोट से उबर गईं हैं और जनता के दबाव में उन्हें अपना विश्व कप पदक भी मिल गया है। ध्यान रहे कि भारत को विश्व कप के फाइनल तक पहुंचाने में प्रतीका के बल्ले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। टीम प्रबंधन भी टॉप आर्डर में उनकी इंटेलिजेंस व स्थिरता का सम्मान करता है, यह अलग बात है कि उनके पास शेफाली (जब वह लय में हों) जैसी फायर-पॉवर नहीं है। हां, शेफाली की बल्लेबाज़ी में प्रतीका जैसी निरंतरता का अभाव है, जिसकी वजह से उन्हें 2024 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ओडीआई श्रृंखला में नहीं खिलाया गया था। शेफाली के साथ तकनीकी व फिटनेस समस्याएं भी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख यह थी कि वह एक ही गलती को बार बार दोहरा रही थीं। चूंकि शेफाली, जो सबसे कम आयु (15 वर्ष) में टी-20 में डेब्यू करने वाली क्रिकेटर बनीं, का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी तकनीक में सुधार लाने की न कोशिश की और न आवश्यकता महसूस की। नतीजतन उनके नंबर गिरते रहे- 31 ओडीआई में उन्होंने 5 अर्द्धशतक, 24.70 औसत, 86.46 स्ट्राइक रेट व 87 रन सर्वश्रेष्ठ के साथ कुल 741 रन बनाये हैं और 93 टी-20 में उनके 27.65 की औसत से 2,378 रन हैं। जबकि 25-वर्षीय प्रतीका के 24 ओडीआई में 50.45 औसत, 82.83 स्ट्राइक रेट, 7 अर्द्धशतक व 2 शतक, 154 रन सर्वश्रेष्ठ के साथ 1,110 रन हैं। इस

पृष्ठभूमि में एक सलामी बैटर के रूप में किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए- शेफाली को या प्रतीका को? ज्ञात रहे कि दूसरी सलामी बैटर के रूप में स्मृति मंधाना की जगह पक्की है क्योंकि उनका कोई विकल्प ही नहीं है और भारत की महिला टीम इस समय इतनी मज़बूत है कि मध्य क्रम में भी कोई जगह खाली नहीं है हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, हरलीन देओल आदि की उपस्थिति में। ऐसे में जहां टीम प्रबंधन के पास शेफाली व प्रतीका के रूप में चयन की अच्छी सिरदर्दी रहेगी वहीं इन दोनों बैटर्स को अपने खेल में निरंतर सुधार लाते रहना होगा। यह स्वस्थ्य प्रतिद्वंदिता टीम के लिए अच्छी है। प्रतीका को अपनी वापसी पर पहले से बेहतर प्रदर्शन करना होगा और शेफाली को लापरवाही छोड़कर अपनी तकनीक व फिटनेस पर निरंतर काम करते रहना होगा। प्रतीका ओडीआई (महिला) इतिहास में सबसे तेज़ गति से 500 रन बनाने वाली बैटर हैं, जोकि उन्होंने अपने करियर की पहली आठ पारियों में ही हासिल कर लिया था। अगर इस लक्ष्य के संदर्भ में पुरुषों को भी शामिल किया जाए तो प्रतीका केवल दक्षिण अफ्रीका के जानेमन मलान से ही पीछे हैं। इससे यह अंदाज़ा लगता है कि प्रतीका हमेशा से ही जल्दी में रही हैं। जब वह कक्षा 3 की छात्रा थीं तो उन्होंने अपने पिता प्रदीप रावल (बीसीसीआई से मान्यता अंपायर) से मालूम किया था कि क्या वह क्रिकेट में अपना करियर बना सकती हैं, जिसे वे दोनों ही प्यार करते हैं? पिता ने जवाब दिया था, "जब तक तुम्हें क्रिकेट में मज़ा आए तब तक इसे खेलो।" हरी झंडी मिलते ही प्रतीका असामान्य पथ पर चल निकलीं। वह सीधे क्रिकेट में नहीं आईं। उन्होंने पहले दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज से मनोविज्ञान में डिग्री हासिल की, जिसका, उनके अनुसार, वह खुद पर ही पालन करती हैं। मनोविज्ञान के बल पर वह अपने मन को समझती हैं और बल्लेबाज़ी औसत में इज़ाफा करती हैं। मनोविज्ञान से क्रिकेट में मदद मिलती है, इसे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक ब्रेरली साबित कर चुके हैं। प्रतीका को वास्तव में मनोविज्ञान से प्यार है। वह बताती हैं, "मैंने इस विषय को यह सोचकर नहीं लिया था कि इससे मेरे खेल में सुधार आएगा। मेरी दिलचस्पी तो यह जानने में थी कि हम अपने दिमागों को प्रोसेस कैसे करते हैं। लेकिन इससे मुझे अपने खेल में ज़बरदस्त लाभ मिला है।" मसलन, अब वह पहचान सकती हैं कि कब उनका दिमाग उनके विरुद्ध काम कर रहा है।

वायरल

## पालतू सांप को हाथों से खिला रहा था खाना, काटना पड़ा शख्स का अंगूठा

धरती पर कुछ जीव-जंतु ऐसे हैं, जिन्हें चाहकर भी पालतू नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि शेर, बाघ, मगरमच्छ और सांप, क्योंकि इन्हें पालतू बनाने का मतलब होता है जानबूझकर अपनी जान को खतरे में डालना। हालांकि फिर भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो खतरे की परवाह नहीं करते और ऐसे खतरनाक जीवों का पालने का रिस्क ले लेते हैं। ऐसा ही एक मामला इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल, चीन के बीजिंग में एक शख्स ने सांप को पालतू बनाया हुआ था और उसी सांप ने उसके साथ जो किया, वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स ने बीमार होने पर अपने पालतू सांप को अपने हाथों से खाना खिलाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सांप ने उसे काट लिया और फिर उसका अंगूठा ही काटना पड़ा। हुआंग नाम के उस शख्स ने लंबी नाक वाले सांप को अपना पालतू बनाया हुआ था क्योंकि उसे बचपन से ही सांपों में रुचि थी, पर उसे क्या पता था कि वहीं सांप उसके लिए मुसीबत बन जाएगा।

## पंचांग

**3 जनवरी 2026**

- विक्रम संवत् - 2082
- शक संवत् - 1947
- रवि - उत्तरायण
- ऋतु - शिशिर
- मास - पौष
- पक्ष - शुक्ल
- तिथि - पूर्णिमा 15.34 तक
- वार - शनिवार
- नक्षत्र - आर्द्रा 17.29 तक
- योग - ब्रह्म 09.06 तक
- करण - बालव 26.00 तक
- सूर्योदय - 07.14 प्रातः (मुंबई)
- सूर्यास्त - 06.12 शाम (मुंबई)
- सूर्योदय - 07.26 प्रातः (भीनमाल)
- सूर्यास्त - 06.03 शाम (भीनमाल)
- चंद्र राशि - मिथुन
- अभिजीत - 12.20 से 13.04
- राहु काल - 09.57 से 11.20
- दिशा शूल - पूर्व
- व्रत त्यौहार - पौषी पूर्णिमा, शाकंभरी पूर्णिमा, माघ स्नानारंभ, अंबाजी प्राकट्योत्सव, पुष्पाभिषेक यात्रा,

• शास्त्री प्रवीण त्रिवेदी, भीनमाल

## X का एक्सरे

मेरी कामना है कि आने वाले समय में आपको अपने हर प्रयास में सफलता मिले। दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति से नए साल में आपके संकल्प की सिद्धि हो। कामना करते हैं कि यह वर्ष हर किसी के लिए नई आशाएं, नए संकल्प और एक नया आत्मविश्वास लेकर आए।

**नरेंद्र मोदी**

अगर कोई देश जानबूझकर लगातार आतंकवाद फैलाता है तो हमारे पास भी आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार मौजूद है। लेकिन ये हम पर है कि हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोई हमें ये नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं।

**डा. एस. जयशंकर**

साल के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें मध्य प्रदेश सरकार और पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गईं। सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले इंदौर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया, शर्मनाक है।

**उमा भारती**

जब भी विदेश में भारत विरोधी कहानी फैलाई जाती है, बैकग्राउंड में एक नाम बार-बार आता है-राहुल गांधी। जो लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं, उसकी चुनी हुई सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, वे अनिवार्य रूप से उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं।

**प्रदीप भंडारी**

**नारायण पब्लिकेशन प्रा. लि.** के लिए मुद्रक-प्रकाशक-हेमल पुरोहित द्वारा एआईएस प्रिंटिंग सोल्यूशंस, प्लॉट नं. ए-544, टीटीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, ठाणे-बेलापुर रोड, महापे, नवी मुंबई 400709 से मुद्रित एवं प्रिमाइसेस नं. 1303/चेंबर्स, 13वां माला, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन के पास, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 099 से प्रकाशित, पोस्टल रजि. MCN/325/2023-24, (चकाला MIDC पी.ओ.) रजि. नं. MAHHIN/2004/13755, संपादक-हेमल पुरोहित, स्थानीय संपादक-नीरज दवे, फोन : 022-46024646, ईमेल : jagruktimes@gmail.com

## कहानी

### शेर, ऊंट, सियार और कौवा

किसी वन में मदोत्कट नाम का सिंह निवास करता था। बाघ, कौआ और सियार, ये तीन उसके नौकर थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे उंट को देखा जो अपने गिरोह से भटककर उनकी ओर आ गया था। उसको देखकर सिंह कहने लगा, 'अरे वाह! यह तो विचित्र जीव है। जाकर पता तो लगाओ कि यह वन्य प्राणी है अथवा कि ग्राम्य प्राणी' यह सुनकर कौआ बोला, 'स्वामी! यह ऊंट नाम का जीव ग्राम्य-प्राणी है और आपका भोजन है। आप इसको मारकर खा जाइए।' सिंह बोला, ' मैं अपने यहां आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वस्त और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। अतः उसको अभयदान देकर यहां मेरे पास ले आओ जिससे मैं उसके यहां आने का कारण पूछ सकूं। ' सिंह की आज्ञा पाकर उसके अनुचर ऊंट के पास गए और उसको आदरपूर्वक सिंह के पास ले लाए। ऊंट ने सिंह को प्रणाम किया और बैठ गया। सिंह ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह साथियों से बिछुड़कर भटक गया है। सिंह के कहने पर उस दिन से वह कथनक नाम का ऊंट उनके साथ ही रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद मदोत्कट सिंह का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के मूसल के समान दांतों के प्रहार से सिंह अधमरा तो हो गया किन्तु किसी प्रकार जीवित रहा, पर वह चलने-फिरने में अशक्त हो गया था। उसके अशक्त हो जाने से कौवे आदि उसके नौकर भूखे रहने लगे। क्योंकि सिंह जब शिकार करता था तो उसके नौकरों को उसमें से भोजन मिला करता था। अब सिंह शिकार करने में असमर्थ था। उनकी दुर्दशा देखकर सिंह बोला, 'किसी ऐसे जीव की खोज करो कि जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं।' सिंह की आज्ञा पाकर वे चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौए और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह की। श्रृगाल बोला, 'मित्र कौवे! इधर-उधर भटकने से क्या लाभ? क्यों न इस कथनक को मारकर उसका ही भोजन किया जाए? ' सियार सिंह के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, 'स्वामी! हम सबने मिलकर सारा वन छान मारा है, किन्तु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला कि जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक भी पग चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो आज कथनक के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए।' पर सिंह ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहां पनाह दी है इसलिए वह उसे मार नहीं सकता। पर सियार ने सिंह को किसी तरह मना ही लिया। राजा की आज्ञा पाते ही श्रृगाल ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया लाया। उसके साथ ऊंट भी आया। उन्हें देखकर सिंह ने पूछा, 'तुम लोगों को कुछ मिला? ' कौवा, सियार, बाघ सहित दूसरे जानवरों ने बता दिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला। पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी-बारी से सिंह के आगे आए और विनती की कि वह उन्हें मारकर खा लें। पर सियार हर किसी में कुछ न कुछ खामी बता देता ताकि सिंह उन्हें न मार सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे-साधे कथनक ऊंट ने जब यह देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं तो वह भी पीछे नहीं रहा। उसने सिंह को प्रणाम करके कहा, 'स्वामी! ये सभी आपके लिए अभक्ष्य हैं। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून हैं, किसी की देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए जिससे कि मुझे दोनों लोकों की प्राप्ति हो सके। ' कथनक का इतना कहना था कि व्याघ्र और सियार उस पर झपट पड़े और देखते-ही-देखते उसके पेट को चीरकर रख दिया।

# आवश्यक है अरावली को बचाना

*अरावली करीब दो अरब वर्ष पुरानी भू-वैज्ञानिक प्रणाली है, जो भूजल भरण को नियंत्रित करती है, मरुस्थलीकरण को रोकती है, जलवायु को संतुलित करती है और उत्तर-पश्चिम भारत में लाखों लोगों की आजीविका का सहारा है। इसे केवल ऊंचाई आधारित नियम से परिभाषित करना न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत था, बल्कि पारिस्थितिकीय रूप से भी खतरनाक था। जिस समिति की रिपोर्ट पर उक्त आदेश आधारित था, वही समिति स्वीकार करती है कि अरावली परिदृश्य में ढलान और ऊंचाई व्यापक रूप से बदलती रहती है। समिति के अनुसार 34 में से 23 अरावली जिलों में औसत ढलान छह डिग्री से कम है, जबकि 12 जिलों में यह तीन डिग्री से भी कम है। रिपोर्ट यह सही निष्कर्ष निकालती थी कि केवल ढाल और ऊंचाई को मानदंड बनाना विसंगति बढ़ाएगा। इसके बावजूद अंतिम सिफारिश में 100 मीटर के प्रविधान को मान्यता दे दी गई थी। यह वैज्ञानिक तर्क और प्रशासनिक विवेक के मूल सिद्धांतों के विपरीत था। भारतीय भू-आकृतिक परिस्थितियों में 100 मीटर ऊंचाई का नियम मनमाना था। अरावली जिलों में औसत ऊंचाई कुछ क्षेत्रों में 100-200 मीटर से लेकर केवल एक जिले में 600 मीटर से अधिक है। इतनी विविधता में एकसमान सीमा लागू करना, भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और सर्वे आफ इंडिया के सिद्धांतों के विपरीत है। इसी प्रकार 500 मीटर 'रेंज कनेक्टिविटी नियम' भी*

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा के संदर्भ में दिए गए अपने ही फैसले पर रोक लगा दी। उस फैसले में सौ मीटर ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने को मंजूरी दे दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप कई छोटी, लेकिन पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण भू-आकृतियां संरक्षण की कानूनी सुरक्षा से बाहर आ सकती थीं। इस पर पर्यावरणीय विरोध और कानूनी प्रश्न उठे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि उसे लागू करने से पहले उसकी वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और कानूनी समीक्षा आवश्यक है।

अदालत ने विशेषज्ञ समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है, ताकि परिभाषा, खनन नियम, संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकीय निरंतरता से जुड़े सभी मुद्दों का विस्तृत अध्ययन हो सके। नवीनतम निर्णय इसका संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी मानता है कि पहले के निर्णय के वैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय परिणाम संदेहास्पद हैं। 20 नवंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की एकसमान परिभाषा को स्वीकृति देने वाला आदेश एक लंबे समय से प्रशासनिक स्पष्टता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। यह आदेश भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला की कानूनी और पारिस्थितिकीय सुरक्षा को कमजोर कर सकता था, खासकर तब, जब वह पहले से ही अभूतपूर्व दबाव में है।

अरावली करीब दो अरब वर्ष पुरानी भू-वैज्ञानिक प्रणाली है, जो भूजल भरण को नियंत्रित करती है, मरुस्थलीकरण को रोकती है, जलवायु को संतुलित करती है और उत्तर-पश्चिम भारत में लाखों लोगों की आजीविका का सहारा है। इसे केवल ऊंचाई आधारित नियम से परिभाषित करना न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत था, बल्कि पारिस्थितिकीय रूप से भी खतरनाक था। जिस समिति की रिपोर्ट पर उक्त आदेश आधारित था, वही समिति स्वीकार करती है कि अरावली परिदृश्य में ढलान और ऊंचाई व्यापक रूप से बदलती रहती है। समिति के अनुसार 34 में से 23 अरावली जिलों में औसत ढलान छह डिग्री से कम है, जबकि 12 जिलों में यह तीन डिग्री से भी कम है। रिपोर्ट यह सही निष्कर्ष निकालती थी कि केवल ढाल और ऊंचाई को मानदंड बनाना विसंगति बढ़ाएगा।

इसके बावजूद अंतिम सिफारिश में 100 मीटर के प्रविधान को मान्यता दे दी गई थी। यह वैज्ञानिक तर्क और प्रशासनिक विवेक के मूल सिद्धांतों के विपरीत था। भारतीय भू-आकृतिक परिस्थितियों में 100 मीटर ऊंचाई का नियम मनमाना था। अरावली जिलों में औसत ऊंचाई कुछ क्षेत्रों में 100-200 मीटर से लेकर केवल एक जिले में 600 मीटर से अधिक है। इतनी विविधता में एकसमान सीमा लागू करना, भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और सर्वे आफ इंडिया के सिद्धांतों के विपरीत है। इसी प्रकार 500 मीटर 'रेंज कनेक्टिविटी नियम' भी चिंताजनक था। इसके अनुसार दो या अधिक पहाड़ियां यदि 500 मीटर के भीतर हों तो उन्हें एक अरावली रेंज माना जाएगा। इसका कोई भू-वैज्ञानिक आधार नहीं और न ही भारतीय पर्वत प्रणाली मानचित्रण में कोई उदाहरण। सबसे अधिक चिंता का विषय यह था कि समिति ने अरावली क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों के खनन की अनुमति का प्रविधान सुझाया था। यह सबसे नाजुक कोर क्षेत्रों में खनन के लिए कानूनी दरवाजा खोल देता। अरावली कम नाजुक नहीं, बल्कि अधिक नाजुक है। अरावली राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में फैली है। इसकी चट्टानें पुरानी और भंगुर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बार-बार मरुस्थलीकरण के विरुद्ध एक पारिस्थितिकीय ढाल के रूप में मान्यता दी है। कोई भी परिभाषा जो इस सुरक्षा सीमा को कम करे, वह विज्ञान और न्यायिक परंपरा दोनों के विरुद्ध है। अरावली एक प्राचीन भू-वैज्ञानिक, जल-चक्र और पारिस्थितिकीय प्रणाली है, जो उत्तर-पश्चिम भारत में जलस्रोत, मरुस्थलीकरण नियंत्रण और स्थानीय जीवन को बनाए रखती है। अरावली संकट का समाधान अल्पकालिक प्रशासनिक कदमों से नहीं होगा। इसके लिए स्थायी, विज्ञान-आधारित समाधान आवश्यक हैं। पर्यावरणविद् एक राष्ट्रीय अरावली विकास प्राधिकरण की स्थापना की वकालत करते रहे हैं। पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे रिज टाप, वनाच्छादित पहाड़ियां और वन्यजीव कारिडोर में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, किसी भी प्रकार की सार्वभौमिक छूट के बिना, क्योंकि एक बार यदि अरावली का खनन हो गया तो उसे कभी पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। अरावली को स्थायी कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए, चाहे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में मिले या फिर भारत की प्राचीन पर्वत विरासत प्रणाली के रूप में एक नई कानूनी श्रेणी बनाकर। अरावली केवल ऊंचाई से परिभाषित नहीं हो सकती। यह एक भू-वैज्ञानिक, जलवैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय प्रणाली है, जो उत्तर-पश्चिम भारत को संभालती है।

## सम्पादकीय

### सबसे स्वच्छ शहर में जहरीला पानी, इंदौर ने फिर याद दिलाया

वह अपने आप में विचित्र और अफसोसनाक है कि जिस शहर को पिछले कई वर्षों से देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिल रहा हो, वहां दूषित पेयजल के सेवन से लोगों के मरने की खबरें आती हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई और करीब दो सौ लोगों को अस्पताल भर्ती होना पड़ा। खबरों के मुताबिक, भागीरथपुरा में नर्मदा नदी की पाइपलाइन में गंदा पानी मिल गया, जिससे पानी दूषित हो गया। लोगों ने इस पानी का सेवन शायद इसलिए भी कर लिया कि साफ और गंदे पानी में फर्क करना मुश्किल हो गया था।

सवाल है कि अगर आम लोग पेयजल के लिए पानी की आपूर्ति पर निर्भर हों, तो उनके पास गंदा और दूषित पानी पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी है। लोगों की मौत के मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने गलती मानते हुए आनन-फानन में कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन यह साफ है कि संबंधित महकमों की नींद तभी खुलती है, जब कोई बड़ा नुकसान हो चुका होता है।

यों, देश भर में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, लेकिन ऐसा लगता है कि आम लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और इस क्रम में उनकी सेहत के साथ क्या होता है, इसकी परवाह शायद किसी को नहीं है। खबरों के मुताबिक, दूषित पेयजल की मार से प्रभावित इलाके में स्थानीय लोगों ने पिछले डेढ़ वर्ष से इससे होने वाली परेशानी और शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने की बात कही। मगर सरकार के कामकाज की शैली का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पेयजल में दूषित पानी मिलने के बाद जब लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, तब भी अगले कई दिन तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

इसके अलावा, पीने के पानी के पाइप लाइन से अलग गंदे पानी के निकासी की लाइन को सुरक्षित मानकों तक दूर रखने की व्यवस्था नहीं की गई, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या यह सिर्फ अक्षम अधिकारियों की अदूरदर्शिता का मामला है या फिर जानबूझ कर की गई अनदेखी का? इस तरह की लापरवाही का इलाज सिर्फ कुछ औपचारिक कदम नहीं हैं, बल्कि इसके लिए सभी स्तर पर सजगता और जिम्मेदारी की जरूरत है।

विडंबना यह है कि सरकार का मकसद प्रचार के लिए किसी शहर की स्वच्छता के तमगे हासिल करना रह गया लगता है। सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में अगर कुछ लोगों को जहरीला पानी पीने पर मजबूर होना पड़ा, तो इस विरोधाभासी हकीकत की पड़ताल करने की जरूरत है कि ऐसे तमगे जारी किए जाने के पैमाने क्या हैं? पीने का पानी सबसे बुनियादी जरूरत है, जिसके बिना ज्यादा वक्त तक नहीं रहा जा सकता।

सरकार देश भर में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना के तहत सबको स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का दावा करती है। मगर इस दावे की हकीकत अक्सर सामने आती रहती है

# आर्थिक मोर्चे पर अच्छी संभावनाएं

*एक अप्रैल से लागू किया जाने वाला नया इनकम टैक्स कानून महज कुछ धाराओं के बदलाव ही नहीं, बल्कि पूरी टैक्स व्यवस्था के कायापलट के साथ आर्थिकी को आगे बढ़ाया है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे मांग बढ़ेगी और निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का जो सिलसिला शुरू किया, उसके इस साल भी जारी रहने के ही आसार हैं। इससे भी मांग और खपत में तेजी आएगी। वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म ग्लोबल वेल्थ मैनेजर की नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 खपत के स्तर में सुधार के मामले में भारत दुनिया का सबसे आकर्षक बाजार होगा। बढ़ते उद्योग-कारोबार, सर्विस सेक्टर, बुनियादी ढांचा, शेयर बाजार और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति के कारण देश में जीएसटी और इनकम टैक्स संग्रहण में तेज वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से नवंबर 2025 के*

नए साल 2026 की आर्थिक संभावनाओं पर प्रकाशित विभिन्न वैश्विक आर्थिक संगठनों की रिपोर्टों के अनुसार नव वर्ष भारत के लिए बेहतर आर्थिक संभावनाओं वाला होगा। केयर एज रेटिंग्स के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। ऐक्सिस बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आगामी वर्ष में भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर पहुंचती दिख सकती है। जहां भारत वर्ष 2025 में 4.18 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिकी बन गया है। नए साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की डगर पर आगे बढ़ेगा। वैश्विक निवेश फर्म इन्वेसको का कहना है कि इस साल भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति कायम रखेगा। हालांकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चिताओं के बीच भारत को आर्थिक और वित्तीय सुधारों को गति भी देनी होगी।

नए वर्ष में घरेलू बाजार की मजबूती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधार बनी रहेगी। इस दौरान भारत का घरेलू बाजार 10 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ेगा और इस तेज गति से वर्ष 2030 तक भारत का घरेलू बाजार लगभग 237 अरब डालर की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। 2026 में महंगाई घटने, टैक्स सुधार और ब्याज दर में कमी से घरेलू बाजार को रफ्तार से बढ़ने के आधार मिलेंगे। रिजर्व बैंक का कहना है कि 2026 में महंगाई में नरमी बनी रहेगी। गत वर्ष जीएसटी की दरों में सुधारों की जो पहल शुरू हुई है, उसके फल इस साल और व्यापक रूप से मिलने शुरू होंगे। नए वर्ष में मनरेगा की जगह लागू वीबी-जी राम जी से भी ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एक अप्रैल से लागू किया जाने वाला नया इनकम टैक्स कानून महज कुछ धाराओं के बदलाव ही नहीं, बल्कि पूरी टैक्स व्यवस्था के कायापलट के साथ आर्थिकी को आगे बढ़ाया है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे मांग बढ़ेगी और निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का जो सिलसिला शुरू किया, उसके इस साल भी जारी रहने के ही आसार हैं। इससे भी मांग और खपत में तेजी आएगी। वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म ग्लोबल वेल्थ मैनेजर की नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 खपत के स्तर में सुधार के मामले में भारत दुनिया का सबसे आकर्षक बाजार होगा। बढ़ते उद्योग-कारोबार, सर्विस सेक्टर, बुनियादी ढांचा, शेयर बाजार और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति के कारण देश में जीएसटी और इनकम टैक्स संग्रहण में तेज वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच जीएसटी संग्रह गत वर्ष की इसी अवधि से बढ़कर 14.75 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी प्रकार मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में बीते हुए वर्ष से अधिक आयकर रिटर्न और अधिक आयकर प्राप्ति का परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिसंबर तक 8.44 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं।

भारत द्वारा ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते इस साल अमल में आएंगे। साथ ही अमेरिका, यूरोपीय संघ, पेरू, चिली, आसियान, मेक्सिको, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल, गल्फ कंट्रीज काउंसिल सहित अन्य प्रमुख देशों के साथ भी एफटीए आकार लेते हुए दिखाई देंगे।

# इंदौर में दूषित पेयजल से 14 लोगों की मौत

देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा रखने वाले इंदौर में दूषित पेयजल से 14 लोगों की मौत हो जाना बहुत ही आघातकारी और शर्मनाक घटना है। यह स्वच्छता के मानकों पर सवाल खड़े करने के साथ ही नगर निगम के नाकारापन को बयान करने वाली एक ऐसी घटना है, जो देश की छवि भी मलिन कर रही है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल की आपूर्ति इसलिए जानलेवा साबित हुई, क्योंकि सीवर की गंदगी पीने की पाइपलाइन में चली गई और फिर वह घरों तक पहुंच गई। यदि दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत पर तत्काल ध्यान दिया गया होता तो इस भयावह त्रासदी को रोका जा सकता था, लेकिन जैसा कि अपने देश में होता है, गंदी जलापूर्ति की शिकायतों पर तब तक ध्यान नहीं दिया गया, जब तक लोग मरने नहीं लगे। 14 लोगों की मौत और एक हजार से अधिक लोगों के बीमार होने और इनमें से सौ से ज्यादा लोगों के अस्पताल में भर्ती होने से यह सहज ही समझा जा सकता है कि कितने अधिक जहरीले जल की आपूर्ति हो रही थी। यह आपूर्ति इंदौर के उस इलाके में हो रही थी, जो नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का निर्वाचन क्षेत्र है और पेयजल की आपूर्ति करने वाला विभाग उनके ही मंत्रालय के तहत आता है। जब मंत्री महोदय से इस हत्यारी लापरवाही पर सवाल किए गए तो उन्होंने संवेदनहीनता का परिचय देते हुए ऐसे सवालों को फोकट का बता दिया। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि चौतरफा आलोचना से घिरने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने खेद जता दिया, क्योंकि उनकी वह संवेदनहीनता तो प्रकट हो ही गई, जो ऐसी घटनाओं का कारण बनती है। यह भी संतोषजनक नहीं कि इंदौर नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि एक तो निलंबन कोई सजा नहीं और दूसरे, इसमें संदेह है कि ऐसे उपाय किए जा सकेंगे, जिससे फिर कभी दूषित जलापूर्ति न हो सके। यह समझा जाए तो अच्छा कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति केवल इंदौर नगर निगम को ही सुनिश्चित नहीं करनी, क्योंकि देश में आम तौर पर पेयजल की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं। इसका प्रमाण यह है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ आदि का सहारा लेना पड़ता है या फिर पीने का पानी खरीदना पड़ता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक ओर जहां पेयजल की गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी होती है, वहीं दूसरी ओर और टूटी-फूटी पाइपलाइनों की सुधि मुश्किल से ही ली जाती है। इसका परिणाम यह है महानगरों तक में गुणवत्ताहीन पेयजल की आपूर्ति होती है। इसके चलते प्रति वर्ष टाइफाइड, हेपेटाइटिस और हैजा जैसी जलजनित बीमारियों के लाखों मामले सामने आते हैं। यह तथ्य नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक का है कि भारत में सुरक्षित पेयजल के अभाव में हर साल लगभग दो लाख लोग जान गंवाते हैं।

# अस्तित्व संकट के बीच पारिवारिक एकता का राग

उमेश चतुर्वेदी

**चाहे ठाकरे कुनबा हो या फिर पवार परिवार, अगर दोनों एक हो रहे हैं तो उसकी सिर्फ अस्तित्व की रक्षा भी नहीं है, बीजेपी रूपी चुनौती से पार पाना भी है और मुंबई महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका पर कब्जे की चाहत भी है। मुंबई महानगर पालिका का सालाना बजट सत्तर हजार करोड़ रूपए का है।**

राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहां कोई न तो स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। राजनीति में ऐसे कम ही उदाहरण मिलेंगे,जहां दोस्ती के मूल में दिल का रिश्ता होता है। गौर से देखें तो संभावनाओं, चुनौतियों और अवसरों की बुनियाद पर पर दोस्ती या दुश्मनी के रिश्ते आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के दो राजनीतिक परिवारों के मिलन को भी इसी अंदाज और संदर्भ में देखा जाना चाहिए। राज्य का पवार परिवार हो या फिर ठाकरे कुनबा, अगर एक होता नजर आ रहा है या एक हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों परिवारों के प्रमुख अलंबरदारों के दिल मिल चुके हैं। बल्कि राजनीतिक संभावनाओं और अवसरों ने उन्हें एक होने को प्रेरित किया है।

चाहे ठाकरे परिवार हो या फिर पवार कुनबा, दोनों में कुछ समानताएं हैं। शरद पवार हों या बाल ठाकरे, एक दौर में दोनों की महाराष्ट्र की राजनीति में तूती बोलती थी। पिछली सदी के आखिरी दशक में तो राजनीतिक हलके का एक बड़ा हिस्सा शरद पवार को देश का भावी प्रधानमंत्री तक मानने लगा था। इसी तरह महाराष्ट्र के टाइगर के रूप में बाल ठाकरे की ख्याति रही। दोनों ही राजनीतिक खानदानों के मुखिया का स्वाभाविक उत्तराधिकारी दोनों के भतीजे ही माने जाते थे। एक दौर तक शरद के उत्तराधिकारी के तौर पर देश और प्रदेश अजित पवार को देखता था। इसी तरह शिवसैनिक भी बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे को अगली पीढ़ी का ठाकरे सीनियर मान चुका था। लेकिन जब उत्तराधिकार सौंपने की बारी आई तो पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले पर भरोसा जताया और बाल ठाकरे ने अपने छोटे बेटे राज ठाकरे को। ऐसे हालात में अजित और राज ठाकरे को अपना भविष्य चुनौतीपूर्ण लगा, राजनीतिक संभावनाएं कम होती दिखीं तो दोनों ने अपनी राह अलग कर ली। उन्नीस साल पहले राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली तो अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के मूल धड़े पर ही कब्जा कर लिया। पार्टी के असल संस्थापक शरद पवार पुछल्ला पार्टी लेकर एक तरह से किनारे का दल संभालने लगे।

पवार परिवार और ठाकरे कुनबे में बिखराव की कहानी भी अलग-अलग रही। जब तक बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को बीजेपी के साथ खड़ा रखे, तब तक तो उनके नेतृत्व को चुनौती नहीं मिली। दल का राज्य में ठीकठाक समर्थन भी रहा। हालांकि महत्वाकांक्षाओं के साथ अलग हुए राज ठाकरे को राजनीतिक सफलताएं न के बराबर मिलीं। लेकिन जब से उद्धव ने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस और पवार की एनसीपी का साथ पकड़ा, राजनीतिक मैदान में उसका आधार घटने लगा। वहीं पवार सीनियर से अलग होने के बावजूद बीजेपी के साथ के चलते अजित का राजनीतिक रूतबा कम नहीं हुआ। अलबत्ता कभी भारत के प्रधानमंत्री मैटेरियल देखे जाते रहे वरिष्ठ पवार की सियासी साख घटती चली गई। कुनबे में बिखराव के चलते दोनों परिवारों की राजनीतिक ताकत बीजेपी के सामने बौनी होती जा रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों परिवारों के राजनीतिक अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगा है।

एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। राजनीतिक अस्तित्व पर जब बन आती है तो कम ही सियासी हस्तियां होती हैं, जो समझौते नहीं करतीं। इसे समझदारी कहें या फिर राजनीति की रवायत, ठाकरे परिवार और पवार कुनबा-दोनों ही एक होने जा रहे हैं। पारिवारिक बिखराव को समेटने की कोशिश तेज हो गई है। ठाकरे बंधु तो बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस करके एक हो चुके हैं, जबकि पवार परिवार अपने गढ़ बारामती में एक होने का संकेत दे रहा है। बारामती में हाल ही में पवार परिवार ने एक आयोजन किया, जिसमें आज के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इसे पवार कुनबे ने खूब प्रचारित किया। इस प्रचार का संदेश साफ है कि दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं।

चाहे ठाकरे कुनबा हो या फिर पवार परिवार, अगर दोनों एक हो रहे हैं तो उसकी सिर्फ अस्तित्व की रक्षा भी नहीं है, बीजेपी रूपी चुनौती से पार पाना भी है और मुंबई महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका पर कब्जे की चाहत भी है। मुंबई महानगर पालिका का सालाना बजट सत्तर हजार करोड़ रूपए का है। यह रकम उत्तर पूर्व के राज्यों के समूचे बजट से भी ज्यादा बैठती है। पिंपरी-चिंचवड़ महानगर पालिका के दायरे में एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। जाहिर है कि यहां से कर के रूप में मोटी रकम आती है। ठाकरे परिवार की एकता के पीछे एक कारण जहां बृहन्नमुंबई महानगर पालिका पर कब्जा जमाना है, वहीं पवार परिवार की एकता के पीछे पुणे महानगरपालिका और पिंपरी-चिंचवड़ महानगर पालिका पर कब्जा जमाना है। दोनों परिवारों को लगता है कि अगर वे बिखरे रहे तो उनके प्रभाव वाली महानगरपालिकाओं में उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यहां यह बताना जरूरी है कि एक दौर में बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहता था तो पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में पवार परिवार का। दोनों परिवारों के मिलन के पीछे की बड़ी वजह यही है।

भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए, अपने विस्तार के पहले चरण में वह अपने साथी दलों के सहयोग पर निर्भर रही। बाद के दौर में उसने खुद का प्रभाव बढ़ाया और अपने दम पर वह स्थापित होती चली गई। हरियाणा, उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के बाद अब इसी तरह वह महाराष्ट्र में वह अपने दम पर उभर चुकी है। जबकि कुछ साल पहले तक महाराष्ट्र में एक तरह से शिवसेना के छोटे भाई की भूमिका में रहती थी। अब चाहे शिवसेना का टूटा हुआ धड़ा हो या अजित पवार वाली एनसीपी, दोनों उसके छोटे भाई की भूमिका में हैं। जिस तरह निकाय चुनावों में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम किया है, उससे पवार परिवार की भी चिंताएं बढ़ी हैं और ठाकरे खानदान की भी। इसीलिए दोनों परिवार एक हुए हैं या होते नजर आ रहे हैं। पवार परिवार अब एक साथ पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ के चुनाव में उतरने जा रहा है तो ठाकरे परिवार मुंबई में। लेकिन यह तय है कि दोनों परिवारों के रिश्तों की मजबूती इन महापालिका चुनाव नतीजों पर निर्भर करेगी। अगर उन्हें जीत मिली तो तय है कि पारिवारिक गठबंधन आगे बढ़ेंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो दोस्ती की नई राह तलाशने की कोशिशें फिर से तेज होंगी।

## संपादकीय

### नियम-कानून की कोई परवाह नहीं

नेशनल हेराल्ड मामले में वैध एफआईआर ही मौजूद नहीं है। क्या ईडी के अधिकारियों को कानून की इतनी बुनियादी जानकारी भी नहीं है? या जब मामला विपक्षी नेताओं से संबंधित हो, तो वे नियम- कानून की कोई परवाह नहीं करते? नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को राहत मिली, मीडिया की सुर्खियों में इसी पहलू को अहमियत दी गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसका यह सिर्फ एक पक्ष है। लेकिन यह मूल बात नहीं है। कांग्रेस नेताओं को राहत इसलिए मिली, क्योंकि जज ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने संज्ञान इसलिए नहीं लिया, क्योंकि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मामले की एफआईआर ही वैध ढंग से दर्ज नहीं हुई है। हुआ यह कि एक व्यक्ति (भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी) ने निजी तौर पर एफआरआर दर्ज कराई। उसमें कांग्रेस नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाए गए।

ईडी ने उसी मामले में जारी समन के आधार पर केस अपने हाथ में लेकर में जांच शुरू कर दी। यानी उसने अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। जज विशाल गोगने ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून की संबंधित धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ईडी निजी एफआईआर के आधार पर चार्जशीट तैयार नहीं कर सकती। जज का यही वो निष्कर्ष है, जो ईडी की कार्यशैली को बेनकाब कहता है। सवाल है कि क्या ईडी के अधिकारियों को कानूनी धाराओं की इतनी बुनियादी जानकारी भी नहीं है? या जब मामला विपक्षी नेताओं से संबंधित हो, तो अपने सियासी आकाओं के इशारे पर वे नियम- कानून की कोई परवाह नहीं करते? सत्ताधारी भाजपा और उसके समर्थक नेटवर्क ने वर्षों से नेशनल हेराल्ड मामले को गांधी परिवार के कथित भ्रष्टाचार की मिसाल बता कर प्रचारित किया है। मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी लंबी पूछताछ हुई। मगर अब सामने आया है कि यह सब उस मामले में हुआ, जिसमें एफआईआर ही वैध नहीं थी। सामान्य स्थितियों में कायदे का इस रूप में उल्लंघन करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाती, ताकि भविष्य में अधिकार के ऐसे दुरुपयोग को रोका जा सके। लेकिन मौजूदा माहौल में इसकी उम्मीद करना बेमतलब है। अभी तो संभावना यही है कि ऊपरी अदालत में अपील की आड़ में सारा मामला पृष्ठभूमि में डाल दिया जाएगा।

## चिंतन-मनन

### धर्मराज युधिष्ठिर ने निभाया था भ्रातृ धर्म

गहन वन से तृषार्त पाण्डव गुजर रहे थे। पानी की तलाश में वे इधर-उधर घूम ही रहे थे कि अकस्मात उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जल पीने के पूर्व ही मृत्यु का ग्रास बन गए। कारण यह था कि एक यक्ष ने उनसे प्रश्न किए थे, किंतु उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया और बिना जवाब दिए ही पानी पीने लगे। लेकिन वे यक्ष का कोपभाजन बने और उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। इतने में युधिष्ठिर आए और पानी पीने की कोशिश करने लगे। उनसे भी यक्ष ने प्रश्न किए, जिनके युधिष्ठर ने समुचित उत्तर दे दिए। तब यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा, तुम जल पीने के अधिकारी हो। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे चारों भ्राताओं में से किसी एक को जीवन दान दूं। बोलो, मैं किसे पुनर्जीवित करूं?

प्रश्न बड़ा ही विचित्र था और साथ ही कठिन भी, क्योंकि युधिष्ठिर को चारों भाई एक समान प्रिय थे, तथापि एक क्षण भी सोचे बिना वे बोले, यक्षश्रेष्ठ आप नकुल को ही जीवन दान दें। यक्ष हंस पड़ा और बोला, धर्मराज, कौरवों से युद्ध में भीम की गदा और अर्जुन का गांडीव बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। इन दो सगे भाइयों को छोड़कर नकुल का जीवन क्यों चाहते हो। धर्मराज बोले, यक्षश्रेष्ठ हम पांचों भ्राता ही माताओं के स्नेह चिह्न हैं। माता पुंती के पुत्रों से मैं शेष हूं, किंतु माद्री मां के तो दोनों ही पुत्र मर चुके हैं। अत? यदि एक के ही जीवन का प्रश्न है, तो माद्री मां के नकुल का ही पुनर्जीवन इष्ट है। यक्ष ने सुना, तो भावविह्वल हो बोला, युधिष्ठिर तुम धर्मतत्व के ज्ञाता हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम वास्तव में धर्म के अवतार हो या नहीं। अतएव मैं चारों भाईयों को जीवन देता हूं।

# उमर खालिद के समर्थन में उतर कर जोहरान मामदानी ने बड़ा खतरनाक खेल खेला है

नीरज कुमार दुबे

न्यूयार्क के मेयर जोहरान मामदानी की ओर से भारत में तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद को भेजे गए एक पत्र ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। हम आपको बता दें कि यह पत्र उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात के दौरान दिया गया और इसमें मामदानी ने खालिद के विचारों की तारीफ करते हुए लिखा कि वे उनके बारे में सोच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उमर खालिद पर वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े गंभीर आरोपों की सुनवाई चल रही है।

इस पत्र के सामने आने के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आलोचकों का कहना है कि किसी विदेशी शहर के मेयर द्वारा भारत के एक संवेदनशील कानूनी मामले में पक्ष लेना अनुचित है। खासकर तब, जब मामला दंगों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। हम आपको याद दिला दें कि उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत आरोप हैं और वह न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। ऐसे में किसी विदेशी जनप्रतिनिधि की ओर से सहानुभूति और प्रशंसा का सार्वजनिक संकेत कई सवाल खड़े करता है।

हम आपको बता दें कि मामदानी के पत्र को सिर्फ एक व्यक्तिगत संदेश नहीं माना जा रहा है बल्कि इसे एक राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में भी इस कदम को असहज माना गया है। भारत में यह तर्क उभरा है कि यदि हर देश का स्थानीय नेता दूसरे देश के न्यायिक मामलों पर टिप्पणी करने लगे तो संप्रभुता और संस्थागत सम्मान पर आंच आएगी।

देखा जाये तो जोहरान मामदानी का यह कदम साफ तौर पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल है। सवाल सीधा है। सवाल उठता है कि न्यूयार्क के मेयर को यह अधिकार किसने दिया कि वह भारत के दंगों से जुड़े एक आरोपी की तारीफ करे और उसे नैतिक समर्थन दे। मामदानी को समझना होगा कि भारत की न्याय व्यवस्था सक्षम है, संवैधानिक है और अपने फैसले खुद लेने में समर्थ है।

उमर खालिद कोई साधारण सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि उस पर दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। ऐसे व्यक्ति को वैश्विक मंच से नैतिक समर्थन देना न केवल भारत के लिए गलत है, बल्कि यह एक खतरनाक परंपरा को जन्म देता है। इससे यह संदेश जाता है कि दंगों और हिंसा से जुड़े आरोपों को वैचारिक खोल पहनाकर महिमामंडित किया जा सकता है। यह संदेश उन तत्वों के लिए संजीवनी का काम करता है जो अराजकता और टकराव की राजनीति में विश्वास रखते हैं।

मामदानी को यह समझना चाहिए था कि भारत का आंतरिक कानून और व्यवस्था किसी विदेशी राजनेता की राय का मोहताज नहीं। यदि उन्हें मानवाधिकार की इतनी ही चिंता है, तो उन्हें अपने देश में चल रही हिंसा, नस्लीय तनाव और अपराध की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। भारत में न्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पत्रों के जरिये।

इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी गलत असर डाल सकता है। जब वहां के नेता दंगों के आरोपी की तारीफ करते हैं, तो यह वहां मौजूद कट्टर और हिंसक विचारधारा के लोगों का हौसला बढ़ाता है। वे इसे यह कहकर पेश कर सकते हैं कि उनके विचारों को वैश्विक मान्यता मिल रही है। यह लोकतंत्र के लिए घातक संकेत है। लोकतंत्र का अर्थ कानून का शासन है, न कि आरोपियों का महिमामंडन। यह भी याद रखना जरूरी है कि भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतंत्र की बुनियाद एक दूसरे की संस्थाओं के सम्मान पर टिकी होती है। जब कोई विदेशी नेता भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है या एक पक्ष को नैतिक ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश करता है, तो यह आपसी विश्वास को चोट पहुंचाता है। यह न तो कूटनीतिक मयार्दा के अनुरूप है और न ही जिम्मेदार राजनीति का उदाहरण।

मामदानी का पत्र उन तमाम भारतीय नागरिकों की भावनाओं का भी अपमान है जिन्होंने दिल्ली दंगों में अपने परिजन खोए, जिनकी दुकाने जलीं और जिनका जीवन तबाह हुआ। उनके लिए दंगे कोई वैचारिक बहस नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। ऐसे में दंगों के मास्टरमाइंड की तारीफ करना घावों पर नमक छिड़कने जैसा है।

भारत को किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं कि वह लोकतांत्रिक है या न्यायप्रिय। यहां की अदालतें स्वतंत्र हैं और फैसले सबूतों के आधार पर होते हैं। यदि उमर खालिद निर्दोष है, तो वह अदालत से बरी होगा। यदि दोषी है, तो सजा पाएगा। इसमें किसी विदेशी मेयर के भावनात्मक पत्र की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।

बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जोहरान मामदानी का यह कदम गैर जिम्मेदार, दखल देने वाला और भड़काऊ है। भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए। लोकतंत्र का सम्मान तभी संभव है, जब हर देश अपनी सीमाएं पहचाने और दूसरों की न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप से बचे। यही संतुलन वैश्विक शांति और आपसी सम्मान की असली कसौटी है।

# पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले जिन्होंने की बालिका शिक्षा की शुरूआत

डॉ श्रीगोपाल नारसन

पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले ने कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिए भी काम किया।

उनके पति ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के कारण जब वह स्कूल जाती थीं, तो उनके विरोधी उन्हें पत्थर मारते थे। कई बार उनके ऊपर गंदगी फेंकी गई। सावित्रीबाई फुले एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थीं और स्कूल पहुंच कर गंदी हुई साड़ी बदल लेती थीं। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ी इलाके में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के लिए इस विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। पुणे में पहले स्कूल खोलने के बाद फूले दंपति ने 1851 में पुणे के रास्ता पेठ में लड़कियों का दूसरा स्कूल खोला और 15 मार्च 1852 में बताल पेठ में लड़कियों का तीसरा स्कूल खोला। उनकी बनाई हुई संस्था सत्यशोधन समाज ने 1876 और 1879 के अकाल में अन्न सत्र चलाया और अन्न इकटठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था की।

सावित्रीबाई ने स्कूल में छात्राओं को पढ़ाने के साथ-साथ समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने 28 जनवरी 1853 को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह सभा का आयोजन किया। जिसमें महिलाओं सम्बन्धी समस्याओं का समाधान किया जाता था। सन 1890 में महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया। प्लेग के मरीजों की देखभाल करने के दौरान सावित्रीबाई की मृत्यु 10 मार्च सन 1897 को हुई।

उनके पिता का नाम खन्दोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने देश के पहले किसान स्कूल की भी स्थापना की थी देश मे 19वीं सदी तक स्त्रियों के कोई अधिकार नही थे, इन अधिकारों को प्राप्त करने व अशिक्षा, छुआछूत, सतीप्रथा, बाल या विधवा-विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर देश की पहली महिला शिक्षिका बनी थीं महाराष्ट्र में जन्मीं सावित्री बाई फुले। जिन्होंने अपने पति समाज सुधारक ज्योति राव फुले से पढ़कर सामाजिक चेतना फैलाई और नारी जाति का मान बढ़ाया।उन्होंने अंधविश्वास और रूढ़ियों की बेड़ियां तोड़ने के लिए लंबा संघर्ष किया था। सावित्रीबाई फुले 3जनवरी सन1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थ?ित नायगांव में पैदा हुई थीं। मात्र 9 साल की छोटी उम्र में पूना के रहने वाले ज्योति राव फुले के साथ उनकी शादी हो गई थी, विवाह के समय सावित्री बाई फुले पूरी तरह अनपढ़ थीं, जबकि उनके पति तीसरी कक्षा तक पढ़े हुए थे।वह भी पढ़ना चाहती थी, जिस दौर में वो पढ़ने का सपना देख रही थीं, तब वंचितों के साथ बहुत भेदभाव होता था, एक दिन सावित्रीबाई अंग्रेजी की किसी किताब के पन्ने पलट रही थीं, तभी उनके पिताजी ने देख लिया, वह दौड़कर आए और किताब हाथ से छीनकर घर से बाहर फेंक दी। वे बोले शिक्षा का हक केवल उच्च जाति के पुरुषों को ही है, दलित और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना पाप है,ऐसा उन्होंने उस समय कहते है बताया तो उसी दिन सावित्री फेंकी गई किताब वापस लाकर प्रण कर बैठीं कि कुछ भी हो जाए वह एक न एक दिन पढ़ना जरूर सीखेंगी।ऐसा हुआ भी,अपने मजबूत इरादों के बल पर सावित्री बाई न सिर्फ पढ़ी बल्कि सावित्रीबाई फुले देश ही नही दुनिया की पहली महिला शिक्षिका भी बन गई। उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास किये थे। उनके पति ने ही सावित्रीबाई के सपने को पूरा करने के लिए शिक्षा ग्रहण करने की इजाजत दी थी,साथ ही अक्षरज्ञान भी उन्होंने ही कराया।

शादी के बाद सावित्रीबाई पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगीं, उनका काफी विरोध भी काफी हुआ। उन्हें रोकने के लिए लोग सावित्री बाई फुले पर पत्थर मारते थे। कूड़ा और कीचड़ फेंकते थे,लेकिन सावित्री बाई फुले ने हार नहीं मानी और पढ़ाई पूरी करके शिक्षिका बनने का स्वप्न पूरा किया।

सावित्रीबाई को महसूस हुआ कि देश में उन जैसी कितनी ही लड़कियां होंगी जो पढ़ना चाहती है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालिकाओं को संघर्ष न करना पड़े, इसके लिए सावित्री बाई फुले ने सन 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश का पहला बालिका स्कूल स्थापित किया। बाद में उन्होंने लड़कियों के लिए 18 स्कूलों का निर्माण कराया।इसलिए हम कह सकते है कि सावित्रीबाई फुले एक समाज सेविका ही नहीं,

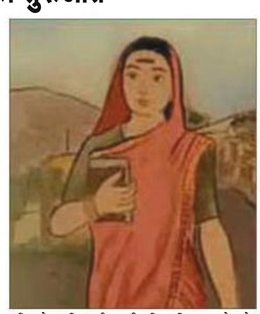

बल्कि देश दुनिया की पहली महिला शिक्षक व देश के पहले बालिका स्कूल की प्रधानाचार्य भी बन गईं थी। 66 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फुले का 10 मार्च सन1897 को निधन हो गया था। सावित्रीबाई ने सन 1848 से लेकर सन1852 के बीच लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले थे। सावित्रीबाई ने सिर्फ शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि देश में मौजूद कई कुरीतियों के खिलाफ भी आवाजा उठाई।उन्होंने छुआ-छूत, बाल-विवाह, सती प्रथा और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों का विरोध किया और इनके खिलाफ जीवनपर्यंत लड़ती रहीं।ऐसी महान नारी शक्ति के जन्मदिवस पर उन्हें शत शत नमन।

(लेखक विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के उपकुलपति व वरिष्ठ साहित्यकार है)

समय बड़ा ही कीमती है, इसे बेकार मत गवाओ, इसका सदुपयोग करो : विनोबा भावे

# खेल, कारोबार और राष्ट्रीय संवेदना

**खेल** को अकसर सीमाओं और राजनीति से परे माना जाता है, कहा जाता है कि खेल देशों को जोड़ता है। लेकिन जब पड़ोसी देश में हिन्दुओं के खिलाफ सुनियोजित हिंसा हो रही हो, निर्दोष लोगों को जिंदा जलाया जा रहा हो और मानवाधिकारों का हनन चरम पर हो, तो क्या खेल और कारोबार को मानवीय संवेदनाओं से ऊपर रखा जा सकता है? यह प्रश्न आज देश के सामने मुँह बाए खड़ा है। कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपये में खरीदे जाने पर संतों, राजनेताओं और सामान्य भारतीय नागरिकों का आक्रोश इसी नैतिक द्वंद्व को रेखांकित करता है। बांग्लादेश से आ रही खबरें विचलित करने वाली हैं। पिछले 12 दिनों में वहां से तीन हिंदुओं की हत्या का दर्दनाक समाचार आया है।

> खेल को अकसर सीमाओं और राजनीति से परे माना जाता है, कहा जाता है कि खेल देशों को जोड़ता है। लेकिन जब पड़ोसी देश में हिन्दुओं के खिलाफ सुनियोजित हिंसा हो रही हो, निर्दोष लोगों को जिंदा जलाया जा रहा हो और मानवाधिकारों का हनन चरम पर हो, तो क्या खेल और कारोबार को मानवीय संवेदनाओं से ऊपर रखा जा सकता है? यह प्रश्न आज देश के सामने मुँह बाए खड़ा है।

31 दिसंबर को शरियतपुर में 50 वर्षीय खोकोन दास को भीड़ द्वारा घेरकर बेरहमी से पीटना और फिर आग के हवाले कर देना, किसी भी सभ्य समाज की रूह कंपाने के लिए काफी है। ऐसे समय में, जब भारत में इस अत्याचार को लेकर गहरा रोष है, एक भारतीय आईपीएल फ्रेंचाइजी द्वारा उसी देश के खिलाड़ी पर करोड़ों रुपये बरसाना कई लोगों के हृदय को कष्ट पहुँचा रहा है। याद रहे कि कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता शाहरूख खान हैं। क्या शाहरूख खान को बांग्लादेश की लक्षित हिंसा की जानकारी नहीं है? मुसलमानों को लेकर होने वाली लक्षित हिंसा पर तो शाहरूख खान अत्यधिक संवेदनशील नजरिया रखते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद जब आम मुसलमानों पर भी आतंकी होने का संदेह किया जा रहा था, तब शाहरूख खान ने अपना आक्रोश एवं संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए 'माय नेम इज खान' फिल्म ही बना दी। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस प्रकार सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मारा जा रहा है, तब उनकी संवेदनाएं कहाँ चली गईं? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उस स्थिति में वहाँ के खिलाड़ियों को भारत में किसी भी प्रकार का महत्व, लाभ या अवसर देना, घोर निंदनीय कृत्य है। शाहरूख खान को यहाँ नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए था। याद रहे कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य और देवकीनंदन ठाकुर जैसे धर्मगुरुओं की आपत्ति को महज भावनात्मक उफान मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। उनका तर्क स्पष्ट है कि जिस देश में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में हो, वहां के खिलाड़ियों को भारत में सम्मान और धन क्यों दिया जाए? देवकीनंदन ठाकुर का यह प्रश्न कि "एक टीम मालिक इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है?" दरअसल उस कॉरपोरेट संस्कृति पर चोट है जो मुनाफे के आगे मानवीय त्रासदी को अनदेखा कर देती है। भाजपा नेता संगीत सोम का यह प्रश्न भी उचित है कि यदि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण वहां के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध है, तो बांग्लादेश में हो रहे सांप्रदायिक अत्याचारों पर हम आंखें क्यों मूंदे हुए हैं? यह विडंबना ही है कि जिस देश (भारत) की जनता ने शाहरुख खान जैसे सितारों को 'सुपरस्टार' बनाया, उनकी फ्रेंचाइजी का निर्णय उसी देश की जनभावनाओं के विपरीत दिखाई दे रहा है। 9.2 करोड़ रुपये की राशि एक बड़ी रकम है। आलोचकों का यह कहना सही है कि यह पैसा यदि बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू परिवारों की मदद या पुनर्वास में लगता, तो यह मानवता की सच्ची सेवा होती।

**जयंती**

# ज्ञान, करुणा और साहस की त्रिवेणी सावित्रीबाई फुले

अतुल गोयल
स्वतंत्र पत्रकार

**भारतीय** इतिहास में 3 जनवरी का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा गया दिन है क्योंकि इसी दिन महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। सावित्रीबाई फुले केवल एक नाम नहीं बल्कि भारत में नारी मुक्ति, शिक्षा की क्रांति और सामाजिक न्याय की उस मशाल का नाम है, जिसने सदियों के अंधेरे को चीरकर महिलाओं और वंचितों के लिए उजाले का मार्ग प्रशस्त किया। 1831 में एक साधारण परिवार में जन्मी सावित्रीबाई ने उस दौर में जन्म लिया था, जब समाज रूढ़ियों, अंधविश्वासों और जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। महिलाओं का घर से बाहर निकलना वर्जित था और शिक्षा पर केवल एक विशेष वर्ग का अधिकार माना जाता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में सावित्रीबाई का जीवन संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है।

सावित्रीबाई फुले का विवाह मात्र नौ वर्ष की आयु में ज्योतिराव फुले से हो गया था। विवाह के समय सावित्रीबाई पूरी तरह अनपढ़ थी लेकिन उनके भीतर ज्ञान अर्जित करने की एक गहरी ललक थी। एक रोचक प्रेरक प्रसंग उनके बचपन का है, जब वे एक अंग्रेजी किताब के पन्ने पलट रही थी और उनके पिता ने यह कहकर किताब फैंक दी कि शिक्षा का हक केवल उच्च जाति के पुरुषों को है और महिलाओं के लिए यह पाप है। उसी क्षण सावित्रीबाई ने संकल्प लिया कि वे पढ़ना जरूर सीखेंगी। उनके इस संकल्प को उनके पति ज्योतिराव फुले ने पंख दिए। ज्योतिराव खुद एक महान समाज सुधारक थे, जिनका मानना था कि समाज को बदलने के लिए स्त्री का शिक्षित होना अनिवार्य है। उन्होंने सावित्रीबाई को घर पर ही अक्षर ज्ञान कराया और उन्हें देश की पहली प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनने के योग्य बनाया।

सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले का अटूट साथ भारत में एक महान शैक्षिक क्रांति का आधार बना। 1848 में उन्होंने पुणे के भिड़ेवाड़ी इलाके में देश का पहला बालिका विद्यालय खोलकर इतिहास रच दिया। यह काम उस समय के कट्टरपंथी समाज को सीधी चुनौती थी। सावित्रीबाई जब स्कूल पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर पत्थर फैंकते थे, कीचड़ और गोबर उछालते थे। समाज के रक्षक कहलाने वाले लोग उन्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन सावित्रीबाई का साहस अटूट था, वे अपने थैले में एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदलकर छात्राओं को पढ़ाने बैठ जाती थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और महज एक साल के भीतर उन्होंने और उनके पति ने मिलकर पांच और स्कूल खोल दिए। 1848 से 1852 के बीच उन्होंने लड़कियों के लिए कुल 18 स्कूल स्थापित किए, जो उस कालखंड में एक चमत्कार से कम नहीं था।

सावित्रीबाई फुले एक प्रखर विचारक होने के साथ-साथ एक संवेदनशील मराठी कवयित्री भी थी। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 'काव्य फुले' और 'बावनकशी सुबोध रत्नाकर' जैसी उनकी रचनाओं में शिक्षा की महत्ता, जातिवाद का विरोध और अज्ञानता को दूर करने का आह्वान मिलता है। वे अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को समझाती थी कि जाओ, शिक्षा प्राप्त करो और आत्मनिर्भर बनो।' उनका मानना था कि अज्ञानता ही सभी दुखों की जड़ है और इसे केवल ज्ञान के प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है। उन्होंने सत्यशोधक समाज के माध्यम से समाज में समानता लाने का प्रयास किया। यह संस्था दहेज प्रथा के खिलाफ थी और बिना किसी पुजारी के सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देती थी, जिसे 'सत्यशोधक विवाह' कहा जाता था। आज भारत की हर शिक्षित महिला सावित्रीबाई फुले की ऋणी है। उनकी 195वीं जयंती पर उन्हें नमन करना वास्तव में उन मूल्यों को नमन करना है, जो समानता, गरिमा और शिक्षा पर आधारित हैं। सावित्रीबाई आज भी हमारे समाज के लिए एक जलती हुई मशाल हैं, जो हमें याद दिलाती रहती हैं कि सामाजिक सुधार का रास्ता शिक्षा की गलियों से होकर ही गुजरता है।

## भारत में विफल वामपंथ के लिए अमेरिका में तैयार होती जमीन

# एनवाईटी की रिपोर्टें और वैश्विक वैचारिक घेराबंदी का नया ढांचा

कैलाश चंद्र
सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ स्तंभकार

**न्यूयॉर्क** टाइम्स में प्रकाशित हालिया रिपोर्टें भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर कोई सामान्य टिप्पणी नहीं हैं, वे एक संगठित, वैश्विक वैचारिक पुनर्स्थापन के संकेत देती हैं। भारत में वामपंथ की क्रमिक सामाजिक एवं राजनीतिक पराजय के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि अंतर्राष्ट्रीय लिबरल-प्रोग्रेसिव मीडिया भारत के लिए एक वैचारिक निर्णायक-क्षेत्र बन गया है-एक ऐसा क्षेत्र, जहां भारत की कथा भारत द्वारा नहीं, बल्कि बाहरी एजेंसियों द्वारा लिखी जाए। यही कारण है कि एनवाईटी जैसी संस्थाएं आज भारतीय राजनीति को 'हिंदू राष्ट्रवाद' 'सत्तावाद' और 'बहुसंख्यक प्रभुत्व' के ढांचे में बांधकर प्रस्तुत करने में विशेष रूप से सक्रिय हैं।

एनवाईटी की रिपोर्ट 'From the Shadows to Power: How the Hindu Right Rose to Remake India' स्पष्ट रूप से उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें भारत के राजनीतिक वाम के पतन के बाद उसके लिए एक नया, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक आश्रय तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 'far-right Hindu nationalist' शक्ति कहा गया, मोदी शासन को 'आरएसएस का उत्पाद' बताकर उसकी नीतियों को 'सांस्कृतिक प्रभुत्व' का परिणाम घोषित किया गया, और भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को 'धार्मिक उग्रता' की उपमा दी गई। इस भाषा में वह परिचित पश्चिमी अहंकार छिपा हुआ है, जो अपनी सभ्यतागत दृष्टि को सार्वभौमिक मानकर अन्य सभी को इसके अनुसार परिभाषित करने का आग्रह रखता है।

यह रिपोर्ट मात्र राजनीतिक आलोचना भर नहीं है, यह भारत की वैचारिक दिशा को प्रभावित करने, बल्कि उसे बदलने का प्रयास है। विशेष रूप से तब, जब भारत में वामपंथ की पारंपरिक सामाजिक जमीन लगभग पूरी तरह खिसक चुकी है। न तो चुनावी राजनीति में उसे प्रभाव बचा है, न ही विश्वविद्यालय-केंद्रित वैचारिक संस्थानों में वह वैसा जनाधार रख पा रहा है, जैसा कभी जेएनयू, डीयू या अन्य कैंपसों में देखना आम था। सीएए विरोध, शाहीन बाग जैसे आंदोलनों, धारा 370 पर अलगपंथी रवैये और राष्ट्रवाद-विरोधी नैरेटिव ने वामपंथ को मुख्यधारा समाज से और भी दूर कर दिया। इसके समानांतर नक्सली उग्रवाद का ह्रास हुआ, और आर्थिक उदारीकरण के बाद मार्क्सवादी आर्थिक मॉडल अपनी वैधता खो बैठा। इस पतन ने वामपंथ को अकादमिक लेखन, विदेशी मीडिया, मानवाधिकार संस्थानों और एनजीओ-नेटवर्क तक सीमित कर दिया।

एनवाईटी की रिपोर्टों का स्वर इसी बदलते परिदृश्य में समझना आवश्यक है। पश्चिम का प्रोग्रेसिव एस्टैब्लिशमेंट भारत में वामपंथ को अपना स्वाभाविक वैचारिक सहयोगी मानता रहा है क्योंकि वामपंथ आज भी पश्चिमी मानवाधिकार-आधारित विमर्श के लिए भारतीय संदर्भों में उपयुक्त नैरेटिव प्रदान करता है। लेकिन देश में वामपंथ की प्रासंगिकता के क्षय ने यह भूमिका कमजोर की है। इसलिए एनवाईटी, वाशिंगटन पोस्ट, इकोनॉमिस्ट जैसे प्लेटफॉर्म अब वामपंथी नैरेटिव को 'बाहरी वैधता' देकर उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं।

एनवाईटी की रिपोर्टों में जिस प्रकार भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को 'माइनॉरिटी-नेगेटिव' और 'अतार्किक धार्मिक उभार' की तरह प्रस्तुत किया गया, वह वस्तुतः दो भिन्न सभ्यताओं के बीच संघर्ष का रूप है। पश्चिम का वैचारिक ढांचा-व्यक्ति-केंद्रित उदारवाद, पूर्णतः अनुष्ठानमुक्त सेक्युलरिज़्म और राज्य का संस्कृति से दूरी - भारतीय सिविलाइज़ेशनल मॉडल से सर्वथा विपरीत है। भारत की दृष्टि सामूहिक है, परिवार-आधारित है, संस्कृति और धर्म उसके सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग हैं। आरएसएस इसी 'सांस्कृतिक जीवन-दृष्टि' का प्रतीक है। पश्चिम इसे समझने के बजाय 'majoritarianism' का नाम देता है, और उसी आधार पर अपने आक्षेप खड़े करता है।

अमेरिका के अखबार न्यूयार्क टाइम्स में 29 दिसम्बर के अंक में प्रथम पेज पर संघ को लेकर गलत तथ्यों पर आधारित एक नकारात्मक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।

ऐसा नहीं कि यह केवल मीडिया की पसंद-नापसंद का मामला है। पश्चिम में एनजीओ-इकोसिस्टम, विशेष रूप से फोर्ड फाउंडेशन, ओएसएफ, एचआरडब्ल्यू और आम माफ़ी जैसे नेटवर्क, लंबे समय से भारत के बौद्धिक विमर्श को प्रभावित करने की दिशा में सक्रिय रहे हैं। एनवाईटी की कई रिपोर्टें इन्हीं फाउंडेशनों के कथित 'शोधों' पर आधारित होती हैं, जिन्हें वह 'वैज्ञानिक' बताकर प्रस्तुत करता है। यह एक परस्पर पोषक तंत्र है- एनजीओ शोध उत्पन्न करते हैं, मीडिया उसे प्रचारित करती है, विश्वविद्यालय उसे पाठ्यक्रमों में शामिल करते हैं, और फिर वही सामग्री भारत के भीतर वामपंथी लेखकों द्वारा उद्धृत होकर वापस मुख्यधारा विमर्श में लौटती है।

भारत के लिए चुनौती यही है-जब देश एक 'सिविलाइजेशनल राष्ट्र' के रूप में उभर रहा है, तब यह वैश्विक नैरेटिव-आधारित दबाव और भी तीव्र होगा। राम मंदिर, धारा 370, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, और आर्थिक शक्ति- ये सब भारत को एक नए आत्मविश्वास की ओर ले जा रहे हैं। यह मॉडल न तो चीन जैसा आक्रामक है, और न ही पश्चिम जैसा व्यक्तिवादी। यह भारतीय है-और यही उसकी पहचान व शक्ति है। पश्चिमी संस्थानों को इस उभार में एक 'असुविधा' दिखाई देती है-क्योंकि यह उनके स्थापित वैचारिक प्रभुत्व को चुनौती देता है।

एनवाईटी द्वारा आरएसएस को 'shadow power' कहना इस बात का प्रमाण है कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को पश्चिम अपने मानकों में मापने पर अड़ा हुआ है। जबकि वास्तविकता यह है कि संघ की शाखाएं, उसके सामाजिक संगठन, सेवा-कार्य, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का विशाल तंत्र-सब भारतीय समाज के भीतर खुले, लोकतांत्रिक और पारदर्शी रूप में सक्रिय हैं। यह किसी 'छाया सरकार' का कार्य नहीं, बल्कि भारतीय समाज का स्व-नियोजित संगठन है। इसके विपरीत, एनवाईटी यह नहीं बताता कि भारत में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या, धार्मिक स्वतंत्रता, मस्जिदों की संख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व-सब बढ़ा है, क्योंकि यह उसके नैरेटिव के अनुकूल नहीं।

भारत एक निर्णायक वैचारिक मोड़ पर है। यह संघर्ष अब गोलियों का नहीं, कथाओं का है-narrative warfare का। एनवाईटी की रिपोर्टें इस युद्ध का एक अध्याय भर हैं। भारत को इस समय न केवल अपनी आंतरिक राजनीतिक स्थिरता को, बल्कि अपनी वैचारिक स्वायत्तता को भी सुरक्षित रखना है। विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता, स्वदेशी शोध संस्थानों का निर्माण, मीडिया साक्षरता और वैश्विक मंचों पर भारतीय दृष्टिकोण की निरंतर उपस्थिति-ये सभी आवश्यक हैं।

भारतीय जनता पिछले एक दशक में वैचारिक रूप से कहीं अधिक परिपक्व हुई है। अब बाहरी नैरेटिव उसे पहले की तरह प्रभावित नहीं करते। यह भारत की नई शक्ति है-और यही कारण है कि वामपंथ का पुनरुत्थान केवल पश्चिमी कागज़ों में संभव है, भारतीय समाज में नहीं। उभरते भारत का आत्मविश्वास आज पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। यह संघर्ष का अंत नहीं-आरंभ है। वैश्विक मीडिया चाहे जितनी घेराबंदी करे, भारतीय सभ्यता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें हिलाया नहीं जा सकता। भारत का उभार अब अविराम है।

*यह लेखक के निजी विचार है*

## डिग्रीधारी बेरोजगार हैं देश की सबसे बड़ी चुनौती

# नए साल में क्या हों भारत के सपने ?

संजय उवाच

प्रो. संजय द्विवेदी

**किसी** राष्ट्र जीवन के प्रवाह में साल का बदलना कैलेंडर बदलने से ज्यादा कुछ नहीं होता। किंतु नए साल पर हम व्यक्ति और समाज के तौर कुछ संकल्प लेते ही हैं। नया साल हमें विहंगावलोकन का अवसर देता है और आगे क्या करना है इसका मार्ग भी दिखाता है। 2026 ऐसा ही एक साल है, जिसने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपनी चुनौतियों को पहचानें और सपनों में रंग भरने के लिए आगे आएं। युवा देश होने के नाते अगर यह अवसरों का जनतंत्र है तो आकांक्षाओं का समुद्र भी लहलहा रहा है। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। यह संकट किसी भी समाज के संकट हो सकते हैं किंतु भारत को इससे जूझकर ही आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा।

**रोजगार सृजन की गुणवत्ता-** भारत की युवा आबादी के सपने बहुत बड़े हैं। वे अच्छा रोजगार चाहते हैं।अस्थायी कम वेतन वाली नौकरियां समाज में असंतोष का ही कारण बनती हैं। गिग इकोनामी, कान्ट्रैक्ट वर्क और आटोमेशन के दौर में युवाओं का संकट गहरा किया है। देश में शिक्षा केंद्र बढ़ें हैं किंतु मुद्दा यह है कि क्या युवाओं को वहां शिक्षा मिल रही है। वे कौशल से युक्त हो रहे हैं या सिर्फ डिग्री उनके लिए बोझ बन रही है। 'उद्योगों के लिए तैयार युवा' कहां हैं। शिक्षा प्रणाली यह विवशता अभी खत्म होती नहीं दिखती। पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और उद्योग के बीच लंबी प्रतीक्षा आज भी बनी हुई है। ऐसे में डिग्रीधारी बेरोजगार इस देश की सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बने रहेंगें।

**कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उपजे संकट-** एआई, मशीन लर्निंग और आटोमेशन हमारे जैसे बहुत बड़ी आबादी वाले समाज के लिए संकट भी है और अवसर भी। तकनीक से बढ़ती उत्पादकता और सक्षम मशीनें अंततः मनुष्य को हाशिए पर लगा रही हैं। बहुत सारा वर्कफोर्स बेमानी होने के आसार हैं। पारंपरिक कामों और नौकरियों पर खतरे के गहरे बादल हैं। कई जगह ये प्रारंभ भी हो गया है। इस साल हमें यह तय करना होगा कि हम सारा कुछ बाजार की शक्तियों के हवाले कर देंगे या अपेक्षित संवेदना के साथ मानवीय आवश्यक्ता के साथ संतुलन बनाएंगें।

**कृषि संकट और ग्रामीण भारत-** पिछले अनेक सालों में नगर केंद्रित विकास के प्रयोगों ने हमारे शहरों को नरक और गांवों को खाली कर दिया। गांधी का ग्राम स्वराज्य का स्वप्न हाशिए पर लगा दिया गया। भारत माता ग्रामवासिनी सिर्फ गीतों का स्वर रह गया। उजड़ते गांवों ने ऐसी कथा लिखी है जिससे कहकर- सुनकर दर्द बढ़ता ही है। बावजूद इसके हमारी आधी से अधिक आबादी की निर्भरता आज भी खेती पर है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनिश्चितता और बाजार की अस्थिरता ने किसानों को गहरे संकट में डाल रखा है। खेती की उपज के मूल्य का अंतर किसान और बाजार के बीच कितना है, यह देखना जरूरी है। कृषि सुधार के अनेक प्रयासों के बाद भी खेती लाभ का व्यवसाय नहीं बन पा रही है। ऐसे में नई पीढ़ी खेती करने से दूर जा रही है और किसानों की जेब और आत्मसम्मान दोनों संकट में हैं।

इसके साथ ही जल संकट और पर्यावरण का सवाल हमारी बड़ी चुनौती है। महानगरों की फिजाओं में घुलता जहर हमने देखा है। इससे हमारी राष्ट्रीय राजधानी भी

मुक्त नहीं है। कई राज्य गंभीर भूजल संकट से जूझ रहे हैं। अनियमित मानसून, प्रदूषण और अंधाधुंध शहरीकरण ने पर्यावरण संतुलन को चौपट कर दिया है। जल, जंगल और जमीन के सवाल हमें देर तक और दूर तक परेशान करते रहेंगें। इसके चलते समाज में गहरा असंतोष पैदा हो रहा है। नए साल में इन सवालों को संबोधित करने की जरूरत है।

**स्वास्थ्य व्यवस्था का संकट-** कोविड संकट ने हमें आईना दिखाया था कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल क्या है। उससे उबर कर हमने बहुत कुछ सीखा और खुद को कई मामलों में आत्मनिर्भर बनाया। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शहर और गांव का खांई और भी गहरी होती जा रही है। आयुष्मान योजना जैसे प्रकल्प भी लगता है कि निजी क्षेत्र की लूट का कारण बन गए हैं। आयुष्मान और बीमा धारकों की हैसियत को देखकर इलाज करने वाले अस्पताल भी खड़े हो गए हैं। रोग के बजाए मरीज तलाशे जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा देने वाले कुछ लोग कई मायने में अमानवीयता की हदें पार कर रहे हैं। निजी सेवाएं महंगी होते जाने से सरकारी तंत्र पर दबाव बहुत बढ़ गया है। सरकारी अस्पतालों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है किंतु सर्वाधिक मरीज उन्हीं के पास हैं। ऐसे में भारत का मध्यवर्ग गहरे संकट का शिकार है। उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। महंगाई, शिक्षा-स्वास्थ्य खर्च, ईएमआई, अस्थाई नौकरियां, करों का बोझ मध्यवर्ग के लिए चुनौती है। इससे सामाजिक अस्थिरता और उपभोक्ता अर्थव्यवस्था का संकट संभव है।

**राज्यों की वित्तीय चुनौतियां-** लोकलुभावन वायदों को पूरा करने में राज्यों ने अपनी आर्थिक स्थिति चौपट कर ली है। संघीय ढांचा संतुलन और सहयोग की धुरी पर टिका हुआ है किंतु हालात संकटपूर्ण हैं। राज्यों के खस्ताहाल आर्थिक तंत्र, कर वितरण और योजनाओं के क्रियान्यवन से जुड़े संकटों को नए साल में हल करने की जरूरत है। इसके साथ ही भारत की जटिल भौगोलिक संरचना में वह हर तरफ विरोधी विचार के देशों से घिरा है। पाकिस्तान और चीन के बाद अब बांग्लादेश की शांत सीमा से भी संकट बढ़ रहा है। ऐसे में सुरक्षा चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। ऐसे में गहरे रणनीतिक संतुलन, कूटनीति और धैर्य की जरूरत दिखती है। नए साल में हमें इन संकटों से दो-चार होना पड़ेगा।

**सूचना का शोर और भरोसे का संकट-** मीडिया को चौथा स्तंभ कहकर लोक ने समादृत किया है। किंतु वह गहरे सूचना शोर से जूझ रहा है जहां भरोसे का संकट गहरा हुआ है। फेक न्यूज, प्रौपेगेंडा, एल्गोरिदमिक एजेंडा और टीआरपी संस्कृति ने समूची मीडिया की नैतिकता और समझदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2026 का साल मीडिया के लिए खुद के आत्ममूल्यांकन और आत्मपरिष्कार का साल भी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया ने नए संकट खड़े किए हैं। मुख्यधारा का मीडिया भी इससे आक्रांत है। सोशल मीडिया संवाद के बजाए विवाद का मंच बना हुआ है। सामाजिक समरसता और सद्भाव से परे हटकर दी जा रही सूचना और कथाएं हमारे लिए विचार का विषय हैं। इससे हमारी स्वाभाविक सद्भावना खतरे में हैं।

इन संकटों के बीच भी हम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। हमें अपने संकटों के हल खुद खोजने होंगें। नया साल वह अवसर है कि हम आत्ममूल्यांकन कर सही दिशा में सामूहिक प्रयत्नों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। 2026 हमारे लिए सिर्फ आर्थिक वृद्धि का साल नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय विवेक, सामाजिक संतुलन और संवेदनशीलता की परीक्षा भी है। अनेक गंभीर चुनौतियों के बाद भी हम नीति, नीयत और ताकतवर नेतृत्व से अपने संकटों का हल कर सकते हैं। आइए अपने भागीरथ हम स्वयं बनें और विकास के साथ करुणा को साधकर एक बार पुनः भारतबोध की यात्रा पर प्रयाण करें।

**(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग में आचार्य और अध्यक्ष हैं।)**

# सम्राट विक्रमादित्य : भारतीय ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना के महान स्तंभ

डॉ शुभम् वर्मा
शोधकर्ता, प्रदेश प्रभारी
नीति शोध एवं प्रशिक्षण
(भाजयुमो, मप्र)

**भारतीय** इतिहास में यदि किसी ऐसे सम्राट का स्मरण किया जाए जिसने शासन, संस्कृति, विज्ञान, कला, न्याय और काल-गणना—इन सभी क्षेत्रों में एक साथ अमिट छाप छोड़ी हो, तो उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। वे केवल एक शक्तिशाली विजेता नहीं थे, बल्कि भारत की बौद्धिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक परंपरा के महान संरक्षक और संवर्धक भी थे। दुर्भाग्यवश, आधुनिक काल के इतिहास लेखन में उनके साथ गंभीर अन्याय हुआ है। उनके काल को लेकर जानबूझकर भ्रम उत्पन्न किया गया और उन्हें योजनाबद्ध ढंग से इतिहास के केंद्र से हटाने का प्रयास किया गया।

प्राचीन भारत में उज्जैन केवल एक राजधानी नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का वैज्ञानिक, खगोलीय और सांस्कृतिक केंद्र था। उज्जैन को प्राचीन काल में भारत की प्रधान मध्यान्ह रेखा माना जाता था, जहां से काल-गणना की जाती थी। इसी उज्जैन से शासन करने वाले सम्राट विक्रमादित्य ने राजनीतिक स्थिरता के साथ-साथ भारत को बौद्धिक नेतृत्व भी प्रदान किया। पुराणों, जैन ग्रंथों, बौद्ध साहित्य और लोक परंपराओं में विक्रमादित्य को शकों पर निर्णायक विजय प्राप्त करने वाला, न्यायप्रिय और विद्वानों का आश्रयदाता बताया गया है। उनका शासन भारतीय आत्मबोध के पुनरुत्थान का काल था।

सम्राट विक्रमादित्य का सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान विक्रम संवत की स्थापना मानी जाती है। विक्रम संवत केवल एक पंचांग प्रणाली नहीं, बल्कि भारत की उन्नत खगोलीय और गणितीय परंपरा का जीवंत प्रमाण है। यह संवत सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की सटीक गणना पर आधारित है और आज भी भारत तथा नेपाल के अनेक भागों में प्रचलित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विक्रमादित्य के काल में काल-गणना और खगोल विज्ञान अत्यंत विकसित अवस्था में थे। उज्जैन की वेधशालाएं और गणनात्मक परंपराएं इसी वैज्ञानिक दृष्टि का परिणाम थीं।

विक्रमादित्य का युग भारतीय विज्ञान और ज्ञान परंपरा का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। इस समय खगोलशास्त्र, गणित, आयुर्वेद, धातु विज्ञान और वास्तु विद्या में उल्लेखनीय प्रगति हुई। ग्रहों की गति की गणना, पंचांग निर्माण, दशमलव पद्धति, त्रिकोणमितीय अवधारणाएं और चिकित्सा विज्ञान का सुव्यवस्थित विकास उस बौद्धिक वातावरण की देन था, जिसे विक्रमादित्य जैसे दूरदर्शी शासक का संरक्षण प्राप्त था। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि सुदृढ़ राज्य व्यवस्था और विद्या सम्मान की नीति का परिणाम था।

कला, शिल्प और स्थापत्य के क्षेत्र में भी विक्रमादित्य का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उनके काल में मंदिर स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला और नगर नियोजन का व्यापक विकास हुआ। उज्जैन, विदिशा, सांची और आसपास के क्षेत्रों में विकसित स्थापत्य परंपराएं आज भी इस बात की साक्षी हैं कि उस युग में कला को केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति माना जाता था। शिल्पकारों और कलाकारों को राजाश्रय प्राप्त था, जिससे भारतीय कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची।

सम्राट विक्रमादित्य के दरबार को नवरत्नों का दरबार कहा जाता है, जो उस युग की बौद्धिक ऊंचाई का प्रतीक है। इस दरबार में कालिदास जैसे महान

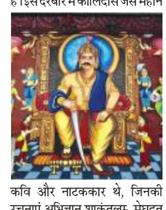

कवि और नाटककार थे, जिनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम्, मेघदूत और रघुवंश आज भी विश्व साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान रखती हैं। वराहमिहिर जैसे खगोलशास्त्री और वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पंचसिद्धांतिका और बृहत्संहिता जैसी रचनाओं के माध्यम से भारतीय विज्ञान को व्यवस्थित रूप दिया। धन्वंतरि जैसे आयुर्वेदाचार्य थे, जिनकी चिकित्सा परंपरा आज भी जीवित है। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश संस्कृत भाषा का आधार ग्रंथ बना, जबकि घटकरपर, क्षपणक, शंकु और वेतालभट्ट जैसे विद्वानों ने साहित्य, व्याकरण और दर्शन को समृद्ध किया। यह नवरत्न मंडली इस बात का प्रमाण है कि विक्रमादित्य का शासन ज्ञान और विवेक पर आधारित था, न कि केवल सैन्य शक्ति पर।

लोककथाओं और जनश्रुतियों में सम्राट विक्रमादित्य को न्याय का प्रतीक माना गया है। सिंहासन बत्तीसी जैसी कथाएं केवल कल्पना नहीं, बल्कि उस युग में स्थापित न्याय और आदर्श राजधर्म की अवधारणा को प्रतिबिंबित करती हैं। कहा जाता है कि राजा स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता था और निष्पक्ष न्याय करता था। यह भारतीय राजपरंपरा का सर्वोच्च आदर्श था, जिसमें शासक को लोकसेवक माना जाता था।

**पुरुषों से तेज बढ़ती महिला कैदी**

# बदलते समाज, कानून और अपराध की नई तस्वीर

कांतिलाल मांडोत

**भारतीय** जेलों में महिला कैदियों की संख्या में आई तेज बढ़ोतरी केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज, कानून व्यवस्था और सामाजिक संरचना में आए गहरे बदलावों का संकेत है। हाल में जारी इंस्टीट्यूट फॉर क्राइम एंड जस्टिस पॉलिसी रिसर्च आईसीपीआर की रिपोर्ट वर्ल्ड फीमेल इम्प्रिजनमेंट लिस्ट बताती है कि पिछले दो दशकों में भारतीय जेलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों और सामान्य जनसंख्या की तुलना में दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। वर्ष 2000 में जहां महिला कैदियों की संख्या 9,089 थी, वहीं 2022 तक यह बढ़कर 23,772 हो गई। यह 162 प्रतिशत की वृद्धि है, जबकि इसी अवधि में पुरुष कैदियों की संख्या 77 प्रतिशत बढ़ी और देश की कुल आबादी में लगभग 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ। यह स्थिति अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। क्या महिलाएं पहले की तुलना में ज्यादा अपराध करने लगी हैं, या फिर कानून और समाज की नजर महिलाओं पर पहले से अधिक सख्त हो गई है। क्या यह बदलाव महिलाओं की बढ़ती स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी का अनचाहा परिणाम है, या फिर सामाजिक-आर्थिक दबावों का असर है। इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी है, क्योंकि महिला अपराध और महिला कैदियों की बढ़ती संख्या समाज के स्वास्थ्य का आईना होती है। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में भारतीय समाज की संरचना अपेक्षाकृत पारंपरिक थी। महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से घर-परिवार तक सीमित मानी जाती थी।

दैनिक सवेरा टाइम्स

नई दिल्ली, शनिवार, 3 जनवरी 2026

प्रकृति किसी भी चीज का यथासंभव कम से कम उपयोग करती है।
-जोहान्स केप्लर

# राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप

भारत की शिक्षा नीति को रोजगारपरक बनाने का फैसला तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा में हो गया था। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 आई। वैसे तो यह शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा नीति का विस्तार है लेकिन इन पांच वर्षों में भारत में जो डिजिटल शक्ति, कृत्रिम मेधा और रोबोटिक्स का विस्तार हुआ है उसके शिक्षण और नई पीढ़ी को उसके प्रति जागरूक करने का प्रयास भी इस शिक्षा नीति में किया गया है। हम सन् 2047 तक अपने देश को पूर्णतः विकसित राष्ट्र बना देने का केवल सपना ही नहीं देख रहे बल्कि यह कल्पना भी करते हैं कि तब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति से पहली शक्ति बनने की छलांग लगा देगा और अपने से आगे चल रही दो शक्तियों अर्थात अमेरिका और चीन को पछाड़ देगा। लेकिन इसके लिए भारत की युवा आबादी जो किसी भी देश की सबसे बड़ी आबादी है, उसे पूर्णतः शिक्षित करना और बदलते जमाने के साथ चलाना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश की शिक्षा नीति को कौशल उन्मुक्त बनाया है, रोजगारपरक बनाया है और अब वह समावेशी शिक्षा प्रणाली को विकसित करने पर जोर देती है। समावेशी प्रणाली का अर्थ यह है कि आप एक ही ज्ञानधारा के कूपमंडूक न बन जाएं बल्कि उसे पूरी तरह से विस्तृत करके ज्ञान जागरण, तकनीकी विकास और हर नए अनवेष्ण को अपने क्षेत्र में समेट लेना है। लक्ष्य यह है कि अब छात्र केवल किताबी ज्ञान के हवाले न रहकर कौशल भी सीखें। प्रौद्योगिकी का नवसंचार इस देश में हो गया है। इस समय कम से कम 19 लाख से अधिक छात्रों को पूरे देश में इसका लाभ मिल रहा है।

जब देश में एआई प्रयोग से क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं तो उसे शिक्षा के विषय क्षेत्र में भी तो शामिल होना चाहिए। नया वर्ष 2026 शुरू हो चुका है, अब 2025 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर सकारात्मक बदलाव मिलें और तेजी से मिलें। इसके लिए सबसे पहले शिक्षकों को इस नवजागरण के प्रति प्रतिबद्ध करना होगा। उसके बाद विद्यार्थियों को इसके लिए तैयार करना होगा। बेशक भारत ने शिक्षा के विकास पर अपना आबंटन लगातार बढ़ाया है। 2019-20 में यह 94,854 करोड़ रुपये था, आज यह 1,28,650 करोड़ रुपये हो चुका है। लेकिन फिर भी बता दें कि पहले योजना आयोग और अब नीति आयोग यह कहता रहा है कि हमारे देश के सकल घरेलू उत्पादन का कम से कम 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के विकास पर अवश्य खर्च होना चाहिए।

हमने आजादी का अमृत महोत्सव तो मना लिया लेकिन शिक्षा के विकास पर कभी भी इतना खर्च हम नहीं कर पाए। इस समय हमारे देश में 14.71 लाख स्कूल हैं और इनमें पढ़ाने वालों की संख्या 1.01 करोड़ है। हां, इनसे पढ़ने वालों की संख्या 24.69 करोड़ है। लक्ष्य यह है कि वर्तमान 28.4 प्रतिशत उच्च शिक्षा तक जाने वालों की संख्या कम से कम 50.1 प्रतिशत तो कर दें। देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या भी धीरे-धीरे बढ़ रही है।

इस समय हमारे देश में 520,81 कालेज हैं और हर तरह के उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 70,018 हैं। देश में शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के आ जाने के बाद विश्वविद्यालयों की संख्या 1338 हो गई है। लेकिन विडम्बना यह है कि जितने छात्र इनमें पढ़ते हैं, उनमें से ड्रापआउट करने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। आजकल तो नौजवानों का घेरा आइलैट्स अकादमियों के गिर्द अपेक्षित बैंड प्राप्त करने के लिए बढ़ता जा रहा है ताकि वे विदेशों में जाकर अपनी गुरबत दूर कर सकें। स्पष्ट है और यह आंकड़े बता रहे हैं कि अगर देश को नवाचार के ज्ञान की ओर बढ़ना है तो न केवल शिक्षा संस्थानों और शिक्षकों की संख्या बढ़नी चाहिए बल्कि छात्रों को भी अपने देश में ही उचित रोजगार मिलने की गारंटी दे दी जाए ताकि वे इस नई शिक्षा की ओर गंभीरता से उन्मुख हो सकें।

-शीतल विज

# वंदे भारत के बाद बुलेट ट्रेन दौड़ाने की उम्मीद

**भारतीय** रेलवे में क्रांति कर देने की घोषणाएं बहुत देर से हो रही हैं। अब भारत के रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्ष 2026 के पहले ही दिन यह खबर दी है कि 15 अगस्त 2027 से हमारे देश में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। पहले चरण में यह बुलेट ट्रेन सूरत से वापी के बीच चलेगी। इसके बाद पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुम्बई तक चलाने की घोषणा है। दोनों मैट्रो शहरों के बीच 508 किलोमीटर का अंतर है, यह 2 घंटे17 मिनट में तय हो जाएगा।

इससे पहले अतिरिक्त द्रुत गति से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेनें तो देश के महत्वपूर्ण शहरों में दौड़ने लगी हैं, लेकिन इसमें भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल पूरा किया गया है। यह स्लीपर ट्रेन 18-19 जनवरी से गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलाई जाएगी। इस ट्रायल रन में ट्रेन में 16 कोच होंगे जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ेंगे। गुवाहाटी और हावड़ा के बीच स्लीपर में द्वितीय एसी का किराया 2700 रुपये हो सकता है जबकि हवाई जहाज से जाने पर यह कम से कम 8 हजार रुपये लगता है।

लक्ष्य यह है कि 2026 में 12 वंदे भारत एक्सप्रैस ट्रेनें भी चलने लगें। बेशक रेलें और उनकी गति विकास पथ पर है, अपने गंतव्य पर ये अधिक तेजी से पहुंचेंगी लेकिन आम आदमी को अधिक सुविधा देने के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम नहीं किया है। आज भी एक टिकट एक सीट की गारंट हम भारतीय रेलों के यात्रियों को नहीं दे सके। उन्हें वेटिंग लिस्ट के अवरोधों को पार करके ही उचित सीट मिलती है। कहा जाता है कि हम वरिष्ठों को लोअर बर्थ देंगे लेकिन वह भी अभी रेल के डिब्बों में गारंटी के साथ नहीं मिलते।

इससे पहले कोविड के दिनों में बुजुर्गों को दी जाने वाली रेल टिकटों में रियायत वापस ले ली गई थी। एक कल्याणकारी राज्य में जहां वरिष्ठ नागरिकों को उचित सम्मान देने का दम भरा जाता है, वहां यह वापस ली गई रियायत फिर से शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन रेलवे अपना घाटा कम करने के प्रयास में यह सुविधा वरिष्ठजनों को पूरी तरह वापस देने की मनःस्थिति में नहीं है। क्या जनसाधारण रेलवे से यह गारंटी पा सकता है कि वरिष्ठजनों को रियायत और आम आदमी को उचित दाम पर निश्चित सीट मिल जाए?

-शीतल विज

Email: letter2editor@dainiksaveratimes.net

# अपने ही फैसलों को स्थगित करना सर्वोच्च न्यायालय की हिम्मत और परिपक्वता

## सुप्रीम कोर्ट जब अपने ही निर्णयों की पुनर्समीक्षा करता है, तो वह स्वयं को संविधान के दायरे में रखने की पुष्टि करता है

लोकमित्र गौतम

हाल के अपने एक फैसले और उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले को गुजरी 29 दिसंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई तक स्थगित करना कोई विरोधाभास नहीं बल्कि न्याय प्रक्रिया की परिपक्वता का प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में ये दो बिल्कुल अलग फैसले, जिनमें से एक का संबंध उन्नाव बलात्कार मामले में जेल में बंद कुलदीप सिंह सेंगर से और दूसरे का संबंध अरावली पर्वतमालाओं से है, साफ पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्याय प्रक्रिया में जीवंत हस्तक्षेप करता है।

कुलदीप सेंगर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 'न्यायपालिका कोई ईश्वरीय संस्था नहीं बल्कि मानवीय विवेक पर टिकी व्यवस्था है, इसलिए गलती किसी से भी हो सकती है।' गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को उन्नाव रेप केस में आरोपी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी थी। मगर 29 दिसंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार करना जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो, तो बिना उसे सुनें ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगायी जाती। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगायी जाती है।' इस मामले में चार हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी। सर्वोच्च अदालत ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में जवाब मांगा है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा संबंधी अपने ही एक आदेश पर रोक लगा दी है।

अब इस मामले में विशेषज्ञों की कमेटी फिर से जांच करेगी। अरावली मामले में जिसे लेकर पिछले कई सप्ताह से देश के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन हो रहे थे, सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'अरावली की परिभाषा को यदि 500 मीटर के दायरे तक सीमित किया जाता है, तो इससे संरक्षण क्षेत्र के सिमटने की संभावना है। कई ऐसे भू-भाग जो पारिस्थितिक रूप से अरावली का हिस्सा हैं, वे कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकते हैं।' इस तरह इस मामले को संरचनात्मक विरोधाभास के रूप में देखा जा रहा है। अतः इस मामले में भी अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी और तब तक के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। लब्बोलुआब यह कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को किसी भी तरह लागू नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस संबंध में अदालत से कहा कि अदालत के आदेशों, सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं।

गौरतलब है कि इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और समिति ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसे ही अदालत ने स्वीकार किया था। बहरहाल भारतीय संविधान में रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन और बड़ी पीठों की व्यवस्था इसलिए ही की गई है कि अगर धोखे से भी किसी न्याय में कमी रह जाए, तो उसे समय रहते दुरुस्त किया जा सके। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्वीकार करना कि न्याय अंतिम सत्य नहीं बल्कि निरंतर खोज है, भारतीय विधि व्यवस्था की परिपक्वकता को दर्शाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में लंबित एक आपराधिक मुकद्दमा, महज दूसरे सामान्य मुकद्दमों जैसा नहीं है बल्कि यह न्यायिक संवेदनशीलता की परीक्षा है। क्योंकि शुरुआती दौर में निचली अदालतों और स्थानीय प्रभावों के कारण पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में जब मामला सर्वोच्च न्यायालय तक मामला पहुंचा, तो सर्वोच्च अदालत ने न केवल ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर किया बल्कि पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए तेज सुनवाई की व्यवस्था की। साथ ही इस संबंध में निष्पक्ष ट्रायल को प्राथमिकता दी गई।

ऐसे में यह साफ है कि पहले सिस्टम से भले चूक हुई हो, पर सर्वोच्च न्यायालय ने उस चूक को अब न सिर्फ स्वीकार कर हस्तक्षेप किया है बल्कि जरूरी समय पर न्यायिक परिपक्वता का उदाहरण भी पेश किया है। ठीक अरावली पर्वतमाला के संबंध में भी अदालत का यह फैसला पर्यावरणीय न्याय में गहरे आत्ममंथन के अनुरूप है। अरावली का मामला बिल्कुल अलग प्रकृति का है। क्योंकि यहां कोई एक आरोपी नहीं बल्कि पूरी विकास प्रणाली ही सवालों के घेरे में है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत में खनन और विनाश को रोकने के लिए कड़े आदेश दिए। लेकिन बाद की समीक्षा से कोर्ट ने महसूस किया कि शायद उनके द्वारा दिए गए फैसले में 'वन' की कानूनी परिभाषा अस्पष्ट है। राज्य रिकॉर्ड और पर्यावरणीय वास्तविकता में विरोधाभास है। साथ ही आदेशों का अतिविस्तृत प्रयोग कानूनी अराजकता पैदा कर सकता है। अतः बिना किसी अहं को आड़े आने का मौका दिये सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही आदेशों के क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक लगा दी। हालांकि यह फैसले को पलटना नहीं बल्कि रि-ट्यूनिंग है। लेकिन इसे न्यायिक अस्थिरता नहीं कहा जा सकता। आलोचक भले कहें, 'अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर रोक लगाएगा, तो कानून का भरोसा कैसे बचेगा?' लेकिन असल में यह इतना श्याम-श्वेत मामला नहीं है। क्योंकि भरोसा फैसलों की जड़ता से नहीं बल्कि उनके न्यायपूर्ण होने से बनता है। अरावली में यदि कोर्ट बिना स्पष्टता के आगे बढ़ता तो आशंका थी कि संरक्षण के न्याय पर अन्याय होता और कहीं विकास के नाम पर विनाश।

इसलिए कोर्ट ने इस पूरे मामले की पुनर्समीक्षा करने के लिए अपनी सुनवाई आदेशों पर रोक लगा दी है। इन दोनों मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की यह कार्यवाई, उसकी परिपक्वता और बिना किसी अहं को आड़े आने देते हुए न्याय के लचीलेपन को बरकरार रखने की हिम्मत का द्योतक है। अतः सुप्रीम कोर्ट के इन दोनो निणार्यो की अगली सुनवाई तक सरहाना और सम्मान किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक संस्था वो होती है, जो कभी यह न माने कि वह गलत भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट जब अपने ही निर्णयों की पुनर्समीक्षा करता है, तो वह स्वयं को संविधान से ऊपर नहीं बल्कि संविधान के दायरे में रखने की पुष्टि करता है। यह न्यायिक विनम्रता ही नहीं बल्कि यही न्याय की असली ताकत है।

# नाबालिगों के साथ यौन हिंसा बनी वैश्विक महामारी

विडम्बना/ ज्ञान चंद पाटनी

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में दसवीं कक्षा की एक छात्रा ने छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पिछले दिनों गुजरात के राजकोट जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना भी सामने आई थी। वहां 6 साल की एक बच्ची के साथ जिस तरह ही हैवानियत हुई, उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। दरिंदे ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड तक डाल दी थी। मामला सामने आने के बाद दिल्ली के निर्भया कांड से जुड़ा खौफनाक घटनाक्रम एक बार फिर लोगों के जेहन में ताजा हो गया था। नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण के बढ़ते मामलों ने अब महामारी का रूप ले लिया है। इससे जुड़े आंकड़े भयावह हैं और मानवता को शर्मसार करने वाले हैं।

ये आंकड़े हर संवेदनशील व्यक्ति को हिला कर रख देते हैं। 'द लैंसेट' पत्रिका की 2023 ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की एक अरब से ज्यादा महिलाओं ने बचपन में यौन हिंसा का काला साया झेला है। लगभग 60.8 करोड़ महिलाएं अपने अंतरंग साथी से शारीरिक व यौन हिंसा की शिकार हुईं। उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां सामाजिक रूढ़ियां, गरीबी, युद्ध और कमजोर कानूनी ढांचे की वजह से ऐसी हिंसा बहुत ज्यादा हो रही है।

बचपन में यौन शोषण न केवल शारीरिक आघात पहुंचाता है बल्कि आजीवन मानसिक घाव छोड़ जाता है। अवसाद, पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, नशे की लत, सिजोफ्रेनिया और आत्महत्या की प्रवृत्ति इसके प्रमुख परिणाम हैं। रिपोर्ट बताती है कि हिंसा झेलने वाली लड़कियों में एक दर्जन से अधिक प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं। यह मामला सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरी मानव जाति का मामला है।भारत भी इस महामारी से अछूता नहीं है। लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 के आंकड़ों के हिसाब से यहां 30 प्रतिशत से अधिक लड़कियों ने बचपन में यौन हिंसा को झेला। यही नहीं 13 प्रतिशत लड़के भी यौन हिंसा के शिकार हुए। साथ ही 23 प्रतिशत महिलाएं पार्टनर की हिंसा की शिकार हुईं। भारत में नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के भयावह मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। ये घटनाएं कानूनी कमियों, समाज की संवेदनहीनता और जांच एजेंसियों की विफलता को उजागर करती हैं। जैसा कि राजस्थान की ताजा घटना के मामले में हुआ।

छात्रा से छेड़छाड़ हुई, विरोध किया तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की। शिकायत करने पर पुलिस ने कार्रवाई भी नहीं की। हताशा में लड़की ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ऐसे गंभीर मामलों में भी कार्रवाई करने में लापरवाही करेगी तो बदमाशों के हौसले बुलंद ही होंगे। जहां तक कानून की बात है भारत में बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए पॉक्सो अधिनियम लागू है। पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें भी स्थापित की गई हैं, ताकि मामलों का तेज और प्रभावी ढंग से निपटारा किया जा सके। इसके बावजूद लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह, दहेज प्रथा और जातिगत भेदभाव से भी इस तरह की हिंसा और शोषण को बढ़ावा मिलता हैं। यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं के पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसमें इंटरनैट, मोबाइल और अश्लील सामग्री की सहज उपलब्धता भी है। इंटरनैट पर फैली हुई अश्लीलता दिमाग विकृत कर रही है। मोबाइल और इंटरनैट के माध्यम से समाज में नैतिक पतन हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से अनजान लोगों से भी संपर्क बढ़ जाता है। बच्चों पर नजर रखना मुश्किल हो गया है। अब कोई किसी की परवाह नहीं करता। सारी वर्जनाएं टूट रही हैं। इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने आग में घी का काम किया है। बचपन में यौन शोषण आजीवन अभिशाप बन जाता है। पीड़ित लड़कियां अवसाद में आ जाती हैं। उनमें एचआईवी का जोखिम बढ़ जाता है।

कई बच्चियां स्कूल जाना बंद कर देती हैं। वे गरीबी के चक्र में भी फंस जाती हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाने की जरूरत है। ऐसे मामलों में पॉस्को कानून के तहत शीघ्र कार्रवाई के साथ घटना से जुड़े साक्ष्य ठीक तरह से इकत्र किए जाएं, ताकि अपराधी बच नहीं सके। शेल्टर होम और पीड़िता के लिए लीगल एड जैसी व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही बच्चियों को गुड टच–बैड टच के बारे में स्कूलों और घरों में समझाया जाए। गलत हरकत के बारे में तुरंत शिकायत करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए। लड़कियों को सैल्फ डिफैंस और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सामाजिक सुधार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बाल विवाह उन्मूलन पर ध्यान देने के साथ पुरुषों की मानसिकता बदलने की भी आवश्यकता है।

साथ ही साथ युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चोट करना होगा। कानूनी ढांचे को मजबूत करने के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। इस तरह की हिंसा से निपटना न केवल मानवाधिकार, बल्कि एक जरूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला भी है। इस समस्या पर ध्यान देने से लाखों लोगों की जान बच सकती है और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी कम हो सकती हैं। देवियों की पूजा करने वाले भारत में भी नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार–यौन शोषण के बढ़ते मामले हमारी कथनी–करनी के अंतर को उजागर करते हैं।

इसके लिए समाज, सरकार, परिवार–सभी जिम्मेदार हैं। यौन हिंसा को रोके बिना हम सभ्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। इस महामारी को खत्म करना आवश्यक है। इसके लिए सबसे जरूरी है पुलिस ऐसे मामलों में जीरो टॉलरैंस की नीति अपनाए। मामला संज्ञान में आने पर तुरंत कार्रवाई करे जिससे बदमाशों के हौसले पस्त हों। छेड़छाड़ जैसी शिकायतों को भी गंभीर माना जाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि पीड़िता का आत्मविश्वास बना रहे और वह निडर होगा बदमाशों के खिलाफ खड़ी हो सके। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में छात्रा ने आत्महत्या करके पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि नाबालिग लड़कियों को बदमाशों से बचाने का शोर तो बहुत होता है लेकिन जमीनी हालात में अभी खास परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे माहौल में इस महामारी से निपटना कठिन लगता है।

# केरल में मजबूत हो रहा भाजपा का जनाधार

गत दिवस एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरल में एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधनों की मैच फिक्सिंग को खत्म करने की बात कही थी। इसे बेशक एक राजनीतिक बयान माना जा सकता है लेकिन केरल की राजनीति बयार इन दिनों भाजपा के लिए मुफीद नजर आ रही है। पिछले दिनों केरल के स्थानीय निकायों के चुनावों में जो नतीजे आए हैं, वो चौंकाने वाले हैं। अभी तक केरल का जो राजनीतिक परिदृश्य था, उसमें वहां पर वाम मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला संयुक्त मोर्चा ही मुख्य धारा के राजनीतिक दल थे। भाजपा को वहां पर एक अलग-थलग रहने वाला दल ही माना जाता था। यद्यपि गत लोकसभा चुनाव में केरल से भाजपा ने कन्नूर की एक सीट जीतकर और तिरुवनंतपुरम की लोकसभा सीट कम मतों से हारकर भाजपा ने राजनीतिक जगत में यह संदेश जरूर दे दिया था कि भाजपा अब केरल की मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी बनने के मुहाने पर खड़ी है।

लेकिन स्थानीय चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ के साथ भाजपा भी अब केरल में मुख्यधारा की पार्टी है। जैसा कि सभी को पता है कि तिरुवनंतपुरम में नगर निगम की 101 सीटों में 50 सीटें जीतकर जो करीब-करीब बहुमत के पास है, और इसमें कोई दो मत नहीं कि वह निर्दलीय सदस्यों के सहयोग से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम में कब्जा कर लेगी। प्रदेश में दूसरी जगहों पर भाजपा को उल्लेखनीय सफलता भले न मिली हो पर वोटरों का रुझान यह बताता है कि केरल में भी ईसाई मतों को भाजपा की ओर रुझान बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब केरल में भाजपा करीब-करीब तीसरी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है तो यह तय माना जाना चाहिए कि बंगाल की तरह केरल में भी वाम मोर्चा अप्रासंगिक होने के कगार पर है। ऐसा इसलिए संभव है कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति के चलते मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन उसे मुख्यधारा की राजनीति शक्ति बनाए रखेगा। दूसरी तरफ हिंदुओं के साथ ईसाई मतदाताओं के एक बड़े वर्ग के समर्थन के चलते यदि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत प्राप्त कर ले तो इससे कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं होनी चाहिए। लोगों की याददाश्त में कहीं-न-कहीं यह होना चाहिए कि त्रिपुरा में जब पहली बार भाजपा सत्ता में आई थी तो उसे 'शून्य से शिखर की यात्रा' ही कहा गया था। गौर करने की बात यह कि भारतीय राजनीति में दो मुख्य पार्टियों कांग्रेस और भाजपा को लेकर यू तो कई बुनियादी भिन्नताएं हैं, पर एक बड़ी बुनियादी भिन्नता यह कि जहां कांग्रेस प्रांत दर प्रांत क्रमशः सत्ता से बेदखल होती जा रही है, वही भाजपा क्रमशः क्रमशः सत्ता में आती जा रही है जिसके चलते कांग्रेस मात्र कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है, वहीं भाजपा अधिकांश राज्यों में सत्ता में है। यदि सत्ता में नहीं है तो पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों को छोड़कर या तो विपक्ष में है, या वहां पर उसकी मजबूत उपस्थिति है।

उभार/ वीरेन्द्र सिंह परिहार

उदाहरण के लिए तेलंगाना जैसे राज्य को देखा जा सकता है जहां भाजपा राज्य में मुख्य विपक्षी दल भले न हो, लेकिन गत लोकसभा में चुनाव में 17 में 8 सीटें जीतकर वह यह बता चुका है कि तेलंगाना में भी भाजपा सत्ता की दहलीज पर खड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे वह बंगाल में सत्ता के दरवाजे पर खड़ी है। यह भी सभी को पता होगा कि 25 वर्ष तक लगातार उड़ीसा की सत्ता में रहने वाले वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा, बीजद को सत्ता से अपदस्थ कर चुकी है।विचारणीय प्रश्न यह कि आखिर में ऐसी कौन-सी बड़ी वजह है कि दिनों-दिन पूरे देश में भाजपा का जनाधार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस का जनाधार छिटकता जा रहा है। निश्चित रूप से कमोबेश इसका एक बड़ा कारण जहां भाजपा एक तरह से परिवारवाद की बीमारी से मुक्त है, वहीं पर यह बड़ी सच्चाई है कि वर्तमान में देश का मतदाता यह मान चुका है कि कांग्रेस की तुलना में ही नहीं, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की तुलना में भी भाजपा एक बेहतर पार्टी है।

परिवारवाद से मुक्त होने के साथ जहां विकास का मापदंड है, वह बेहतर नतीजे दे रही है। इसके अलावा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि भाजपा का जहां राज है, वहां रामराज्य है परन्तु अवश्य कहा जा कहा जा सकता है कि वहां सुशासन की दिशा में प्रयास अवश्य दिखाई देता है। बड़ी बात यह कि भाजपा की चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें, वहां घोटाले की गूंज सुनाई नहीं पड़ती जबकि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों से शासित राज्यों में कुशासन और घोटाले आम तौर पर सुनने को मिलते रहते हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात भाजपा का हिंदुत्व, भारतीय संस्कृति के प्रति आग्रह और स्व के प्रति जागरण का प्रयास भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नैतिक दबाव के चलते भाजपा एक विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा की पार्टी सतत बनी हुई है। यही कारण है कि भाजपा का दिग्विजयी अश्व बीच-बीच में झटके भले खाता हो पर वह सतत आगे बढ़ता ही जा रहा है।

## कार्टून कोना

विश्वा मित्र

# महिलाओं के मोबाइल पर बैन-जब चौपाल संविधान के ऊपर बैठ जाए

फरमान/ बाबू लाल नागा

राजस्थान के जालोर जिले के जसवंतपुरा क्षेत्र के गाजीपुरा गांव में पिछले दिनों आयोजित एक सामाजिक पंचायत के पंच-पटेलों ने महिलाओं और बेटियों के लिए कैमरा युक्त मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। महिलाएं मोबाइल फोन को सार्वजनिक समारोहों के साथ-साथ पड़ोसियों के घर जाने के दौरान भी नहीं ले जा सकेंगी। यह पाबंदी किसी एक गांव तक सीमित नहीं है बल्कि 14 पट्टियों (उप-मंडलों) के अंतर्गत आने वाले 15 गांवों पर इसे लागू करने की तैयारी है। आगामी गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) से समुदाय की सभी महिलाओं और बेटियों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जालोर से आई ये खबर सिर्फ एक गांव की सामाजिक सनक नहीं है बल्कि यह उस खतरनाक मानसिकता का खुला प्रदर्शन है जो आज भी भारत के संविधान से ऊपर खुद को समझती है।

जाति पंचायत द्वारा महिलाओं के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर रोक लगाने का फरमान दरअसल तकनीक के खिलाफ नहीं, महिलाओं की आजादी, उनकी चेतना और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के खिलाफ एक सुनियोजित हमला है। यह फैसला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम 21वीं सदी के भारत में रह रहे हैं या फिर समाज का एक हिस्सा अब भी मनुवादी अंधकार में कैद है। मोबाइल फोन आज सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रह गया है। यह शिक्षा का दरवाजा है, रोजगार की संभावना है, सरकारी योजनाओं तक पहुंच का माध्यम है और सबसे बढ़कर महिलाओं के लिए सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का औजार है। जब पंचायत द्वारा महिलाओं से मोबाइल छीनने का आदेश दिया जाता है तो वह केवल एक पाबंदी नहीं लगाती बल्कि महिलाओं की आवाज, उनकी स्वतंत्र सोच और उनके नागरिक अधिकारों पर ताला लगाने की कोशिश करती है।

यह वही सोच है जो सदियों से महिलाओं को घूंघट, चूल्हा-चौका और खामोशी तक सीमित रखना चाहती रही है। इस फरमान के पीछे दिया गया तर्क भी उतना ही खोखला और पाखंडी है-कि मोबाइल से 'संस्कृति बिगड़ती है' और 'परंपरा खतरे में पड़ती है'। सवाल यह है कि क्या संस्कृति इतनी कमजोर होती है कि एक मोबाइल फोन से ढह जाए? या फिर सच्चाई यह है कि पुरुष वर्चस्व और जातिगत नियंत्रण की दीवारें दरकने लगी हैं और उसी डर में ऐसे फैसले सुनाए जा रहे हैं। संस्कृति के नाम पर महिलाओं की आजादी पर पहरा बैठाना दरअसल संस्कृति नहीं, सत्ता का संरक्षण है। भारत का संविधान महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देता है। समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार किसी पंचायत की दया पर निर्भर नहीं है। जाति पंचायत का यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 की खुली अवहेलना है। क्या देश में कानून का राज है या फिर गांव की चौपालें समानांतर अदालत बन चुकी हैं। सबसे विडंबनापूर्ण तथ्य यह है कि ऐसे हर फरमान में 'महिलाओं की इज्जत' का तर्क आगे किया जाता है लेकिन इज्जत का ठेका हमेशा महिलाओं के सिर पर ही क्यों?

पुरुषों के मोबाइल, उनके सोशल मीडिया, उनकी आजादी पर कोई सवाल नहीं उठता। यानी नैतिकता सिर्फ महिलाओं के लिए और छूट पुरुषों के लिए। यही दोहरा चरित्र भारतीय समाज की सबसे गहरी बीमारी है। जालोर की यह घटना कोई अपवाद नहीं है। इससे पहले भी देश के कई हिस्सों में खाप और जाति पंचायतें प्रेम विवाह, अंतरजातीय रिश्तों, महिलाओं के कपड़ों, आवाजाही और शिक्षा पर फरमान जारी करती रही हैं। अब नियंत्रण का नया हथियार मोबाइल बन गया है, क्योंकि मोबाइल सवाल पूछना सिखाता है, जानकारी देता है, डर की दीवारें तोड़ता है और यही पितृसत्तात्मक सत्ता को सबसे ज्यादा खलता है। अगर यही फैसला किसी शहर में होता, तो शायद तत्काल कार्रवाई होती। लेकिन ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों को अक्सर 'सामाजिक मामला' कहकर टाल दिया जाता है।

यह चुप्पी सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि इस अन्याय में मौन सहमति जैसी है। एक तरफ सरकारें 'डिजिटल इंडिया' और महिला सशक्तिकरण के बड़े-बड़े नारे लगाती हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर महिलाओं से डिजिटल साधन ही छीन लिए जाते हैं। क्या यही सशक्तिकरण है? अगर समाज को सुधारना है तो पाबंदी बाल विवाह, दहेज, घरेलू हिंसा, नशे और बेरोजगारी पर लगनी चाहिए। इन मुद्दों पर पंचायतों की जुबान खामोश रहती है, क्योंकि वहां सवाल सत्ता और पुरुष वर्चस्व का होता है। महिलाओं पर नियंत्रण आसान है, इसलिए निशाना वही बनती हैं।

दैनिक सवेरा टाइम्स

सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक शीतल कुमार विज के स्वामित्व में, दैनिक सवेरा न्यूज एंड मीडिया नेटवर्क, एस.-9, इंडस्ट्रियल एरिया जालंधर से मुद्रित एवं डी.-55, प्रीत विहार, नई दिल्ली से प्रकाशित किया।

DELHIN/2013/53563

पोस्टल रजि. नं. PB-JL-058/25-27

फोन 0181-2370100, 4625005, 4626006, 4629009

समाचार (फैक्स) 0181-2224455

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा उनसे उत्पन्न समस्त विवाद जालंधर न्यायालय के अधीन होंगे।

C M Y K

**कल्पमेधा**

*अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं, तो पानी में कूदें। सूखी जमीन पर कोई भी कभी भी तैरने में आपकी मदद नहीं कर सकता।*

*– ब्रूस ली*

# उत्पीड़न के परिसर

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि कोई विद्यार्थी अपना भविष्य बेहतर बनाने के सपनों के साथ किसी कालेज में दाखिला ले और वहां परिचय के नाम पर होने वाली प्रताड़ना की वजह से उसकी जान चली जाए। उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह की रैगिंग के चलन पर पाबंदी है, लेकिन आज भी इसके बहाने अलग-अलग रूप में विद्यार्थियों को जानलेवा शक्ल में प्रताड़ित किए जाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। हिमाचल प्रदेश में एक छात्रा के साथ रैगिंग का जैसा मामला सामने आया है, उससे फिर यह सवाल उठा है कि किसी भी रूप में इस चलन का जारी रहना शिक्षा से लेकर समाज तक के कितने हित में है। साथ ही, तमाम सख्ती के बावजूद आज भी इस पर रोक क्यों नहीं लग सकी है? गौरतलब है कि धर्मशाला स्थित एक कालेज की तीन छात्राओं के खिलाफ रैगिंग और मारपीट, जबकि एक प्रोफेसर के विरुद्ध पीड़ित छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दर्ज मामले के मुताबिक, बीते 18 सितंबर को पिटाई और प्रताड़ना की वजह से पीड़ित छात्रा की हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।

इस घटना में शर्मनाक यह भी है कि कालेज के जिस प्राध्यापक को उत्पीड़न की घटना को रोकना चाहिए था, वह खुद भी छात्रा को प्रताड़ित करने में शामिल हो गया। इस घटना में संस्थान भी कठघरे में है, क्योंकि वहां का प्रबंधन रैगिंग के नाम पर होने वाली ऐसी हरकतों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा। हिमाचल प्रदेश में यह कोई पहली घटना नहीं है, जिसमें किसी विद्यार्थी को रैगिंग की वजह से जानलेवा हद तक यातना दी गई। करीब डेढ़ दशक पहले राज्य में कांगड़ा के एक कालेज में मेडिकल पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्र अमन काचरू के साथ वहीं के चार वरिष्ठ छात्रों ने रैगिंग के दौरान मारपीट की थी, जिसके बाद उसकी जान चली गई थी। ऐसी कई घटनाओं के जैसे त्रासद नतीजे सामने आए, उससे एक व्यापक बहस खड़ी हुई कि उच्च शिक्षण संस्थानों में नवागंतुक विद्यार्थियों की रैगिंग को क्यों नहीं तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। इसी क्रम में कानून के तहत शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर प्रतिबंध लगाए गए और खुद सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की किसी भी तरह की कोई घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख पर होगी।

यह समझना मुश्किल है कि कालेज में कुछ वरिष्ठ कहे जाने वाले विद्यार्थियों के भीतर नए विद्यार्थी को किसी भी रूप में प्रताड़ित करने के मानसिक ढांचे के स्रोत क्या हैं! क्या इसके पीछे किसी नवागंतुक विद्यार्थी के मनोबल को तोड़ देने की मंशा काम करती है? आपसी परिचय या सहजता के नाम पर किसी विद्यार्थी को इस हद तक प्रताड़ित करना कि वह उसके लिए जानलेवा साबित हो, क्या एक सामंती कुंठा का परिचायक नहीं है? अगर परिचय के नाम पर यातना देने के चलन को आपस में सहज होने के लिए सिर्फ मनोविनोद के रूप में देखा-जाना जाता है, तो क्या यह एक आपराधिक तरीका नहीं है, जिसमें कालेज में आए एक नए विद्यार्थी के मन पर गहरी चोट पहुंचती है, वह खुद को अपमानित महसूस करता है, उसकी पढ़ाई बाधित हो सकती है? इस क्रम में शारीरिक और मानसिक यातना दिए जाने की वजह से किसी विद्यार्थी की जान जाने की घटनाएं अक्सर व्यापक चिंता का कारण बनती रही हैं और इस पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए।

# असुरक्षित सफर

जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो यह व्यवस्था में एक गहरी और चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। इससे आमजन में असुरक्षा, निराशा और अविश्वास की भावना पैदा होना स्वाभाविक है। अगर कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने लगें, तो सुरक्षा और न्याय की उम्मीद किससे की जाए! बिहार में एक ऐसी ही चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें करीब डेढ़ करोड़ रुपए के सोने की लूट की जांच कर रहा राजकीय रेलवे पुलिस का अधिकारी ही मामले में संलिप्त पाया गया। इस बात का खुलासा तब हुआ, जब पटना रेलवे पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष जांच दल ने गहन तहकीकात की। हैरत की बात है कि जिस अधिकारी को रेल में सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वही अपराधियों की जमात में खड़ा पाया गया। ऐसे में यह सवाल और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि व्यवस्था में पनप रहे इस तरह के भ्रष्टाचार और अपराध के दरख्तों को खाद-पानी कहां से मिल रहा है?

गौरतलब है कि कोलकाता स्थित एक स्वर्ण कारोबारी के कर्मचारी ने बिहार के गया रेल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि गत वर्ष नवंबर में हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस रेल में यात्रा के दौरान गया स्टेशन पर पुलिस वर्दी में चार लोग ट्रेन में सवार हुए। पहले उन्होंने सोने को लेकर उनसे पूछताछ की और बाद में वे एक किलो सोने के बिस्कुट लेकर फरार हो गए। इसके बाद गया रेल थाना प्रभारी ने जांच शुरू की। जाहिर है कि जब लूट में शामिल पुलिस अधिकारी ही जांच कर रहा हो, तो सच सामने आने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। भारतीय रेल आए दिन अलग-अलग बहाने से किराए में बढ़ोतरी करने या अधिक पैसे वसूलने में तो कोई संकोच नहीं करती, लेकिन यात्रियों के सुरक्षित और सुविधाजनक सफर को सुनिश्चित करने में शायद उसकी कोई रुचि नहीं है। विडंबना यह है कि यात्रियों के सामने आपराधिक तत्त्वों के अलावा अब वैसे लोगों से भी खुद को बचाने की चुनौती है, जो उनकी सुरक्षा के लिए ही तैनात किए जाते हैं।

# कोहरे की मुश्किल और सड़क सुरक्षा

**इसमें दोराय नहीं कि कोहरा सड़क सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सबसे भ्रामक और खतरनाक परिस्थितियों में से एक है। हर वर्ष सर्दी में घना कोहरा भीषण हादसों का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना अब एक तकनीकी जरूरत बन चुकी है।**

## नृपेंद्र अभिषेक नृप

कोहरा सड़क सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सबसे भ्रामक और खतरनाक प्राकृतिक परिस्थितियों में से एक है। भारी वर्षा या तूफान की तरह कोहरा शोर या तीव्रता के साथ नहीं आता, बल्कि यह चुपचाप वातावरण को अपनी चादर में ढक लेता है। यह दृश्यता को अत्यधिक कम कर देता है, दूरी के आकलन में भ्रम पैदा करता है और मनुष्य की प्रतिक्रिया क्षमता को धीमा कर देता है। हर वर्ष, विशेषकर उत्तर भारत में सर्दी के महीनों के दौरान घना कोहरा राष्ट्रीय राजमार्गों, शहरी सड़कों और ग्रामीण मार्गों पर भीषण हादसों का कारण बनता है। कई वाहनों की एक साथ टक्कर, खड़े वाहनों से टकराव, तथा बसों, ट्रकों और निजी वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाएं अब लगभग रोजमर्रा की बात हो गई हैं। ऐसे में कोहरे के दौरान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना एक तकनीकी जरूरत बन चुकी है।

कोहरे से होने वाली दुर्घटनाओं के घातक होने का एक मुख्य कारण दृश्य संकेतों का अचानक गायब हो जाना है। चालक वाहन चलाते समय दूरी, गति और सड़क की दिशा का अनुमान लगाने के लिए मुख्य रूप से अपनी दृष्टि पर निर्भर रहता है। जब कोहरे के कारण दृश्यता कुछ मीटर तक सीमित हो जाती है, तो अनुभवी चालक भी समय पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज गति से चलने वाले वाहन अक्सर धीमी गति से चल रहे या सड़क किनारे खड़े वाहनों, अवरोधकों या पैदल यात्रियों से टकरा जाते हैं। ऐसी सूरत में पीछे से आने वाले चालक आगे की स्थिति को समय रहते नहीं देख पाते, जिससे शृंखलाबद्ध टक्कर होती हैं। रात के समय यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जब अंधेरा और कोहरा मिलकर वाहनों की साधारण रोशनी को निष्प्रभावी बना देते हैं और कई बार प्रकाश का परावर्तन दृश्यता को और खराब कर देता है।

इस संकट में तकनीकी कमियां भी हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। कई राष्ट्रीय राजमार्गों सहित देश की अधिकांश सड़कों पर दृश्यता बढ़ाने वाली आधुनिक संरचनाओं का अभाव है। सड़क पर बनी परावर्तक रेखाएं उचित रखरखाव के अभाव में जल्दी फीकी पड़ जाती हैं। संकेतक बोर्ड या तो परावर्तक नहीं होते या धूल, मिट्टी और झाड़ियों से ढके रहते हैं। हालांकि, नियमों के अनुसार वाहनों में 'फाग लैंप' होना चाहिए, लेकिन बड़ी संख्या में वाहनों में ये या तो लगे नहीं होते या काम नहीं करते हैं। जहां तकनीक उपलब्ध है, वहां भी उसका प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित निगरानी और चालकों में जागरूकता की भारी कमी देखने को मिलती है। उपलब्ध समाधानों और जमीनी हकीकत के बीच की यही खाई लगातार लोगों की जान ले रही है।

आधुनिक तकनीक कोहरे से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए कई प्रभावी उपाय प्रदान करती है। 'इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम' (आइटीएस) इस दिशा में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है। ये प्रणालियां सेंसर, कैमरे और वास्तविक समय के आंकड़ों की सहायता से मौसम तथा यातायात की स्थिति पर लगातार निगरानी रखती हैं। परिवर्तनीय संदेश संकेतक बोर्ड चालकों को आगे कोहरे की तीव्रता की जानकारी दे सकते हैं, गति कम करने की सलाह दे सकते हैं और दुर्घटना या जाम की चेतावनी भी दे सकते हैं। विकसित देशों में व्यस्ततम राजमार्गों पर कोहरे की सघनता का पता लगाने वाले सेंसर लगाए गए हैं, जो अपने आप

चेतावनी संकेत सक्रिय कर देते हैं और वाहनों की गति सीमा को समायोजित कर देते हैं। यदि भारत के कोहरा-प्रभावित राजमार्गों पर ऐसी प्रणालियां स्थापित की जाएं, तो दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

वाहन-आधारित तकनीकें भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं। 'एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम' जैसे- स्वतः आपातकालीन ब्रेकिंग, लेन से बाहर जाने की चेतावनी और अनुकूल क्रूज कंट्रोल, कम दृश्यता और धीमी मानवीय प्रतिक्रिया की भरपाई कर सकते हैं। इंफ्रा-रेड कैमरे और थर्मल इमेजिंग प्रणाली, जो विदेश में महंगे वाहनों में पहले से उपयोग हो रहे हैं, वे दृश्य सीमा से परे बाधाओं और जीवित प्राणियों का संकेत दे सकते हैं। हालांकि, वर्तमान में इस तरह की तकनीक महंगी हैं, लेकिन सरकारी प्रोत्साहन और चरणबद्ध नीति के माध्यम से इन्हें ट्रकों और बसों जैसे वाणिज्यिक वाहनों में लागू किया जा सकता है, जो अक्सर बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। सड़क की रूपरेखा और आधारभूत संरचना को भी जलवायु की वास्तविकताओं के अनुरूप विकसित करना होगा।

> **जन-जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है। नागरिकों को यह समझना होगा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक साझा दायित्व है। जनसंचार माध्यमों, सामाजिक मंचों और स्थानीय अभियानों के माध्यम से लोगों को कोहरे के खतरों तथा सावधानी बरतने के महत्त्व के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेना, घने कोहरे में अनावश्यक रात्रि यात्रा से बचना और वाहन की तकनीकी स्थिति सुनिश्चित करना जैसे छोटे कदम भी कई जिंदगियां बचा सकते हैं। स्वच्छ ईंधन, उत्सर्जन नियंत्रण और सतत शहरी नियोजन के माध्यम से प्रदूषण कम करना भी दृश्यता सुधारने में सहायक हो सकता है।**

राजमार्गों की योजना बनाते समय कोहरा-प्रवण क्षेत्रों को विशेष ध्यान में रखना आवश्यक है। उचित जल निकासी, सड़क किनारे परावर्तक संकेत, प्रकाशित लेन चिह्न और 'रंबल स्ट्रिप्स' कम दृश्यता में भी चालकों को साफ संकेत प्रदान कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले एलईडी स्टड, जिन्हें सड़क में लगाया जाता है, वे कोहरा भरी रातों में लेन और मोड़ों को स्पष्ट रूप से दर्शा सकते हैं। ओवरब्रिज, अंडरपास और दुर्घटना-प्रवण हिस्सों पर बेहतर रोशनी तथा स्पष्ट संकेतक अनिवार्य होने चाहिए। बुनियादी ढांचे की योजना में मौसम संबंधी आंकड़ों को शामिल करना होगा, कोहरे को एक अपरिहार्य मौसमी समस्या मानकर छोड़ देने से मसला हल नहीं होगा। मानवीय व्यवहार इस पूरी समस्या में निर्णायक भूमिका निभाता है। कई चालक कोहरे में भी असुरक्षित गति से वाहन चलाते हैं, वे या तो खतरे को कम आंकते हैं या अपनी क्षमता को अधिक समझते हैं। चालक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोहरे में सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने की विशेष तकनीकों पर जोर दिया जाना चाहिए।

राजमार्गों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों, सड़क किनारे अतिक्रमण और अनधिकृत ढाबों की समस्या का समाधान भी जरूरी है, क्योंकि ये अचानक रुकावटें पैदा करते हैं और कोहरे में जानलेवा साबित होते हैं। ऐसे में कोहरे से जुड़ी सड़क सुरक्षा के लिए एकीकृत योजना, डेटा साझा करने और समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र की आवश्यकता है। आपातकालीन सेवाओं को हादसों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें एंबुलेंस, क्रेन और चिकित्सा सुविधाओं की त्वरित उपलब्धता शामिल हो। बचाव कार्य में देरी अक्सर उन दुर्घटनाओं को भी घातक बना देती है, जिनमें लोगों की जान बचाई जा सकती है।

जन-जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता भी उतनी ही आवश्यक है। नागरिकों को यह समझना होगा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक साझा दायित्व है। जनसंचार माध्यमों, सामाजिक मंचों और स्थानीय अभियानों के माध्यम से लोगों को कोहरे के खतरों और सावधानी बरतने के महत्त्व के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेना, घने कोहरे में अनावश्यक रात्रि यात्रा से बचना और वाहन की तकनीकी स्थिति सुनिश्चित करना जैसे छोटे कदम भी कई जिंदगियां बचा सकते हैं। वायु प्रदूषण कोहरा घना करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे दृश्यता और भी कम हो जाती है। स्वच्छ ईंधन, उत्सर्जन नियंत्रण और सतत् शहरी नियोजन के माध्यम से प्रदूषण कम करना दृश्यता सुधारने में सहायक हो सकता है। कोहरे से होने वाली सड़क दुर्घटनाएं प्रकृति की देन नहीं हैं, बल्कि तकनीक को अपनाने में कमी, आधारभूत संरचना की कमजोर योजना, ढीले प्रवर्तन और जन-जागरूकता के अभाव का परिणाम है। कोहरे में दृश्यता बढ़ाना एक बहुआयामी चुनौती है, जिसके लिए तकनीकी नवाचार, सशक्त शासन, जिम्मेदार तरीके से वाहन चलाना और सामाजिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। प्रकृति को नियंत्रित करना संभव नहीं है, लेकिन उसके खतरों का प्रबंधन अवश्य किया जा सकता है।

# पीड़ा के स्तर

**दुनिया मेरे आगे**

## रेखा शाह आरबी

कई बार लोग कहते हैं कि हम आपको समझते हैं... आपकी पीड़ा, आपके दुख और तकलीफ, भावनाओं को समझते हैं। ऐसे शब्द अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। कई बार हमारे बहुत करीबी, रिश्ते-नातेदार अपनी निकटता दिखाने के लिए कहते हैं कि हम आपके दुख, आपकी पीड़ा को समझते हैं। उनका यह कहना वास्तव में मात्र जुबानी जमा खर्च होता है, जिसे कोई भी किसी को सांत्वना देने के लिए आमतौर पर औपचारिकता निभाने की खातिर कह देता है। हालांकि ऐसा कहना एक तरह की कठोरता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सच यही है। अगर हम एक इंसान के रूप में थोड़े-से संवेदनशील हैं, तो हम किसी के दुख के प्रति भावुक हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके दुख से हम थोड़े बहुत दुखी भी हो जाएं, पर पूरी तरह किसी के दुख, पीड़ा, मर्म को समझ पाना लगभग असंभव है। एक हद तक अगर संभव है भी, तो यह तब हो पाता है, जब कोई व्यक्ति खुद उसी के बराबर की पीड़ा से गुजरा होता है।

किसी को समझना और किसी की पीड़ा की गहराई में उतरना क्या आसान है? इंसान का दुख एक अंधेरे गहरे कुएं की तरह होता है। उस अंधेरे और गहराई में कितनी तहें हैं, यह कोई नहीं जानता है। बाहर से देखने पर कुछ और लगता है और अंदर उतरने पर कुछ और भी हो सकता है। और जब कोई चीज दिखाई ही नहीं दे रही, तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, सौ फीसद क्या है, यह हम नहीं बता सकते। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी के दुख के कुएं में कूद जाएं। जाने के लिए भावनाओं की एक पूरी नदी पार करनी पड़ती है। अपनत्व की सीढ़ी बनानी पड़ती है। संवेदना से अपनी हृदय-भूमि को सिंचित करना पड़ता है। उसके बाद एक-एक सीढ़ी उतरना पड़ता है। वह भी बेहद संभल-संभल कर, तब जाकर कहीं नीचे तक हम पहुंचने की राह मिल पाती है। अगर हम जरा भी जल्दबाजी और अनमनापन दिखाते हैं, तो आधे रास्ते से वह सीढ़ियां गायब हो जा सकती हैं और वहीं से हमें वापस आना पड़ जा सकता है।

> **किसी को समझना और पीड़ा की गहराई में उतरना क्या आसान है? इंसान का दुख एक अंधेरे गहरे कुएं की तरह होता है। उस अंधेरे और गहराई में कितनी तहें हैं, यह कोई नहीं जानता है। बाहर से देखने पर कुछ और लगता है और अंदर उतरने पर कुछ और भी हो सकता है।**

जुबान भले ही कुछ भी कहे, लेकिन वास्तव में देखा जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई किसी की पीड़ा को पूरी तरह से समझ ले। जिस रूप में व्यक्ति पीड़ा को भोग रहा है, उसी रूप में, उन्हीं भावनाओं के साथ कोई महसूस कर ले। क्या यह संभव है? अपने पांव पर चलने वाला पूरी तरह स्वस्थ इंसान साल भर से बिस्तर पर अशक्त रूप से पड़े हुए किसी इंसान के मन के दुख को किस तरह समझ सकता है। पूरी तरह स्वस्थ तो छोड़ दिया जाए, जो उस अवस्था से गुजर रहा है, वह व्यक्ति भी उस व्यक्ति की पीड़ा को सौ फीसद नहीं समझ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों की परिस्थितियां अलग हों। हम किसी की पीड़ा का मात्र कुछ अंश ही समझ सकते हैं, पूरी तरह समझना असंभव है, क्योंकि जो व्यक्ति पीड़ा भोग रहा है, वह पूरे समय इस दुख में जीता है। और जो व्यक्ति समझने का दावा कर रहा है कि उसकी पीड़ा को समझ रहा है, वह मात्र उस व्यक्ति के समंदर-से दुख के मात्र एक कतरे को समझने का प्रयास कर रहा है। यह कतई संभव नहीं है कि हम एक पूरी किताब को एक पन्ना पढ़कर समझ जाएं। किसी के दुख को पूरी तरह या पर्याप्त गहराई के साथ समझने के लिए उस किताब को पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसी परिस्थिति में पढ़ना पड़ेगा और उसी अवस्था, भावना में पढ़ना पड़ेगा और उतना ही समय लेना पड़ेगा। तब जाकर हो सकता है कि कहीं हम किसी व्यक्ति की पीड़ा की तहों में पहुंच पाएं।

इसीलिए यह संभव नहीं है कि हम कितने भी संवेदनशील व्यक्ति हों, किसी के दुख को समझ सकते हैं। दुख-सुख दरअसल परिस्थिति, भावनाओं, अपनों के व्यवहार के अलावा भी बहुत सारी बातों के साथ मिलकर संगति करता है। एक पति-पत्नी बरसों साथ रहते हैं। एक खुशहाल परिवार के रूप में रहते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे की पीड़ा को पूरी तरह समझते हों। अक्सर हम लोगों को उतना ही समझते हैं, जितनी हमें आवश्यकता होती है। उसके बाद अन्यथा के रूप में छोड़ देते हैं। हर इंसान को हर रिश्ते में सबसे बड़ा दुख या फिर शिकायत यही होती है कि सामने वाला हमें समझ नहीं रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, अपने आप को यह बात समझा लेना चाहिए कि हमारे दुख को सौ फीसद कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि बहुत बार हम खुद नहीं समझ सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि दुख भी रूप बदलता रहता है।

यों भी, यह हम दूसरों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि दूसरा एकदम हमारे मन के अनुरूप हमारी बात, भावना, पीड़ा को समझ पाएगा। अगर कोई हमारी बातों को, भावनाओं को कुछ हद तक भी समझ जाता है, तो यह मान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को हमारी परवाह, हमसे लगाव और प्रेम है। उसे रिश्ते को प्रसन्नता के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। किसी की भावना, पीड़ा या दुख, किसी की समझ, सोच को समझना दरअसल एक जटिल, बेहद थकाने वाला काम है। भागती-दौड़ती इस दुनिया में यह उम्मीद करने की जरूरत नहीं है कि कोई हमें पूरी तरह समझ पाएगा, क्योंकि यह उम्मीद पालना ही एक नए दुख को जन्म दे देगा। और मन में कड़वाहट उपजेगा, वह अलग दुख होगा। थोड़े को ही पूरा मानना हमें सहज और सरल बनाएगा, जो सुखी मन से जीने के लिए जरूरी है।

## स्मृतियों में जखम

वर्ष 2025 कुछ ऐसे जख्म छोड़ गया है जो समय के साथ आसानी से नहीं भरने वाले। बीता साल एक ओर विज्ञान, कूटनीति, खेल और अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत का साक्षी बना, तो दूसरी ओर आतंक, तकनीकी विफलताओं, भीड़ प्रबंधन की चूक और सुरक्षा में सेंध ने पूरे राष्ट्र को भीतर तक झकझोर दिया। कश्मीर की शांत वादियों में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने मानवता को शर्मसार किया और यह एहसास कराया कि आतंकवाद का जहर समाप्त नहीं हुआ है। लालकिला के पास विस्फोट यह बताने के लिए काफी था कि खतरे केवल सीमाओं से नहीं, बल्कि समाज के भीतर छिपे षड्यंत्रों से भी पैदा होते हैं। बंगलुरु में आइपीएल जीत का उत्सव जिस तरह मातम में बदला, उसने साबित कर दिया कि खुशियों के क्षण भी अव्यवस्था के कारण त्रासदी बन सकते हैं, वहीं अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में तकनीकी उत्कृष्टता के दौर में भी प्रणालीगत चूक सामने आई। सवाल है कि क्या हम केवल प्रतिक्रिया देने वाला समाज बन कर रह गए हैं या समय रहते सीख लेकर भविष्य को सुरक्षित बनाने की इच्छाशक्ति भी रखते हैं।

*– विभूति बुपक्या, दिल्ली*

## अरावली की फिक्र

अरावली पर्वतमाला वैधानिक रूप से आरक्षित वन घोषित है। यह आज भी जैव-विविधता से भरपूर और वन्यजीवों का सुरक्षित आश्रय बनी हुई है। मगर दुर्भाग्यवश, इस पर्वत शृंखला का अधिकांश भाग संरक्षित वन की श्रेणी में रखा गया है जहां इसकी वानस्पतिक क्षमता, वन घनत्व और पारिस्थितिकी गुणवत्ता कमजोर होती चली गई है। दरअसल, संरक्षित वन के रूप में घोषित इन क्षेत्रों में संरक्षण और संवर्द्धन की गंभीर आवश्यकता है, न कि प्रयोग और दोहन की। विशेष रूप से हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अरावली पर्वत के साथ जिस प्रकार उपयोग के अनुसार समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी की गईं, उसने इसे दोहन की वस्तु बना दिया है। खनन, निर्माण, अवैध बसावट और विकास के नाम पर इसके प्राकृतिक स्वरूप को लगातार क्षति पहुंचाई है। अरावली को उसके मूल पारिस्थितिकी स्वरूप में बनाए रखने के लिए इसका संरक्षण विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य दायित्व होना चाहिए।

*– खुमानसिंह चुंडावत, मंदसौर*

## इंसाफ का संदेश

उन्नाव प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला केवल एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और शासन-तंत्र के लिए एक स्पष्ट संदेश है। शीर्ष न्यायालय ने रेखांकित किया है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, जवाबदेही से बच नहीं सकता। इस फैसले ने एक बार फिर यह साबित किया है कि पीड़ित को न्याय दिलाने में देरी स्वयं अन्याय के समान है। अदालत की सख्त टिप्पणियां दर्शाती हैं कि सत्ता, पद और राजनीतिक प्रभाव न्याय की राह में बाधा नहीं बनने चाहिए। ऐसे संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष जांच, गवाहों की सुरक्षा और पीड़ित को समयबद्ध राहत अत्यंत आवश्यक है। यह निर्णय केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि निवारक संदेश भी देता है। यदि कानून का डर और न्याय की गति बनी रहे, तो ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। अदालत का यह रुख आम नागरिकों के न्याय प्रणाली में विश्वास को मजबूत करता है।

*– सीपी शर्मा, रानी बाग, दिल्ली*

## प्रकृति के विरुद्ध

वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार वैश्विक ताप खतरनाक गति से बढ़ रहा है। यदि यही स्थिति लगातार बनी रही, तो इक्कीसवीं सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में लगभग छह डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। आज हाल यह है कि जलवायु परिवर्तन का असर हिमालयी ग्लेशियरों पर पड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन कर हमने विनाश की भूमिका स्वयं ही लिखी है। परिणामस्वरूप हिमनद पिघल रहे हैं। अत्यधिक वर्षा हो रही है, तो कभी बादल फट रहे हैं। यदि यही स्थिति रही, तो वर्ष 2040 तक हिमनद पिघल कर समाप्त हो सकते हैं। हिमनदों के पिघलने से रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी तथा प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और प्रकृति के बीच संतुलन आवश्यक है।

*– वेद प्रकाश, गुरुग्राम*

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

1917 की रूसी क्रांति ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। भारत में वामपंथी विचारधारा के विभिन्न संगठनों ने 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया। आधिकारिक तौर पर इस सम्मेलन को ही भाकपा की स्थापना माना जाता है। एसवी घाटे इसके पहले महासचिव थे। भाकपा ने ब्रितानी उपनिवेशवाद का मुखर विरोध किया, और पूर्ण स्वराज की मांग के साथ आजादी की लड़ाई में भाग लिया।

बेबाक बोल

अपना लहू यतीम था कोई रंग न ला सका
मुंसिफ सभी खामोश थे उज्र-ए-जफा के सामने
-खलीफ तनवीर

नफासत भरी उर्दू के साथ शुरुआत के बाद याद आ रहा ट्रकों के पीछे लिखा गया वाक्य-जलो, नहीं रीस करो। हरियाणवी या राजस्थानी में रीस करो का अर्थ होता है, गुस्से या जोश के साथ प्रतिस्पर्धा करो। इन दिनों विपक्षी दलों के नेताओं में प्रतिस्पर्धा लगी है संघ के सांगठनिक ढांचे की तारीफ करने की। इसके बाद उन नेताओं को दक्षिणपंथी मानसिकता का करार देकर इसे पार्टी की सफाई का अवसर बता दिया जाता है। नए साल की राजनीतिक लड़ाई में विपक्ष के लिए हम सड़क का ही शब्द 'रीस' दे रहे हैं। सत्ता को शक्तिशाली होते देख जलने से अच्छा है, जोश में मुकाबला करना। मुकाबला आप अपनी राजनीतिक विचारधारा के तहत ही करें। मुकाबले के बिना आप सियासी यतीम हो जाएंगे। नए साल में विपक्ष की चुनौतियों पर चर्चा करता बेबाक बोल।

# सियासी यतीम!

**मुकेश भारद्वाज**

वर्ष 2025 दो विपरीत राजनीतिक विचारधाराओं के सांस्थानिक जन्म का शताब्दी वर्ष था। पहली संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरी संस्था है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।

जब संघ अपनी स्थापना के सौ साल मना रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से लगातार सत्ता में है। सत्ता, यानी शक्ति। इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आकर्षण शक्ति के प्रति होता है। मौजूदा शक्तिशाली से कोई कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य शक्तिशाली बनना ही होता है। मानव अस्तित्व का संघर्ष ही अशक्त से सशक्त बनने का रहा है।

एक ही समय में दो विचारधाराओं का शताब्दी वर्ष, लेकिन पूरी सियासी जमात का आकर्षण सिर्फ उस संस्था की तरफ हो रहा है, जिसे मौजूदा सत्ता की पितृ-संस्था कहा जाता है। उसकी चमक और धमक के आगे अन्य राजनीतिक शक्तियां धूमिल सी हो गई हैं।

दक्षिण और वाम, इन दो विचारधाराओं के मध्य में तीसरी विचारधारा भी है, जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। 2014 के बाद से ही कांग्रेस अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। राजनीति के मैदान में एक बार शक्तिहीन होने के बाद आपका आकर्षण खत्म हो जाता है। आकर्षण सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में नहीं हैं। आकर्षण इसलिए भी खत्म हो रहा है कि विपक्ष के रूप में आपकी मौजूदगी शक्तिशाली नहीं है। यह सत्ता पक्ष की रणनीति रही कि वह विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़े। कांग्रेस ने इस स्थिति को झुक कर कबूल, कबूल, कबूल कर भी लिया कि उसे नकारात्मकता का प्रतीक बना दिया गया है।

लोकतंत्र की अवधारणा जितनी भी सहिष्णु हो, व्यावहारिक राजनीति में विचारधारा का अस्तित्व

असहिष्णु प्रवृत्ति की ही मांग करता है। एक समय था, जब भाजपा के दो नेता और दो सांसद पूरे देश में हम दो और हमारे दो का ताना सुनते थे। कांग्रेस, संघ और भाजपा के प्रति सहिष्णु होती गई और विचारधारा का मैदान खाली कर घोषणा भी कर बैठी कि 'हम दो और हमारे दो' वाले रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भाजपा व संघ ने न सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति की, बल्कि आगे भी विस्तार करना शुरू कर दिया। दो से आगे इतना बड़ा संयुक्त परिवार हो गया कि कांग्रेस से लेकर विपक्ष के कई दलों के नेता उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। विपक्षी दलों के नेता अपने एकल होते परिवार से डर रहे हैं।

गिलास आधा भरा है, या आधा खाली है वाले जुमले ने बीसवीं सदी में प्रेरणा देने का जो भार उठाया था, अब उसकी मियाद भी खत्म हो चुकी है। आज जिस तरह से राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण एकपक्षीय हो चुका है, वैसे में कांग्रेस के लिए जुमला भी नया गढ़ना होगा। पिछले दिनों मुंबई से लेकर कर्नाटक तक के निकाय चुनावों के परिणाम देख लीजिए। कांग्रेस निकाय स्तर पर भी लोगों का भरोसा नहीं जुटा पा रही है।

आज के दौर में कांग्रेस की राजनीतिक शक्ति का गिलास खाली है। गुरुत्वाकर्षण के वैज्ञानिक नियम के तहत उसे गिलास नीचे से ही भरना शुरू करना होगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने राजनीतिक शक्ति वापस पाने की कोशिश ही नहीं की है। अगर राजनीति को विज्ञान माना जाए तो कांग्रेस बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से गिलास को भरने की कोशिश कर रही है, यानी ऊपर से। अभी तक कांग्रेस का सारा राजनीतिक श्रम ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को निखारने में जुटा रहा। इसमें वह कामयाब भी हुई। राजनीति के मैदान में राहुल गांधी बहुत हद तक अपनी पहचान बना चुके हैं। लेकिन यह प्रक्रिया ही अवैज्ञानिक है तो राहुल गांधी को उसका नतीजा चुनावी जीत के रूप में नहीं मिल रहा है।

आज के दौर में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है देश के बड़े तबके से लेकर खुद कांग्रेसियों का संघ की तरफ आकर्षण। संघ के प्रति हर आकर्षित कांग्रेसी के सामने आने के बाद कांग्रेस इसे पार्टी की सफाई मानती है। संघ की तरफ यह आकर्षण इसलिए नहीं है, क्योंकि वह फलां समय में स्थापित फलां विचारधारा की संस्था है। संघ की तरफ आकर्षण की एकमात्र वजह है उसका राजनीतिक शक्ति में तब्दील हो जाना। जो शक्ति आपके अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट है, उसका जिक्र आपकी महफिल में होना ही है। अभी कुछ दिनों पहले डीके शिवकुमार ने कर्नाटक विधानसभा में संघ की प्रार्थना गाई, और हंगामा बरपा। शशि थरूर मौजूदा सत्ता के प्रति अपने आकर्षण को कई बार जाहिर कर चुके हैं।

ताजा मामला है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का, जो संघ की सांगठनिक क्षमता की तारीफ करने वालों की कतार में शामिल हुए। अब दिग्विजय सिंह को भी कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी विचारधारा का व्यक्ति करार दिया जा रहा है। यही वक्त है, जब कांग्रेस नेतृत्व को समझ लेना चाहिए कि असली राजनीतिक लड़ाई संगठन बनाम संगठन की ही होती है, यानी गिलास में नीचे भरे पानी की। कांग्रेस नेतृत्व को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए कि जब भी बाएं से उसकी कमियों के बारे में बात की जाएगी, तभी दाएं से संघ की तारीफ नमूदार हो जाएगी।

किसी भी पार्टी के लिए संगठन उसके अभिभावक की तरह होता है। बिना संगठन के राजनीतिक दल सियासी यतीम की तरह होते हैं। जनता को राजनीतिक दल की विचारधारा से संगठन ही जोड़ते हैं। चुनिंदा लोकप्रिय चेहरों के भरोसे राजनीतिक शक्ति नहीं हासिल की जा सकती है।

जिन वामपंथी दलों की पहचान ही संगठन होते थे, आज वे सबसे बड़े सियासी यतीम हैं। एक वह भी दौर था, जब आजादी के बाद हुए आम चुनाव में वामदल विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा था। आज वह दौर है कि केरल के अगले विधानसभा चुनाव में एलडीएफ हारा तो पूरे देश में कहीं भी वामपंथ का शासन नहीं रहेगा। एक समय पश्चिम बंगाल में लाल किले की पहचान रखने वाली माकपा को ममता बनर्जी की अगुआई में तृणमूल कांग्रेस ने क्या हराया, पार्टी अभी तक वहां हार माने बैठी है।

पिछले वर्षों में एक प्रवृत्ति यह भी देखी गई है कि एक बार सत्ता की शक्ति खोने के बाद राजनीतिक दल संघर्ष की राह पर लौटना ही नहीं चाहते। चाहे कांग्रेस हो या वाम दल, सभी व्यवस्था विरोधी माहौल के आने और उससे किसी चमत्कार हो जाने की उम्मीद में रहते हैं। इसलिए उनकी राजनीतिक शैली में दिखता भी सिर्फ व्यवस्था का विरोध है। जनता उन्हें सत्ता वाली व्यवस्था के विरोध में तो पाती है, लेकिन अपने साथ महसूस नहीं कर पाती है। किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा तक जनता खुद नहीं पहुंचती है। जनता तक पहुंचते हैं, राजनीतिक दलों के संगठन। जो विचारधारा जनता तक पहुंची, जनता उसी की हो जाती है। राजनीति-विज्ञान के रसायन की बात करें तो संगठन ही शक्ति है।

राजनीति में शक्ति को ही शुभ मानने की परंपरा है। वामपंथ भी सर्वहारा की शक्ति और सत्ता की ही बात करता है जो जनसंगठनों से ही संभव है। आज इंटरनेट के जमाने में उत्पादन के साधनों के साथ श्रमिकों का संबंध भी बदल गया है। नई समस्याओं से घिरी जनता की लड़ाई पुराने राजनीतिक औजारों से नहीं की जा सकती है।

मौजूदा सत्ता ने अपनी शक्ति का चौतरफा विकास कर लिया है। आज केंद्रीय सत्ता के पास देश के अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की शक्ति है। दोहरे इंजन के दौर में विपक्ष के लिए विकल्प कम हो रहे हैं। जनता जिस मुद्दे पर शक्तिहीन है, उस संघर्ष के क्षेत्र में उतरने के लिए शक्ति जुटाए बिना कांग्रेस हो या वाम, उनका बचा-खुचा आधार भी खत्म हो जाएगा। मौजूदा एक वर्ष में इस तरफ ईमानदारी से सक्रिय नहीं हुए तो 2027 की राजनीतिक तस्वीर आपको पूरी तरह सियासी यतीम के रूप में ही दिखाएगी। शक्ति खोना जितना मुश्किल है, उसे पाना उतना ही मुश्किल। कैलेंडर बदलते वक्त नहीं लगता। जुट जाइए बाधाओं से भरे संघर्ष के मैदान में।

## राजपाट

### भतीजे का सहारा

शरद पवार चिंतित हैं। उनका चिंतित होना स्वाभाविक भी है। अप्रैल में राज्यसभा का उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। विधानसभा में उनकी पार्टी के इस समय सिर्फ दस विधायक हैं। जबकि राज्यसभा की एक सीट के लिए 35 वोट चाहिए। राज्य में कुल सात सीटों का चुनाव होगा। विधानसभा के संख्याबल के हिसाब से

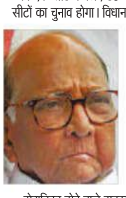

महायुति यानी सत्तारूढ़ गठबंधन का छह सीट जीतना तय है। विपक्ष को महज एक सीट मिल सकती है, वह भी तभी जब महाविकास अघाडी एकजुट रहे। अघाडी में उद्धव ठाकरे के 20 और कांग्रेस के 16 विधायक हैं। उद्धव का दावा प्रबल होगा। कांग्रेस के समर्थन से वे अपना एक उम्मीदवार जिता सकते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों में पवार के अलावा प्रियंका चतुर्वेदी, फौजिया खान और रजनी पाटिल हैं। महायुति के तीन सदस्यों में रामदास अठावले भी हैं। माना जा रहा है कि महायुति उन्हें फिर मौका देगी। रही शरद पवार की संभावना, तो उन्हें भतीजे अजित पवार का सहारा लेना पड़ेगा। महायुति में अपने हिस्से की राज्यसभा सीट अगर भतीजे ने चाचा को दी, तभी शरद पवार की मुराद पूरी होगी। शहरी निकाय चुनाव में जिस तरह चाचा-भतीजे ने हाथ मिलाया है, उसे देखते हुए भतीजे की मदद नामुमकिन नहीं। वैसे भी इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में परिवार के मिलन का समय है। ठाकरे परिवार भी अपने अस्तित्व के लिए एकजुट हो चुका है।

### बेघर धनखड़

जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से पिछले साल 21 जुलाई को त्यागपत्र दिया था। पांच महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, पर वे अभी तक बेघर हैं। दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर स्थित एक फार्महाउस में वे बतौर मेहमान रह रहे हैं, जो उनके पारिवारिक मित्र चौटाला परिवार का है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के बाद राजधानी में सरकारी आवास मिलता है। आमतौर पर उनके लिए आवास की व्यवस्था सेवानिवृत्ति से पहले ही हो जाती है, पर चूंकि धनखड़ ने त्यागपत्र अचानक दिया था लिहाजा उनके मामले में यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने अपने लिए सुनहरी रोड का 9 नंबर बंगला चाहा था, पर यह बंगला भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को आबंटित हो चुका है। धनखड़ की संजीदगी की दाद देनी होगी। अपने त्यागपत्र पर आज तक मुंह नहीं खोला, अन्यथा सरकार को असहज स्थिति में ला सकते थे।

### गफलत में राजनीतिक दल

निर्वाचन आयोग ने देश भर में मतदाता सूची की गहन जांच (एसआइआर) और जांच प्रक्रिया (एसआर) शुरू की है। इसे लेकर आम जनता ही नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक दलों के नेता भी फंस रहे हैं। कई राज्यों में एसआइआर की प्रक्रिया इतने लंबे समय बाद हो रही है कि स्थानीय दलों के पास इससे संबंधित प्रक्रियागत जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये दल बार-बार आयोग के सवालों के घेरे में फंस रहे हैं। वे कमरे के अंदर की बैठकों में अलग और बाहर के सियासी मैदान में अलग बातें उठा रहे हैं। इन नेताओं को अब आयोग ने यह कहकर फंसा दिया है कि मतदाता सूची पर राजनीतिक दलों की आपत्तियों की वजह से एक लंबे समय बाद आयोग को एसआइआर शुरू करना पड़ रहा है।

### नया विवाद

अंकिता भंडारी प्रकरण से उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आ गया है। अंकिता की 2022 में हत्या कर दी गई थी। वह एक रिसार्ट पर स्वगात विभाग की कर्मचारी थी। हत्या में तीन आरोपियों को अदालत से उम्रकैद की सजा हो चुकी है। रिसार्ट भाजपा के एक नेता का था। भाजपा की खूब बदनामी भी हुई थी। बहराल इस मामले का जिन्न तीन साल बाद फिर बोतल से बाहर आ गया है। भाजपा के एक पूर्व विधायक और उनकी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला उर्मिला की आडियो बातचीत ने इस मामले को गरम कर दिया है। इसमें भाजपा के एक दलित नेता और राष्ट्रीय महासचिव व सूबे के संगठन मंत्री के आचरण पर उंगली उठाई गई है। दोनों नेताओं ने इसे अपने चरित्र हनन का प्रयास बताया है। कांग्रेस को बैठे-बिठाए यह संवेदनशील मुद्दा मिल गया है। इस कांड की सीबीआइ जांच की मांग जोर पकड़ गई है। पूर्व मंत्री और भाजपा की कद्दावर महिला नेता विजया बड़थ्वाल ने भी मांग की है कि निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आए। भाजपा के कुछ नेताओं ने इस्तीफे भी दे दिए हैं। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले ने पहले ही भाजपा की किरकिरी करवाई थी। इस मुद्दे पर पूरे देश में आक्रोश फैला था और आम जनता कड़ी कार्रवाई की उम्मीद कर रही थी। मामले के नए मोड़ के बाद एक बार फिर से भाजपा को कई तर्क गढ़ने होंगे। उत्तराखंड की भाजपा सरकार कई मुद्दों के साथ अब इस पर भी घिरी है।

### बंगाल में शिव और शक्ति

अवैध घुसपैठियों से लेकर मुसलिम तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर भाजपा ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने का दांव चला है। ऊपर से हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करके भाजपा को नया मुद्दा दे दिया। कबीर तृणमूल कांग्रेस का प्रमुख मुसलिम चेहरा थे। ममता ने भाजपा के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कबीर को पार्टी से निकाल दिया। इतना ही नहीं, उन्हें हिंदू वोट बैंक की भी पूरी चिंता है। पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा के 'जय श्री राम' नारे को काली मां के हथियार से परास्त किया था। इस बार उन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवाया है। पांच जनवरी को सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की आधारशिला रखेंगी। उन्होंने कहा है कि वे ईद के कार्यक्रम में जाती हैं तो भाजपा को दिख जाता है, पर गुरुद्वारे में माथा टेकती हैं तो भाजपाई आंख बंद कर लेते हैं। इस बार ममता का पूरा ध्यान शिव और शक्ति की पूजा पर है, जिसकी संस्कृति बंगाल में गहरे तक पैठी है।

*संकलन : मृणाल वल्लरी*

## आपके पत्र

### अवाम-निजाम

किसी भी मुल्क के बदलते चेहरे के पीछे खड़ी तजुर्बेगाह में सियासत की मेज पर मेंढकों की तरह जकड़ी जनता मजहबी सुइयों की नई खुराक बर्दाश्त करने के लिए मजबूर है। सवाल इन तजुर्बों के नतीजों का है, जो नए हिंदुस्तान के ठप्पे में जम्हूरियत के चमचमाते डब्बों में दुनिया में पेश किए गए। सियासत के वार से हुए लहू-लुहान हिंदुस्तान से विश्वगुरु होने की हैसियत पाना यकीनन मुमकिन नहीं है। हर हार के लिए नेहरू की सालों बुझी राख आखिर कब तक कुरेदी जाएगी? मुमकिन और नामुमकिन के बीच चीखती अवाम और खामोश निजाम की हर गांठ को खोलता मजमून है 'नामुमकिन'। लहजे में मुलायमियत के बगैर कहने में कोई परेशानी नहीं कि पिछले कुछ सालों में मजहब के कुंड से उठी आग ने मुल्क को अपनी चपेट में ले रखा है। न केवल मुल्क के अंदर बल्कि पड़ोसी मुल्कों में अपने बाशिंदों तक ये लपटें पहुंच रही हैं। मजहबी भेदभाव की पटरी पर दौड़ती सियासत की बेबसी है कि पड़ोसियों के पांव तले कुचलते अपनों को खामोश नजरों से देखती रहे। 'दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं' कोई सियासी बयान नहीं बल्कि पत्थर की लकीर है। हैरानी की बात है कि हमने पड़ोसियों से दुश्मनी की खरीदारी में हमख्याल दोस्ती के खजाने भी गंवा दिए हैं। वे छोटे मुल्क जो हमारी अंगुलियां थामे बड़े हुए, पंजे हमारी गर्दन की तरफ बढ़ाने लगे हैं। इन पंजों के खतरे समझने में वक्त क्यों लग रहा?

**-एमके मिश्रा, रांची, झारखंड।**

### सामान्य समझ भी नहीं

मुमकिन-नामुमकिन को लेकर आज एक द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। कभी महापुरुषों की जीवनियों या 'एकता में बल है' जैसी बाल कथाओं में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने के शिक्षाप्रद संदेश पढ़ने-सुनने को मिलते थे। लेकिन अब 'एक रहेंगे सेफ रहेंगे' जैसे बोलों ने एकता के भी संदर्भ सीमित कर दिए। सवाल परेशान करने लगा कि वह मुमकिन आखिर है क्या! क्या यही जो हो रहा है? घृणा के प्रहारों से तार-तार होता सामाजिक सौहार्द, दोगलेपन की राजनीति, ढोंग और हुड़दंग से दूषित हो रही धार्मिकता? निरंतर बेकाबू होती जा रहीं ये स्थितियां विदेशों के साथ हमारे संबंधों को कटुतर बना रही हैं। बांग्लादेश हो, अन्य महाद्वीपों के देश हों, या फिर अपना ही देश क्यों न हो, अल्पसंख्यक हर कहीं हैं और अपनी गहरी जड़ों के साथ मौजूद हैं। दुख की बात है कि यह सामान्य-सी समझ भी अब जैसे नहीं बची।

**- शोभना विज, पटियाला, पंजाब।**

### सद्भाव का दें संदेश

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां विश्व भर के प्रमुख धर्मावलंबियों का बसेरा है। इसे लेकर बखेड़ा खड़ा करने की आदत त्याज्य होनी चाहिए क्योंकि मीडिया वैश्विक हो चुका है। इससे निकलने वाली हर तरह की खबरों की पहुंच बढ़ी है। ऐसे में सद्भाव वाली सांस्कृतिक छवि को नुकसान पहुंचने से विदेश नीति के प्रभावित होने के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा भारत को ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, जो पड़ोसियों के लिए ग्रहणशील हो। ऐसे सभी पड़ोसियों को यह आभास कराना जरूरी है कि भारत के साथ उनके संबंध बेहद जरूरी हैं। मगर ऐसा आभास कराते समय लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ख्याल रखना जरूरी है। दिलचस्प है कि जिस देश का जन्मदाता भारत है, वह इस अहसास को भूलकर भारत विरोधी अभियान में मशगूल है। संबंधित देश का जो राजनीतिक वर्ग ऐसा कर रहा है, उससे निपटने के लिए कूटनीतिक परिपक्वता जरूरी है।

**-मुकेश कुमार मनन, पटना।**

### आभासी आत्मप्रवंचना

अमेरिकी डालर के स्थापित ऐश्वर्य के समक्ष भारतीय रुपए का अनवरत रुदन राग धरातलीय दृष्टिकोण का यक्ष प्रश्न है कि क्या इस संक्रमण काल से उबरते हुए हम संसार की तृतीय अर्थव्यवस्था के नायक बन सकेंगे? इस सत्य से मुंह मोड़ने में देश के खजाने की लक्ष्मी यदि आत्ममुदित हैं तो फिर 'वचनम किम दरिद्रम' के आभासी इंद्रधनुष में ही भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारब्ध निहित दिख रहा है। सत्ता का चरित्र आज स्वीकार्य और नकार के मध्य वैचारिक द्वंद्व दरिया में ऊहापोह की मन:स्थिति में डूब रहा है क्योंकि उसकी भीतरी प्रतिबद्धता उजागर न हो जाए। पड़ोसी देशों से बिगड़ते हालात को नकारवाद से युक्त करने की मौन मंशा निश्चय ही वैदेशिक नीति-रीति की जड़ को निर्बलता प्रदान कर रही है, भले हम विश्व गुरु के काल्पनिक लोक में क्यों न विचरण करते रहें। विदेश नीति में यह नकारवाद यदि उसकी अक्षय पूंजी बन गई तो बुनियादी चिंतन अटल जी के पड़ोस एवं मित्र की मानक मान्यता के नीर क्षीर विवेचन का भी है। भारत के प्रभावी प्रतिरोध की अक्षमता के फलस्वरूप ही बांग्लादेश में हिंसक वृत्ति की लौ तेज हो रही है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की जगह मामले पर नजर रखने की खानापूर्ति के विदेश मंत्रालय के धीमे बयान से हालात खराब हो चुके हैं। हर मुमकिन परिस्थितियों को नामुमकिन के सांचे में ढलते रहने की जिम्मेदारी से हम मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि देश के भाग्य विधाताओं ने चाणक्य नीति के व्यावहारिक सूत्रों को विस्मृत कर आत्ममुग्धता और आत्म प्रवंचना की चादर ओढ़ रखी है। लेख निष्कर्ष में सत्यता का प्रतिबिंब है कि मानव मन दुविधा के प्रारब्ध से टकराने तक यथास्थिति का पालक बना रहता है। जीवन मर्म का एक पक्ष यह भी है कि हम कर्मवाद के कंटक मार्ग में भी साहस, संकल्प एवं सफलता की त्रिवेणी प्रवाहित करते रहें।

**-अशोक कुमार, पटना, बिहार।**

### ठोस हल निकले

भारत के बुद्धिजीवियों और अन्य लोगों को चाहिए कि वे कोई ऐसी बात बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के लिए न करें जिससे वहां रह रहे हिंदुओं के लिए मुश्किल बढ़ जाए। मीडिया को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। भारत को बांग्लादेश का माहौल खराब करने वाले लोगों को चेतावनी देनी चाहिए। भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाने में अब और देरी नहीं करनी चाहिए। दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित करके बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा तय करने के लिए बांग्लादेश सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए। सरकार कोशिश करे कि इस मसले का कोई ठोस हल निकले।

**-राजेश कुमार चौहान, जलंधर।**

### विशेष पन्ना कैसा लगा

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

# ममता की कमजोर स्थिति उजागर

पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, राजनीति भी करवट ले रही है। ये बदलाव खासकर हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के साथ नई पार्टी बनाने के ऐलान के बाद देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्थानीय जनता का झुकाव ममता को कमजोर कर रहा है। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर इस बार पार्टी का रुख आत्मविश्वास से भरा दिखने की बजाय आत्मरक्षा करता हुआ ज्यादा नजर आया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के पच्चीस वर्ष पूरे होने पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दुष्ट ताकतों के आगे नहीं झुकने का संकल्प तो दोहराया, लेकिन उनके शब्दों की तीव्रता के पीछे छिपी चिंता साफ महसूस की जा सकती थी। मां माटी मानुष के नारे के साथ शुरू हुई यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए ममता ने जनता के प्रेम और आशीर्वाद की बात कही, पर जमीन पर बदलते राजनीतिक हालात ने उनकी पार्टी के हर्षोल्लास की चमक को फीका कर दिया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ने ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। पार्टी को लोकतांत्रिक ताकत बताने और बंगाल विरोधी शक्तियों से लड़ने की बातें दोहराई गईं। परंतु यह भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार, हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा और प्रशासनिक विफलताओं के आरोपों ने तृणमूल की साख को गहरा आघात पहुंचाया है। स्थापना दिवस का भाषण भविष्य की रणनीति कम और बीते गौरव की याद अधिक प्रतीत हुआ। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय दौरा चुनावी अभियान का शंखनाद था। शाह ने घुसपैठ और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर तृणमूल सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने न केवल आरोप लगाए, बल्कि 2026 के चुनाव के लिए संगठन को स्पष्ट लक्ष्य और कार्ययोजना भी सौंपी। शाह की यात्रा का सबसे अहम संकेत यह रहा कि भाजपा ने अब बंगाल में संगठनात्मक ढांचे को कसना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ समन्वय, जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद, बंद कमरे की बैठकों में स्पष्ट निर्देश और पुराने नेताओं को फिर से सक्रिय भूमिका देना दर्शाता है कि भाजपा इस बार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कमर कस चुकी है। साथ ही दिलीप घोष को दोबारा आगे लाना पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश है। हम आपको बता दें कि अमित शाह ने ममता सरकार पर राज्य की जनसांख्यिकी बदलने, सिंडिकेट राज चलाने और उद्योगों को भगाने के आरोप लगाए। उन्होंने यह दावा भी किया कि बंगाल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है और अब बदलाव अपरिहार्य है। भाजपा ने दो तिहाई बहुमत का दावा कर राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सप्ताह में चार दिन क्षेत्र में रहने और रोज नुक्कड़ सभाएं करने का निर्देश इस बात का प्रमाण है कि भाजपा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। बंगाल में साफ दिख रहा है कि एक ओर जहां तृणमूल कांग्रेस सोशल मीडिया पर अपने संकल्प दोहरा रही है, वहीं भाजपा सड़क पर उतरकर रणनीति को अमल में लाने में जुट गई है। यही अंतर बंगाल की राजनीति की दिशा तय करता नजर आ रहा है। देखा जाये तो पश्चिम बंगाल की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। तृणमूल कांग्रेस आज सत्ता की थकान और आत्मसंतोष की शिकार दिख रही है। स्थापना दिवस के भाषणों में संघर्ष की बातें जरूर हैं, लेकिन उन शब्दों में वह धार नहीं दिखती जो कभी ममता बनर्जी की पहचान हुआ करती थी। दुष्ट ताकतों का जिक्र दरअसल अपनी कमजोरियों से ध्यान हटाने का प्रयास अधिक लगता है। लंबे समय तक सत्ता में रहने का बोझ अब तृणमूल पर साफ दिखने लगा है। भ्रष्टाचार के मामलों, संगठनात्मक ढीलापन, जमीनी कार्यकर्ताओं में असंतोष और जनता के रोजमर्रा के सवालों से कटाव ने पार्टी को रक्षात्मक बना दिया है। मां माटी मानुष का नारा आज भी दोहराया जा रहा है, लेकिन मानुष के मन में उठ रहे सवालों के ठोस जवाब तृणमूल के पास नहीं दिखते। इसके विपरीत भाजपा आक्रामक आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतर चुकी है। अमित शाह की यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी घुसपैठ, सुरक्षा, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दों को एक साथ जोड़कर तृणमूल कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। साथ ही संगठन को मजबूत करने पर जोर और अनुशासनात्मक निर्देश यह बताते हैं कि भाजपा ने पिछली गलतियों से सीख ली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने बंगाल में वैचारिक और संगठनात्मक दोनों स्तरों पर लड़ाई की तैयारी कर ली है। संघ के साथ तालमेल और पुराने चेहरों की वापसी यह संकेत देती है कि पार्टी अंदरूनी मतभेदों को पीछे छोड़कर एकजुट मोर्चा बनाना चाहती है। यह एक ऐसी रणनीति है जो तृणमूल के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। देखा जाये तो राजनीति में भावनात्मक भाषण तभी असर करते हैं जब उनके साथ ठोस काम और भरोसेमंद नेतृत्व हो। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस शब्दों के सहारे आत्मबल बढ़ाने की कोशिश में दिख रही है, जबकि भाजपा जमीन पर संगठन और मुद्दों के सहारे बढ़त बनाती नजर आ रही है। आने वाले महीनों में यदि तृणमूल ने आत्ममंथन नहीं किया और केवल विरोधियों को दोष देने की राजनीति जारी रखी, तो सत्ता की जमीन उसके पैरों से खिसक सकती है। बहराहल, पश्चिम बंगाल की लड़ाई अब केवल नारों की नहीं, बल्कि संगठन, विश्वसनीयता और भविष्य की दृष्टि की लड़ाई बन चुकी है। इस लड़ाई में फिलहाल पलड़ा भाजपा की ओर झुका हुआ दिख रहा है और तृणमूल को इस सच्चाई का सामना करना ही होगा।

### कटाक्ष | सुरेश मिश्र

*कोहरा के पहरा परल, तहरा नाइं बुझाइ*
*सहरा के तजि द्या पिया, गउवां रहल बुलाइ*
*गउवां रहल बुलाइ, सुना ननदी के भइया*
*नीक न लागइ सेज, काम उकसावइ दइया*
*कह सुरेश कविराय न होई घर मा सोहरा*
*कइसे लागइ जिया, पिया छाइल बा कोहरा*

# पश्चिम बंगाल में संस्कृति को बचाने की लड़ाई!

> बंगाल की घुसपैठ का असर असम, त्रिपुरा से लेकर बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी पड़ा है। इसलिए असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि घुसपैठियों के बंगाल द्वार को बंद करना देश के लिए बेहद जरूरी है। बंगाल में घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। अक्सर घुसपैठिए अवैध कारोबार में संलिप्त होते हैं। अवैध हथियार से लेकर नशे के कारोबार में इनकी भूमिका पाई जाती है।

बंगाल से लगातार हो रहे घुसपैठ और उसकी वजह से हो रहा डेमोग्राफी बदलाव देश के लिए खतरनाक है। बंगाल की संस्कृति और उसकी पहचान को इससे खतरा पैदा हो गया है। राजनीतिक संरक्षण में हो रहा ये घुसपैठ बंगाल चुनाव के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि इससे देश की सुरक्षा, संप्रभुत्ता जुड़ी हुई है। इसलिए भाजपा नेता बीएल संतोष ने देश को बचाने के लिए बंगाल चुनाव को जीतने पर बल दिया है। भाजपा नेता बीएल संतोष के अनुसार हमारे लिए बंगाल सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि एक सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। उनका मानना है कि भारत को बचाने के लिए बंगाल को बचाना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में डेमोग्राफी बदलावों को रोकना और हर हाल में सरकार बनाना उनका लक्ष्य है, जिसे वे भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। बीएल संतोष बंगाल चुनाव को सियासी लड़ाई से बढ़कर बंगाल की संस्कृति और पहचान को बचाने की लड़ाई से जोडकर देखते हैं। बंगाल में लगातार हिन्दुओं का पलायन हो रहा है। यहाँ कट्टरपंथियों द्वारा हिन्दु त्यौहारों का कई बार विरोध किया गया। कई बार दुर्गापूजा विसर्जन और मुहर्रम के जुलूस एक दिन होने पर विसर्जन की तारीख बदल दी गई। प्रशासन ने दुर्गापूजा उत्सव को कैंसिल कर दिया। यही हाल राम नवमी जुलूस पर भी रहा। कई जगहों पर हिंसा और झड़पें हुई। होली-दिवाली जैसे पर्व मनाने के दौरान भी कई बार विवाद हुए। मार्च 2025 में बसंत उत्सव के दौरान शांतिनिकेतन के सोनाझुरी हाट में पर्यावरण संरक्षण का हवाला देते हुए होली समारोह पर

प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस पर काफी बवाल भी हुआ। बंगाल में 2011 की जनगणना के मुताबिक, पूरे देश में हिन्दू आबादी घटी है। ये करीब 0.7 फीसदी कम हुई है जबकि पश्चिम बंगाल में हिन्दू आबादी 1.94 फीसदी घटी है। यहाँ मुस्लिम आबादी में 0.8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये तो 2011 के आंकड़े हैं। इससे पता चलता है कि राज्य में मुस्लिम की तुलना में हिन्दुओं की संख्या तेजी से घट रही है। इस बीच लगातार घुसपैठ बढ़ी है। ये घुसपैठिए बंगाल के गाँव में घुस कर अपनी पैठ जमा लेते हैं। धीरे धीरे टीएमसी के संरक्षण में पहचान पत्र प्राप्त कर लेते हैं और भारत का नागरिक बन जाते हैं। यही वजह है कि बंगाल में 2001 में मुस्लिम आबादी 25 फीसदी थी, जो 2011 में बढ़कर 27 फीसदी के पार जा चुकी थी। बंगाल की 9.5 करोड़ की आबादी में करीब 2.5 करोड़ मुस्लिम हैं। ये दर्शाता है कि घुसपैठ कितना बड़ा सिरदर्द है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक घुसपैठिए एक वोटर की तरह है। बांग्ला भाषी होने की वजह से गाँव गाँव में फैले होते हैं। ये लोग पूरे बंगाल में मौजूद हैं लेकिन बांग्लादेश से सटे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर जैसे इलाकों में इनकी संख्या 50 फीसदी तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना क्षेत्र में इसकी संख्या और ज्यादा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर चुके पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूँ कबीर के मुताबिक मुर्शिदाबाद में 70 फीसदी मुस्लिम आबादी है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि बंगाल में डेमोग्राफी में कितना बदलाव आया है। जानकारों के अनुसार यह कोई इत्तफाक से नहीं है बल्कि राजनीतिक संरक्षण में किया गया एक सुनियोजित और व्यवस्थित बदलाव है। 46 विधानसभा क्षेत्रों में, केवल एक दशक के भीतर मतदाताओं की जनसंख्या में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इनमें से ज्यादातर वे जिले हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। इससे पता चलता है कि डेमोग्राफी में कितना बदलाव आया है। डेमोग्राफी बदलावों की वजह से सामाजिक तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ा है। हिन्दू परिवारों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। हिन्दुओं पर हमले बढ़े हैं। बंगाल में हिंदू परिवारों का लगातार पलायन हो रहा है और पारंपरिक त्योहारों व सांस्कृतिक रीति रिवाजों पर इसका असर पड़ रहा है। बंगाल की मूल पहचान को खतरा पैदा हो रहा है। हाल ही में मुर्शिदाबाद में पूर्व टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए शिलान्यास किया है। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम पहुँच रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बाबर जैसे आक्रांताओं के नाम पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का क्या औचित्य है। जब राम जन्मभूमि के निर्माण के साथ ही बाबरी मस्जिद का नामोनिशान मिट गया तो फिर बाबर के नाम पर बंगाल में मस्जिद बनाना सामाजिक समरसता को कमजोर ही करता है। मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से ममता सरकार इसे रोक भी नहीं रही है बल्कि खुद हुमायूँ कबीर ने बताया है कि बंगाल पुलिस उनकी मदद कर रही है। माना जाता है कि राज्य की 294 सीटों में से 80-100 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं। ऐसे में ममता सरकार लगातार घुसपैठियों को संरक्षण देकर अपना वोट बैंक पुख्ता करने में लगी है। कहा ये भी जाता है कि 2011 और 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार इन घुसपैठियों की बदौलत ही सत्ता तक पहुँची। इससे पहले 2006 तक ये वोट बैंक लेफ्ट के साथ था। बंगाल की घुसपैठ का असर असम, त्रिपुरा से लेकर बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी पड़ा है। इसलिए असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि घुसपैठियों के बंगाल द्वार को बंद करना देश के लिए बेहद जरूरी है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "यही असली बात है। असम और त्रिपुरा घुसपैठ के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहीं बंगाल घुसपैठियों के लिए अपने दरवाज़े खोल रहा है। हमें पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश बॉर्डर पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। होम मिनिस्टर ने एक नेशनल ग्रिड का प्रस्ताव दिया है; हम इसका स्वागत करते हैं।" बंगाल में घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। अक्सर घुसपैठिए अवैध कारोबार में संलिप्त होते हैं। अवैध हथियार से लेकर नशे के कारोबार में इनकी भूमिका पाई जाती है। आतंकवाद से लेकर स्थानीय अपराध तक में घुसपैठिए संलिप्त पाए गए है। ऐसे में भाजपा नेता बीएल संतोष ने ठीक ही कहा है कि देश के लिए एवं बंगाल की पहचान और संस्कृति के संरक्षण के लिए बंगाल से ममता सरकार का जाना जरूरी है।

■ रामस्वरूप रावतसरे

### 3 जनवरी जन्म दिवस

# स्त्रियों के स्वाभिमान की प्रेरणा पुंज सावित्रीबाई फुले

समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले व्यक्तित्वों की परंपरा में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव अपने समय से आगे तक जाता है। उनके विचार और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए दीपस्तंभ बन जाते हैं। ऐसी ही महान समाज-सुधारक सावित्रीबाई फुले की 3 जनवरी को जयंती मनाई जाती है। वे न केवल भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका थीं, बल्कि स्त्री शिक्षा, दलित उत्थान और सामाजिक न्याय के आंदोलन की सशक्त अग्रदूत भी थीं। उनके जीवन का प्रत्येक चरण संघर्ष, साहस और करुणा का उदाहरण है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में खन्दोजी नेवसे और माता लक्ष्मी के घर हुआ। उस दौर में बालिकाओं की शिक्षा की कल्पना भी अस्वीकार्य मानी जाती थी। 1840 में मात्र नौ वर्ष की आयु में उनका विवाह समाज-सुधारक ज्योतिबा फुले से हुआ। विवाह के समय वे निरक्षर थीं, किंतु उनके मन में शिक्षा की तीव्र जिज्ञासा थी। यह वह समय था जब जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और स्त्री-विरोधी रूढ़ियां समाज में गहरे पैठी हुई थीं। एक प्रसंग के अनुसार, एक दिन सावित्रीबाई किसी अंग्रेजी पुस्तक के पन्ने उलट रही थीं। यह देखकर उनके पिता ने पुस्तक छीनकर घर से बाहर फेंक दी क्योंकि उस समय शिक्षा को केवल उच्च जाति के पुरुषों का अधिकार माना जाता था। स्त्रियों और दलितों के लिए पढ़ना पाप समझा जाता था। इसी घटना ने सावित्रीबाई के भीतर शिक्षा प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प जगा दिया। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी बाधाएँ आएं, वे पढ़ना अवश्य सीखेंगी। उनके जीवन में ज्योतिराव फुले केवल पति ही नहीं बल्कि शिक्षक और मार्गदर्शक बनकर आए। 1841 में उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ना-लिखना सिखाना आरंभ किया। आगे चलकर पूना में अंग्रेज अधिकारी रे जेम्स मिचेल की पत्नी के सहयोग से सावित्रीबाई को नॉर्मल

स्कूल में विधिवत शिक्षक प्रशिक्षण मिला। अंग्रेजी भाषा में दक्ष होने के बाद उन्होंने टॉमसन क्लार्कसन की जीवनी पढ़ी जिन्होंने अश्वेतों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया था। इससे सावित्रीबाई को भारत में अछूतों और स्त्रियों की दयनीय स्थिति के प्रति और अधिक चेतना मिली। जनवरी 1848 से मार्च 1852 के बीच सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने बिना किसी सरकारी सहायता के बालिकाओं के लिए 18 विद्यालय स्थापित किए। यह कार्य उस समय एक सामाजिक क्रांति के समान था किंतु इस साहसिक पहल का उन्हें भारी विरोध भी झेलना पड़ा। जब सावित्रीबाई विद्यालय पढ़ाने जातीं तो कट्टरपंथी लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंकते थे। प्रतिदिन होने वाली इस अपमानजनक प्रताड़ना के बावजूद वे विचलित नहीं हुईं। वे अपने साथ अतिरिक्त साड़ी लेकर जातीं और विद्यालय पहुंचकर वस्त्र बदल लेतीं। यह उनके अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का अनुपम उदाहरण है। सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने ऐसे समय में शिक्षा का दीप जलाया, जब स्त्रियों को घर की चारदीवारी में सीमित कर दिया गया था। स्त्री का जीवन केवल चूल्हा-चैका, संतानोत्पत्ति और पति-सेवा तक सीमित माना जाता था। विशेषकर दलित और पिछड़ी महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। सावित्रीबाई ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दी और शिक्षा को मुक्ति का माध्यम बनाया। वे केवल शिक्षिका ही नहीं, बल्कि कुशल समाज सेविका और चिंतनशील कवयित्री भी थीं। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल-विवाह विरोध और सामाजिक समानता के लिए निरंतर संघर्ष किया। 1853 में उन्होंने 'बालहत्या प्रतिबंधक गृह' की स्थापना की, जहाँ विधवाएं सुरक्षित रूप से बच्चों को जन्म दे सकती थीं। यह कदम उस समय समाज के लिए अत्यंत क्रांतिकारी था। 24 सितंबर 1873 को सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने का साहसिक प्रयास किया। उन्होंने मजदूरों के लिए रात्रिकालीन विद्यालय खोले और दलितों के लिए अपने घर का कुआं खोल दिया, जो उस समय सामाजिक समानता का ऐतिहासिक उदाहरण बना। 1897 में पुणे में प्लेग महामारी फैली। 66 वर्ष की आयु में भी सावित्रीबाई अपने दत्तक पुत्र डॉ. यशवंत के साथ रोगियों की सेवा में जुट गईं। सेवा करते-करते वे स्वयं प्लेग की शिकार हो गईं और 10 मार्च 1897 को इस महान आत्मा का निधन हो गया। उनका जीवन सेवा, त्याग और मानवता का प्रतीक बन गया। वर्तमान दौर में केंद्र और राज्य सरकारें उनके योगदान को सम्मान पूर्वक स्मरण कर रही हैं। उनके नाम पर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और योजनाएं संचालित हो रही हैं। सावित्रीबाई फुले नारी शिक्षा और सामाजिक स्वाभिमान की शाश्वत प्रेरणा हैं। उनके विचार आज भी हमें समानता, न्याय और मानव गरिमा के मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। ऐसी युगप्रवर्तक विभूति को शत-शत नमन।

■ डा. वीरेन्द्र भाटी

# छात्रों की फिटनेस पर सोचें...

चालीस पार करते ही कई युवा बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। जब इस बात का अध्ययन किया तो पता चलता है कि बचपन से लेकर अठारह वर्ष तक यानी विद्यार्थी जीवन में फिटनेस कार्यक्रम की कमी रही थी। साथ-साथ आजकल अपने आसपास पिछले एक वर्ष में दर्जनों युवाओं ने हृदयघात से दुनिया कोअलविदा कह दिया है। जब किशोर अवस्था में फिटनेस पर काम नहीं होगा तो ऐसे हालात आम देखने को मिलेंगे। जब मन का विकास स्कूल का काम है तो फिर विद्यार्थी के स्वास्थ्य का जिम्मेदार कौन? शिक्षण विषयों के रिपोर्ट कार्ड की तरह स्वास्थ्य के मानकों का रिपोर्ट कार्ड भी प्रत्येक विद्यार्थी का हर स्कूल में अनिवार्य रूप से हो। क्योंकि भाषा व अन्य शिक्षण विषयों की तरह ही स्वास्थ्य के मूल स्तंभ स्पीड, स्ट्रेंथ, इडोरैंस व लचक आदि का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी उसी उम्र में शुरू करना होता है। शिक्षण विषयों के लिए तो स्कूलों के पास शिक्षक सहित पूरा प्रबंध है, मगर स्वास्थ्य के घटकों को विकसित करके उनका मूल्यांकन करने की कोई भी सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस कॉलम के माध्यम से कई बार इस विषय पर स्कूलों व अभिभावकों को चेताया जा चुका है, मगर कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी देश को इतनी क्षति युद्ध या महामारी से नहीं होती है जितनी तबाही नशे के कारण हो सकती है। आज जब देश के अन्य राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में भी नशा युवा वर्ग पर ही नहीं किशोरों तक चरस, अफीम, स्मैक, नशीली दवाओं तथा दूरसंचार के माध्यमों के दुरुपयोग से शिकंजा कस रहा है। इसलिए सरकार, स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों को इस विषय पर जरूरी कदम जल्दी ही उठा लेने चाहिए। यदि विद्यार्थी किशोरावस्था में नशे से बच जाता है तो वह फिर युवावस्था आते आते समझदार हो गया होता है। माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विद्याओं में व्यस्त रखने के साथ साथ शारीरिक फिटनेस की तरफ मोडऩा बेहद जरूरी हो जाता है। मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा के बिना अधूरा है। शिक्षा की परिभाषा में साफ-साफ लिखा है कि यहां शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से बराबर विद्यार्थियों का विकास करना है, जिससे वह आगे चलकर जीवन को सफलतापूर्वक खुशहाल जी सके। शारीरिक विकास के लिए खेलों के माध्यम से फिटनेस कार्यक्रम बहुत जरूरी हो जाता है। खेल ही वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थी को नशे से दूर रखा जा सकता है। पड़ोसी राज्य पंजाब एक समय तरक्की में देश का अग्रणी राज्य रहा है। खेलों में उत्कृष्टता उस प्रदेश की तरक्की व खुशहाली का भी पैमाना होती है। पंजाब में हजारों प्रशिक्षक विभिन्न खेलों में खेल प्रशिक्षण के लिए नियुक्त होने के साथ-साथ खेल प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचा होना वहां के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रमुख कारण रहा था। बाद में जब पंजाब धीरे-धीरे खेलों से दूर हुआ तो पहले वहां आतंकवाद और फिर आजकल पंजाब नशे का अड्डा बना हुआ है। यही कारण है कि हर क्षेत्र में आज हरियाणा पंजाब से काफी आगे निकल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने एशियाई, राष्ट्रमंडल व ओलंपिक खेलों में पदक विजेता होने पर खिलाडिय़ों को करोड़ों रुपए के नगद ईनाम व सम्मानजनक नौकरी देकर हरियाणा में खेलों के लिए बहुत ही उपयुक्त वातावरण तैयार किया है। उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा का हर किशोर व युवा किसी न किसी खेल के मैदान में नजर आता है।

■ भूपिंद्र सिंह

### आज का कार्टून

साभार

# उन्नाव रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट की दखल

देश के सबसे चर्चित और संवेदनशील आपराधिक मामलों में शामिल उन्नाव रेप केस एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद, जिसमें दोषी करार दिए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर जमानत दी गई थी, यह मामला केवल एक व्यक्ति की रिहाई या कैद तक सीमित नहीं रह गया है। यह फैसला दरअसल न्याय प्रणाली, सामाजिक विश्वास और कानून की आत्मा की परीक्षा बन गया है। उन्नाव की पीड़िता की कहानी केवल एक अपराध की दास्तान नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जहां सत्ता, भय और दबाव के बीच न्याय की राह अत्यंत कठिन हो जाती है। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, उसके परिवार पर लगातार हमले, पीड़िता के पिता की हिरासत में संदिग्ध मौत और गवाहों को डराने की घटनाओं ने इस केस को सामाजिक-न्याय का प्रतीक बना दिया। ऐसे में जब किसी अदालत द्वारा दोषी को राहत दी जाती है तो सवाल केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक भी हो जाते हैं। इस मामले में दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम के तहत हुई थी। पॉक्सो कानून विशेष रूप से बच्चों के यौन शोषण से सुरक्षा के लिए बनाया गया है और इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अपराध किसी प्रभावशाली व्यक्ति या लोक सेवक द्वारा किया जाए, तो उसे गंभीरतम श्रेणी में माना जाएगा। यहीं से विवाद की जड़ शुरू होती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह टिप्पणी की कि विधायक को पॉक्सो के संदर्भ में 'लोक सेवक' की परिभाषा में नहीं रखा जा सकता, और इसी आधार पर गंभीर आरोपों की धार कमजोर मानी गई। इस तकनीकी व्याख्या ने पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए साफ किया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। अदालत ने कहा कि विधायक जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को 'लोक सेवक' मानने या न मानने का प्रश्न केवल शब्दों की व्याख्या नहीं बल्कि कानून की मंशा और समाज पर उसके प्रभाव से जुड़ा है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई बल्कि दोषी को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब तलब किया। कुलदीप सिंह सेंगर की संभावित रिहाई का विरोध केवल कानूनी दलीलों तक सीमित नहीं है। यह विरोध उस डर और अविश्वास से उपजा है, जो वर्षों से यौन हिंसा की शिकार महिलाओं और बच्चों के मन में घर कर चुका है। जब एक प्रभावशाली आरोपी को राहत मिलती है तो संदेश केवल पीड़िता तक नहीं जाता बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति तक पहुंचता है, जो न्याय की उम्मीद लेकर थाने और अदालत का दरवाजा खटखटाता है। महिला अधिकार संगठनों का कहना है कि ऐसे फैसले पीड़ितों का मनोबल तोड़ते हैं और भविष्य की पीड़िताओं को चुप रहने के लिए मजबूर करते हैं। उन्नाव केस में तो पीड़िता और उसके परिवार ने न्याय पाने के लिए असाधारण साहस दिखाया। ऐसे में दोषी को राहत देना उस संघर्ष को कमजोर करने जैसा प्रतीत होता है। यह मामला इस सवाल को भी जन्म देता है कि क्या कानून की व्याख्या सत्ता-संपन्न व्यक्तियों के लिए अलग हो सकती है? लोकतंत्र में विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है और संविधान उसे विशेष जिम्मेदारियां सौंपता है। यदि वही प्रतिनिधि कानून तोड़ता है, तो क्या उसे आम नागरिक से कम जवाबदेह माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की रोक को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। यह संदेश स्पष्ट है कि न्याय केवल तकनीकी खामियों से नहीं बल्कि कानून की भावना से संचालित होना चाहिए। पॉक्सो जैसे कानून का उद्देश्य बच्चों को भयमुक्त वातावरण देना है, न कि अपराधियों को व्याख्याओं के जाल से बाहर निकलने का रास्ता। उन्नाव केस ने यह भी उजागर किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में जनता का भरोसा कितना नाजुक होता है। वर्षों की सुनवाई, संघर्ष और बलिदान के बाद यदि फैसले तकनीकी आधार पर पलटते दिखें तो आम नागरिक का विश्वास डगमगाना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस विश्वास को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

■ बाबूलाल नागा

## प्रेरणा

बिना कर्म के कोई भी ज्ञान बेकार है, बिना ज्ञान के कर्म करना मूर्खता है। - **अल गजाली**

## संपादकीय

# समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करनी जरूरी है

**ताजा** एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार बंगाल और झारखंड आज भी बाल-विवाह में अव्वल हैं, जबकि इस कुप्रथा को लगभग सौ साल पहले गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसी तरह दो सौ साल पहले लार्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा खत्म की, लेकिन सती होने की अंतिम रिपोर्टेड घटना वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ में हुई, जब 75 वर्षीय लालमती ने अपने पति की जलती चिता पर कूद कर जान दे दी। एमपी में जानकीरानी, यूपी में विद्यावती और राजस्थान में रूप कंवर के सती होने की घटनाएं आज भी लोगों के जेहन में बसी हैं। बाल-विवाह ऐसी कुप्रथा है, जिसमें न केवल कम उम्र की बच्चियों की जान गर्भ धारण के कारण खतरे में पड़ जाती है, बल्कि बच्चे की जान और उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर भी खतरा होता है। यही कारण है कि भारत के कई राज्य लो-वेट-एट-बर्थ (जन्म के समय कम वजन का होना) और बाल-मृत्यु दर में गरीब और अति-पिछड़े अफ्रीकी देशों के समकक्ष खड़े हैं। अकसर पाया गया है कि कम विकसित क्षेत्रों में झाड़-फूंक से इलाज करवाने में विश्वास रखा जाता है, जिससे मरीजों की अकाल मृत्यु हो जाती है। भारत के संविधान में समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करना राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल तो किया गया, लेकिन कुप्रथाओं के खिलाफ इस सोच को लाने में शिक्षा में क्रांति की जरूरत होगी।

## जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com


# हनुमान जी से जुड़े रहें तो शानदार उड़ान भर सकेंगे

**दुनिया** में जब भी उड़ान की बात आएगी, हनुमान जी याद आएंगे। निर्दोष, समयबद्ध, सफलता के साथ उड़ने की कला जैसी हनुमान जी के पास है, वैसी किसी के पास नहीं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण उड़ान उड़ी थी लंका की ओर। जितनी सफलता से गए थे, उतनी सफलता से लौटे। इसकी कहानी रामायण के सुंदरकांड में है। हनुमान जी को उड़ता देख रावण बहुत चिंतित हुआ था। हनुमान जी की उड़ानों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली वो थी, जिसमें वे मूर्च्छित लक्ष्मण के लिए औषधि लाए। बाधाएं हनुमान जी को उड़ते समय हर बार आईं, लेकिन उनका कभी ऑपरेशनल ब्रेकडाउन नहीं हुआ। आसमान में उड़ान भरते समय गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने के अलावा जान का जोखिम, अस्तित्व की रक्षा, प्रतिस्पर्धा का भी बड़ा खतरा रहता है। जो लोग उड़ान के प्रति लापरवाह हैं, वो कीमत बड़ी चुकाएंगे। हमारी युवा पीढ़ी अब चलने, दौड़ने से ऊपर निकल चुकी है। अब उड़ान ही भरनी है। यदि हनुमान जी से जुड़े रहें तो शानदार उड़ान भर सकेंगे।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

## विश्लेषण • मुस्लिम वोटबैंक से जी-राम-जी तक...

# बंगाल का चुनाव ममता की सबसे कठिन परीक्षा होगा

## सियासत

मिन्हाज मर्चेंट
लेखक, प्रकाशक और सम्पादक
mmleditorial@gmail.com


**बंगाल** में चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सामने पांच चुनौतियां हैं। पहली, 15 साल की सत्ता विरोधी लहर से पार पाना। दूसरी, संदेशखाली और शिक्षक भर्ती घोटाले में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटना। तीसरी, तृणमूल कार्यकर्ताओं के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों के चलते वोटरों का खोया भरोसा वापस पाना। चौथी, एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग से टकराना।

लेकिन पांचवीं चुनौती उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। यह है मुस्लिम वोटरों का तृणमूल से छिटककर ओवैसी की एआईएमआईएम और टीएमसी के बागी नेताओं के पाले में जाना। तृणमूल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि वे मुस्लिम वोटबैंक को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में ममता ने जन-भावनाओं को लामबंद करने के लिए मनरेगा का नाम बदलने संबंधी कानून को औजार बनाया है।

एक कार्यक्रम में ममता ने कहा कि 'मुझे शर्म महसूस हो रही है। एक विधेयक लाया गया है। गांधीजी के नाम पर बनी मनरेगा में अब उन्हीं का नाम नहीं होगा। हम राष्ट्रपिता को भूल रहे हैं। मैं इस देश की हूं तो इसके लिए मैं अपने सिवाय किसी को दोष भी नहीं दे सकती। हमने 'कर्मश्री' योजना शुरू की थी, इसका नामकरण अब गांधीजी के नाम पर किया जाएगा।'

लेकिन मनरेगा का नाम बदलने की बहस जल्द ही साम्प्रदायिक रंग में रंग गई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य ने कहा- 'यह विधेयक महात्मा गांधी के सम्मान के लिए ही लाया गया है, क्योंकि वे मानते थे कि राम ही भारत है और भारत ही राम हैं। तृणमूल तो 'जयश्री राम' के नारे को भी अनुचित मानती है। कुछ लोग राम के बजाय बाबर के रास्ते पर चलना चाहते हैं।'

लेकिन इस सियासी तू-तू-मैं-मैं ने 'वीबी-जी राम जी' कानून के असल असर को दबा दिया। इस कानून का बड़ा फायदा है कि भुगतान वाले कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। लेकिन एक कमी भी है कि योजना के खर्च का 40% बोझ राज्यों पर डाल दिया गया है। हालांकि, हिमालयी और पूर्वोत्तर के राज्यों को 10% ही हिस्सेदारी देनी होगी।

मनरेगा अब तक शत-प्रतिशत केंद्र से वित्तपोषित रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्यों पर लगभग आधा खर्च डालने से मजदूरी के भुगतान में देरी होगी तो गरीब मजदूरों को ही नुकसान पहुंचेगा। केंद्र का दावा है कि पहले मनरेगा के तहत राज्यों को दिए गए पैसे में घोटाले हुए थे। केंद्र-राज्य हिस्सेदारी तय करने से योजना अधिक पारदर्शी बनेगी। हालांकि भाजपा और सहयोगी दलों के शासन वाले कई राज्यों ने ही इस पर नाखुशी जाहिर कर दी है। एनडीए की सहयोगी टीडीपी शासित आंध्र प्रदेश ने साफ कर दिया है कि अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना उसके लिए मुश्किल होगा।

'लाडकी बहिन योजना' के कारण पहले से वित्तीय दबाव झेल रहा महाराष्ट्र भी इससे खासा प्रभावित होगा। 'वीबी-जी राम जी' योजना के तहत 2026 में राज्य में अनुमानित 1.51 लाख करोड़ के खर्च में से महाराष्ट्र को करीब 6 हजार करोड़ अतिरिक्त देने होंगे।

तो वापस आते हैं कि क्या मनरेगा विवाद ममता बनर्जी को खोई चुनावी साख वापस दिला सकता है? शायद नहीं। लेकिन यह प्रचार के दौरान ममता सरकार पर लगे घोटालों के दागों से ध्यान भटकाने में मददगार जरूर बन सकता है।

ममता जल्द ही 71 साल की हो जाएंगी। उनके उत्तराधिकारी और भतीजे अभिषेक बनर्जी टीएमसी के

**मुस्लिम वोटरों का तृणमूल से छिटककर ओवैसी और टीएमसी के बागी नेताओं के पाले में जाना ममता को चिंतित कर रहा है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का कहना है वे मुस्लिम वोटबैंक तोड़ने की योजना बना रहे हैं।**

कार्यकर्ताओं में उतने लोकप्रिय नहीं हैं। वे रूखे मिजाज वाले हैं और अपमानजनक व्यवहार भी कर सकते हैं। 2024 में ममता बनर्जी ने कुछ वक्त के लिए उनसे दूरी भी बना ली थी, लेकिन कई घोटाले सामने आने पर उनकी वापसी कराई गई है।

इधर, पड़ोसी बांग्लादेश की उथल-पुथल इस चुनाव में दोधारी तलवार जैसी हो सकती है। एसआईआर के चलते तृणमूल के वोटर समझे जाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या घटी है। लेकिन ढाका में बढ़ता साम्प्रदायिक तनाव पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटरों को ममता के पक्ष में लामबंद कर सकता है। क्योंकि वे जानते हैं कि ओवैसी और हुमायूं कबीर टीएमसी वोटरों का छोटा-सा हिस्सा ही तोड़ सकते हैं। ऐसे में ममता ही भाजपा से उनका बचाव कर सकती हैं।

लेकिन यदि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार रोकने में नाकाम रहती है तो बंगाल चुनाव पर इसका गम्भीर असर हो सकता है। इससे अब तक पसोपेश में फंसे हिंदू वोटर भाजपा का दामन थाम सकते हैं।

**(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

## नजरिया • जरूरी मुद्दों पर हम उदासीन नहीं रह सकते

# 2026 में हमें बहुत सारी चीजें अलग तरह से करनी होंगी

## देशकाल

पवन के. वर्मा
पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक
pavankvarma1953@gmail.com


**बीते** वर्ष को देखने के दो तरीके होते हैं। पहला, उसके प्रमुख घटनाक्रमों को यंत्रवत रूप से रेखांकित भर करना; और दूसरा, उनका मूल्यांकन करना, उनके प्रासंगिक पहलुओं को चिह्नित करना और यह देखना कि आने वाले वर्ष में क्या किए जाने की आवश्यकता है।

मेरे विचार से, 2025 को चार केंद्रीय मुद्दों के लिए याद किया जाएगा : चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर उठते सवाल; दिल्ली तथा उससे सटे क्षेत्रों में साफ हवा का संकट; हमारे पड़ोस में जारी उथल-पुथल और ट्रम्प की अप्रत्याशित हरकतों के कारण भारत-अमेरिका संबंधों में पैदा हुई अस्थिरता।

बिहार में एसआईआर को जिस तरह से अंजाम दिया गया, और अब जिस तरीके से इसे पूरे देश में किया जा रहा है, वह बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित छोड़ देता है। यहां मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करने के चुनाव आयोग के अधिकार पर सवाल नहीं हैं। लेकिन जिस अंदाज में वो अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, वह जरूर चिंताओं के दायरे में है। यह धारणा लगातार मजबूत हो रही है कि इस प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता का अभाव है। और यह इस अन्य धारणा का परिणाम है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव आयोग की स्वायत्तता अपेक्षित स्तर की नहीं रह गई है।

वास्तविक लोकतंत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिस्पर्धी दलों के बीच होने वाले चुनाव निष्पक्ष हों और उनके नियम सभी पर समान रूप से लागू हों। इसके लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग अनिवार्य है। और इसके लिए यह जरूरी है कि उसके आयुक्त तटस्थ हों। वे किसी दल के प्रति झुके न हों। यदि यह विश्वास खंडित होता है तो चुनावों की वैधता सवालों के घेरे में आ जाती है। 2025 ने इस संदर्भ में एक चेतावनी दी है। 2026 को आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने होंगे।

2025 में जारी वायु संकट- जिसने उत्तर भारत को हांफने पर मजबूर कर दिया और दिल्ली के निवासियों का दम घोंट दिया- ने भी नागरिकों को यह पूछने पर विवश किया कि यह समस्या हर साल क्यों दोहराई जाती है? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब इसके भयावह नतीजे अच्छी तरह से मालूम हैं, तब भी सरकार इसे ठीक करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? सरकार को इस आपदा के सामने असहाय देखना इस धारणा को जन्म देता है कि सत्ता में बैठे लोग केवल वहीं पर सक्रिय होते हैं, जहां वोट दांव पर हों। नागरिकों की ओर से यदि कोई संगठित पहल नहीं हो तो सरकारें बस इंतजार करती रहती हैं कि सालाना संकट अपने आप टल जाए। लेकिन 2025 ने संकेत दिया है कि लोग अब कह रहे हैं : बहुत हुआ। 2026 वह वर्ष हो सकता है, जब नागरिक जवाबदेही की मांग करें। और तब सरकार को कार्रवाई करनी ही होगी।

अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, पहले नेपाल और फिर बांग्लादेश में उभरे जेन-जी विद्रोह ने भारत को अलग-थलग करने की चीन और पाकिस्तान की दुर्भावनापूर्ण मंशाओं को आगे बढ़ाने में मदद ही की। विशेष रूप से बांग्लादेश में शेख हसीना को उनके शासन के प्रति बढ़ती अलोकप्रियता के बारे में समय रहते सचेत न कर पाना हमारी कूटनीतिक विफलता रही। लगता है कि हमने वहां के विपक्ष के साथ संवाद के रास्ते खुले रखे बिना अपने सारे दांव उन्हीं पर लगा दिए। जमात-ए-इस्लामी जैसे अतिवादी दलों और भारत-विरोधी तत्वों को वित्तपोषित और प्रोत्साहित करने में पाकिस्तान की भूमिका का आकलन न कर पाना भी एक चूक रही।

**हम आशा ही कर सकते हैं कि 2026 में हालात 2025 की तुलना में बेहतर होंगे। नए साल की शुरुआत बीते साल पर आत्ममंथन का अवसर देती है। 2026 इसी के लिए एक आमंत्रण है। आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का भी।**

उधर पाकिस्तान में, कट्टरपंथी जनरल मुनीर का उभार चिंता का विषय है। मुनीर का ट्रम्प के साथ भोजन करना, सऊदी अरब को रिझाना और चीन के साथ तालमेल बैठाना भी इसी कड़ी में है। ट्रम्प पर हमारा भरोसा भी गलत साबित हुआ और उनके पक्षपातपूर्ण टैरिफों का हमने आक्रामक ढंग से प्रतिकार भी नहीं किया। जबकि चीन ने ट्रम्प की धमकियों का डटकर सामना किया और अब ट्रम्प अमेरिका और चीन से मिलकर बने 'जी-2' की बात कर रहे हैं।

हम आशा ही कर सकते हैं कि 2026 में हालात बेहतर होंगे। नए साल की शुरुआत बीते साल पर आत्ममंथन का अवसर भी देती है। 2026 इसी के लिए एक आमंत्रण है, और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का भी। नववर्ष की शुभकामनाएं।

**(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

**3 जनवरी के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में**

इकोनॉमिस्ट मैग्जीन ने फ्लाइंग कार, क्वांटम कंप्यूटिंग और फ्यूजन एनर्जी में प्रगति पर खबर की है। मैग्जीन ने अमेरिका में महंगाई के मामले पर भी प्रकाश डाला है।

The Economist

दैनिक भास्कर — **अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।**

## वर्ल्ड इन ब्रीफ

### टेस्ला अब सबसे बड़ी ईवी निर्माता नहीं रह गई है

**टेस्ला** ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी होने का खिताब अपने चीनी प्रतिद्वंद्वी बीवाईडी के हाथों गंवा दिया है। 2025 में टेस्ला ने 16.4 लाख इलेक्ट्रिक वाहन डिलीवर किए, जो 2024 की तुलना में 8.6 प्रतिशत कम हैं। वहीं बीवाईडी ने पिछले वर्ष 22.6 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतारे, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक चौथाई से अधिक की बढ़ोतरी है। यानी बाजार के एक और अहम सेगमेंट में चीन अमेरिका पर अपनी बढ़त दर्ज करा रहा है।

### नेतन्याहू को मिल रहा है ट्रम्प का खासा समर्थन

**बेंजामिन** नेतन्याहू इस साल फिर से चुनाव जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में वे डोनाल्ड ट्रम्प को अपना चुनाव अभियान प्रबंधक रखने पर विचार कर सकते हैं। 29 दिसंबर को फ्लोरिडा स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास की यात्रा के दौरान ट्रम्प ने खुले दिल से कहा कि नेतन्याहू 'सबसे उच्च स्तर के युद्धकालीन प्रधानमंत्री' हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि कोई और सत्ता में होता, तो आज इज़राइल का अस्तित्व ही नहीं होता। मुश्किल दौर से गुजर रहे इजराइली प्रधानमंत्री खुद भी इससे बेहतर चुनावी नारे नहीं गढ़ सकते थे। वे अधिकांश जनमत सर्वेक्षणों में पिछड़ रहे हैं।

### ईरान में हो रहे प्रदर्शनों पर अमेरिका की चेतावनी

**अमेरिका** ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिंसक हत्या करता है तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने कहा कि उनका देश कार्रवाई के लिए तैयार है। यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब ईरान की कमजोर अर्थव्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन छठे दिन में प्रवेश कर चुके हैं और हिंसक हो गए हैं। देशभर से झड़पों की खबरें आ रही हैं। अतीत में भी ईरान से मानवाधिकार हनन की चिंताजनक खबरें सामने आती रही हैं। ईरानी महिलाओं का हिजाब विरोधी आंदोलन खासा चर्चित हुआ था।


© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved


## ओपिनियन चीन-यूएई में इस साल उड़ सकती है एयर टैक्सी, क्वांटम कम्प्यूटिंग में एनवीडिया, जेपी मॉर्गन निवेश कर रहे हैं

# फ्लाइंग कार, क्वांटम कंप्यूटिंग व फ्यूजन एनर्जी का सपना सच हो रहा

**फ्लाइंग** कारें, फ्यूजन एनर्जी और क्वांटम कंप्यूटिंग को हमेशा भविष्य की तकनीक माना जाता था। अब ये तीनों टेक्नोलॉजी वास्तविकता के धरातल पर उतर रही हैं।

मार्च में चीन की इहैंग और अमेरिका की जॉबी इस साल एयर टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है। जॉबी, ईहैंग और दो अन्य प्रतिद्वंद्वी कंपनियों का कुल मूल्य एक लाख 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वहीं गूगल के रिसर्चर्स ने 2024 में बताया कि अधिक क्यूबिट्स के इस्तेमाल से गलती की दर को कम कर सकते हैं। फ्यूजन एनर्जी के क्षेत्र में भी विस्तार देखा जा रहा है। इसे बनाने के लिए टोकामैक्स की दरकार होती है, जितने ताकतवर टोकामैक्स उतनी ज्यादा बिजली। उच्च तापमान वाले सुपरकंडक्टरों की वजह से इस क्षेत्र में भी क्रांति आ गई है।

### क्वांटम कंप्यूटिंग : इससे जुड़ी कंपनियों की दो साल में 12 गुना ग्रोथ हुई

क्वांटम कंप्यूटिंग को लंबे समय तक 'आने वाली तकनीक' के दायरे में ही रखा जाता था। लेकिन अब इसका अच्छा विस्तार हुआ है। तीन क्वांटम कंप्यूटिंग कंपनियों- डी वेव, लोनक्यू और रिगेटी का बाजार मूल्य दो लाख 97 हजार करोड़ रुपए होने का दावा किया गया है। यह 2023 के बाद 12 गुना बढ़ोतरी है। दो महीने पहले, क्वांटिनम नामक 11 अरब डॉलर के स्टार्टअप ने न्यूयॉर्क में नया व्यावसायिक क्वांटम कंप्यूटर पेश किया। इसमें एनवीडिया, जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियों व बैंक ने भी निवेश किया है।

### फ्लाइंग कारें : प्रमुख कंपनियों की वैल्युएशन करीब 1 लाख 80 हजार करोड़

चीन के ग्वांगझोउ, हेफेई में एयर टैक्सी की अनुमति मिल गई है। वहीं दुबई में भी इस साल ये शुरू हो जाएंगी। जॉबी, ईहैंग और दो प्रतिद्वंद्वी कंपनियों का कुल मूल्य एक लाख 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।

### फ्यूजन एनर्जी : समय के साथ बेहतर और ताकतवर हो गए हैं टोकामैक कंटेनर

फ्यूजन एनर्जी कंपनियों हेलिओन और कॉमनवेल्थ फ्यूजन सिस्टम्स ने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल से बिजली मुहैया कराने के करार किए हैं। दोनों कंपनियों का कुल मूल्य 90 हजार करोड़ रुपए से अधिक है। फ्यूजन टेक्नोलॉजी में छोटे परमाणुओं को दबाकर बड़े परमाणु बनाए जाते हैं। इससे बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होती है। गर्म प्लाज्मा से भरे टोकामैक नामक कंटेनर के अंदर एटम्स को दबाते हैं। अब टोकामैक बेहतर व ताकतवर हो गए हैं। इस प्रक्रिया से अनंत और कम प्रदूषण से एनर्जी पैदा की जा सकती है।

**एआई और सप्लाई चेन सुधरने से प्रगति**

एआई के आने के बाद फ्लाइंग कार, फ्यूजन एनर्जी और क्वांटम कंप्यूटिंग का क्षेत्र तेजी से बढ़ा है। एआई से बैटरी मटेरियल की डिजाइन, क्वांटम की गलतियां सुधारने में मदद मिलती है। वहीं फ्यूजन एनर्जी पैदा करने वाले टोकामैक्स कंटेनर के अस्थिर प्लाज्मा नियंत्रित भी करती है। इसके अलावा दुनियाभर में सप्लाई चेन अच्छी होने से भी इन सेक्टर में मदद मिली है। कारों की बैट्री का मटेरियल आसानी से मिल जाता है। नियम भी आसान हुए है। क्वांटम कंपनियों को लेजर की सप्लाई हो या फ्यूजन के लिए कंडक्टर की आसान सप्लाई ने इन तकनीकों को विस्तार दिया है। लेकिन कुछ कंपनियों को आय तो हो रही है लेकिन कोई भी मुनाफा नहीं कमा पा रही है।

## बिजनेस अगले साल डेढ़ लाख करोड़ का खर्च

# ओपनएआई को घाटे की आशंका, जेमिनी दे रहा है कड़ी टक्कर

**चैटजीपीटी** की पैरेंट कंपनी ओपनएआई ने साल 2025 में 81 हजार करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन वह 2026 में 1.53 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में उसे घाटा होगा। गूगल का जेमिनी चैटबॉट कंपनी के लिए चुनौती बन गया है। कंपनी अब तक निवेशकों से 5.40 लाख करोड़ रुपए जुटा चुकी है। 2026 में ओपनएआई 74 लाख करोड़ रुपए बाजार मूल्य के आधार पर 9 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। अमेजन 90 हजार करोड़ रुपए वहीं एनवीडिया ओपनएआई में 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है।

2023 में उसकी आय 9 हजार करोड़ रुपए से अधिक रही। वहीं 2025 में यह 1.17 लाख करोड़ रुपए हो गई। गूगल और फेसबुक को ऐसा करने में क्रमश: पांच और छह वर्ष लगे थे। इस बीच बिजली के लिए ओपनएआई की मांग तेजी से बढ़ रही है। बिजली की जरूरत 2023 के 200 मेगावॉट से बढ़कर 2025 में 1.9 गीगावॉट हो गई। उसने 126 लाख करोड़ रुपए में 30 गीगावॉट बिजली क्षमता बढ़ाने के लिए करार किए हैं। कंपनी की सबसे अधिक लागत बिजली पर लगती है।

**यूजर्स की संख्या थमी**

सेंसर मॉनिटर के अनुसार दिसंबर मध्य तक जेमिनी के 34.50 करोड़ मासिक एक्टिव यूजर्स थे। वहीं ओपनएआई के करीब 91 करोड़ थे। जेमिनी तेजी से बढ़ रहा है। ओपनएआई चैटबॉट के कंज्यूमर सब्स्क्रिप्शन ठहर गए हैं।

प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच ट्रेनिंग का खर्च बढ़ रहा है। नवंबर में जारी गूगल जेमिनी 3 ने ओपनएआई के जीपीटी- 5.1 को कई मामलों में पीछे छोड़ दिया है।


© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved


## समरनीति

# यूरोप में दी जा रही है रूस से युद्ध छिड़ने की चेतावनी

**कई** यूरोपीय देशों में सैनिक अधिकारी कह रहे हैं कि रूस से युद्ध हो सकता है। जनता से युद्ध के लिए तैयार रहने की अपीलें की जा रही हैं। फ्रांसीसी सेना के प्रमुख जनरल फैबियन मैनडोन ने कहा कि 2030 तक रूस से युद्ध की आशंका है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सेना नहीं हर किसी को तैयार रहने की जरूरत है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की प्रमुख ब्लेस मेत्रेवेली ने कहा कि पश्चिम यूरोप को समझने में मुश्किल हो रही है कि वह शांति और युद्ध के बीच रह रहा है। सैनिक संगठन नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रटे ने कहा कि हमें ऐसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, जो हमारे पूर्वजों ने लड़े हैं। इसके बाद ब्रिटिश सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल सर रिचर्ड नाइटन ने कहा कि सुरक्षा का जिम्मा केवल सेनाओं पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है। इन चेतावनियों के बाद यूरोपीय सरकारों ने दो तरह की तैयारियों की शुरुआत की है। किसी तरह की सैनिक सेवा शुरू की जा रही है। नागरिकों संघर्ष के लिए तैयार किया जा रहा है। जर्मन सरकार ने सेना में भर्ती का नया मॉडल पेश किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 18-28 साल की आयु के लोगों के लिए दस माह की सवैतनिक स्वैच्छिक सैनिक सेवा की घोषणा की है। पोलैंड में भी सभी वयस्कों को मिलिटरी ट्रेनिंग दी जाएगी। फिनलैंड, नार्वे में पहले से सैन्य सेवा अनिवार्य है।


© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved


## इकोनॉमी बड़े शहरों में रहना खर्चीला

# अमेरिका में महंगाई बढ़ रही, पर आमदनी बढ़ने से यह बेअसर

**डोनाल्ड** ट्रम्प ने 2024 में अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव महंगाई को मुद्दा बनाकर जीता था। उन्होंने तेजी से मूल्य कम करने का वादा किया था। लेकिन टैरिफ लगाकर मूल्य बढ़ाए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने रहन-सहन के खर्च को मुद्दा बनाया है। न्यूयॉर्क मेयर के चुनाव अभियान में जोहरान ममदानी ने मकान किराए फ्रीज करने और मुफ्त बस सेवाओं का वादा किया था। न्यूजर्सी की निर्वाचित गवर्नर मिकी शेरिल ने बिजली के मूल्य घटाने का ऐलान किया है। इससे ट्रम्प परेशान हैं। हकीकत में गौर करें तो अमेरिका में वेतन लगातार बढ़ने से महंगाई बेअसर हो गई है।

डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा रहन-सहन का खर्च बढ़ने को मुद्दा बनाने पर ट्रम्प शिकायत नहीं कर सकते हैं। ट्रम्प ने ही इसे मुद्दा बनाया था। खर्च की क्षमता का आकलन वास्तविक आय से होता है। चीजों की कमी से होने वाली महंगाई से असली आय प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पेट्रोल, गैस के दाम बढ़े तो यूरोप में कामगारों की खरीद शक्ति में गिरावट आई है। यूरोप में खाने-पीने की चीजों के मूल्य बढ़े हैं। अमेरिका की स्थिति अलग है। वहां वास्तविक वेतन पिछले दशक से लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में अमेरिका में जीवन-यापन इतना किफायती और अच्छा पहले नहीं रहा।

विशेषज्ञ कहते हैं कि ग्रॉसरी, एनर्जी और हाउसिंग जैसा जरूरी खर्च बढ़ा है। ग्रॉसरी का खर्च इकोनॉमी का बहुत छोटा हिस्सा हैं। इसकी तुलना में बिजली का खर्च 2019 के बाद 10% बढ़ा है। लेकिन पेट्रोल के मूल्यों में कुछ वर्षों से लगातार गिरावट हो रही है।

अफोर्डेबिलिटी या रहन-सहन के संकट का सबसे मजबूत मुद्दा हाउसिंग का है। अमेरिका के बड़े शहरों में रहना बेहद खर्चीला है। न्यूयॉर्क के मैनहटन, ब्रुकलिन में औसत संपत्ति के लिए आवास ऋण पर ब्याज, इंश्योरेंस और टैक्स का खर्च औसत परिवार की आय का 90% है। लेकिन अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों की स्थिति ऐसी नहीं है। अन्य स्थानों में हाउसिंग का खर्च वहन किया जा सकता है। इसलिए सवाल उठता है माजरा क्या है? दरअसल लोगों का ध्यान मूल्यों के स्तर पर है, जो महामारी के पहले से लगभग 25% अधिक हैं। इस तथ्य से लोग संतुष्ट नहीं हैं कि इस अवधि में सामान्य वेतन में 30% बढ़ोतरी हुई है। एक स्टडी के मुताबिक लोग मूल्य वृद्धि को अपने नियंत्रण से बाहर मानते हैं लेकिन वेतन में बढ़ोतरी को अपनी पेशेवर क्षमता और योग्यता से जोड़ते हैं।


© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

**बिग अपडेट** 2026 में स्मार्टफोन में आएंगे ये बड़े बदलाव; नए डिजाइन, एआई फीचर्स व तेज कस्टमर सर्विस पर जोर

# पहला फोल्डेबल आईफोन होगा लॉन्च, सैमसंग लाएगा **नया प्रोसेसर**

**तुषार मेहता**
को-फाउंडर athenil
व टेक एक्सपर्ट

**2026** में एपल पहला फोल्डेबेल आइफोन लॉन्च करेगा। इसी तरह सैमसंग नया प्रोसेसर पेश करेगा और गूगल पिक्सल भी अपनी नई टेंसर जी6 सीरीज पर काम करेगा। वहीं चीन की कंपनियां ओपो और शाओमी अब प्रीमियम फोन पर फोकस बढ़ाएंगे। हालांकि फोन की बिक्री गिरेगी। काउंटरपॉइंट के रिसर्च एनालिस्ट शुभम सिंह के अनुसार 2026 में भारत में स्मार्टफोन की बिक्री औसतन 3 से 5% तक घट सकती है।

### दैनिक भास्कर टेक पॉडकास्ट

इस खबर को आप पॉडकास्ट के जरिए भी सुन सकते हैं। इस QR को स्कैन करें और टेक्नोलॉजी की इस खबर को सामान्य बातचीत के अंदाज में सुनें। हर हफ्ते आपको टेक पेज पर मिलेगा पॉडकास्ट।

## एपल अपना एआई सिस्टम पेश करेगा; ओपो का जोर सर्विस पर

### • सैमसंग: फोल्ड फोन पर फोकस

सैमसंग इस साल अपना नया प्रोसेसर एक्सिनॉस 2600 पेश करेगी। यह कंपनी का अब तक का सबसे तेज प्रोसेसर होगा। सैमसंग ने हाल ही में अपना पहला ट्राईफोल्ड फोन भी लॉन्च किया है। हालांकि यह भारत में कब लॉन्च होगा इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन कंपनी अपने प्रीमियम स्टोर्स में इसे शो कर सकती है।

### • एपल: खुद का एआई सिस्टम बनाएगी कंपनी

इस साल एपल का फोकस दो चीजों पर होगा। पहला एआई और दूसरा पहला फोल्डेबल आईफोन पर। कंपनी अपने एपल इंटेलिजेंस का कंप्लीट वर्जन पेश करेगी... जिसे 2024 से टालना पड़ रहा है। इसमें एपल का सिरी भी अपडेट किया जाएगा, यानी कंपनी गूगल की तरह ही अपना खुद का एआई सिस्टम बनाने जा रही है। इसके इतर इस साल एपल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन भी लॉन्च कर सकती है, जिसका डिजाइन काफी हद तक आईपैड मिनी जैसा दिखेगा।

### • शाओमी: प्रीमियम फोन पर जोर देगी

शाओमी इंडिया के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुधिन माथुर बताते हैं कि इस साल शाओमी मिड-प्रीमियम सेगमेंट और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड डिवाइसेज पर फोकस बढ़ा रही है। आने वाली रेडमी नोट सीरीज को भी अब ज्यादा फ्लैगशिप-ग्रेड एक्सपीरियंस देने की तैयारी है, ताकि अलग-अलग कीमत पर प्रीमियम फील मिल सके। कंपनी अपने सर्विस पर भी फोकस बढ़ाएगी। फिलहाल शाओमी के एक-तिहाई प्रोडक्ट्स की रिपेयर कॉस्ट 1000 रुपए से कम है।

### • ओपो: 24x7 कस्टमर केयर पर जोर देगी

ओपो इंडिया के हेड ऑफ कम्युनिकेशन गोल्डी पट्टनायक बताते हैं कि ओपो अब सुपर-प्रीमियम सेगमेंट में भी हाथ आजमा रही है। ओपो का फाइंड एक्स9 प्रो है, जिसकी कीमत करीब 1.10 लाख रुपए है, जो सीधे एपल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स को चुनौती देता है। इसके अलावा ओपो भारत में 570 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स चला रही है। कंपनी 24x7 कस्टमर केयर, घर से पिक-अप-ड्रॉप और इंटरनेशनल वारंटी जैसी सुविधाओं पर फोकस बढ़ाएगी।

### 2026 के 4 बड़े स्मार्टफोन, तकनीक ऐसे बदलेगी

- **गूगल पिक्सल 11:** इस साल लॉन्च होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी इसका नया प्रोसेसर टेंसर जी6। अभी तक गूगल के टेंसर प्रोसेसर सैमसंग के एक्सिनॉस प्रोसेसर से काफी मिलते-जुलते रहे हैं। लेकिन कंपनी पूरी तरह से अपने इस प्रोसेसर को खुद कस्टमाइज करेगी।
- **सैमसंग गैलेक्सी एस26:** सैमसंग अपनी गैलेक्सी एस26 सीरीज में पहली बार नया प्रोसेसर एक्सिनॉस 2600 पेश करेगी। इसका फोकस पावर एफिशिएंसी पर होगा। यानी बैटरी गर्म होने की दिक्कत कम हो सकती है।
- **शाओमी 17 अल्ट्रा:** यह कंपनी का पहला फोन होगा जिसमें कैमरा फोकस रिंग के साथ डिजाइन किया गया है।
- **ओपो फाइंड एक्स9 अल्ट्रा:** यह कंपनी का पहला अल्ट्रा प्रीमियम फोन है। यह पूरी तरह से कैमरा-सेंट्रिक फोन है। इसमें 200 मेगापिक्सल सोनी के सेंसर दिया गया है।

## बेस्ट ऑफ द वीक

### 1. सैमसंग के Wi-Fi स्पीकर्स

सैमसंग ने अपने 2026 ऑडियो लाइन-अप में दो नए Wi-Fi स्पीकर्स म्यूजिक स्टूडियो 5 और म्यूजिक स्टूडियो 7 शामिल किए हैं। इसमें हाई-रेज ऑडियो सपोर्ट है, जिससे साउंड स्टेज और क्लैरिटी बेहतर होती है।

- **खासियत:** एआई-डायनेमिक बेस कंट्रोल

### 2. वॉट्सएप का न्यू ईयर अपडेट

वॉट्सएप ने नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। इसमें नए स्टिकर्स, वीडियो कॉल के लिए इफेक्ट्स व स्टेटस टूल्स शामिल हैं। यह नए फीचर्स अपडेट्स पर मिलेंगे।

- **खासियत:** रियल-टाइम इफेक्ट्स दिखेंगे।

### 3. BSNL ने शुरू किया VoWiFi

बीएसएनएल ने अपनी वॉइस ओवर वाईफाई (VoWiFi) सेवा को भारत के सभी सर्कलों में रोलआउट कर दिया है। इसे सामान्य फोन नंबर से इस्तेमाल किया जा सकता है।

- **खास:** सामान्य वाईफाई से बेहतर अनुभव।

**यूटिलिटी** स्किल, फोकस और कम्युनिकेशन बढ़ाने वाले एप्स, जानें इनके फायदे

# बच्चे को जब पहला स्मार्टफोन दें, तो ये **4 एप्स डाउनलोड करें**

© The New York Times
दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

**जब** किसी बच्चे को पहली बार स्मार्टफोन मिलता है, तो सबसे पहली मांग होती है... इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या टिकटॉक। इसी तरह बच्चे फोन पर ऑनलाइन गेम्स भी बहुत अधिक खेलते हैं। माता-पिता के मन में अक्सर डर भी वहीं से शुरू होता है कि कहीं फोन सिर्फ स्क्रॉल करने की आदत न बना दे। लेकिन सच्चाई यह भी है कि फोन अगर सही एप्स के साथ दिया जाए, तो वह सीखने, फोकस बढ़ाने और अच्छी आदतें बनाने का टूल भी बन सकता है। ऐसे में जानें वो चार एप्स, जो सीखने, ध्यान लगाने, क्रिएटिविटी और जिम्मेदारी सिखाते हैं।

## हेडस्पेस और वेवलेंथ जैसे एप उपयोगी

### 1. हेडस्पेस: स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए

हेडस्पेस ऐसा एप है, जिसमें मेडिटेशन, नींद और फोकस से जुड़े छोटे-छोटे ऑडियो सेशन होते हैं, जिन्हें बच्चा 5 से 10 मिनट में कर सकता है। एग्जाम के समय, होमवर्क का दबाव जैसे हालात में यह एप बच्चे को मन शांत करना और दोबारा फोकस बनाना सिखाता है।

- प्लेस्टोर पर 4.3 रेटिंग है।

### 2. टिकटिक: पढ़ाई और काम संभालने में मददगार

टिकटिक एक टू-डू लिस्ट और रिमाइंडर सेट करने वाला एप है। यह बच्चों को अपना होमवर्क, प्रोजेक्ट और रोज के काम खुद मैनेज करना सिखाता है। साथ में टाइम मैनेजमेंट का महत्व बताता है।

- प्ले स्टोर पर रेटिंग 4.6 है।

### 3. वेवलेंथ: सोशल मीडिया के बिना भी दोस्तों से बात करें

वेवलेंथ सवाल-जवाब वाला गेम है, जिसे अकेले नहीं खेल सकते। दोस्त या परिवार के लोग साथ जुड़ते हैं और ऐसे सवालों पर अपनी राय रखते हैं, जिनका कोई सीधा सही-गलत जवाब नहीं होता।

- प्लेस्टोर पर रेटिंग 4.7 है।

### 4. डुओलिंगो: तरह-तरह की भाषा सीखने के लिए उपयोगी

गेम की तरह डिजाइन किया गया एप है, जिसमें रोज 5 से 10 मिनट का टास्क होता है, जिससे नई भाषा सीखी जा सकती है। स्पेनिश, फ्रेंच से चाइनीज तक जैसे कई विकल्प भी मौजूद हैं।

- प्ले स्टोर पर रेटिंग 4.6 है।

**भविष्य की टेक्नोलॉजी**

# एक पेन जैसा होगा ओपनएआई का **पहला एआई डिवाइस**

**ओपनएआई** अपने पहले एआई हार्डवेयर डिवाइस पर काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट में उसके साथ हैं जॉनी आइव, वही डिजाइनर जिन्होंने आईफोन और मैकबुक जैसी आइकॉनिक डिवाइसेज को आकार दिया। अब इस सीक्रेट प्रोजेक्ट को लेकर एक नई बात सामने आई है। कुछ इंडस्ट्री टिप्स्टर के मुताबिक, ओपनएआई का यह एआई-फर्स्ट डिवाइस पेन जैसे फॉर्म फैक्टर में हो सकता है। हालांकि ओपनएआई या डिजाइनर जॉनी आइव की तरफ से अब तक इस डिवाइस को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ऑनलाइन इस पर चर्चा तेज हो गई है।

### ऑडियो डिवाइस की तरह भी काम करेगा

यह डिवाइस एआई-पावर्ड पेन जैसा हो सकता है। यह चलते-फिरते ऑडियो इनपुट और आउटपुट का काम भी कर सकता है। यूजर इसे स्मार्टफोन या किसी अन्य डिवाइस से कनेक्ट कर चैटजीपीटी से दो-तरफा बातचीत कर पाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, इस डिवाइस का निर्माण ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉम कर सकती है, जो आईफोन और गूगल पिक्सल जैसे प्रोडक्ट्स असेंबल करती है।

**रिसर्च**

# हर 5 में से 1 यूट्यूब वीडियो होता है **एआई जनरेटेड**

यूट्यूब पर नए यूजर्स को सुझाए जा रहे वीडियो में से करीब 20% वीडियो कम-गुणवत्ता वाले एआई जनरेटेड कंटेंट हैं, यानी 'एआई स्लॉप' हैं। यह दावा वीडियो-एडिटिंग कंपनी कैपविंग की एक नई स्टडी में किया गया है। कैपविंग ने दुनिया के 15,000 सबसे पॉपुलर यूट्यूब चैनलों का विश्लेषण किया। इसमें पाया गया कि 278 चैनल ऐसे हैं, जो सिर्फ AI स्लॉप वीडियो ही अपलोड कर रहे हैं। इन चैनलों को कुल मिलाकर 63 अरब व्यूज और 22.1 करोड़ सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं।



**लाइव म्यूजिक** पिछले साल देश में 34 हजार से ज्यादा कॉन्सर्ट हुए, अब लिंकिन पार्क-जॉन मेयर जैसे सितारे आ रहे

# इस साल भारत में पहली बार परफॉर्म करेंगे **7 बड़े ग्लोबल आर्टिस्ट**

**भारत** लाइव म्यूजिक डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच देश के अलग-अलग शहरों में कई बड़े इंटरनेशनल लाइव कॉन्सर्ट होने जा रहे हैं, भारत का ऑर्गनाइज्ड लाइव इवेंट सेक्टर 2024 में 12,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है और इसमें आने वाले सालों में करीब 19% सालाना ग्रोथ का अनुमान है। बीते साल 70 से 80 बड़े कॉन्सर्ट हुए, जिनमें हर एक में 10,000 से ज्यादा दर्शक पहुंचे। इस साल मई तक भारत में 8 बड़े विदेशी आर्टिस्ट टूर करेंगे, इनमें 7 सिंगर पहली बार भारत आएंगे।

## ये ग्लोबल सितारे आएंगे भारत... जानें कौन कब आ रहा?

- **जॉन मेयर: 22 जनवरी** ग्रैमी अवॉर्ड विनर जॉन पॉप म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। स्पॉटिफाई पर 3 करोड़+ मंथली लिसनर्स हैं।
- **द लूमीनीर्स: 1 फरवरी** यह बैंड स्टोरीटेलिंग म्यूजिक के लिए जाना जाता है। स्पॉटफाई पर 2 करोड़ से अधिक मंथली लिसनर्स हैं। भारत में यह उनका पहला लाइव शो है।

- **लिंकिन पार्क: 23 जनवरी:** स्पॉटिफाई पर 4 करोड़ से अधिक मंथली लिसनर्स हैं। भारत में उनका फैनबेस मजबूत रहा है। इस बैंड का देश में पहला टूर है।
- **कैल्विन हैरिस: 17 अप्रैल** दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले डीजे में शामिल। 6 करोड़+ मंथली लिसनर्स हैं।
- **डेफ लेपर्ड: 25 मार्च** सबसे बड़े बैंड्स में शामिल, जिनके एल्बम्स की 10 करोड़+ कॉपियां बिक चुकी हैं। भारत में यह इनका मल्टी-सिटी टूर होगा।

### म्यूजिक टूरिज्म: 5 लाख लोगों ने ट्रैवल किया

पिछले साल देशभर में 34,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट और लाइव शोज हुए, जिनके लिए 5.6 लाख से अधिक लोग एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचे। इससे न सिर्फ कॉन्सर्ट कल्चर को बढ़ावा मिला, बल्कि होटल, ट्रैवल और लोकल बिजनेस को भी बड़ा फायदा हुआ।

**फैशन इस हफ्ते**

# ट्रेंड फटीग: प्रयोग से दूरी, अब सिंपल कपड़े चुन रहे लोग

FAST COMPANY
से विशेष

**कुछ** महीने पहले तक सोशल मीडिया पर अजीब तरह के जूते, स्टेटमेंट स्क्रंची और नए-नए फैशन ट्रेंड छाए रहते थे। लेकिन अब लगातार बदलते फैशन से लोग थकने लगे हैं। इसे ही 'ट्रेंड फटीग' कहा जा रहा है, यानी हर बार नए ट्रेंड के पीछे भागने से लोगों का मन उचट जाना। पर्सनल स्टाइलिंग कंपनी स्टिच फिक्स का कहना है कि उसके करीब दो-तिहाई ग्राहक अब ट्रेंड्स पर ध्यान ही नहीं दे रहे। लोग ऐसे कपड़े चाहते हैं जो लंबे समय तक चलें और हर जगह काम आ सकें।

### • हल्के रंग के कपड़े पसंद कर रहे लोग

अब लोग पूरी तरह रंगीन कपड़े पहनने के बजाय बेसिक आउटफिट के साथ थोड़ा सा रंग जोड़ना पसंद कर रहे हैं। स्टिच फिक्स के अनुसार, चिली रेड जैसे रंगों की बिक्री बढ़ी है, लेकिन सिर्फ बैग या ज्वेलरी जैसे छोटे आइटम्स में। आउटफिट में लोग हल्के रंग चुन रहे हैं।

### • बेसिक लेकिन क्लासिक कपड़ों की मांग बढ़ी

स्टिच फिक्स के मुताबिक, अब ज्यादातर लोग सिंपल कपड़े मांग रहे हैं, जैसे ब्लैक टॉप, सफेद शर्ट और आसान डिजाइन। कंपनी का कहना है कि ग्राहक अब ट्रेंड से ज्यादा ऐसे कपड़ों की मांग कर रहे हैं जो क्लासिक और मल्टी पर्पज हों।

### • नया खरीदने के दबाव से थक रहे

फास्ट फैशन ब्रांड्स ने फैशन की रफ्तार बहुत तेज कर दी। हर हफ्ते कोई नया ट्रेंड सामने आता है और कुछ ही दिनों में खत्म भी हो जाता है। लगातार नया खरीदने का दबाव लोगों को थका रहा है। कई लोग मानते हैं कि इतने ज्यादा ट्रेंड्स के बीच समझ ही नहीं आता कि क्या पहनें, इसलिए वे नजरअंदाज करने लगे हैं।

### • ट्रेंड्स से दूरी फायदेमंद बन रही

फैशन ट्रेंड से दूरी पर्यावरण के लिए भी अच्छी मानी जा रही है। कम कपड़े खरीदना और टिकाऊ स्टाइल अपनाना इसका एक तरीका है। फास्ट फैशन के कारण बड़ी मात्रा में कपड़े बेकार हो जाते है। साथ ही, लोग सेलिब्रिटीज की सादी और भरोसेमंद स्टाइल से भी इंस्पायर हो रहे हैं। अब फैशन समझदारी की ओर बढ़ रहा है।

**ट्रैवल**

# हशपिटेलिटी: साइलेंट ट्रैवल बना नई लग्जरी

**शांति** और सुकून अब सामान्य चीज नहीं रही। ट्रैफिक, नोटिफिकेशन, कॉल, स्क्रीन और लगातार चलती आवाजों के बीच लग्जरी होती जा रही है। इसी वजह से 2026 में ट्रैवल की दुनिया में 'हशपिटैलिटी' ट्रेंड उभरा है। यह एक ऐसा ट्रैवल एक्सपीरियंस है जहां भीड़, म्यूजिक और एक्टिविटीज सीमित होती हैं और खामोशी ही सबसे बड़ा अनुभव बन जाती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित कोको शंबाला है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर अपनी फैमिली के साथ यहां घूमने गए थे। यह भीड़ से दूर शांत अनुभव के लिए प्रसिद्ध है।

### अब होटल भी डिजाइन कर रहे हैं साइलेंट ट्रैवल जैसे अनुभव

दुनिया भर में होटल और रिसॉर्ट्स अब साइलेंट ट्रैवल पर काम कर रहे हैं, यानी ऐसी प्लानिंग, जहां शोर अंदर पहुंचे ही नहीं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित कोको शंबाला का ही उदाहरण लें तो यहां कई तरह के ट्रैवल पैकेज हैं। जैसे-प्रपोजल पैकेज, बर्थडे पैकेज और हनीमून पैकेज। इसमें ट्रैवल से लेकर फूड जैसी सभी सुविधाएं मिलती हैं, हालांकि इस तरह के पैकेज की कीमत 2 से 3 लाख रुपए होती है।

**एंटरटेनमेंट** मार्वल और डीसी के प्रसिद्ध सुपरहीरो दोबारा स्क्रीन पर लौटेंगे

# स्पाइडरमैन से एवेंजर्स तक: 2026 में हॉलीवुड लाएगा **23 सीक्वल फिल्में**

भास्कर रिसर्च

**2026** सिनेमा के लिए पुरानी हिट कहानियों की वापसी का साल बनने जा रहा है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, थिएटर में इस साल दो बड़े ट्रेंड साफ दिखेंगे। सीक्वल फिल्मों की भरमार और सुपरहीरो यूनिवर्स की वापसी। सिर्फ हॉलीवुड की बात करें तो सिनेमा ब्लेंड की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में 23 सीक्वल फिल्में रिलीज होंगी। इनमें से 8 से 10 फिल्में सुपरहीरो जॉनर की होंगी। एवेंजर्स: डूम्सडे, स्पाइडरमैन, ड्यून पार्ट-3 और जुमांजी-4 जैसी बड़ी फ्रेंचाइज इस लिस्ट में शामिल हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिलहाल एवेंजर्स की दो नई फिल्मों पर काम कर रहा है। 2019 में आई एवेंजर्स: एंडगेम के बाद यह मार्वल का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। हालांकि सुपरहीरो फिल्मों का यह ट्रेंड 2025 से ही तेज हो गया था। पिछले साल भी कैप्टन अमेरिका, फैंटास्टिक फोर और सुपरमैन जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं।

## हॉलीवुड: ये होंगी साल की बड़ी सीक्वल फिल्में

### • एवेंजर्स:डूम्सडे

• रिलीज: 18 दिसंबर

यह मल्टीवर्स के कई किरदारों को एक साथ लाएगा, जिसमें थॉर (क्रिस हेम्सवर्थ), कुछ फैंटेस्टिक फोर और पुराने एवेंजर्स शामिल होंगे।

### • ड्यून पार्ट-3

• रिलीज: 18 दिसंबर

टिमोथी चालामेट, जेंडाया और रॉबर्ट पैटिंसन इसमें मुख्य रोल में हैं। यह फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट होगा। यह स्पेस ओपेरा जॉनर की फिल्म है।

### • स्पाइडरमैन 4

• रिलीज: जुलाई 2026

टॉम हॉलैंड, जेंडाया और जैकब बतालोन मुख्य रोल में हैं। यह आखिरी पार्ट 'नो वे होम' के बाद के नए चैलेंज पर आधारित होगी।

### • द डेविल वियर्स प्राडा-2

• रिलीज: 1 मई

मेरियल स्ट्रीप और ऐनी हैथवे वापस मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। इसमें फैशन इंडस्ट्री में आज के बदलाव जैसे विषयों पर फोकस होगा।

### • द सोशल रिकॉनिंग

• रिलीज: 9 अक्टूबर

यह द सोशल नेटवर्क फिल्म का सीक्वल है। फिल्म की कहानी फेसबुक से जुड़े विवादों पर केंद्रित होगी, खासकर प्राइवेसी लीक्स पर।

### बॉलीवुड में 8 सीक्वल फिल्में रिलीज होंगी

2026 में बॉलीवुड बड़े पर्दे पर सीक्वल्स का दमदार साल बनने जा रहा है। इस साल दर्शकों को पुराने आइकॉनिक किरदारों की वापसी देखने को मिलेगी। बॉर्डर 2 और दृश्यम 3 जैसी फिल्मों के साथ कई बड़े सीक्वल रिलीज की कतार में हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल करीब 8-10 सीक्वल फिल्में रिलीज हो सकती हैं। इसमें रानी मुखर्जी की मर्दानी-3, अक्षय कुमार की वेलकम टू जंगल और रणवीर सिंह की धुरंधर-2 भी शामिल हैं।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**



राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

# सुंदरता नहीं, जनस्वास्थ्य हो शहरों की प्राथमिकता

दूषित पानी पीने से मौत की घटना देश में कहीं भी हो- शर्मनाक है। इंदौर जैसे शहर में ऐसी घटना का होना और भी चिंता की बात है क्योंकि यह शहर कई वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा लिए फिरता है। स्वच्छता सर्वेक्षणों में लगातार अव्वल आने वाले शहर में अगर सैंकड़ों लोग दूषित पानी के कारण बीमार पड़ जाएं और उन्हें जीवन-मौत से जूझना पड़े, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या 'स्वच्छता' का अर्थ केवल सड़कों की सफाई और पेंटिंग तक ही सीमित है? क्या नागरिकों को शुद्ध पेयजल जैसा मौलिक अधिकार देना नगर निगम और प्रशासन की प्राथमिकता में नहीं है? यह त्रासदी हमें इसलिए भी झकझोरती है क्योंकि अन्य शहरों के मुकाबले यहां कहीं अधिक चाक-चौबंद व्यवस्था की अपेक्षा रही है। यह महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि व्यवस्थागत विफलता का भयावह चेहरा है। जिम्मेदारों पर आपराधिक लापरवाही की कार्रवाई होनी चाहिए।

इंदौर के भागीरथपुरा की घटना ने यह साबित कर दिया है कि स्वच्छता का जो महल खड़ा किया गया है, उसकी नींव में बुनियादी ढांचे की भारी कमजोरी है। पाइपलाइन में लीकेज के कारण गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें की जा रही थीं लेकिन, प्रशासन की कुंभकर्णी नींद तब तक नहीं खुली, जब तक घरों से अर्थियां नहीं निकलीं। जब जनता अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए गुहार लगा रही हो और जिम्मेदार अधिकारी उदासीन रहें तो इसे 'आपराधिक लापरवाही' के अलावा और क्या नाम दिया जाए? इस त्रासदी में सबसे अधिक आहत करने वाला पहलू मंत्री एवं स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय का रवैया रहा है। लोकतंत्र में जनता अपने नुमाइंदों को इसलिए चुनती है कि वे संकट के समय उनके साथ खड़े होंगे, न कि इसलिए कि वे उनकी मौतों को 'फोकट की बात' करार देंगे। एक तरफ इंदौर को 'स्मार्ट सिटी' और 'स्वच्छ शहर' के रूप में ग्लोबल ब्रांड बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं के अभाव में गरीब बस्तियों के लोग दम तोड़ रहे हैं। ऊपर से राजनीतिक नेतृत्व का यह अहंकार न केवल निंदनीय है, बल्कि यह उस भरोसे का कत्ल भी है जो जनता अपने प्रतिनिधियों पर करती है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी इस मामले में एक उम्मीद की किरण है। अदालत ने स्पष्ट रूप से प्रशासन की विफलता को रेखांकित किया है। फौरी तौर पर कुछ अधिकारियों पर हुई कार्रवाई इस समस्या का समाधान नहीं है। पानी की पाइपलाइनों का ड्रेनेज लाइनों के साथ मिलना या उनमें लीकेज होना कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन इसकी नियमित निगरानी की कमी एक बड़ा अपराध है। यह घटना केवल इंदौर के लिए नहीं, बल्कि देश के उन तमाम शहरों के लिए एक चेतावनी है जो बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज कर बाहरी सौंदर्यीकरण पर पैसा बहा रहे हैं। जन-स्वास्थ्य किसी भी शहर की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

**माया कहने को ब्रह्म की शक्ति है,** वास्तव में तो कर्ता-धर्ता माया ही है। ब्रह्म तो साक्षी भाव है। दोनों रहते साथ हैं। माया की भूमिका को देखकर मानवी (स्त्री) की भूमिका समझ में आ जाती है।

# माया ही विश्व संचालिका

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

**शरीर ही ब्रह्माण्ड**

सभी स्तरों पर ब्रह्म मात्र चलाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर- माया द्वारा। स्वयं कुछ करता ही नहीं है। सम्पूर्ण विश्व की रचना, संचालन, पोषण-रक्षण आदि कार्य माया एवं प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं।

अव्यक्त आत्मा का अर्थ है ऋत सृष्टि। ऋताग्नि तथा ऋत सोम से ही व्यक्तात्मा उत्पन्न होता है। इसी को अव्यय या द्विनियति कहा है। अव्यय का विद्या भाग स्थिर-अनेजत् तथा अविद्या भाग- एजत्- गतिमान है। विद्या रस प्रधान, कर्म भाग बल प्रधान है। आनन्द-विज्ञान-मन ही परात्पर है (अविद्या गर्भित)। बल भाग क्षणिक, क्षोभ रूप है। इस क्षोभ के कारण अव्यय पुरुष असत् है। रस भाग अक्षण, शान्ति रूप है। अतः इसको सत् कहते हैं। नित्य शान्त अमृत-मृत्यु रूप सदसत् तत्त्व ही ओंकार है। ईश्वर है। वही अहंकार (जीव) है, वही अहस्कार (विश्व) है। अमृत-मृत्यु मूल में एक ही है।

अव्यय की पांच कलाएं हैं–आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण और वाक्। विद्या (स्थिति) और अविद्या (गति) दोनों मन के भीतर ही समाहित हैं। दोनों एकतत्त्व हैं- अभिन्न सत्ता भाव है। इसी एक तत्त्व (मन) में मातरिश्वा अप् (कर्म) का आधान करता है। मन की प्राण कला के क्षोभ से वाक् (अप्) उत्पन्न होता है। स्वयंभू (अव्यय) का प्राण ही ब्रह्मनिःश्वसित वेद है। इसी वेद वाक् से पानी उत्पन्न होता है। अर्थात्–वेदमूर्ति अव्यय पर ही अबाहुति संभव है। अव्यय स्वयं विद्याकर्ममय है। अतः इसके आत्मक्षर के पंचीकृत प्राणभाग से प्रकट होने वाला वेद भी विद्याकर्ममय ही है।

अव्यय मन में कामना रूप कर्म के कारण प्राण कला से वाक् (जल) पैदा हुआ। जो सोम चारों ओर फैला था, वही उष्ण होकर जल (आप) बना। इस में वेदत्रयी युक्त अव्यय मन प्रविष्ट हो जाता है। प्रविष्ट ही रहता है। इसी भाग को महत् लोक कहते हैं। शेष परमेष्ठी सोममयी रहती है। भृगु-अंगिरा-अत्रि परमेष्ठी के मनोता हैं। भृगु का सोम अंगिरा के अग्नि में (अत्रि के धरातल पर) आहुत होता है। अत्रि पर पड़ा बिम्ब ही जीव कहलाता है। इसी पर अहंकृति-प्रकृति-आकृति के बिम्ब पड़ते हैं। पहली कृति सूर्य ही बनता है।

अव्यय-अक्षर-क्षर की 15 कलाओं से युक्त परात्पर ही षोडशकल सूर्य जगत की पहली आत्म सृष्टि है। आगे की सृष्टि के लिए यही सबका आत्मा बनता है। **'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च...'** कहा है। यही सूर्य (विवस्वान) गीता ज्ञान का प्रथम ग्राहक है। सूर्य के केन्द्र में जो केन्द्रस्थ पुरुष है, वही मनु है। सूर्य से बुद्धि, चन्द्रमा से मन, पृथ्वी से शरीर का सम्बन्ध है, वहीं इस आत्मरूप मनु के समन्वय के साथ ही 'मानव' की उत्पत्ति हुई। सूर्य विराट है। भृगु-अंगिरा-वेद के दस अंगों से विराट बना। वही **'सहस्रशीर्षा-सहस्राक्षः'** पुरुष है। मानव के भी यही शक्ति लक्षण हो जाते हैं–

**सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्।**
**सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति।।** (गीता 13.13)

यह है विराट पुरुष सूर्य। इसका शरीर तो एक कृष्ण पिण्ड मात्र है, शेष जो कुछ महिमा है विश्व में, इसकी रश्मियां हैं। ये ही राधा के नाम से जानी जाती हैं। शक्तिरूपा रश्मियां ही सूर्य के सारे कर्म संचालित करती हैं। परमेष्ठी लोक से सोम ग्रहण करके रश्मियां ही सूर्य ज्योति और तापमान को प्रतिष्ठित रखती हैं। सोम के माध्यम से सूर्याग्नि में आहुति के कारण ब्रह्म का आहरण होता है। रश्मियां ही माया भाव में पंचाग्नि सिद्धान्त को प्रतिष्ठित करती हैं–**'यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः।।'** (3.14)

यज्ञ से पर्जन्य (बादल) उत्पन्न होता है। रश्मियां दिन में समुद्र से जल लेकर आती हैं। जल को बादलों में वर्षा ऋतु पर्यन्त संग्रह करती हैं। नौ माह गर्भ में रखती हैं। इसी बादल में परमेष्ठी सोम (अन्न) द्वारा प्रेषित ब्रह्मांश पलता रहता है। वर्षा ऋतु में विद्युताग्नि के योग से अग्नि-सोम यज्ञ होकर वर्षा होती है। ब्रह्म का प्रसव होकर वह पृथ्वी की अग्नि में आहुत होकर अन्न बनता है। ब्रह्मांश सूर्य से आता है अतः वही हमारा पिता बनता है, धरती माता। राधा और वर्षा जल दोनों ही ब्रह्म का माया रूप होकर स्थानान्तरण करती हैं। देखा जाये तो जिस प्रकार सूर्य सहस्रशीर्षा पुरुष है, वैसे ही पर्जन्य और पृथ्वी का भी स्वरूप है। समष्टि भाव के कारण विराट ही हैं। आगे प्राणी शरीर में माया भी व्यष्टि रूप ही कार्य करती है।

सभी स्तरों पर ब्रह्म मात्र चलाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर- माया द्वारा। स्वयं कुछ करता ही नहीं है। सम्पूर्ण विश्व की रचना, संचालन, पोषण-रक्षण आदि कार्य माया एवं प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। मानव जीवन भी इसी की प्रतिकृति है–यथाण्डे तथा ब्रह्माण्डे। माया ही तय करती है कि किस समुद्र का किस दिन का पानी किस देश में और कहां बरसेगा। वहीं जीवात्मा पैदा होगा। वहीं औषधि और वनस्पति (उसी अनुरूप) पैदा होंगे। जलाशयों में भावी उपयोग के लिए जल संग्रहित होगा।

अन्न का (अनाज-फल-मेवे-घास आदि) पैदा होना ही काफी नहीं है। उसे भी उसी प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों तक पहुंचाना है, आयात-निर्यात करना है, रोगग्रस्त करना है, कीड़े लगेंगे या नहीं, कीटनाशक कितना भोक्ता के शरीर में पहुंचेगा आदि अनेक आयामों पर विचार होगा। कहां कौनसा अन्न दान में दिया जाएगा, यज्ञ में उपयोग किया जाएगा, मन्दिरों में चढ़ेगा, जीव-जन्तु (पशु-पक्षी-चींटी) खाएंगे अथवा सड़ जाएगा। चूंकि अन्न ब्रह्म है, अतः इसके वितरण-भोगादि पर जो कुछ निर्णय किए जाएंगे, उनमें भी माया की भूमिका माननी पड़ेगी।

अन्न ही वैश्वानर अग्नि में आहुत होकर भोक्ता के शरीर का निर्माण भी करता है, शुक्र-शोणित का निर्माण भी करता है। जीवात्मा का स्थानान्तरण भी करता है, अतः माया के निर्णय ही निर्माण में प्रभावी होते हैं। माया कहने को ब्रह्म की शक्ति है, वास्तव में तो कर्ता-धर्ता माया ही है। ब्रह्म तो साक्षी भाव है। दोनों रहते साथ हैं। माया की भूमिका को देखकर मानवी (स्त्री) की भूमिका समझ में आ जाती है।

आज एकल जीवन में माया स्त्रैण पक्ष में कोई भूमिका नहीं निभाती। वहां महामाया और योगमाया का साम्राज्य है। ऋत रूप होने से, स्वभाव से चंचल है, कोई कामना पूर्ण होने का नाम नहीं। जीवन में स्थायी भाव संभव नहीं। लिव-इन का स्वरूप और भी भयानक। दोनों पर किसी प्रकार का नैतिक दबाव नहीं हैं। दोनों स्वच्छन्द हैं। कब कौन किसको छोड़ दे, हर हाल में जाना तो स्त्री को ही पड़ेगा। चूंकि लिव-इन में आमतौर पर सन्तान की चर्चा नहीं होती, माया ब्रह्म की कामना रूपता का उपयोग नहीं करती। ब्रह्म और माया दोनों सुप्त रहते हैं। जीवन केवल प्रकृति चलाती है। स्त्री को भी सन्तान के लिए स्वीकृति माया की चाहिए। लव जिहाद में भी नहीं मिलती। पुरुष के पास संवेदना होती ही नहीं। बलात्कार माया तक नहीं पहुंचता। सन्तति भी भावशून्य ही होती है। आक्रामकता लिए होती है। सन्तति का व्यक्तित्व दम्पती के मनोभावों पर टिका होता है।

-क्रमशः

gulabkothari@epatrika.com

क्यूआर कोड को स्कैन कर आप आलेख सुन भी सकते हैं।

## बुक इनसाइट

### हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर

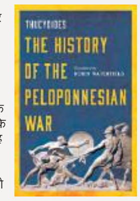


थूकिदीदीस की लिखित 'द हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर' प्राचीन ग्रीस के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण कृति है। यह पुस्तक ग्रीस के दो प्रमुख शहर-राज्यों, एथेंस और स्पार्टा के बीच 431 ई.पू. से लेकर 404 ई.पू. तक हुए युद्ध की गहराई से पड़ताल करती है। लेखक ने इस युद्ध की घटनाओं को न केवल एक इतिहासकार की दृष्टि से, बल्कि एक नीतिज्ञ और सैनिक नेता के रूप में भी प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक युद्ध की घटनाओं का विवरण देती है, लेकिन इसके साथ ही मानव स्वभाव, युद्ध की नीति और सत्ता के संघर्ष पर भी गहरी टिप्पणी करती है। थूकिदीदीस ने यह बताया कि युद्ध केवल सैनिक संघर्ष नहीं होता बल्कि इसे राजनीति, समाज और मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए। पुस्तक में लेखक ने दोनों पक्षों के नेताओं और सैनिकों के विचार, रणनीतियों और उनके निर्णयों का विश्लेषण किया है।

## आर्ट एंड कल्चर

### गोल घेरा यानी नृत्य कला का उद्गम

चिन्मय मिश्र
वरिष्ठ संस्कृतिकर्मी
@patrika.com

मनुष्य ने नृत्य करना कब प्रारंभ किया होगा? जाहिर है इसके लिए कोई विशिष्ट काल निर्धारण तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यह तो तय है कि मनुष्य सृष्टि की शुरुआत से ही नृत्य करता आ रहा है। कभी हम उसे अनुष्ठानिक नृत्य करते देखते हैं, तो कभी युद्ध नृत्य। कहीं उसकी प्रकृति के प्रति श्रद्धा और विश्वास नृत्य मुद्रा में दिखती है तो कहीं उसका नृत्य दर्शाता है कि कैसे फसल बोई जाती है और कैसे काटी जाती है। आदिवासियों के नृत्य आखेट और प्रेम, दोनों को अपनी देह की लय और गति से साकार करते दिखाई दे जाते हैं। परंतु ऐसा अनायास नहीं, बल्कि क्रमबद्ध विकास या प्रक्रिया से हुआ। नृत्य का उदय तो संभवतः स्वस्फूर्ति से ही हुआ है। साथ ही जंगल निवासी पशु-पक्षियों की गतिविधियों ने भी मनुष्य को लय का आभास कराया। धीरे-धीरे मनुष्य एक समूह का हिस्सा बनता चला गया और उसका वैयक्तिक अस्तित्व समूह में समाहित होता चला गया। वह सामूहिक गतिविधियों का हिस्सा बन गया। उसका सिर्फ स्वयं के बारे में सोचना और उत्तेजित होना कम होने लगा था। वह अपनी भावनाओं पर काबू पाकर दूसरों की भावनाओं को समझने और एक सामूहिक परिणिति पर पहुंचने की ओर अग्रसर होने लगा था। इसी प्रक्रिया में आदिवासी और लोकनृत्यों की शुरुआत हुई। यह एक ऐसा कर्म था जिसकी लय को सभी साझा करते थे। इसलिए आज जब इन नृत्यों को ध्यान से देखते हैं तो उनमें व्याप्त आदिम प्रवृत्ति अब भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती दिखाई देती है। उसकी लयात्मकता, विन्यास की सरलता, जोश और ताकत का समन्वय हमें परिपूर्णता का साक्षात्कार कराता है।

आदिवासी नृत्य में नर्तक एक गोल घेरे में ही नृत्य करते हैं। ऐसा क्यों? गौर से समझेंगे तो पाएंगें कि घेरे में एक परिपूर्ण एकता मौजूद रहती है। प्रत्येक व्यक्ति समूह के अन्य व्यक्ति से जुड़ा होता है और इसी वजह से व्यक्ति की पहचान सम्पूर्णता से होती जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को केंद्र में स्थान मिलता है और इसी वजह से समूह में होते हुए भी उसकी व्यक्तिगत पहचान बनी रहती है। वह हमेशा मुख्य समूह का अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा बना रहता है।

सोचिए, किस तरह एक अनियोजित गतिविधि घेरे में बदलकर सामूहिक गतिविधि बन गई होगी, पता ही नहीं चला होगा। यह स्वस्फूर्त परिकल्पना कमोबेश हमारी पृथ्वी (जो कि गोल है और अपनी कक्षा व धुरी पर परिक्रमा करती है) से अनायास ही जुड़ गई। गोलाई में नृत्य, पृथ्वी का अपनी धुरी पर निरंतर घूमना और सूर्य और चंद्रमा द्वारा परिक्रमा कमोबेश निरन्तरता का बोध कराते हैं। हमारे पारंपरिक नृत्य भी उसी निरन्तरता और शाश्वतता को हमें संप्रेषित करते हैं। आज हम इन्हें अमूर्त या कुछ और नाम दे देते हैं, परंतु वास्तविकता तो यही है कि नृत्य ने हमारे जीवन को सार्थकता की ओर अग्रसर किया है।

**दृष्टिकोण** अमरीका-चीन के मध्य तकनीकी प्रतिस्पर्धा भविष्य का निर्धारण करेगी

# जी-2 समीकरण और भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां

डॉ. मिलिंद कुमार शर्मा
प्रोफेसर, एमबीएम विवि, जोधपुर
@patrika.com

कुछ सप्ताह पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के मध्य दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई भेंट को इन दो राष्ट्रों के जी-2 गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है। इक्कीसवीं सदी की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अमरीका और चीन दो ऐसी महाशक्तियां हैं जिनका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, विज्ञान, तकनीक और कूटनीति पर स्पष्ट एवं प्रभावी रूप से देखा जा सकता है। हाल के वर्षों में जी-2 गठबंधन की अवधारणा चर्चा में रही है, जिसमें यह कल्पना की जाती है कि अमरीका और चीन मिलकर वैश्विक प्रकरणों की दिशा एवं भविष्य निर्धारित करेंगे। इसके औपचारिक गठबंधन न होने के उपरांत भी इन दोनों राष्ट्रों के मध्य सहयोग व प्रतिस्पर्धा का संतुलन विश्व व्यवस्था को अत्यंत गहराई से प्रभावित करता है। ऐसे में निसंदेह भारत जैसे उभरती वैश्विक आर्थिक शक्ति के लिए यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण है कि अमरीका-चीन के संभावित जी-2 गठबंधन समीकरण के मध्य वह अपनी रणनीति किस प्रकार निर्धारित करे।

सर्वप्रथम, भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए अत्यंत सजग रहना होगा। भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत सर्वदा यह रहा है कि वह किसी एक शक्ति-गुट या ध्रुव पर पूर्ण निर्भर न रहे। यह रेखांकित करना उचित होगा कि अमरीका और चीन दोनों से भारत के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं- अमरीका के साथ रक्षा, विज्ञान, तकनीक और व्यापारिक सहयोग है, तो वहीं दूसरी ओर चीन सीमा विवाद के उपरांत भी भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जी-2 गठबंधन की स्थिति में भारत को किसी एक पक्ष का 'अनुयायी' बनने की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने होंगे।

दूसरे, भारत को आर्थिक सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल देना होगा। यदि अमरीका और चीन मिलकर वैश्विक आर्थिक नियम निर्धारित करते हैं, तो विकासशील देशों के हितों की अनदेखी होने की प्रबल संभावना रह सकती है। आर्थिक रूप से सुदृढ़ भारत ही वैश्विक शक्ति संतुलन में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। साथ ही भारत को बहुपक्षीय कूटनीति को और भी प्रभावी एवं सशक्त करना होगा। जी-2 गठबंधन जैसे द्विध्रुवीय ढांचे के स्थान पर भारत सदैव बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थक रहा है। इसलिए भारत को संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, जी-20 और क्वाड जैसे मंचों पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इसके अतिरिक्त भारत को सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करना होगा। अमरीका-चीन प्रतिस्पर्धा का एक बड़ा क्षेत्र हिंद-प्रशांत है, जहां भारत की भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत को अपनी नौसेना, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षमताओं को सुदृढ़ करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा में जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी। साथ ही, सीमा विवादों के उपरांत भी चीन के साथ अनवरत संवाद बनाए रख और संघर्ष टालने के लिए प्रयास करने आवश्यक हैं।

हमें वैश्विक दक्षिण 'ग्लोबल साउथ' में सफल नेतृत्वकर्ता बनकर उभरने के लिए अनवरत प्रयास करने होंगे। भारत के लिए विज्ञान, तकनीक, कौशल और नवाचार में तेजी से निवेश अत्यंत आवश्यक है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि अमरीका-चीन के मध्य तकनीकी प्रतिस्पर्धा यथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5जी/6जी, सेमीकंडक्टर और हरित तकनीक- भविष्य की शक्ति का निर्धारण करेगी। भारत को शिक्षा, अनुसंधान और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ कर तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने होंगे, जिससे वह किसी भी जी-2 गठबंधन व्यवस्था में पिछड़ा न रहे। जब वैश्विक राजनीति में सत्ता-केंद्रित और प्रतिस्पर्धात्मक रवैया बढ़ रहा है, भारत अपने मूल्यों के माध्यम से विश्व को वैकल्पिक नेतृत्व का मार्ग दिखा सकता है।

## चीन में हवा में तैरते तीन अनोखे पुलों से बना रूयी ब्रिज

*चीन के झेजियांग प्रांत के ताइझोउ शहर में शेनशियानजु घाटी के ऊपर फैला अनोखा पुल वास्तव में तीन अलग-अलग पुलों से मिलकर बना है, जो हवा में तैरते से प्रतीत होते हैं। इसकी संरचना पारंपरिक चीनी 'रूयी' प्रतीक से प्रेरित है, जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। रूयी ब्रिज की सबसे बड़ी विशेषता इसका कांच की फर्श वाला वॉकवे है।*

## आपकी बात

### सोशल मीडिया की सीमाएं तय करें

**बच्चों** एवं किशोरों के लिए सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। यह उन्हें दोस्तों से जुड़ने, सीखने और सहायता पाने के अवसर देता है, लेकिन कई गंभीर जोखिम भी पैदा करता है। बच्चों के बढ़ते दिमाग के लिए इसके उपयोग की सीमाएं निर्धारित करना जरूरी है। समय रहते सोशल मीडिया के उचित उपयोग के लिए नियम बनाने चाहिए। - **सुरेश मांजू,** फलौदी

### संतुलित नीति बनाने की जरूरत

**शहरों** और कस्बों में आवारा श्वानों के हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। माता-पिता के मन में असुरक्षा व चिंता बढ़ रही है। नसबंदी और टीकाकरण की धीमी प्रक्रिया के कारण इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके लिए ठोस और संतुलित नीति बनाने की आवश्यकता है।

- **लहर सनाढ्य,** उदयपुर

### प्रदूषण को कम करना आवश्यक

**देश** में बढ़ते प्रदूषण का एक बड़ा कारण पुराने उद्योगों की कमजोर निगरानी, आधुनिक जीवनशैली से उत्पन्न प्रदूषण व प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सीमित अधिकार हैं। जागरूकता के साथ प्रदूषण नियंत्रण मंडल को सीधी व त्वरित कार्रवाई का अधिकार मिले, तो हालात सुधर सकते हैं। सिर्फ एनजीटी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है।

- **बी.एल. शर्मा,** उज्जैन

**आज का सवाल**

**नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए?**

ईमेल करें: edit@epatrika.com

**सावित्रीबाई फुले जयंती** पति ज्योतिराव फुले ने उनके सपने को साकार करने में पूरा साथ दिया

# कुरीतियों के अंधेरे में शिक्षा की मशाल जलाकर नई राह बनाई

राजेन्द्र गहलोत
सांसद, राज्यसभा
@patrika.com

कहते हैं, जहां चाह होती है वहां राह अपने आप निकल आती है। भले ही फिर दौर कोई भी हो। हमारा देश सामाजिक कुरीतियों के जंजाल में सदियों से फंसा हुआ है। इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए हर दौर में समाज सुधारक सामने आए हैं, जिन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। ऐसे ही समाज सुधारकों में एक नाम सावित्री बाई फुले का भी है, जिन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने की पहल की।

कल्पना कीजिए, लगभग पौने दो सौ साल पहले अगर कोई लड़कियों को विद्यालय भेजने की बात कहता होगा तो समाज की प्रतिक्रिया किस रूप में सामने आती होगी और वो भी एक 18 साल की लड़की अगर समाज के विरोध को दरकिनार करते हुए लड़कियों को शिक्षित करने की आवाज न सिर्फ उठाए बल्कि एक विद्यालय खोलकर नए युग की

शुरुआत करे तो आश्चर्य तो होगा ही। जी हां, आज से लगभग 195 साल पहले 1831 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के सतारा जिले के नयागांव में जन्मीं सावित्रीबाई फुले ने उस दौर में वह किया जो शायद सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। यह किसी से छिपा नहीं है कि आजादी से पहले देश में महिलाओं की हालत अच्छी नहीं थी। उन्नीसवीं सदी के पूर्वाह्न में लड़कियों का विद्यालय जाना एक तरह से पाप समझा जाता था। उस समय अपने पति के सहयोग से सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में बालिका विद्यालय खोला। सावित्रीबाई स्वयं अधिक पढ़ी नहीं थीं, लेकिन उनके पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें आगे पढ़ाया भी और बालिका शिक्षा की उनकी चाह के लिए राह भी प्रदान की।

उनके विद्यालय में पहले दिन सिर्फ नौ छात्राएं आई थी लेकिन धीरे-धीरे उनकी मुहिम रंग लाई। समाज के विरोध के बावजूद सावित्रीबाई अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाती गईं। उस दौर में अपने पति के अलावा सावित्रीबाई का साथ देने वाले कम और विरोध करने वाले अधिक थे। बालिका शिक्षा के साथ-साथ छुआछूत और विधवा विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने में भी उन्होंने अनूठे कार्य किए। अनेक आश्रम भी खोले और छुआछूत को मिटाने में समाज को जागृत किया। सावित्रीबाई फुले की मुहिम रंग तो लाई लेकिन धीमी गति से। सावित्रीबाई के निधन के 50 साल बाद देश को आजादी मिली लेकिन तब भी हर 12 लड़कियों में से 11 निरक्षर ही होती थी।

आजादी के बाद देश की चुनी हुई सरकारों ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास किए। पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालिका शिक्षा के महत्व को अलग रूप दिया। उन्होंने बेटी पढ़ाओ की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। पीएम मोदी का मानना है कि बेटी तभी पढ़ेगी जब वह बचेगी। पिछले 11 साल से ये नारा जन-जन के मन तक पहुंच चुका है। सरकार इसी गति से काम करती रही तो जल्द देश में कोई बालिका अशिक्षित नहीं रहेगी।

“ इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है, जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं।

–एपीजे अब्दुल कलाम

## कालेज के सान्निध्य में मौत

**दीवारें** चीख रही हैं, एक कालेज की स्याह मुट्ठी और पुलिस के टूटे हाथों में गुनाह फिसल गया। एक शार्गिद की शवयात्रा में धर्मशाला कालेज का जुलूस निकल गया। छात्रा की मौत के सौ बहाने ढूंढे जाएंगे, लेकिन सारे दर्पण आकर टूट रहे हैं। आई होंगी कई शिकायतें कालेज प्रशासन के पास और पुलिस के पास भी एक बेटी की फरियाद क्यों ढह गई, कोई नहीं जानता। मौत खुद बोली है, तो सोशल मीडिया में तैर रहीं वीडियो में हर आंख के आंसू बेचैन हैं। यह एक छोटा किस्सा नहीं, छात्रा के जीवन का विकराल अंत है। हजारों प्रश्न और अब हजारों वकील भी होंगे, लेकिन इस जुर्म के सामाजिक कारण जिंदा हैं। क्या कालेज में जातीय प्रताड़ना का मनहूस साया दौड़ता रहा या कोई अध्यापक अपनी मर्यादा भूल गया। क्या रैगिंग की कोई क्लास पूरे परिसर में चल रही थी। बीस दिसंबर की ऑनलाइन शिकायत पर पुलिस का मसखरापन ईमानदार था या हम मान लें कि उस दौरान तो पुलिस ग्राउंड की महफिल में अपराध दर्ज करना हराम था। हम नहीं जानते कि किस सत्य के आधार पर एक बेटी के परिवार को चारों तरफ रावणों की लंका दिखाई दे रही है, लेकिन मौत आने से पहले जो बयान लड़की ने अपनी जुबां से दिए, उन्हें ठुकराने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। यहां सबसे बड़ी ताकत से सोशल मीडिया तफतीश कर रहा है, इसलिए अब केस भी दर्ज हो गया और मुद्दा सड़क से विपक्ष का हो गया। जीवन के असहाय पन्ने अगर कालेज में बिखरे या कानून की नजर में उजड़े, तो न समाज का घर आबाद है और न ही देश का सही हाल है। एक छात्रा का वर्तमान अगर कालेज के सान्निध्य में असुरक्षित है या पूरा परिसर बीहड़ बन कर किसी बच्चे को मानसिक संताप की अति से गुजार दे, तो हमारा हिसाब न्याय नहीं। कालेज हाथ धो के बैठ सकता है कि उसकी आंखों ने कुछ नहीं देखा, उसके कानों ने कुछ नहीं सुना, लेकिन छात्रा का व्यक्तित्व इसकी राहों से गुजरा है, इसकी निगाहों से गुजरा है। अब जो आरोप सामने आए हैं, उनके आधार पर जुर्म की फेहरिस्त लंबी हो रही है, अपराध के संज्ञान में धाराएं सख्त हो रही हैं। क्या कालेज की गलियां जातिवाचक रहीं। क्या रैगिंग में संलिप्त छात्राएं सुरक्षा में रहीं और क्या कोई अध्यापक अपनी नीच हरकतों से कालेज का ईमान बेचता रहा। आखिर हो क्या रहा और होता क्या रहा। बेटी की इज्जत को पालने से डर है, तेरे हाथों में मौत सी गंध है। पिछले साल को हम प्राकृतिक आपदाओं के कारण कोसते रहे, लेकिन एक आपदा कालेज परिसर में संगठित अपराध कर रही थी। अपनी तरह से दिल हिला देने वाले इस घटनाक्रम के कई सिरे हैं और कई नासूर दिखाई देने लगे हैं। यहां माननीय विकास कुपित है और साक्षरता दर पाषाण काल की कंदराओं में ध्वस्त है। बेटी की वीडियो ही बेटी की गवाही दे रही है। इसलिए फैसलों की कीमत से पहले ही उसने मौत को गले लगाया ताकि उसकी तरह किसी अन्य बेटी को अपनी इज्जत के लिए शहादत न देनी पड़े। अब चौराहों पर फैसले आएंगे, सियासत पर फैसले आएंगे, समाज भी फैसले देगा, जबकि पुलिस कानून के फैसले पर मेहरबान हो जाएगी, लेकिन इस बेटी की मौत नए संबोधन करती रहेगी। अब अगर सजा हो भी जाए तो क्या होगा, इस सफर में एक बेटी की रूह को गिला रहेगा। कालेज छात्रा का वृत्तांत खुद कफन से निकल कर बता रहा है कि इस मौत की वजह हमारी व्यवस्था से जुड़ी है। पहली व्यवस्था समाज की दृष्टि में हमें पतित कर रही है, दूसरी शिक्षण की गलियों का पतन कर रही है, तो तीसरी प्रदेश की कानून व्यवस्था से बचें या खुद को बचाएं के बीच संघर्ष कर रही है। चारों तरफ जब अन्याय खड़ा हो, तो हम जंगल में खुद को किस भेड़िये से बचाएं। धर्मशाला की छात्रा की मौत में कई हाथ रंगे नजर आ रहे हैं, फिर भी हम शरीफजादे कहां ढूंढ पाएंगे इस जुल्म की कोई एक कहानी। न्याय की दहलीज पर पहुंची एक मौत अपनी ही वीडियो में दे रही गवाही। देखें हम इस स्थिति से उबर कर किसका दामन पाक और किसके दामन में छेद ढूंढ पाते हैं।

## दूषित पानी का हत्याकांड

**कितना** अभिशप्त और कलंकित शहर है इंदौर! जिस शहर को स्वच्छता के लिए लगातार राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है, उसी शहर में लोग दूषित पानी पीने से मर रहे हैं। यह इंदौर का काला सच है! इससे विरोधाभासी त्रासदी और क्या होगी? हमें नए साल की शुरुआत में ही ऐसा शोकाकुल, संतप्त, अफसोसनाक, व्यवस्था के ‘फालतूपन’, संवेदनहीनता और मंत्री जी के ‘घंटे’ पर विश्लेषण करना पड़ रहा है, लिहाजा हमारी विवशता समझिए। यह त्रासद घटना मप्र के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव-क्षेत्र के भागीरथपुरा की है। क्या विडंबना और अंधेरगर्दी है कि नर्मदा के पानी की लाइन में मल की पाइपलाइन जुड़ गई और लोग वही विषाक्त पानी पीते रहे! आखिर यह नालायकी कैसे संभव है? यदि यह हत्याकांड (हम इसे हत्याकांड ही मानेंगे) सामने न आता, तो न जाने कितनी और अर्थियां उठानी पड़तीं? विषाक्त पानी पीने से अभी तक 14 मौतें हो चुकी हैं और 32 मरीजों की स्थिति गंभीर बताई गई है। उनमें से अधिकतर अस्पतालों के आईसीयू में उपचाराधीन हैं। ईश्वर उन्हें नई जिंदगी दें। अस्पतालों में 201 मरीज भर्ती हैं। कुल 8571 प्रभावित लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 338 संक्रमित पाए गए हैं। अब हैजा फैलाने वाले घातक विषाणु भी मिले हैं। मप्र सरकार बेशक अफसरों को निलंबित करे या बर्खास्त कर दे अथवा सूली पर चढ़ा दे, लेकिन जिन परिवारों के चिराग बुझे हैं, कमाऊ पूत भरी जवानी में चले गए हैं, बड़ों के साये भी छिन गए हैं, क्या उनकी क्षतिपूर्ति संभव है? ऐसी किसी भी त्रासद घटना की क्षतिपूर्ति की ही नहीं जा सकती। जिन लोगों ने गुस्से या आक्रोश में सरकारी चेक कबूल करने से इंकार कर दिया है, हम उनकी हिम्मत की दाद देते हैं। सरकार या राजनीतिक नेतृत्व को कभी-कभार ‘लाल आंखें’ दिखाना सही होता है। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में हैं और मालवा के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर गिने जाते हैं। उन्होंने पत्रकारों से भिड़ते हुए कहा-फोकट के सवाल मत पूछें।’’ इससे उनकी मानसिकता स्पष्ट हुई है। वह मौत के आंकड़ों को ‘घंटा’ करार दे रहे हैं। क्या ऐसे नेता को जनता को खारिज नहीं कर देना चाहिए? दरअसल सवाल खोखले नारों, दावों और सतही शृंगार का है। इंदौर पर ग्लैमर और आकर्षण थोपा जा रहा है। वह स्वच्छता का शहर भी नहीं है। यह हमारा दावा है, क्योंकि हमने इंदौर को नंगी आंखों से देखा है। वहां अराजकता और अतिक्रमण चारों ओर देखा जा सकता है। इंदौरवाले अव्वल दर्जे के ‘खाऊ’ हैं, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर बसे शहर में चेतावनीपूर्ण जल-संकट की स्थितियां हैं। गर्मियों में लोगों को पानी के टैंकर खरीद कर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री या खुद जनता ने पानी के संकट की कभी भी चिंता नहीं की। अब इंदौर को इतना विकसित बनाने की योजनाओं पर काम चल रहा है कि प्रधानमंत्री का दूसरा आवास वहीं बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री इंदौर में बस कर क्या करेंगे? इंदौर को सिर्फ ऊपर से सजाने-संवारने की कोशिशें की जाती रही हैं। यह कैसा शहर है, जहां 95 फीसदी से अधिक दोपहिया चालक हैलमेट ही नहीं पहनते, लाल बत्ती की गंभीरता से नहीं मानते और वाहन आपस में लगभग काटते, टकराते चलते रहते हैं। ऐसे शहर को बेनकाब करना जरूरी है। हत्याकांड के बाद जिन सैंपलों की रपटें सार्वजनिक हो चुकी हैं, उनमें फीकल कॉलिफार्म, ई-कोलाई, विब्रियो, क्लेबसेला और प्रोटोजोआ सरीखे खतरनाक और जानलेवा बैक्टीरिया पाए गए हैं। फिर लोग कैसे बचेंगे? अब पानी की आपूर्ति की लाइनों को साफ किया जा रहा है। मप्र उच्च न्यायालय ने सख्ती बरतते हुए सरकार से दो दिन में ही स्टेटस रपट मांगी है और बीमार लोगों का मुफ्त इलाज करने के निर्देश दिए हैं। सवाल नगर निगम की अंदरूनी व्यवस्था का है। यह पाइपलाइन बदली जानी थी, लोग शिकायतें कर रहे थे, टेंडर भी आमंत्रित कर लिए गए थे, उसके बावजूद व्यवस्था निकम्मी रही और इन मौतों का इंतजार करती रही! अफसरों का निलंबन या बर्खास्तगी ही पर्याप्त नहीं है।


संपादकीय लेखों पर सुधी पाठकों की प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं, भेजें : पाठकों के पत्र, द्वारा संपादक, पोस्ट बॉक्स 14, धर्मशाला-176215

फोन : 01892-264713, 260676

फैक्स : 01892-264700

Email : feature@divyahimachal.com या edit.dshala@divyahimachal.com


# दूषित जल से होने वाली मौतें और विकास

योगेंद्र योगी

स्वतंत्र लेखक


**केंद्र** सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद देश में दूषित पेयजल जैसी बुनियादी समस्याएं विकास को मुंह चिढ़ा रही हैं। देश में स्वच्छता में नंबर एक रैंकिंग हासिल करने वाले मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पानी पीने से आठ लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब सौ लोग बीमार हो गए। यह तस्वीर बताती है कि देश में पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान अभी कोसों दूर है। सरकारें आंकड़ों के जरिए बेशक कितनी ही उपलब्धि का दावा कर लें किन्तु जमीनी हकीकत कुछ अलग है। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है और देश के लगभग 70 प्रतिशत जल स्रोत प्रदूषित हैं। इंदौर में जो हुआ उसने ये शक पैदा कर दिया है कि देश में कहीं भी ऐसी ‘जहरीली मौत’ की सप्लाई हो सकती है। ऐसा तब होता है जब सारे नियम और मानक भुला दिए जाते हैं। भारत में सप्लाई वॉटर की गुणवत्ता और पाइपलाइनों के रखरखाव को लेकर मानक तय हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सप्लाई वाले पानी के केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स तय करता है।

गाइडलाइंस कहती हैं कि उपभोक्ता के नल तक पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एजेंसी की जिम्मेदारी है। फिर वो सरकारी हो या प्राइवेट। गाइडलाइंस के मुताबिक पाइपलाइनों को 30 से 50 वर्ष के अंदर बदला जाना जरूरी है। अगर बार-बार लीकेज की शिकायत आती है तो बिना देरी किए पाइप बदला जाना चाहिए। इन गाइडलाइंस का कितना पालन होता है, इंदौर की घटना के बाद इस पर सवाल उठ रहे हैं। जिस पर सफाई भी दी जा रही है। जुलाई 2022 में गंदे पानी से जुड़े आंकड़े लैंसेट स्टडी में बताया गया कि भारत में करीब 1.95 लाख बस्तियों में लोग दूषित पानी पी रहे हैं। जिसकी वजह से साल 2019 में 23 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। शहर ही नहीं गांवों में भी साफ पानी की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। गंदे पानी में बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स और हेवी मेटल्स जैसे खतरनाक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अशुद्ध पानी पीने से हैजा, पीलिया, पेचिश, गले की बीमारी, टायफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। भारत में हर दिन बड़ी संख्या में लोगों को दूषित पानी पीना पड़ता है। कम्पोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दूषित यानी गंदा पानी पीने से हर साल दो लाख लोगों की मौत हो जाती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 तक करीब 600 मिलियन लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ सकता है, जो देश की कुल आबादी का 40 फीसदी है। दूषित पानी की समस्या से सबसे ज्यादा दिल्ली और एनसीआर प्रभावित है। यहां की आबादी बढ़ने के साथ साफ पानी की मांग बढ़ गई है, लेकिन गंदे पानी की आपूर्ति कई लोगों की सेहत को खराब कर रही है। भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है, जबकि देश में पीने योग्य जल संसाधनों का मात्र 4 प्रतिशत भाग ही उपलब्ध है। देश में अत्यधिक जल दोहन तथा अकुशल प्रबंधन के कारण भू-जल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके परिणामस्वरूप आने वाले समय में देश को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। देश के कई राज्य इस समय पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु देश के ऐसे टॉप तीन राज्य हैं जहां के अधिकतर जिलों में पानी का संकट छाया हुआ है। मौजूद आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 38 जिलों के लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। इनमें से कई जिले ऐसे हैं, जिन्हें अति-दोहित, गंभीर और अर्ध गंभीर श्रेणी में रखा गया। इसके बाद राजस्थान में 29 और तमिलनाडु में 22 जिले हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा मूल्यांकित भारत के गतिशील भूजल संसाधनों का राष्ट्रीय संकलन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 जिलों को अति-दोहित, 22 जिलों को गंभीर और 69 जिलों को अर्ध गंभीर श्रेणी में रखा गया है। हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में 16 अति दोहित जिले हैं। पंजाब में 19 अति दोहित और 1 गंभीर जिला है। नीति आयोग के अनुसार, वर्तमान में स्वच्छ जल की अपर्याप्त पहुंच के कारण लगभग 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं तथा इसके कारण प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु होती है। वर्ष 2030 तक देश में जल की मांग, आपूर्ति की दोगुनी होने की संभावना है। इससे देश में करोड़ों लोगों को जल के गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा तथा देश के सकल घरेलु उत्पाद में 6 प्रतिशत की हानि होने की संभावना है। जल संसाधन मंत्रालय के एकीकृत जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च उपयोग परिदृश्य में वर्ष 2050 तक जल की आवश्यकता 1180 अरब घन मीटर होने की संभावना है। देश में जल की उपलब्धता वर्तमान में 1137 अरब घन मीटर है। वर्ष 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी को पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रतिदिन 135 लीटर जल की आवश्यकता होती है जबकि सिर्फ भारत के कुछ बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली इत्यादि में शहरी विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बावजूद प्रति दिन प्रति व्यक्ति को 150 लीटर से अधिक जल दिया जाता है। भारत प्रति व्यक्ति जल की खपत के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। यहां प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल की खपत लगभग 250 लीटर है। इसका प्रमुख कारण जल की बर्बादी तथा औद्योगिक खपत है।

बढ़ती जनसंख्या एवं नगरीकरण देश में बढ़ते जल संकट का एक प्रमुख कारण है। वर्ष 2001 में प्रतिव्यक्ति जल की उपलब्धता 1816 घन मीटर थी जो कि वर्ष 2011 में घटकर 1545 घन मीटर हो गई और वर्ष 2031 तक इसके घटकर 1367 घन मीटर होने की संभावना है। जल-गहन फसलों की कृषि देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 54 प्रतिशत भाग पर जल गहन फसलों जैसे, चावल, गेहूं, गन्ना, कपास इत्यादि की कृषि की जाती है। भारत में सिंचाई के लिए भूजल का 65 फीसदी और पीने के पानी के लिए 85 फीसदी हिस्सा है। इस पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में। सीमित जल संसाधनों के आवंटन को लेकर संघर्षों को भी जन्म देता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पार्क की जल आवश्यकताओं और स्थानीय किसानों की सिंचाई मांगों के बीच बार-बार होने वाले संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह महाराष्ट्र की ऊपरी गोदावरी परियोजना में पानी के असमान वितरण को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं। जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन और सरकार की अपर्याप्त भागीदारी इन तनावों को और बढ़ा देती है। जनसंख्या वृद्धि से पानी के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो जाती है। सवाल यही है कि देश की तमाम उपलब्धियों के सरकारी आंकड़ों के बावजूद आम लोगों को जब तक बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं होंगी तब तक ये उपलब्धियां बेमानी साबित होंगी।

> जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन और सरकार की अपर्याप्त भागीदारी इन तनावों को और बढ़ा देती है। जनसंख्या वृद्धि से पानी के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो जाती है। सवाल यही है कि देश की तमाम उपलब्धियों के सरकारी आंकड़ों के बावजूद आम लोगों को जब तक बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं होंगी तब तक ये उपलब्धियां बेमानी साबित होंगी...

### प्रसंगवश

## ठंड और प्रदूषण की मार

**हिमाचल** प्रदेश अपनी मनोहारी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी ऊंची-ऊंची पहाड़ियों, हरी-भरी वादियों और समृद्ध कृषि-बागवानी परंपरा के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है। यहां की स्वच्छ हवा, शांत वातावरण और प्राकृतिक दृश्य हर वर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, वहीं सेब, सब्ज़ियां और अन्य नकदी फसलें राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन और कृषि-बागवानी से ही प्राप्त होता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। लेकिन हाल के वर्षों में ठंड की तीव्र लहर, अनियमित बर्फबारी और लगातार बढ़ता प्रदूषण इन दोनों प्रमुख क्षेत्रों के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। अत्यधिक ठंड और मौसम की अनिश्चितता से जनजीवन प्रभावित होता है, सड़कों के बंद होने और सुविधाओं में बाधा आने से पर्यटन गतिविधियां कम हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर, पाले और असामान्य मौसम के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है, जिससे किसानों और बागवानों की आय घट रही है। इसके साथ ही वाहनों, निर्माण कार्यों और अनियंत्रित विकास से बढ़ता प्रदूषण हिमाचल के पारंपरिक स्वच्छ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इन परिस्थितियों ने राज्य के आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। पर्यटन पर प्रभाव : हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। यह समय पर्यटन व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जब ठंड की लहर अत्यधिक तीव्र हो जाती है, तो यही आकर्षण कई बार संकट का कारण बन जाता है। भारी बर्फबारी और शीतलहर के चलते राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों के साथ-साथ संपर्क सड़कें बंद हो जाती हैं, जिससे पर्यटक कई स्थानों पर फंस जाते हैं या अपनी यात्रा बीच में ही रद्द करने को मजबूर हो जाते हैं। अत्यधिक ठंड के कारण बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित होती है, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। इससे पर्यटकों को असुविधा होती है और राज्य की पर्यटन छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, वाहनों की बढ़ती संख्या, लकड़ी और ईंधन के अधिक उपयोग तथा मौसमीय परिस्थितियों के कारण प्रदूषण और धुंध की समस्या भी बढ़ जाती है। दृश्यता कम होने से न केवल हवाई और सड़क यातायात प्रभावित होता है, बल्कि पर्यटक स्थलों का प्राकृतिक सौंदर्य भी ढका-सा नजर आने लगता है। इन परिस्थितियों का सीधा असर पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों पर पड़ता है। पर्यटकों की संख्या घटने से होटल और होमस्टे खाली रह जाते हैं, टैक्सी और ट्रांसपोर्ट सेवाओं की मांग कम हो जाती है, और छोटे दुकानदार, गाइड, रेस्तरां व हस्तशिल्प विक्रेताओं की आमदनी में गिरावट आती है। लंबे समय तक ऐसी स्थिति बने रहने पर स्थानीय लोगों की आजीविका पर गहरा असर पड़ता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान उठाना पड़ता है। हिमाचल की कृषि और बागवानी मुख्य रूप से प्राकृतिक मौसम पर निर्भर करती है। ये क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं।

– राजन कुमार शर्मा, ऊना

### हिमाचल : स्वास्थ्य

# सॉरी सुनने को लग गए सात दिन

डा. सुरेश शर्मा

शिक्षाविद


**हालांकि** हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला के सीनियर रेजिडेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डाक्टर राघव नरूला तथा शिमला जिला के कुपवी निवासी अर्जुन के बीच हाथापाई, मारपीट एवं लात-घूंसे के दु:खद प्रकरण का सुखद पटाक्षेप हो चुका है और अन्तिम फैसला सरकार द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। 22 दिसंबर को दोनों के बीच गलतफहमी का हल ढूंढने के लिए प्रदेश सरकार व हिमाचल प्रदेश के लोगों को सात दिन सजा भुगतनी पड़ी। केवल एक शब्द ‘सॉरी’ बोलने और सुनने के लिए सात दिन लग गए। प्रदेश मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के कार्यालय में दोनों पक्षों की बात हुई। मीडिया के सामने दोनों मरीज अर्जुन तथा डाक्टर राघव ने एक-दूसरे को तथा प्रदेश की जनता को अव्यवस्था तथा हड़ताल से हुई असुविधा के लिए ‘सॉरी’ कहा। दोनों एक दूसरे के गले मिले। अब मरीज अर्जुन के परिजन कुछ समय के पश्चात डाक्टर राघव नरूला की शादी में शामिल होंगे। मामले को पूरी तरह से सुलझाने के लिए नई कमेटी बन जाएगी, चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन नए तरीके से रिपोर्ट तैयार कर देगा। स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर राघव नरूला का सरकारी सेवा से निलंबन तथा बर्खास्तगी भी रद्द कर दी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों के प्रति नरम रवैया अपनाते हुए मीडिया वार्ता में इसका संकेत दे चुके हैं।

डाक्टर, मरीज तथा सरकार की ओर से घटनाक्रम को सुलझाने के लिए जो भी प्रयास किए गए वो स्वागत योग्य हैं, लेकिन कुछ सवाल तथा नसीहतें हैं जो सभी पक्षों को विचार करना होगा। इस तरह की घटनाएं तो रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्तियों, परिवारों, समाजों, मजहबों, गांवों, शहरों, सरकारी कार्यालयों, संस्थानों में होना स्वाभाविक है क्योंकि जहां लोग रहेंगे वहां पर अपना दृष्टिकोण, विचार, नजरिया, वाद-विवाद, बहस, छोटा-मोटा लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहेगा, परन्तु क्या प्रत्येक प्रकरण में कर्मचारी, कर्मचारियों की यूनियन्स, आम जनता, विभागों के प्रशासनिक अधिकारी, सम्बन्धित मंत्री तथा मुख्यमंत्री शामिल होते रहेंगे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। संस्थानों को व्यक्तिगत विवादों तथा घींगामुश्ती का अड्डा नहीं बनाया जा सकता। दो पक्षों के आपसी विवाद तथा झगड़े से हुई लोगों को असुविधा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इससे व्यवस्था का पतन होता है और लोगों का विश्वास उठता है। आवश्यक तो यह है कि व्यवस्था का शुद्धिकरण हो। व्यावसायिक नीति संहिता को और अधिक मजबूत बनाया जाए तथा कर्मचारी और अधिकारी के लिए विभागीय नियम संहिता का प्रशिक्षण और पालन सुनिश्चित किया जाए। इस दु:खद प्रकरण में प्रदेश स्वास्थ्य प्रशासन तथा सरकार एकदम से इस छोटी सी लड़ाई में शामिल हो गई। सोशल मीडिया से वायरल इस घटनाक्रम में पूरे प्रदेश के डाक्टर, स्वास्थ्य विभाग, पूरी सरकार, राजनीतिक दलों के नेता, मरीज अर्जुन तथा डॉक्टर राघव के पुश्तैनी इलाकों की जनता शामिल हो गई। दो व्यक्तियों की इस छोटी सी लड़ाई ने प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान, पुनीत व्यवसाय की गरिमा और मर्यादा की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य की गर्म मिजाजी की कीर्ति संचार माध्यमों से पूरी दुनियां में पहुंची। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया की सुर्खियों में बनी यह खबर मरीज और डाक्टर के सम्बन्धों की एक नवीन कहानी है। इस प्रकरण के होते ही मेडिकल कॉलेज में धरना, नारेबाजी और तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। पत्रकार वार्ताएं, राजनीतिक हस्तक्षेप, पुलिस तथा चिकित्सा प्रशासन में खलबली, चार घण्टे में आन्तरिक छानबीन की रिपोर्ट, निलंबन और फिर चौबीस घण्टे में डाक्टर की बर्खास्तगी हो जाती है। आवश्यक तो यह था कि घटना में स्वास्थ्य प्रशासन, स्वास्थ्य मंत्री तथा मुख्यमंत्री के शामिल होने से पूर्व चिकित्सा महाविद्यालय की आन्तरिक जांच या छानबीन होती जिसे सम्बन्धित निदेशालय में भेजा जाता, उस पर निलंबन जैसा कोई आदेश आता, दोनों पक्षों को पूरी तरह से सुना जाता। सरकारी नियमों तथा प्रक्रिया के अनुसार आरोपी डॉक्टर को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाता, लेकिन मीडिया ट्रायल तथा उच्च स्तर पर जनता के दबाव के चलते डाक्टर की बर्खास्तगी का फरमान जारी हो गया। यहां पर यह आवश्यक हो जाता है कि विभागीय नियम संहिता कर्मचारी तथा विभागीय अधिकारियों के लिए होती है, परन्तु इस मामले में निर्णय सीधे सरकार द्वारा ले लिया गया। यहां प्रश्न यह उठता है कि कर्मचारियों तथा अधिकारियों के मामले में अब तक सम्बन्धित मंत्री तथा मुख्यमंत्री सीधे हस्तक्षेप करते रहेंगे? यह हर व्यक्ति के मामले में हर समय संभव नहीं है और दूसरे जब व्यवस्था का मुखिया सीधे-सीधे प्रकरण में शामिल हो जाए तो किसी भी प्रकरण की गम्भीरता और भी अधिक हो जाती है। सात दिनों के बाद एक शब्द ‘सॉरी’ सुनने के लिए कितने प्रदेशवासियों को भुगतना पड़ा, यह कोई सामान्य घटना भी नहीं है। इस प्रकरण में जहां चिकित्सक के कृत्य को बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता, वहीं पर मरीज के व्यवहार को भी प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर चिकित्सा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा सरकार द्वारा बर्खास्तगी रूपी त्वरित कार्रवाई का भी समर्थन नहीं किया जा सकता। कार्रवाई से पूर्व डाक्टर के पक्ष को रिकार्ड किया गया होगा लेकिन मामले में प्रशासनिक त्वरित कार्रवाई की जल्दबाजी में समझ से परे है। सरकारी कर्मचारी की सेवा नीति संहिता के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया होती है तथा बर्खास्त डॉक्टर के भी अपने अधिकार होंगे।

प्रथम दृष्टया इस मामले में आरोपी डॉक्टर की सुनवाई के लिए पूरा समय नहीं मिला। डॉक्टर का पक्ष पूरी तरह से समय लेकर सुना जाना चाहिए था। इस संदर्भ में प्रदेश के मुख्यमंत्री की परिपक्वता तथा उनके दृष्टिकोण की भी प्रशंसा करनी होगी जब उन्होंने कहा कि ‘मरीज भी, डाक्टर भी तथा जनता भी इसी प्रदेश की है तथा सरकार की मंशा किसी का भविष्य खराब करने की नहीं है।’ फिर भी इस प्रकरण में कुछ बिन्दुओं से विचार आवश्यक है। सोशल मीडिया ट्रायल, विभागीय त्वरित कार्रवाई, जनता के दबाव के चलते बर्खास्तगी का त्वरित फरमान चिंतनीय और विचारणीय है। आवश्यक यह था कि आरोपी डाक्टर को स्पष्टीकरण के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए था। सभी कर्मचारियों को संवेदनशील तथा व्यवहार कुशल होना चाहिए।

> इस मामले में आरोपी डॉक्टर की सुनवाई के लिए पूरा समय नहीं मिला। डॉक्टर का पक्ष पूरी तरह से समय लेकर सुना जाना चाहिए था...

### छिलकों की छाबड़ी

गुरमीत बेदी

साहित्यकार


## माहौल अब शांत है...

**जिसने** जिनको पीटना था, पीट चुका है। जिसने जिनको लात मारनी थी, मार चुका है। जितना हंगामा मचना था, मच चुका है। जितनी खिल्ली उड़नी थी, उड़ चुकी है। जो एक्शन लिए जाने थे, लिए जा चुके हैं। मार-पिटाई का जो सीन पब्लिक ने देखना था, देख चुकी है। अस्पताल के भीतर भी और सड़कों पर भी। हड़ताल-शड़ताल भी समाप्त हो चुकी है। फेसबुक पर टिप्पणियां करने वाले भी अब किसी नए घटनाक्रम का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि पिटाई प्रकरण अब पुराना पड़ रहा है। कानून व्यवस्था भी अब जम्हाई लेकर जागृत हो गई है। सरकारी भाषा में कहें तो स्थिति कंट्रोल में आ गई है। मीडिया की सुर्खियां अब यही बन रही हैं कि स्थिति शांत है। माहौल भी शांत है। यानी कारवां गुजर गया है और गुबार भी अब उतर गया है। सरकार अपने काम में लग गई है। विपक्ष अपने काम में लग गया है। फेसबुकिया अपने काम में लग गए हैं। अब शांति है। इतनी शांति कि अगर कोई सच बोल दे तो वह शांति भंग करने वाला घोषित हो जाए। इतनी शांति कि सवाल पूछने वाला ‘एजेंडा’ वाला कहलाए और जवाब देने वाला ‘जिम्मेदार’। शहर में पोस्टर उतर चुके हैं, नारों की आवाज भी बैठ गई है। जिन हाथों में डंडे थे, उनमें अब चाय के कुल्हड़ हैं और जिन जुबानों में आग थी, वे अब मौसम की बात कर रही हैं। घायलों के बदन पर पट्टियां बंध गई हैं, लेकिन सिस्टम के घाव खुले ही हैं। अस्पताल की पर्चियां फाइलों में दब गई हैं और फाइलें अलमारियों में। जांच बैठ गई है- मतलब कुर्सी पर। जांच के नाम पर बैठी जांच, अब बैठी ही रहेगी, क्योंकि खड़े होकर सच ढूंढना पड़ता है और बैठकर सिर्फ तारीखें मिलती हैं। मीडिया ने भी राहत की सांस ली है। ब्रेकिंग न्यूज की धड़कन अब नॉर्मल हो गई है। स्टूडियो में बहस का तापमान कम कर दिया गया है। एंकरों ने भी टाई ढीली कर ली है। वे जानते हैं कि शांति में सवाल नहीं पूछे जाते, शांति में विज्ञापन चलते हैं। सरकार ने बयान दे दिया है। बयान देने के बाद बयान की जरूरत नहीं रहती। विपक्ष ने विरोध कर लिया है- मतलब ट्वीट कर लिया है। सड़क पर जाने की जरूरत नहीं, सड़क पर तो वैसे भी गड्ढे हैं। न्याय अपने रास्ते पर है, इतना लंबा रास्ता कि चलते-चलते थक जाए और कहीं बैठ जाए। पब्लिक भी समझदार है। उसने तमाशा देख लिया, वीडियो फॉरवर्ड कर दिए, गुस्सा निकाल लिया। अब वह अपने काम पर लौट आई है। अगले तमाशे तक। क्योंकि इस देश में घटनाएं नहीं होतीं, सीरीज चलती हैं। एक खत्म, दूसरा शुरू। और अंत में वही पंक्ति दोहराई जाती है- ‘माहौल अब शांत है।’ यह पंक्ति इतनी बार बोली जाती है कि सच भी शर्म से चुप हो जाता है। क्योंकि जब माहौल शांत बताया जा रहा होता है, तब असल में सिर्फ आवाजें बंद की जा रही होती हैं। समस्याएं नहीं। समस्याएं फाइलों के भीतर कसमसा रही होती हैं। नेता लोग फाइलों के ऊपर सो रहे होते हैं। कई बार सदन में भी बहस के बीच सो रहे होते हैं। सो जाना, मतलब समस्याओं से आंख मूंद लेना। मतलब नीरो चैन की बंसी बजाने लगा है। बंसी बजती है तो लगता है माहौल शांत है। बस, सवाल सो रहे हैं।

### पाठकों के पत्र

## चिंताजनक है हिंदुओं की हत्याएं...

**बांग्लादेश** में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की हत्याएं और उत्पीड़न अब सारी हदें लांघ चुके हैं। दीपू चंद्र दास की हत्या हृदयविदारक है। यूनुस के कार्यकाल में 2900 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। जब भारत 1971 में मानवता के नाते बांग्लादेश को स्वतंत्र करवा सकता है, लाखों तिब्बतियों, नेपालियों और रोहिंग्याओं के भार को झेल सकता है, तो क्या बांग्लादेश में बलि के बकरे बनते हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता? पीड़ितों की सहायता को भारत को आगे आना चाहिए और विश्व समुदाय को भी इस नरसंहार से आंखें न मूंदकर शीघ्र बीच-बचाव कर हस्तक्षेप करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की पुनरावृत्ति का सही समय है। हिंदू हितों की बात करने का भी यही मौका है।

–कार्तिकेय ठाकुर, सतौन, सिरमौर

## संपादकीय

# इंदौरः स्वच्छता की चादर से ढंकी गंदगी

**इंदौर** मध्य प्रदेश ही नहीं देश के स्वच्छतम शहरों की श्रेणी में रहा है लेकिन अब इसकी आई सच्चाई ने उजागर कर दिया कि इस महानगर की गंदगी को स्वच्छता की चादर से ढंक दिया गया था। जिससे इंदौर को देशव्यापी स्वच्छता का खिताब मिलता रहे। अब दूषित पेयजल से हुई 10 से ज्यादा लोगों की मौत ने झूठ से पर्दा उठा दिया है। स्वच्छता के कथित मानकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हम अपने नागरिकों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने में क्यों असफल हो रहे हैं। मानव शरीर के लिए शुद्ध पेयजल पहली जरूरत है। क्योंकि हम बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं लेकिन जल के बिना जीवन कतई संभव नहीं है। मानव शरीर में 70 प्रतिशत जल की उपलब्धता है। भागीरथपुरा में नर्मदा नदी से पाइपलाइन के जरिए आने वाले जल में शौचालय का दूषित पानी लंबे समय से मिलता रहा। बस्ती के लोग इस पानी को यह मानकर पीते रहे कि नगर निगम द्वारा पिलाया जाने वाला शुद्धता के मानकों पर खरा होगा ही। लेकिन धरती के नीचे बह रहा सीवर का मल नर्मदा के जल में पाइप लाइन फूट जाने से घुलता रहा। लोगों को जब पानी में गंदगी का अहसास हुआ तो शिकायत भी की गई। लेकिन निगम और जिला प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। जब 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 1000 लोग अस्पतालों में भर्ती हुए, तब प्रशासन जागा और नागरिकों द्वारा बताए स्थल की खुदाई की। तब जाकर पता चला कि सीवर और पेयजल की लाइनें फूट जाने से नर्मदा के जल में गंदगी डेढ़ वर्ष से मिल रही थी। इस कारण लोगों की प्रतिरोधात्मक क्षमता घटती गई और बीमारी एवं मौत कहर बनकर टूट पड़े। अब कुछ कर्मचारियों को निलंबित करके प्रशासन मामले को ठंडा करना चाहता है लेकिन निलंबन कोई सजा नहीं है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के इसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं और पेयजल की आपूर्ति करने वाला विभाग भी उन्हीं के अधीन है। अतएव जब जिम्मेबार मंत्री से इस जानलेवा लापरवाही से जुड़े सवाल किए गए तो उन्होंने बौखलाकर अपा खो दिया और बोले, ये सब फोकट के सवाल हैं, इन्हें मत पूछिए। यह उनकी संवेदनहीनता दशार्ने वाला उत्तर था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब उनकी थू-थू हुई तो उन्होंने खेद जताकर मुक्ति पा ली। लेकिन साफ है, भाजपा सरकार के मंत्री इस हद तक मद में चूर हो गए हैं कि उन्हें अपने उत्तरदायित्वों का उचित ख्याल तक नहीं रहता। यदि रहता तो कैलाश विजयवर्गीय को एहसास होता कि इस तरह की लापरवाही का उपचार महज सरकारी खानापूर्ति न होकर सजगता के साथ समस्या का हल खोजना था। दूषित पेयजल कांड के चलते इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव तो इतने विचलित हुए कि जब अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने उनके निर्देश को महत्व नहीं दिया तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि अधिकारी सुनते नहीं है।

# ईरानी बहनें तोड़ रही बुर्का की जंजीरे, भारत में बढ़ रही है कट्टरता

**संजय सक्सेना**

> मुस्लिम महिलाएं उसी हिजाब या बुर्का को धार्मिक फर्ज बताकर प्रदर्शन कर रही हैं। पाकिस्तान में हाल ही में लाहौर और कराची की सड़कों पर महिलाओं ने जुलूस निकाले। वे कह रही हैं कि स्कूलों में हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है। वहां के सर्वे बताते हैं कि साठ से सत्तर प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं इसे अपनी मर्जी से पहनती हैं। लेकिन कट्टर गुट दबाव बनाते हैं। पड़ोसियों की नजरें, मौलवियों की फतवे और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से कई लड़कियां मजबूर हो जाती हैं। बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय के परिसरों में छात्राओं ने हिजाब अनिवार्य करने की मांग की

ईरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का साहसी विद्रोह पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है, जहां कुरान के नाम पर थोपी गई बुर्का और नकाब जैसी परंपराओं के खिलाफ सड़कों पर आवाज उठ रही है। खामेनेई की तानाशाही वाली सरकार के सामने ईरानी महिलाएं बिना नारे लगाए, बिना हिंसा किए, बस सिर से दुपट्टा उतारकर सड़कों पर उतर आई हैं, जो महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद 2022 से चला आ रहा आंदोलन अब 2025-2026 में और तेज हो गया है। यह बगावत न केवल ईरान तक सीमित है, बल्कि अरब और अन्य मुस्लिम देशों में भी बुर्का हटाने की हवा चल रही है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत जैसे स्थानों पर इसके पक्ष में कट्टरता बढ़ रही है। यह और बात है कि इन देशों के मुसलमानों को अरब जगत मुस्लिम मानने को ही नहीं तैयार होता है।

गौरतलब हो, ईरान को पूरी तरह इस्लामिक राष्ट्र कहा जाता है, जहां 1979 की क्रांति के बाद अयातुल्लाह खुमैनी ने कुरान आधारित शासन स्थापित किया और महिलाओं पर सख्त हिजाब अनिवार्य कर दिया। नैतिक पुलिस द्वारा सड़कों पर गश्त कर महिलाओं को पकड़ना और सजा देना आम हो गया, लेकिन 2022 में 22 वर्षीय महसा अमीनी की हिरासत में संदिग्ध मौत ने चिंगारी जला दी। उसके बाद लाखों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर दुपट्टा जलाया, बाल कटवाए और नारे लगाए, जिससे पूरे देश में आंदोलन फैल गया।

हालिया समाचारों के अनुसार, दिसंबर 2025 में तेहरान और अन्य शहरों में महिलाएं खुलेआम बिना दुपट्टे के घूम रही हैं, जो सरकार को डरा रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने विवादास्पद हिजाब कानून को स्थगित कर दिया, लेकिन सर्वोच्च नेता खामेनेई के दबाव में सैन्य बल तैनात हैं। प्रदर्शनों में कम से कम छह मौतें हो चुकी हैं और दर्जनों गिरफ्तारियां हुई हैं, फिर भी महिलाओं का खामोश विरोध जारी है।

बहरहाल, यह आंदोलन सिर्फ ईरान का नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर इस्लाम के नाम पर थोपी गई कट्टरता के खिलाफ जागृति का प्रतीक है। अरब प्रायद्वीप से इस्लाम फैला, लेकिन अब सऊदी अरब जैसे देशों में महिलाओं को पहले से अधिक स्वतंत्रता

मिल रही है, जहां अब पूर्ण बुर्का अनिवार्य नहीं। मध्य एशिया के मुस्लिम बहुल देशों में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। कजाकिस्तान, जहां 70 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है, ने 2025 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का-नकाब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जुमार्ना 10 हजार से एक लाख रुपये तक। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने पहले ही चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर रोक लगा रखी है, ताकि धार्मिक कट्टरपंथ न फैले। कुल 16 से अधिक देशों ने बुर्का या नकाब पर कानूनी पाबंदी लगा दी है। यूरोपीय देशों में स्विट्जरलैंड ने 2021 के जनमत संग्रह में 51.21 प्रतिशत वोटों से 2025 में इसे लागू किया, जबकि फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, बुल्गारिया, इटली और जर्मनी ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर जुमार्ना या जेल की सजा निर्धारित की। बेल्जियम में मात्र 300 महिलाएं ही बुर्का पहनती थीं, फिर भी 10 लाख मुसलमानों के बीच इसे प्रतिबंधित किया गया। इसके विपरीत, दक्षिण एशिया में स्थिति उलटी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में, जहां इस्लाम स्थानीय रूप से फैला, वहां कट्टरता बढ़ रही है। भारत के बिहार में हाल ही में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला डॉक्टर का दुपट्टा हटाने पर विवाद हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान तक से विरोध के सुर उठे। बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि बुर्का पसंद है तो पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाएं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में महिलाएं दुपट्टा या बुर्का पहनने को धार्मिक अधिकार बताकर प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि वहां के सर्वेक्षणों में 60-70 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं इसे स्वैच्छिक बताती हैं, लेकिन कट्टर समूह दबाव बनाते हैं। भारत में कर्नाटक हिजाब विवाद के बाद स्कूल-कॉलेजों में बहस चली, जहां मुस्लिम छात्राओं ने पहनने पर जोर दिया। यह विरोधाभास दशार्ता है कि जहां मूल इस्लामिक केंद्रों में महिलाएं आजादी चाह रही हैं, वहीं यहां आयातित कट्टरता बुर्का को मजबूरी बना रही है। सऊदी अरब में भी महिलाएं ड्राइविंग और बिना नकाब के घूमने की मांग कर रही हैं। लेकिन दक्षिण एशिया में तस्वीर उलट है। यहां बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में मुस्लिम महिलाएं उसी हिजाब या बुर्का को धार्मिक फर्ज बताकर प्रदर्शन कर रही हैं। पाकिस्तान में हाल ही में लाहौर और कराची की सड़कों पर महिलाओं ने जुलूस निकाले। वे कह रही हैं कि स्कूलों में हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है। वहां के सर्वे बताते हैं कि साठ से सत्तर प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं इसे अपनी मर्जी से पहनती हैं। लेकिन कट्टर गुट दबाव बनाते हैं। पड़ोसियों की नजरें, मौलवियों की फतवे और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से कई लड़कियां मजबूर हो जाती हैं। बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय के परिसरों में छात्राओं ने हिजाब अनिवार्य करने की मांग की। वहां भी तहरीक-ए-तालिबान जैसे संगठन पीछे हैं। महिलाएं कहती हैं कि बिना हिजाब के पढ़ाई नहीं करेंगी। लेकिन गुप्त सर्वेक्षणों में पता चलता है कि आधी से ज्यादा लड़कियां इसे बोझ मानती हैं। फिर भी भीड़ का दबाव उन्हें चुप करा देता है। भारत में कर्नाटक का हिजाब विवाद तो चरम पर पहुंच गया। उदुपी के कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं ने कक्षा में घुसने से इनकार कर दिया। वे दुपट्टा या हिजाब के बिना परीक्षा नहीं देंगी, ऐसा हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों के पीछे जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे संगठन थे। कोर्ट ने फैसला दिया कि यूनिफॉर्म का पालन जरूरी है, लेकिन बहस थम नहीं रही। मंड्या, बीदर जैसे जिलों में स्कूलों के बाहर जुलूस हुए। छात्राओं के माता-पिता भी सड़क पर उतरे। वे चिल्ला रहे थे- हमारी बेटियों का धर्म सुरक्षित रखो। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रामीण इलाकों में कई लड़कियां डर से हिजाब पहनती हैं। पड़ोस के हिंदू-मुस्लिम तनाव में इसे ढाल बना लिया जाता है। उक्त देशों में यह प्रवृत्ति चिंताजनक है। जहां दुनिया महिलाओं को सशक्त बना रही है, वहां दक्षिण एशिया में कट्टरता उन्हें पुराने जंजीरों में जकड़ रही। सर्वे बताते हैं कि ज्यादातर महिलाएं स्वतंत्रता चाहती हैं। लेकिन अल्पसंख्यक कट्टर गुट बहुमत को दबा रहे हैं। क्या यह धार्मिकता है या राजनीति? नेताओं को चाहिए कि वे तथ्यों पर ध्यान दें। महिलाओं को चुनाव दें- पहनें या न पहनें। तब सच्ची तस्वीर सामने आएगी। अन्यथा यह आयातित आग स्थानीय संस्कृति को भस्म कर देगी। दक्षिण एशिया की महिलाओं को मूल आजादी मिलनी चाहिए, न कि मजबूरी। बात ईरान में आए बदलाव की कि जाए तो इसके पीछे गहन कारण हैं। ईरान जैसे देशों में आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी ने महिलाओं को जागृत किया, जहां प्रदर्शनों में आजीविका की मांगें भी जुड़ गईं। मुस्लिम बहुल देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा को बहाना बनाकर बुर्का प्रतिबंध बढ़ा, क्योंकि चेहरा ढका होना अपराध को आसान बनाता है। वैश्विक स्तर पर 16 देशों के प्रतिबंध से संदेश साफ है कि बुर्का महिलाओं के उत्पीड़न का प्रतीक माना जा रहा। दक्षिण एशिया में कट्टरता का कारण विदेशी धन-सहायता और राजनीतिक उन्माद है, जहां बांग्लादेश-पाकिस्तान में मदरसों से प्रेरित युवतियां बुर्का को पहचान बना रही हैं। ईरानी महिलाओं की बगावत ने दुनिया को दिखाया कि इस्लाम के नाम पर थोपी गई परंपराएं टूट रही हैं। यदि यह लहर फैली, तो कट्टरता वाले क्षेत्रों में भी परिवर्तन अपरिहार्य होगा। आंकड़ों से सिद्ध है कि जहां प्रतिबंध लगे, वहां महिलाओं की भागीदारी 20-30 प्रतिशत बढ़ी है।

**नई दिल्ली कार्यालय**
एक्शन बालाजी हाउस, बी-244, मजलिस पार्क, दिल्ली- 110033

**उत्तरी दिल्ली कार्यालय**
शक्ति कॉम्पलैक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110042

**चंडीगढ़ कार्यालय**
फर्स्ट फ्लोर, देश सेवक बिल्डिंग, सेक्टर- 29डी, चंडीगढ़

**पंजाब कार्यालय**
7/2, थर्ड फ्लोर, मोनिका, टावर, ईआर-146, पक्का बाग, मिलाप चौक, जालंधर

**करनाल कार्यालय**
224, सेक्टर 32पी, करनाल- 132001

**सोनीपत कार्यालय**
एक्शन इंडिया कार्यालय, अपोजिट एनएस कम्प्यूटर, झंडी रोड़, गीता भवन चौक सोनीपत- 131001

**शिमला कार्यालय**
किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001

**ऊना कार्यालय**
कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना-174303

**देहरादून कार्यालय**
7/1, बल्लूपुर रोड़, कृष्णा नगर चौक, देहरादून

# पश्चिम में कम्युनिटी लिविंग का बढ़ता चलन

**डॉ. नीलम महेंद्र**

**हाल** ही में एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि ब्रिटेन में परिवार के सदस्यों (दादा-दादी, माता-पिता, बच्चे) या गैर-पारिवारिक सदस्यों के साथ एक छत के नीचे रहने का चलन बढ़ रहा है। सिर्फ माता-पिता के साथ ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में सैकड़ों कम्युनिटी लिविंग ग्रुप्स बन गए हैं, जहाँ लोग सस्ते में रहते हैं और अकेलेपन से बचते हैं। वहां समाजशास्त्रियों की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कम्युनिटी लिविंग या मल्टी-जेनरेशनल घरों में रहने वाले लोग अकेले या न्यूक्लियर फैमिली (एकल परिवार) में रहने वालों की तुलना में अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। नतीजन जो लोग अपने घर का खर्च उठा सकते हैं, वे भी अब कम्युनिटी लिविंग चुन रहे हैं, जिससे यह सिर्फ आर्थिक मजबूरी नहीं, बल्कि वहां एक जीवनशैली का विकल्प बनता जा रहा है। इसके विपरीत हम पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी की ओर भाग रहे हैं।आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ आर्थिक प्रगति, तकनीकी विकास और वैश्विक पहचान के शोर में एक अत्यंत मौन लेकिन गहरी सामाजिक त्रासदी घट रही है और वो है संयुक्त परिवारों का विघटन। विडंबना यह है कि जिस संयुक्त परिवार व्यवस्था को भारत ने पिछड़ेपन का प्रतीक मानकर त्यागना शुरू किया, वही व्यवस्था आज पश्चिमी देशों में नए सामाजिक समाधान के रूप में अपनाई जा रही है। भारत में संयुक्त परिवारों का विघटन केवल जीवन-शैली का बदलाव नहीं है बल्कि यह हमारे मूल सामाजिक दर्शन से विचलन है। दरअसल भारत में संयुक्त परिवार कभी केवल साथ रहने की व्यवस्था मात्र नहीं रहा। अपितु यह एक ऐसा सांस्कृतिक सुरक्षा कवच था जहाँ बच्चे संस्कार सीखते थे, युवा जिम्मेदारी निभाते थे और बुजुर्ग सम्मान पाते थे। यह वह व्यवस्था थी जिसने बिना किसी मनोवैज्ञानिक परामर्श के पीढ़ियों को भावनात्मक रूप से संतुलित रखा। लेकिन आज वही व्यवस्था ह्यस्पेसह्न, ह्यप्राइवेसीह्न और ह्यइंडिविजुअल फ्रीडमह्न जैसे शब्दों के नीचे दम तोड़ रही है।और जब परिवार टूटते हैं, तब केवल दीवारें अलग नहीं होतीं,तब संस्कार, संवेदनाएँ और सामाजिक संतुलन भी दरकने लगता है। आंकड़े इस सामाजिक बदलाव की पुष्टि करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 58.2% परिवार अब एकल (न्यूक्लियर) संरचना के हैं, जबकि संयुक्त परिवारों की हिस्सेदारी लगातार घट रही है । यह स्पष्ट संकेत है कि संयुक्त परिवार अब अपवाद बनते जा रहे हैं। शहरीकरण और रोजगार की मजबूरियाँ इस टूटन को और तेज कर रही हैं। शोध बताते हैं कि शहरी युवाओं में स्वतंत्रता और निजता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

## विचार

# अरावली पर्वतमाला उम्मीद जगाने वाला फैसला

**राजेश माहेश्वरी**

**अरावली** पर्वतमाला केस में उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विचार कर अपने ही आदेश पर रोक का जो निर्णय दिया है, वह स्वागतयोग्य और उम्मीद जगाने वाला है। अरावली पर्वतमाला और इससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के नष्ट होने का जो खतरा जनमानस के मन मस्तिष्क पर मंडरा रहा था, वह भी दूर हो जाएगा यह उम्मीद की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की संशोधित परिभाषा को लेकर पर्यावरण समूहों और सामाजिक संगठनों व नागरिक द्वारा उठाई गई चिंताओं और सार्वजनिक विरोध के बाद स्वतः संज्ञान लिया था। अरावली क्षेत्र अपनी इकोलॉजिकल अहमियत के लिए जाना जाता है। बताया जाता है कि विशेष तौर पर मरुस्थलीकरण को रोकने और भूजल स्तर बनाए रखने में इसकी भूमिका अहम है। यह आशंका जताई गई थी कि परिभाषा को कमजोर किए जाने से उन क्षेत्रों में खनन और निर्माण गतिविधियों को वैधता मिल सकती है, जिन्हें पहले संरक्षित माना जाता था। यह मुद्दा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावली पहाड़ियों और अरावली पर्वतमालाओं की अलग-अलग परिभाषाओं के कारण उत्पन्न हुआ था, जिससे नियामकीय खामियां और अवैध खनन के मामले सामने आए। इन असंगतियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित कमेटी और भारतीय वन पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशों को स्वीकार कर केवल सौ मीटर से ऊंची पहाडि?ों को ही अरावली पर्वतमाला का हिस्सा मानने की परिभाषा दे दी थी। समिति ने सिफारिश की थी कि 'अरावली पहाड़ी' को नामित अरावली जिलों में स्थित किसी भी ऐसे भू-आकृतिक स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जाए, जिसकी ऊंचाई स्थानीय भू-आकृति से 100 मीटर या उससे अधिक हो, और ह्यअरावली पर्वतमालाह्न ऐसी दो या अधिक पहाड़ियों का समूह होगी, जो एक-दूसरे से 500 मीटर के भीतर स्थित हों। अरावली जिलों में स्थित कोई भी भू-आकृतिक स्वरूप, जिसकी ऊंचाई स्थानीय भू-आकृति से 100 मीटर या उससे अधिक हो, अरावली पहाड़ियां कहलाएगा। उस पहाड़ी, उसकी सहायक ढलानों और संबंधित भू-आकृतियों सहित, उनकी ढाल चाहे जैसी भी हो, अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाएगा। समिति ने अरावली पर्वतमाला की भी परिभाषा दी और कहा था कि दो या अधिक अरावली पहाड़ियां, जो एक-दूसरे से 500 मीटर की निकटता में स्थित हों, वह अरावली पर्वतमाला का निर्माण करेंगी। सब जानते हैं कि अरावली पर्वतमालाएं पारिस्थितिकी संतुलन में अहम भूमिका निभाती रही है। अरावली करीब दो अरब वर्ष पुरानी भू-वैज्ञानिक प्रणाली है, जो भूजल भरण को नियंत्रित करती है, मरुस्थलीकरण को रोकती है, जलवायु को संतुलित करती है और उत्तर-पश्चिम भारत में लाखों लोगों की आजीविका का सहारा है। इसे केवल ऊंचाई आधारित नियम से परिभाषित करना न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत था, बल्कि पारिस्थितिकीय रूप से भी खतरनाक था। पिछले सवा महीने से छात्र, आमजन, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद् और पर्यावरणप्रेमी सभी अरावली की नई परिभाषा के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। यह आशंका जताई गई थी कि परिभाषा को कमजोर किए जाने से उन क्षेत्रों में खनन और निर्माण गतिविधियों को वैधता मिल सकती है, जिन्हें पहले संरक्षित माना जाता था। ताजा निर्णय में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अरावली मुद्दे की व्यापक और समग्र जांच के लिए क्षेत्र विशेषज्ञों वाले एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा। इसका मतलब है कि अब इस मामले को सुलझाने के लिए ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्हें इस क्षेत्र की पूरी जानकारी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों के तहत और उसकी ओर से मंजूर की गयी नीतियों के तहत अरावली के संरक्षण और खनन के लिए नये क्षेत्रों की पहचान नहीं हो जाती, तब तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। मंत्रालय का यह निर्देश इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार पर आरोप लग रहा था कि अरावली के बड़े क्षेत्र में खनन की अनुमति दिये जाने के लिए ही उसने अरावली की नयी परिभाषा बनायी है।

# एक्शन इंडिया दैनिक

**भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।**

आरएनआईः HARHIN / 2016 / 68417

एक्शन इंडिया मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक रवि भारद्वाज द्वारा 224, सेक्टर – 32 पी, यूई, ज़िला करनाल, हरियाणा से प्रकाशित एवं मारुतिनंदन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, शक्ति कॉम्प्लेक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–110042 से मुद्रित।

संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी

समूह संपादक : रवि भारद्वाज ( 9999889104)

स्थानीय संपादक : राजकुमार शर्मा ( 9671890000)

‘एक्शन इंडिया’ में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। संपादक या प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

ई–मेल : actionindiaharyana@gmail.com

**वैधानिक सूचना**

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच–पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

## आलेख

# नारी जागरण नहीं, नारी आगमन का समय है

**कृति आरके जैन**

**जब इ**तिहास अपने पन्ने पलटता है, तो कुछ वर्ष केवल तारीख नहीं रहते, वे चेतना बन जाते हैं। वर्ष 2026 ऐसा ही एक कालखंड है, जहां भारतीय नारी की पहचान अबला की परिधि तोड़कर सबला, सक्षम और निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित हो रही है। अब प्रश्न यह नहीं कि स्त्री क्या कर सकती है, प्रश्न यह है कि बिना स्त्री के क्या संभव है? यह परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि सदियों की चुप्पी, संघर्ष और आत्मचेतना से उपजा हुआ है। आज महिला दया या सहानुभूति की नहीं, अधिकार, अवसर और नेतृत्व की भाषा बोल रही है। वह केवल बदलाव का हिस्सा नहीं, बल्कि बदलाव की धुरी बन चुकी है। यही युगांतकारी बदलाव 2026 को नारी चेतना का स्वर्णिम अध्याय बनाता है। भारतीय समाज में लंबे समय तक स्त्री को त्याग, सहनशीलता और मौन की प्रतिमूर्ति माना गया। परंतु समय के साथ उसने प्रश्न पूछना सीखा, निर्णय लेना सीखा और अपनी पहचान स्वयं गढ़ी। शिक्षा के विस्तार, सामाजिक आंदोलनों और नीतिगत प्रयासों ने उसे नई दृष्टि दी। अब वह परिवार की सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि समाज की दिशा तय करने वाली शक्ति है। 2026 तक आते-आते महिला आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं, वैचारिक भी बन चुकी है। वह परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन साधते हुए अपने लिए नए रास्ते बना रही है। यही संतुलन उसे विशिष्ट, प्रभावशाली और प्रेरणादायी बनाता है। पिछले वर्षों में महिलाओं की श्रम भागीदारी और निर्णयात्मक भूमिकाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह परिवर्तन आंकड़ों से अधिक मानसिकता का द्योतक है। आज महिलाएं नौकरी खोजने वाली नहीं, रोजगार देने वाली बन रही हैं। वे नेतृत्व, प्रबंधन और नवाचार के क्षेत्र में नई मिसालें गढ़ रही हैं। आत्मनिर्भरता ने उन्हें आत्मविश्वास दिया है, और आत्मविश्वास ने समाज में उनकी स्वीकार्यता बढ़ाई है। 2026 की महिला आर्थिक इकाई नहीं, बल्कि आर्थिक दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति है। वह घर की अर्थव्यवस्था से लेकर राष्ट्र की विकास नीति तक अपनी स्पष्ट छाप छोड़ रही है।

# धर्म का स्वरूपः सेवा या स्वार्थ?

**डॉ प्रियंका सौरभ**

**भारत** को सदियों से धर्म, आस्था और आध्यात्म की भूमि माना जाता रहा है। यहाँ धर्म केवल पूजा-पाठ या कर्मकांड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जीवन के हर पक्ष को दिशा देने वाला तत्व रहा है। आस्था ने व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में संबल दिया, उसे नैतिकता और मानवता से जोड़े रखा। किंतु बदलते समय के साथ यह देखा जा रहा है कि आस्था का स्वरूप धीरे-धीरे विकृत होता जा रहा है। धर्म, जो आत्मिक शांति का माध्यम था, कई स्थानों पर भय, अंधविश्वास और व्यापार का साधन बनता जा रहा है। आज का यथार्थ यह है कि धार्मिक परंपराओं का एक बड़ा हिस्सा अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका है। जिन कर्मकांडों का उद्देश्य मनुष्य को आत्मिक संतुलन देना था, वे अब आर्थिक लेन-देन और दिखावे से जुड़ गए हैं। तीर्थस्थल, जो कभी तप, त्याग और साधना के केंद्र हुआ करते थे, आज कई बार बाजार का रूप धारण कर चुके हैं। श्रद्धालु की भावना से अधिक उसकी आर्थिक स्थिति को महत्व दिया जाने लगा है। आस्था का मूल आधार विश्वास है—ईश्वर में, जीवन में और स्वयं में। यह विश्वास किसी डर या लालच से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष से उपजता है। जब आस्था भय पर आधारित हो जाती है, तब वह पाखंड में बदल जाती है। दुर्भाग्यवश, आज अनेक धार्मिक गतिविधियाँ इसी भय को केंद्र में रखकर संचालित की जा रही हैं। लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि यदि उन्होंने किसी विशेष परंपरा का पालन नहीं किया या तय राशि का दान नहीं दिया, तो अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार धर्म, जो आश्वासन देने वाला था, भय पैदा करने वाला बनता जा रहा है। परंपराएँ किसी भी समाज की पहचान होती हैं। वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी अनुभव और ज्ञान के माध्यम से विकसित होती हैं। लेकिन परंपराएँ तब तक ही उपयोगी हैं, जब तक वे समय, विवेक और मानवता के अनुरूप हों। परंपराओं को पत्थर की लकीर मान लेना समाज के विकास में बाधा बनता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम परंपराओं की समीक्षा करें—यह समझें कि उनका उद्देश्य क्या है और वे वर्तमान समय में कितनी प्रासंगिक हैं।

दैनिक ट्रिब्यून
स्थापना 15 अगस्त 1978

# जानलेवा पेयजल

## मौतें सबसे स्वच्छ शहर पर कलंक

यह शर्मनाक है कि जिस शहर को पिछले सात सालों से देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा दिया जा रहा था, वहां पेयजल में सीवर का पानी मिल जाने से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो जाए। बताया जाता है कि इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन में सीवर के पानी के रिसाव से हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। घटनाक्रम के बाद सौ के करीब लोग अस्पताल में भर्ती हुए और सैकड़ों लोग दूषित पेयजल के उपयोग से बीमार हैं। वैसे भी किसी सभ्य समाज में व्यक्ति आत्मग्लानि से यह सुनकर बीमार हो जाएगा कि जिस पानी को उसने उपयोग किया, उसमें सीवर का गंदा पानी मिला था। निस्संदेह, यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही ही है, जिसके चलते हजारों लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। नगर निगम ही नहीं, इस महकमे से जुड़े सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल, इंदौर लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा हासिल करता रहा है तो इस दुर्घटना ने पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खी बना दिया। इस दुखद स्थिति के चलते मानवाधिकार आयोग और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने के लिये बाध्य होना पड़ा। विडंबना यह है कि नागरिकों ने पहले ही दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत की थी, लेकिन नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये जवाबदेह अधिकारी तब हरकत में आए, जब कई लोगों की जान जा चुकी थी। यहां तक कि इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि और राज्य के नगरीय विकास मंत्री, जिनके अधीन पेयजल आपूर्ति का महकमा आता है, उनकी संवेदनहीन बयानबाजी ने लोगों का आक्रोश बढ़ाया है। हालांकि, तल्ख आलोचना के बाद मंत्री ने खेद जताया है। यहां तक कि इस घटना के बाद मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती ने भी दोषियों से प्रायश्चित करने व दंड देने की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ छोटे स्तर के अधिकारियों के निलंबन और स्थानांतरण से इन मौतों के लिये जिम्मेदार लोगों का प्रायश्चित हो पाएगा?

लेकिन विडंबना है कि यह समस्या केवल इंदौर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के छोटे-बड़े शहरों में गाहे-बगाहे दूषित जल आपूर्ति के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। दुर्घटना के बाद जांच समितियों का गठन, मुआवजे की घोषणा और कनिष्ठ अधिकारियों का निलंबन मामले में लीपापोती का उपक्रम बन चुका है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सुधार, क्रियान्वयन और रूपांतरण' के मंत्र पर जोर दिया था। तब उन्होंने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जीवनयापन को सुगम बनाने के लिये प्रणालियों को अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया था। सवाल है कि जब नागरिकों को स्वच्छ हवा और जल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रखा जाएगा तो जीवनयापन को सुगम कैसे बनाया जा सकता है? मध्य प्रदेश की दोहरे इंजन वाली सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। कोई भी बड़ी योजना व नारा तब तक अर्थहीन है जब तक उन्हें जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई का समर्थन प्राप्त न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद-21 के तरह जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इंदौर की त्रासदी दर्शाती है कि शहरी बुनियादी ढांचे के खराब रखरखाव के कारण इस अधिकार का उल्लंघन कितनी आसानी से हो सकता है। निष्कर्ष यह भी है कि स्वच्छता रैंकिंग, स्मार्ट सिटी के दावे और शासन संबंधी नारे व्यवस्थागत नाकामी को छिपा नहीं सकते। इंदौर की घटना के बाद देश के सभी राज्यों में संबंधित विभागों व स्थानीय निकायों को पेयजल से जुड़ी व्यवस्था का ध्यान रखना होगा कि कहीं पेयजल आपूर्ति लाइन जर्जर होकर दूषित पानी से तो नहीं मिल रही है। पेयजल आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइप लाइनों का नियमित रूप से अवलोकन होना चाहिए। इस बाबत मंत्रालय और निकाय के अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसे गंभीर मामलों में लापरवाही के दोषियों को सख्त सजा देने का भी प्रावधान होना चाहिए। यह मामला गैर इरादतन हत्या जैसा भी तो है।

### आज का विचार

अपने अज्ञान का आभास होना ही ज्ञान की तरफ बड़ा कदम है।

– डिजरायली

### एकदा

#### मन की शांति से उजाला

एक बार एक प्रतापी राजा एक घने जंगल में भटक गया। वहां उसे एक गुफा में एक सिद्ध महात्मा ध्यान में लीन मिले। राजा ने पूछा, 'महात्मा जी, इस घोर अंधेरे में आप बिना दीपक के कैसे बैठे हैं?' महात्मा ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, 'दीपक बाहर जलता है तो केवल मिट्टी की दीवारें दिखाता है, लेकिन जब दीपक भीतर जलता है तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है।' राजा ने आश्चर्य से पूछा, 'भीतर का दीपक कैसे जलता है?' महात्मा बोले, 'जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का तेल खत्म कर देता है और केवल संतोष की बाती जलाता है, तब ज्ञान का वह प्रकाश होता है जिसे कोई हवा नहीं बुझा सकती।' राजा को समझ आ गया कि महल की रोशनी से बड़ी मन की शांति है। **प्रस्तुति : राजेन्द्र कुमार जांगिड़**

### 40 साल पहले

दैनिक ट्रिब्यून

#### कार स्कूटर वालों में अकारण घबराहट

नरेश कौशल द्वारा

चंडीगढ़, 2 जनवरी। वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर मोटे अक्षरों में लिखवाने के कथित आदेश से वाहन मालिकों में जो घबराहट फैली है उसका लाभ उठाकर चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा के विभिन्न नगरों में पेंटर चांदी कूट रहे हैं और कई जगह पुलिस कर्मचारी उनसे कमीशन वसूल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली दूरदर्शन पर यह चेतावनी दी गयी थी कि जिन वाहनों के आगे और पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर निर्धारित आकार में नहीं लिखे होंगे उनके मालिकों को मौके पर ही 500 रु. तक जुर्माना हो सकेगा। बताया जाता है कि यह चेतावनी केवल दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए थी लेकिन इसके कारण हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी घबराहट फैल गयी। आज चंडीगढ़ में पेंटरों की दुकानों पर सैकड़ों स्कूटरों, मोटर साइकिलों की लाइनें लगी रही हैं। इस घबराहट के कारण पेंटरों ने अपने रेट दो-तीन गुणा बढ़ा दिये हैं लेकिन डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबरों संबंधी किसी आदेश की जानकारी नहीं, यही बात डी.एस.पी. ट्रैफिक सतीश्वर राय ने भी कही है।

# आस्था कोई भी हो मगर इंसान अच्छा हो

विश्वनाथ सचदेव

यदि हिंदू हूं तो अच्छा हिंदू बनूं, मुसलमान हूं तो बेहतर मुसलमान बनूं, ईसाई हूं तो अच्छा ईसाई बनूं। और यह अच्छा होने का मतलब है अच्छा इंसान होना। अच्छा इंसान यानी वह जो अपनी आस्था में पूरा विश्वास रखने के बावजूद दूसरे की आस्था का भी सम्मान करें।

लगभग दो दशक पुरानी बात होगी। हमारे समय के एक महत्वपूर्ण संगीतकार खैयाम साहब के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला था। दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के बाद लौट रहे थे हम। उस कार्यक्रम में जो वे नहीं कह पाये थे, वही सब बता रहे थे वे। मेरी भूमिका तो सिर्फ श्रोता की थी। अचानक वह बोलते-बोलते रुक गये। कार की खिड़की से दायीं ओर देख रहे थे वे। उनके दोनों हाथ जुड़ गये थे। सिर झुक गया था उनका। मैंने देखा हमारी कार मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के सामने से गुजर रही थी। 'आपके धर्म में तो मूर्तिपूजा मना है,' मैंने अनायास ही जैसे उनसे पूछ लिया। वे मुस्कुराये, 'आदत है,' उन्होंने कहा। और फिर इसके बाद हम हिंदू-मुस्लिम संबंधों पर बात करने लग गये थे।

आज जब मैं यह लिख रहा हूं, अचानक मुझे खैयाम की यह बात याद आ गयी। इसके साथ ही एक और बात भी याद आ रही है। मेरी बेटी कान्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई है। स्कूल छोड़े उसे दशकों बीत गये। पर अब भी जब वह अपने बचपन के स्कूल के सामने से गुजरती है तो अनायास उसके हाथ 'क्रॉस' बनाने की मुद्रा में हरकत करने लगते हैं। और अपनी बात करूं– मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे के सामने से गुजरते हुए मेरा सर भी, जैसे अपने आप झुक जाता है। और मैं यह भी जानता हूं कि पूजागृहों के प्रति यह रवैया सिर्फ खैयाम, मेरी बेटी, या मेरा ही नहीं है– हम जैसे न जाने कितने हैं जो ऐसा करते हैं। और यह सब अनायास हो जाता है। लेकिन कैसे?

इस सवाल का जवाब तो यही है कि ऐसा करने के लिए किसी ने हमें कहा नहीं। मैंने अपनी बेटी से यह कभी नहीं कहा कि वह ऐसा किया करे। आप चाहें तो इसे संस्कारों का परिणाम कह सकते हैं। यह तो संभव है कि मैंने बेटी से कभी यह कहा हो कि सब धर्म समान होते हैं, पर मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी उसे समान मानने के लिए भी कहा हो। कम से कम मेरी तरफ से ऐसा कोई दबाव बच्चों पर नहीं डाला गया। मेरे माता-पिता ने भी कभी ऐसा कोई दबाव हम भाई-बहनों पर नहीं डाला।

उस दिन सिद्धिविनायक मंदिर के सामने से गुजरते हुए खैयाम साहब का अनजाने में ही सिर झुकाना भी किसी दबाव का परिणाम नहीं था। उन्होंने बताया था कि वे न जाने कब से ऐसा करते आ रहे हैं, और यह भी बताया था उन्होंने कि 'पूजागृह के सामने सिर झुकाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर धरा गया है।'

सच है, आशीर्वाद का यह अहसास मंदिर, मस्जिद, चर्च, या गुरुद्वारा, सब देते हैं। और सब धर्मों का आदर करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सर्व धर्म समभाव की संस्कृति है हमारी। हमारा धर्म, यानी हिंदू धर्म, हमें यह सिखाता है कि चाहे ईश्वर कहें या खुदा, गॉड कहें या एक ओंकार, अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं, पर पहुंचते सभी एक ही जगह हैं–पहुंचाते सभी एक ही जगह हैं हमें यह अलग-अलग रास्ते!

जैन धर्म का एक सिद्धांत है– अनेकांत वाद। यह विचार हमें समझाता है कि मैं सही हूं, पर तुम भी सही हो सकते हो। इतनी-सी बात यदि हम समझ लेते हैं तो फिर कोई विवाद बचता ही नहीं है। ईश्वर एक है फिर मेरा ईश्वर तुम्हारे ईश्वर से भिन्न या बेहतर कैसे हो सकता है? बस इतनी-सी बात समझने की आवश्यकता है कि हमारा अलग-अलग धर्म का होना एक संयोग मात्र है। मैं किसी एक धर्म में विश्वास करने वाले परिवार में पैदा हुआ इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरे माता-पिता हिंदू थे, इसलिए मैं भी हिंदू हो गया, वे मुसलमान होते तो मैं आरती की जगह नमाज़ पढ़ रहा होता। इस संदर्भ में मेरी कोई भूमिका हो सकती है तो वह यही है कि यदि हिंदू हूं तो अच्छा हिंदू बनूं, मुसलमान हूं तो बेहतर मुसलमान बनूं, ईसाई हूं तो अच्छा ईसाई बनूं। और यह अच्छा होने का मतलब है अच्छा इंसान होना। अच्छा इंसान यानी वह जो अपनी आस्था में पूरा विश्वास रखने के बावजूद दूसरे की आस्था का भी सम्मान करें।

यहीं गड़बड़ हो रही है। हम अपनी आस्था की चिंता तो करते हैं पर दूसरे की आस्था को कुछ नहीं समझते। इसी का परिणाम है कि आज पंथ-निरपेक्षता में विश्वास करने वाले हमारे भारत में धर्म के नाम पर आये दिन झगड़े-फसाद होते रहते हैं। हमारा संविधान हर भारतीय को अपनी आस्था के अनुसार धार्मिक क्रिया-कलाप की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यही नहीं, हमारा संविधान हमें अपनी आस्था अपने धर्म के प्रचार-प्रसार का भी अधिकार देता है। शर्त सिर्फ यह है कि कोई नागरिक अपने अधिकार की सीमाओं को न लांघे। ये सीमाएं भी परिभाषित हैं हमारे संविधान में– सब नागरिक समान हैं, कोई नागरिक किसी दूसरे को अपने धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए किसी प्रकार का लालच अथवा दबाव काम में नहीं ले सकता। पर अक्सर हम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं–और इसके लिए दोषी दूसरे को ठहराते हैं। धर्म के नाम पर आज जो गड़बड़ियां हो रही हैं, वे इसी अतिक्रमण का परिणाम हैं।

ऐसे ही अतिक्रमण का उदाहरण इस बार क्रिसमस के अवसर पर दिखा। देश के अलग-अलग हिस्सों में चर्चों पर, ईसाइयों पर दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिक्रिया हुई। दंगा करने वाले को यह भी स्वीकार नहीं था कि सांताक्लाज की टोपियां बेचकर कोई अपना पेट भरने के लिए कुछ कमा ले। हद तो यह भी हुई कि चर्चों के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया! क्रिसमस के आयोजनों के संदर्भ में हुए विवाद और झगड़े हैरान भी करते हैं और दुखी भी। एक ओर तो हमारे प्रधानमंत्री क्रिसमस के अवसर पर चर्च में जाकर ईसाइयों की पूजा-अर्चना में भाग लेते हैं, धार्मिक भाईचारे का संदेश देने का प्रयास करते हैं, और दूसरी ओर कुछ कथित धार्मिक संगठन क्रिसमस के रंग में भंग डालने का खुलेआम अपराध करते हैं। ऐसे कुकृत्य के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिन्हें देखकर हर विवेकशील नागरिक को शर्म आ जाये। शर्म आनी चाहिए कहना, ज़्यादा सही होगा।

हमारा भारत, बहुधर्मी है, बहु जातीय और बहुभाषी भी। यह विविधता हमारी विशेषता ही नहीं, हमारी ताकत भी है। इस विविधता पर अभिमान होना चाहिए हमें। पर धर्म के नाम पर जिस तरह एक-दूसरे को नीचा दिखाने या कम भारतीय समझने की गतिविधियां हो रही हैं, उन्हें देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि 'हे ईश्वर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर देना'।

ईश्वर तो क्षमा कर भी देगा, पर हमारी अपनी चेतना जब तक हमें बेहतर मनुष्य बनने के लिए प्रेरित नहीं करेगी, हम सही अर्थों में इंसान नहीं बन सकते। अब हमें तय करना होगा कि हम बेहतर इंसान बनना चाहते हैं या नहीं।

*लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।*

### एनईपी का क्रियान्वयन

# नयी शिक्षा नीति के समक्ष मौजूद कानूनी बाधाएं

डॉ. सुधीर कुमार

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवा पीढ़ी की तकदीर बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने एनईपी के प्रावधानों को सबसे पहले अपनाया व शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए। यह प्रमाण है कि अकादमिक स्वतंत्रता से सरकारी संस्थान भी नवाचार के केंद्र बन सकते हैं। बशर्ते कानूनी बाधाओं को दूर किया जाये।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 केवल एक सरकारी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि यह 21वीं सदी के बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की नई आकांक्षाओं का जीवंत प्रतिबिंब है। 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आई यह नीति शिक्षा जगत में उस 'पैराडाइम शिफ्ट' की वकालत करती है, जिसका इंतज़ार भारत का युवा और बौद्धिक वर्ग दशकों से कर रहा था। यह नीति जहां एक ओर लचीलेपन, कौशल विकास और बहुविषयक दृष्टिकोण के माध्यम से भारत को 'विश्व गुरु' बनाने का स्वप्न देखती है, वहीं इसे जमीनी स्तर पर लागू करने की राह में कई सूक्ष्म प्रशासनिक और कानूनी जटिलताएं भी मौजूद हैं। इस नीति की वास्तविक सफलता और विफलता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसका 'कानूनी कार्यान्वयन' है। इस वैचारिक यात्रा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने प्रेरणादायक पहल की है।

जब देश के कई राज्य और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इस नीति के जटिल नियमों और बदलावों को समझने की जद्दोजहद में उलझे थे, तब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। यह समझा कि कोई भी नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसे जमीनी वास्तविकता से न जोड़ा जाए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश के उन अग्रणी संस्थानों में शामिल हुआ, जिसने एनईपी के प्रावधानों को सबसे पहले अपनाया व अपने शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन किए। परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को एनईपी के सफल क्रियान्वयन के लिए 'प्लेटिनम अवार्ड' से नवाजा गया।

शिक्षा जगत में प्रायः एनईपी के शैक्षणिक लाभों जैसे रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति और कौशल आधारित शिक्षा - पर व्यापक चर्चा होती है, लेकिन इसके 'कानूनी पेचों' पर खामोशी बरती जाती है। इन 'साइलेंट' समस्याओं को सुलझाए बिना नीति का पूर्ण लाभ मिलना दुष्कर है। सबसे बड़ी चुनौती 'संवैधानिक विरोधाभास' की है। संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। जब केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय नीति लागू करती है, तो राज्यों के अपने विश्वविद्यालय अधिनियमों के साथ उसका स्वाभाविक टकराव होता है। मसलन, एनईपी 'मल्टीपल एंट्री और एग्जिट' की सुविधा देती है। कानूनन, यदि एक छात्र एक राज्य के विश्वविद्यालय से एक वर्ष बाद सर्टिफिकेट लेकर निकलता है और दूसरे राज्य के विश्वविद्यालय में डिप्लोमा में प्रवेश चाहता है, तो दोनों राज्यों के नियमों में भिन्नता छात्र का भविष्य संकट में डाल सकती है। इस 'क्रेडिट ट्रांसफर' की कोई ठोस कानूनी गारंटी स्पष्ट नहीं है।

दूसरा महत्वपूर्ण और मौन मुद्दा 'स्वायत्तता बनाम नियंत्रण' का है। नीति कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने का प्रस्ताव करती है, लेकिन प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के तहत चार अलग-अलग वर्टिकल - नियमन, मान्यता, वित्त पोषण और मानक निर्धारण - कैसे एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना काम करेंगे, यह एक कानूनी भूलभुलैया बनी हुई है। यहां शक्ति के केंद्रीकरण का अंदेशा भी रहता है, जो लंबी कानूनी लड़ाइयों और मुकदमों का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल संप्रभुता और डेटा सुरक्षा एक गंभीर पहलू है जिस पर पर्याप्त बहस की आवश्यकता है। 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' और डिजिटल लॉकर के माध्यम से करोड़ों छात्रों का संवेदनशील शैक्षणिक इतिहास ऑनलाइन उपलब्ध होगा। ऐसे में डेटा हैक होने या दुरुपयोग होने की स्थिति में कानूनी जवाबदेही किसकी होगी, यह अपरिभाषित है।

विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस खोलने की बात एक बड़ा कदम है, लेकिन यहां भी 'भारतीय ट्रस्ट कानून' आड़े आता है। भारत में अधिकांश शिक्षण संस्थान 'लाभ के लिए नहीं' के सिद्धांत पर चलते हैं, जबकि विदेशी संस्थान अक्सर व्यावसायिक मॉडल अपनाते हैं। उन्हें फेमा (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट) और आयकर कानूनों के तहत आय वापस भेजने की अनुमति देना भारतीय संस्थानों के साथ भेदभावपूर्ण लग सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत कानूनी चुनौती बन सकता है। साथ ही, निजी संस्थानों में फीस नियंत्रण को लेकर नीति की चुप्पी शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ा सकती है, जिससे गरीब छात्रों के लिए समान अवसर का संवैधानिक अधिकार प्रभावित होगा। शिक्षा का बाज़ारीकरण रोकना समावेशी भारत के लिए अनिवार्य है।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए अब समय है कि एनईपी को एक मजबूत कानूनी कवच प्रदान किया जाए। जब तक इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं होगी, तब तक राज्यों के बीच क्रेडिट ट्रांसफर और प्रशासनिक बाधाएं बनी रहेंगी। इसके लिए 'विशेष शिक्षा न्यायाधिकरण' की स्थापना अनिवार्य है, जो तकनीकी विवादों का त्वरित निपटारा कर सके। सरकार को चाहिए कि वह एक उच्च-स्तरीय सलाहकार समिति का गठन करे। शिक्षाविदों का व्यावहारिक अनुभव राज्यों के पुराने अधिनियमों और नई नीति के बीच का अंतर पाटने के लिए एक 'मॉडल एक्ट' तैयार करने में मददगार होगा। नई शिक्षा नीति युवा पीढ़ी की तकदीर बदलने का एक ऐतिहासिक अवसर है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का मॉडल प्रमाण है कि अकादमिक स्वतंत्रता से सरकारी संस्थान भी नवाचार के केंद्र बन सकते हैं। लेकिन इसकी दीर्घकालिक सफलता के लिए हमें उन कानूनी बाधाओं को पहचानना होगा जो गतिरोध पैदा कर सकती हैं।

*लेखक कुरुक्षेत्र विवि के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।*

### आपकी राय

#### अरावली से जीवन

अरावली पर्वत शृंखला दिल्ली-एनसीआर के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन खनन माफिया के काले कारनामों ने इसे खतरे में डाल दिया है और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को बढ़ावा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले में अरावली पर्वत के सौ मीटर नीचे तक खनन की अनुमति दी गई थी, जिस पर पर्यावरणविदों ने विरोध-प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई, जो स्वागत योग्य कदम है। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और जीवन की कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला पर्यावरण के संरक्षण में मददगार साबित होगा।

**अनिल कौशिक,** क्योड़क, कैथल

#### कर्तव्य के नए रन-वे

एक जनवरी के दैनिक ट्रिब्यून में नरेश कौशल का लेख 'कृपया पेटी बांध लें, हम कर्तव्य के नए रन-वे पर उतरने को हैं' बीते वर्ष 2025 का लेखा-जोखा और नए वर्ष में लक्ष्यों को पूरा करने का आह्वान था। वर्ष 2025 में बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, सांप्रदायिकता, महिलाओं के प्रति अन्याय जैसी समस्याओं ने सिर उठाया, लेकिन कुछ अच्छी घटनाएं भी हुईं, जैसे विज्ञान और तकनीक में तरक्की और सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला। सरकार को अपने दावों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

**शामलाल कौशल,** रोहतक

#### गिग-वर्कर्स की बदहाली

संपादकीय 'मेहनतकशों की बेकद्री' में बताया गया है कि वर्तमान में गिगवर्कर्स की संख्या सवा करोड़ है, जो 2030 तक बढ़कर ढाई करोड़ हो सकती है। ये मजदूर 14 घंटे काम करने के बावजूद केवल 700-800 रुपये ही प्राप्त करते हैं, और इनका दुर्घटना बीमा भी नहीं होता है। वे मोटरसाइकिल से जरूरत का सामान घर-घर पहुंचाते हैं। 31 दिसंबर की हड़ताल और संसद में मामला उठने के बाद सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। इन श्रमिकों के बेहतर भुगतान और श्रम सुधार कानून में बदलाव की आवश्यकता है, ताकि उनका शोषण रुक सके।

**बीएल शर्मा,** तराना, उज्जैन

**संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशनार्थ लेख इस ईमेल पर भेजें :-**
dtmagzine@tribunemail.com

### तिरछी नज़र

# दांत किटकिटाते आम और दांत निपोरते खास

**सहीराम**

वे हंसे थे यह दिखाते हुए कि मैं चाहे यह करूं, मैं चाहे वो करूं। मेरी मर्जी। वे एक संप्रभु राज्य की बेबसी पर हंसे थे कि उसके चोर-दरवाजों से हम किस खूबी से निकल भागे हैं।

देखो जी, जिस तरह की शीतलहर चल रही है, उसमें तो हंसने की बजाय दांत किटकिटाने की संभावना ही ज्यादा है। लेकिन बेशर्मों पर बेशरमाई इस कदर सवार रहती है कि वे हंसने के नाम पर कभी दांत दिखाने लगते हैं, जिसे अगर हरियाणवी अंदाज में कहें तो दांत फाड़ना भी कह सकते हैं। लेकिन जब थू-थू होने लगती है तो वे दांत निपोरने भी लगते हैं। ललित मोदी और विजय माल्या ने इसी तरह पहले तो दांत फाड़े और फिर दांत निपोरने लगे हैं। उन्होंने पार्टी करते और बेशर्मी दिखाते हुए पहले तो अपनी महानता का बखान किया, जिसे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना ही कहा जा सकता है। उन्होंने अपने आपको भारत के महान भगोड़े बताया और हंसे। वे उस तरह से नहीं हंसे थे जैसे बलात्कारी सेंगर, जेल जाते हुए हंसा था। वे तो भारतीय गणराज्य पर, यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, अदालती प्रक्रिया पर, कानून के चोर-दरवाजों पर, कानूनी ढील-ढिलाई पर और भी न जाने किस-किस पर हंसे थे।

वे हंसे थे अपना यह अहंकार दिखाते हुए कि हम इस मुल्क की दौलत लूटकर भागे, बताओ तुमने हमारा क्या बिगाड़ लिया? वे हंसे थे अपनी कुटिलता और अपनी धूर्तता पर कि देखो हमने तुम्हें कितनी सफाई से लूटा। वे सिर्फ अपने भ्रष्ट आचरण पर नहीं हंसे थे, वे देश में व्याप्त उस भ्रष्टाचार पर भी हंसे थे, जिसके चलते उन्हें इतने बड़े-बड़े कर्ज मिले और जिसके चलते वे अपने सैकड़ों नहीं तो दर्जनों तो अवश्य ही, सूटकेसों को हवाई जहाजों में लाद-लाद कर विदेश भाग गए और अब वहां आराम से पार्टियां कर रहे हैं।

वे हंसे थे इस देश की मेहनतकश, लेकिन गरीब जनता पर कि देखो मेहनत से तो रोटी भी नहीं कमाई जा सकती, लेकिन बेईमानी से विदेशों में ऐश की जा सकती है। जब चाहे पार्टी करो। जब चाहे बीमार हो जाओ। जब चाहो अदालत का सहारा लेकर अपना प्रत्यर्पण रोके रहो और जब चाहे पोडकास्ट करके सरकार को कटघरे में खड़ा कर दो। वे हंसे थे यह दिखाते हुए कि मैं चाहे यह करूं, मैं चाहे वो करूं। मेरी मर्जी। वे एक संप्रभु राज्य की बेबसी पर हंसे थे कि उसके चोर-दरवाजों से हम किस खूबी से निकल भागे हैं।

वे हंसे थे उस समर्थन पर, जो लुके-छुपे ढंग से राजनीतिक हलकों से, नौकरशाही से, न्यायिक व्यवस्था से उन्हें मिलता रहा है। और वे शायद इसलिए भी हंसे थे कि यह समर्थन उन्हें आगे भी मिलता रहेगा। वे अपनी चालाकी, अपनी बेशर्मी, अपनी बेईमानी, अपनी कुटिलता, अपनी धूर्तता और अपनी ठसक पर इतराते हुए हंसे थे। वे हंसे थे इस देश की नासमझी पर, लापरवाही पर और उदासीनता पर। लेकिन फिर जब डरे तो उन्होंने दांत भी निपोरे। देखा ना? नहीं?

अमृत विचार
शनिवार, 3 जनवरी 2026

यदि विश्वास विवेक का ताप नहीं सह सकता है, तो वह अपने आप ध्वस्त हो जाएगा।
-शहीदे आजम भगत सिंह

# दर्दनाक दुर्घटना के सबक

स्विट्ज़रलैंड जैसे अत्यंत विकसित, अनुशासित और सुरक्षित माने जाने वाले देश में नववर्ष की पूर्व संध्या पर क्रान्स मोंटाना के एक स्की रिसॉर्ट बार में विस्फोट और आग से लगभग 47 लोगों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उत्सव, सुरक्षा और प्रशासनिक सतर्कता के बीच संतुलन पर गंभीर प्रश्न है। प्रथम दृष्टया यह हादसा 'उत्सव के अति उत्साह' और लापरवाही का परिणाम प्रतीत होता है। नववर्ष समारोहों में मोमबत्तियां, शैंपेन की बोतलों पर सजावट, फुलझड़ियां और कथित तौर पर 'पायरोटेक्निक डिवाइस' का उपयोग किया जा रहा था। यदि मोमबत्तियां लकड़ी की छत के पास रखी गईं या बेसमेंट में रखी आतिशबाजी से चिंगारी फैली, तो यह सीधी मानवीय चूक है। गैस लीक की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। विकसित देशों में भी जब नियमों को 'एक रात की छूट' दे दी जाती है, तो हादसे की ज़मीन तैयार हो जाती है।

यह तथ्य और भी चौंकाने वाला है कि मात्र 15 हजार आबादी वाले इस नगर के एक बार में करीब 150 लोग मौजूद थे और उनमें से एक-तिहाई की जान चली गई। इसे स्विट्ज़रलैंड के हालिया इतिहास की सबसे भीषण अग्नि दुर्घटनाओं में गिना जा रहा है। 150 से अधिक हेलीकॉप्टर, सैकड़ों बचावकर्मियों और बड़े पैमाने पर आपात संसाधनों की तैनाती इस बात की पुष्टि करती है कि हादसा कितना व्यापक और भयावह था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बाहर निकलने के रास्ते और सीढ़ियां अत्यंत संकरी थीं। 30 सेकंड के भीतर लगभग 200 लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिससे भगदड़ मच गई और लोग दबने व दम घुटने से मारे गए। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या रिसॉर्ट की डिजाइन और फायर-सेफ्टी ऑडिट में गंभीर खामियां थीं? क्या आपदा प्रबंधन, प्रशिक्षित स्टॉफ, स्पष्ट एग्ज़िट साइन और त्वरित मार्गदर्शन की व्यवस्था नहीं थी? यदि स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में भी ऐसी चूक संभव है, तो यह चेतावनी है कि 'विकास' सुरक्षा की गारंटी नहीं होता। भारत के संदर्भ में यह घटना और भी प्रासंगिक है। गोवा जैसे पर्यटन स्थलों पर हुए अग्निकांडों में भी संकरे रास्ते, अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के कारण लोगों की जान गई। फर्क केवल इतना है कि वहां हम अक्सर इसे 'व्यवस्था की विफलता' कहकर आगे बढ़ जाते हैं। क्रान्स मोंटाना की त्रासदी सिखाती है कि नियम चाहे यूरोप में हों या भारत में, उनका कठोर पालन ही जीवन बचाता है।

आने वाले समय में इस घटना का असर क्रान्स मोंटाना में प्रस्तावित एफआईएस वर्ल्ड कप जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों पर भी पड़ेगा। इससे उसे साख का नुकसान हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा मानकों की पुनर्समीक्षा अनिवार्य होगी। इससे पहले 2000 और 2020 में स्विट्ज़रलैंड के अन्य शहरों में लगी आग से यदि पर्याप्त सबक लिया गया होता, तो शायद यह दिन न देखना पड़ता। निष्कर्षतः, भारत समेत सभी देशों को यह सीख लेनी चाहिए कि उत्सव, पर्यटन और व्यवसाय तभी सार्थक हैं जब सुरक्षा सर्वोपरि हो। आपदा प्रबंधन कोई औपचारिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि जीवित व्यवस्था होनी चाहिए— हर इमारत, हर आयोजन के लिए।

## प्रसंगवश

# साल की पहली पूर्णिमा पर दिखेगा वुल्फ सुपरमून

तीन जनवरी 2026 की रात आकाश एक असामान्य खगोलीय स्थिति का साक्षी बनेगा। इसी रात वर्ष का पहला पूर्ण चंद्रमा वुल्फ़ सुपरमून के रूप में दिखाई देगा, जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट होकर सामान्य से अधिक बड़ा और अधिक चमकीला नजर आएगा। यह स्थिति केवल दृश्य परिवर्तन नहीं है, बल्कि सूर्य-पृथ्वी-चंद्रमा की दुर्लभ ज्यामिति का परिणाम है। ठंडी रात में फैली इसकी तेज रोशनी पूरे आकाशीय परिदृश्य को बदल देगी और सामान्य पूर्णिमा से अलग, अधिक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराएगी। यह दृश्य खगोलीय गणनाओं की सटीकता और प्रकृति की नियमित शक्ति दोनों को एक साथ उजागर करेगा।

यह सुपरमून इसलिए विशेष माना जा रहा है, क्योंकि इसी समय चंद्रमा अपनी कक्षा के उस बिंदु पर होगा जहां वह पृथ्वी के सबसे अधिक समीप होता है, जिसे खगोल विज्ञान में 'पेरिगी' कहा जाता है।

प्रो. आरके जैन
शिक्षाविद्

इस निकटता का सीधा प्रभाव उसके आकार और प्रकाश पर पड़ता है। सामान्य पूर्णिमा की तुलना में चंद्रमा अधिक बड़ा और कहीं अधिक चमकीला दिखाई देगा। भारत में इसका पूर्ण चरण भले ही दोपहर में बने, पर इसका वास्तविक प्रभाव सूर्यास्त के बाद दिखाई देगा, जब पूर्वी क्षितिज से उभरता चंद्रमा असामान्य रूप से विशाल और प्रभावशाली लगेगा। वायुमंडल की परतें उसकी रोशनी को पीले-सुनहरे और तांबे जैसे रंगों में ढाल देंगी, जिससे पूरा दृश्य ऐसा प्रतीत होगा, जैसे आकाश ने नववर्ष के स्वागत में प्रकाश प्रज्वलित कर दिया हो।

'वुल्फ़ मून' नाम केवल एक संबोधन नहीं, बल्कि मानव इतिहास से जुड़ी एक गहरी स्मृति है। उत्तरी गोलार्ध की प्राचीन संस्कृतियों ने जनवरी की पूर्णिमा को यह नाम इसलिए दिया, क्योंकि इसी समय सर्द रातों में भेड़ियों की आवाज़ें अधिक सुनाई देती थीं। यह हूक भय या अभाव की नहीं, बल्कि आपसी संकेत, समूहबोध और जीवन-चक्र की निरंतरता का स्वर थी। भेड़िये सिर उठाकर आकाश की ओर हौल करते हैं, ताकि उनकी आवाज़ दूर तक फैल सके, मानो वे चंद्रमा को साक्षी मानकर अपने अस्तित्व और क्षेत्र की घोषणा कर रहे हों। वुल्फ़ मून केवल एक खगोलीय घटना नहीं रह जाता, बल्कि प्रकृति की सामूहिक स्मृति और जीव-जगत के संवाद का प्रतीक बन जाता है।

इस वर्ष वुल्फ़ सुपरमून को और अधिक उल्लेखनीय बनाता है, एक दुर्लभ खगोलीय संयोग। ठीक तीन जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट बिंदु, पेरिहेलियन पर भी होगी। इसका परिणाम यह होगा कि सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा के साथ चंद्रमा पर पड़ेंगी, जिससे उसकी चमक में हल्की अतिरिक्त गहराई और तीव्रता दिखाई देगी। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टि से यह अंतर सूक्ष्म होता है, पर दृष्टिगत प्रभाव अत्यंत आकर्षक बन जाता है। समुद्री क्षेत्रों में इस संयुक्त गुरुत्वीय प्रभाव के कारण ज्वार-भाटे सामान्य से कुछ अधिक ऊंचे उठ सकते हैं, जिससे प्रकृति की यह खगोलीय संगति धरती पर भी अपना असर छोड़ती दिखाई देगी।

इस खगोलीय दृश्य में रोमांच का एक और आयाम जुड़ता है- क्वाड्रैंटिड उल्का वर्षा। तीन और चार जनवरी की रात यह वर्षा अपने चरम पर होती है और अनुकूल परिस्थितियों में प्रति घंटे अनेक उल्काएं दिखाई दे सकती हैं। यद्यपि पूर्ण चंद्रमा की तीव्र रोशनी कई छोटी उल्काओं को ढक देगी, फिर भी कुछ अत्यंत चमकीली अग्नि-रेखाएं आकाश को चीरती हुई स्पष्ट दिख सकती हैं। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होगा मानो स्थिर और गंभीर चंद्रमा के सामने समय स्वयं प्रकाश की लकीरों में बह रहा हो। स्थायित्व और क्षणभंगुरता का यह संगम मन को गहराई से छू जाता है।

# आर्थिक प्रगति और असमानता की समानांतर दास्तान

राजेश श्रीनेत
वरिष्ठ पत्रकार

आर्थिक सुधारों को भारत की विकास यात्रा का निर्णायक मोड़ माना जा सकता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। उत्पादन बढ़ा, बाजार खुले, विदेशी निवेश आया और भारत वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बनकर उभरा है। सरकार का दावा है कि इन सुधारों का प्रतिफल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि आर्थिक क्षमता और विकास की गति का संकेत देती है, लेकिन इसके साथ यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या इस आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग को समान रूप से मिल पाया है।

आंकड़ों के स्तर पर भारत की प्रगति प्रभावशाली दिखती है। 1991 में देश की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 275 अरब डॉलर था, जो 2024-25 में बढ़कर लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। बीते एक दशक में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा है। सरकार इस उपलब्धि को आर्थिक सुधारों, मजबूत घरेलू बाजार और बढ़ते बुनियादी ढांचे का परिणाम बताती है। इसके बावजूद जमीनी सच्चाई यह है कि इस विकास का वितरण असमान रहा है और समाज का एक बड़ा हिस्सा अब भी इसके पूरे लाभ से वंचित है।

आंकड़ों के स्तर पर भारत की प्रगति प्रभावशाली दिखती है। इसके बावजूद जमीनी सच्चाई यह है कि इस विकास का वितरण असमान रहा है और समाज का एक बड़ा हिस्सा अब भी इसके पूरे लाभ से वंचित है।

ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि देश की शीर्ष एक प्रतिशत आबादी के पास कुल संपत्ति का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा केंद्रित है, जबकि निचले 50 प्रतिशत लोगों के पास कुल संपत्ति का केवल 3 प्रतिशत हिस्सा है। यह स्थिति दर्शाती है कि आर्थिक वृद्धि का बड़ा भाग सीमित वर्गों तक सिमट गया है। आर्थिक सुधारों से पैदा हुई समृद्धि का लाभ व्यापक स्तर पर फैलने के बजाय ऊपर की ओर केंद्रित होता गया। रोजगार के क्षेत्र में यह असमानता और अधिक साफ हो जाती है। सरकारी और निजी दोनों आकलन बताते हैं कि देश का करीब 90 प्रतिशत कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहां न तो स्थायी रोजगार है और न ही सामाजिक सुरक्षा।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 2023-24 में शहरी बेरोजगारी दर औसतन 7 से 8 प्रतिशत के बीच रही, जबकि युवाओं में यह दर 15 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई। आर्थिक सुधारों के बाद संगठित क्षेत्र का विस्तार तो हुआ, लेकिन रोजगार सृजन की रफ्तार श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले युवाओं की संख्या के अनुरूप नहीं रही।

ग्रामीण भारत की स्थिति भी इस असंतुलित विकास को उजागर करती है। देश की लगभग 45 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में केवल 15 प्रतिशत के आसपास सिमटा हुआ है। नीति आयोग के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों की औसत मासिक आय अब भी 10 से 12 हजार रुपये के आसपास है। बढ़ती लागत, अनिश्चित मौसम और बाजार की अस्थिरता ने कृषि को कम लाभकारी बना दिया है। आर्थिक सुधारों का लाभ उद्योग और सेवा क्षेत्र तक तो पहुंचा, लेकिन कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत पीछे छूटती चली गई।

शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी असमानता की खाई गहरी हुई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल स्वास्थ्य व्यय का करीब 55 प्रतिशत हिस्सा लोगों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। इतना अधिक निजी खर्च गरीब और निम्न मध्यम वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात लगभग 28 प्रतिशत है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच आज भी सीमित वर्गों तक ही सिमटी हुई है। निजी शिक्षा संस्थानों की बढ़ती फीस ने अवसरों की असमानता को और बढ़ा दिया है।

क्षेत्रीय असमानता भी आर्थिक सुधारों की एक बड़ी चुनौती रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य तेजी से आगे बढ़े, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य अब भी विकास की दौड़ में पीछे हैं। नीति आयोग के अनुसार देश के शीर्ष 10 जिलों की प्रति व्यक्ति आय, निचले 10 जिलों की तुलना में चार से पांच गुना अधिक है। यह अंतर केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक विकास के सूचकांकों में भी दिखाई देता है।

सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में करीब 50 करोड़ लोग स्वास्थ्य बीमा से जुड़े हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सब्सिडी और सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई जा रही है। इन पहलों से गरीब और कमजोर वर्गों को राहत मिली है, लेकिन ये उपाय असमानता की संरचनात्मक जड़ों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाते।

भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सरकारी दावे के साथ यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है कि इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति होने के बावजूद रोजगार, आय और अवसरों की समानता क्यों नहीं बन पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि अगले दशक में भारत को हर साल लगभग एक करोड़ नए रोजगार सृजित करने होंगे। यदि विकास अधिक पूंजी और तकनीक केंद्रित ही रहा, तो यह चुनौती और गंभीर हो सकती है।

समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि आर्थिक सुधारों को मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना होगा। छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त कर रोजगार सृजन की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश से आय के स्थायी स्रोत विकसित होंगे और क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। साथ ही कर प्रणाली को अधिक प्रगतिशील बनाकर संसाधनों का न्यायसंगत वितरण भी जरूरी है।

## आमने सामने

**आमने:** वह व्यक्ति भगवान राम को समझ ही नहीं पाया है। श्रीराम और राहुल गांधी की किसी भी तरह से तुलना नहीं की जा सकती है। भगवान ही जानें राहुल गांधी किस तरह का काम कर रहे हैं।
-स्वामी रामभद्राचार्य
प्रसिद्ध संत

**सामने:** रामभद्राचार्य जी बड़े और सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए वह उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी की लड़ाई किसानों, गरीबों और वंचितों के हक के लिए है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, वह देश के हित में है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
-नाना पटोले
कांग्रेस नेता

# खालिदा जिया के शासनकाल में भारत से संबंध

विवेक शुक्ला
पूर्व सूचना अधिकारी, यूएई एंबेसी

खालिदा जिया ने बांग्लादेश में दो बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। पहली बार 1991 से 1996 तक और दूसरी बार 2001 से 2006 तक। उनके शासनकाल को बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में, विशेष रूप से भारत के साथ, यह अवधि कटुता और अविश्वास की छाया में गुजरी। खालिदा जिया की नीतियां और निर्णय अक्सर पाकिस्तान-समर्थक और भारत-विरोधी माने जाते थे, जिसने दोनों देशों के बीच सहयोग को बाधित किया। उनके प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान, हिंदुओं पर हमले होते रहे और टाटा समूह के प्रस्तावित निवेश को रोका गया। ये दोनों मुद्दे न केवल बांग्लादेश की आंतरिक चुनौतियों को दर्शाते हैं, बल्कि भारत-बांग्लादेश संबंधों में उत्पन्न तनाव के प्रमुख कारण भी बने।

खालिदा जिया की नीतियां और निर्णय अक्सर पाकिस्तान-समर्थक और भारत-विरोधी माने जाते थे, जिसने दोनों देशों के बीच सहयोग को बाधित किया।

सबसे पहले, हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 8-10 प्रतिशत है और ऐतिहासिक रूप से यह समुदाय विभिन्न राजनीतिक उथल-पुथल का शिकार रहा है। खालिदा जिया के 2001 में सत्ता में आने के बाद, स्थिति विशेष रूप से गंभीर हो गई। 2001 के आम चुनावों में बीएनपी और उसके सहयोगी जमात-ए-इस्लामी की जीत के तुरंत बाद, देशभर में हिंदू समुदाय पर संगठित हमले शुरू हो गए।

इन हमलों में हजारों हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक अनुमान के मुताबिक, कम से कम 30,000 से अधिक हिंदू प्रभावित हुए और कई को देश छोड़कर भारत भागना पड़ा। ये हमले मुख्य रूप से बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए, जो चुनावी जीत को 'इस्लामी विजय' के रूप में प्रचारित कर रहे थे।

खालिदा जिया की सरकार ने इन हमलों को रोकने या दोषियों को दंडित करने में स्पष्ट रूप से विफलता दिखाई। हालांकि सरकार ने कुछ जांच समितियां गठित कीं, लेकिन व्यावहारिक कार्रवाई नगण्य रही। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन घटनाओं की निंदा की और इन्हें 'संगठित सांप्रदायिक हिंसा' करार दिया। उदाहरण के लिए, 2001 में बारिसाल, खुलना और ढाका जैसे क्षेत्रों में हिंदू गांवों पर हमले हुए, जहां संपत्ति जब्ती और जबरन धर्मांतरण की घटनाएं आम थीं।

खालिदा जिया की सरकार का रुख यह था कि ये 'छिटपुट घटनाएं' हैं, लेकिन वास्तव में, जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी सहयोगियों को खुश रखने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। यह विफलता न केवल बांग्लादेश की आंतरिक एकता को प्रभावित करती थी, बल्कि भारत के साथ संबंधों को भी कटु बनाती थी। भारत, जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, ने इन हमलों को गंभीरता से लिया और बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। भारतीय मीडिया और राजनीतिक हलकों में इसे 'हिंदू उत्पीड़न' के रूप में चित्रित किया गया, जिसने दोनों देशों के बीच अविश्वास को बढ़ाया।

खालिदा जिया की भारत-विरोधी छवि पहले से ही मजबूत थी, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार में भारत को 'दुश्मन' के रूप में पेश किया था। ऐसे बयानों ने हिंदू सुरक्षा के मुद्दे को और जटिल बना दिया, क्योंकि भारत ने इसे सीमा पार शरणार्थी समस्या के रूप में देखा। परिणामस्वरूप, 2001-2006 के दौरान दोनों देशों के बीच राजनयिक वार्ताएं सीमित रहीं और भारत ने बांग्लादेश को 'अल्पसंख्यक सुरक्षा' पर दबाव डाला, जो खालिदा सरकार द्वारा नजरअंदाज किया गया।

दूसरा प्रमुख बिंदु टाटा समूह के प्रस्तावित निवेश का रहा। 2004-2005 में, भारतीय औद्योगिक दिग्गज टाटा ग्रुप ने बांग्लादेश में लगभग तीन अरब डॉलर के निवेश का प्रस्ताव रखा। इस योजना में स्टील प्लांट, उर्वरक कारखाना और बिजली उत्पादन इकाइयां शामिल थीं, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा अवसर था। यह निवेश न केवल हजारों रोजगार पैदा करता, बल्कि बांग्लादेश की ऊर्जा और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करता। टाटा ने प्राकृतिक गैस की सस्ती आपूर्ति की मांग की, जो बांग्लादेश के पास उपलब्ध थी, हालांकि खालिदा जिया की सरकार ने इस प्रस्ताव पर लगातार देरी की और अंततः इसे अस्वीकार कर दिया।

टाटा ने 2006 तक कई दौर की वार्ताएं कीं, लेकिन सरकार की ओर से गैस मूल्य और अन्य शर्तों पर असहमति बनी रही। अंत में, 2008 में टाटा ने योजना त्याग दी और बांग्लादेश ने पाकिस्तानी दाऊद ग्रुप जैसे अन्य निवेशकों को आमंत्रित किया। यह निर्णय बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक साबित हुआ, क्योंकि निवेश की कमी से विकास दर प्रभावित हुई। खालिदा जिया की 2006 में भारत यात्रा के दौरान भी इस मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं हुई, हालांकि ट्रेड डील पर चर्चा हुई। भारतीय पक्ष ने इसे 'अवसर की बर्बादी' माना, क्योंकि टाटा का निवेश दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दे सकता था।

## सोशल फोरम

# सारा एक गुमनाम शायरा

सारा शगुफ्ता का नाम उर्दू शायरी में बहुत कम लिया जाता है। इतिहास मानो उससे पल्ला छुड़ाने की ही कोशिश में था कि ये प्रयास सफल नहीं हो पाए। उर्दू हलके ने पचास सालों तक ख़ूब कोशिश की दक्षिण एशियाई बौद्धिक-स्त्रीवादी इतिहास से सारा शगुफ़्ता को मिटाने की। अमृता प्रीतम से सारा ने कई साल पत्र-व्यवहार किया। अपने जीते-जी एक बार वादा लिया था कि अमृता उसका कविता संग्रह अनुवाद करके छपवाएंगी। सारा के जाने के बाद उसके तमाम ख़त और कविताओं को सामने रखते हुए अमृता ने एक किताब लिखी।

सुजाता चोखेरबाली
एसोसिएट प्रोफेसर

सारा का जन्म 1954 में गुजरांवाला, पाकिस्तान में हुआ था। बहुत कम वक्त गुज़ारा इस दुनिया में उसने। 29 की उम्र में आत्महत्या कर ली। पिता के साथ बेहद ख़राब रिश्ता मिला तो 17 की उम्र में ब्याह दी गई अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। नवजात बच्चा चल बसा और इसके लिए इल्ज़ाम आया सारा के सर। इन सदमों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। पति को छोड़कर निकल गईं और अपनी देह से बेगानी हो गई। चार विवाह और इसके अलावा बहुत से संबंध।

उसके जीवन की अराजकता मानो कोई बदला था दुनिया से कि जिस देह को, जिसके सेक्स को तुम स्त्री के वजूद के ऊपर मानते आए हो और जिसके लिए यह सारी सांसारिक प्रताड़ना है औरत के हिस्से, उसी को मैं आग, पानी, मिट्टी, हवा के हवाले करती हूं। एक जगह कभी उसने लिखा था- मेरा शरीर बहुत साधारण था, तो मैंने उसे कुत्तों को दे दिया, लेकिन सारा की आत्मा साधारण नहीं थी कि तुम्हारे हाथों उसे बिक जाने देती। एक कविता में सारा कहती हैं- तुझे जब भी कोई दुख दे उस दुख का नाम बेटी रखना। अपने स्त्री होने के कारण उसने जो भोगा उसे लिखा। यही शायद सबसे बड़ा गुनाह किया। वह लिखती हैं-

**आसमान के सीने में ग़म चरख़ा कात रहा है**
**संग-ए-मील**
**पहरों चलता है और साकित है**
**रात मुझ से पहले जाग गई है**
**लिबास पर पड़े हुए धब्बे**
**मेरे बच्चों के दुख थे**
**मेरे लहू को तन्हाइयां चाट रही हैं**
**शहर की मुंडेर से तिनके चुराए थे**
**सूरज ने दुख बना दिए**
**मेरे सपनों का दाग़ आंखें हैं**
**मेरी क़ब्र मुझे छुप कर देख रही है।**

*-फेसबुक वॉल से*

## सामयिकी

# सोच बदली तो हरियाणा में सुधरने लगा लिंगानुपात

हरियाणा आज लिंगानुपात में निरंतर सुधार का उदाहरण बनता जा रहा है। यह बदलाव किसी एक दिन या एक साल में नहीं आया, बल्कि वर्षों की योजनाबद्ध कोशिशों, सामाजिक जागरूकता और सरकारी सख्ती का परिणाम है। हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 910 था। निरंतर सरकारी निगरानी और सामाजिक प्रयासों के चलते 30 दिसंबर 2025 तक यह बढ़कर 923 तक पहुंच गया। यह 13 अंकों की वृद्धि है, जिसे पिछले छह वर्षों का बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है।

हरियाणा में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना लिंगानुपात सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने और बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने में मदद मिली है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि अकाउंट जैसी योजनाओं से बेटियों के भविष्य के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना आसान हुआ है। यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्ची को जीवन में समान अवसर मिलें।

धनीश शर्मा
लेखक

हरियाणा राज्य का एक समय ऐसा भी रहा है, जब बेटियों को बोझ समझा जाता था। सामाजिक दबाव, अंधविश्वास और पितृसत्तात्मक सोच के कारण गर्भ में ही कन्या भ्रूण हत्या जैसे अमानवीय कृत्य किए जाते थे। उस दौर में लिंगानुपात लगातार गिरता गया और यह स्थिति समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी बन गई। समय के साथ सोच में बदलाव आया। सरकार और समाज दोनों ने यह समझा कि यदि बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, तो भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा।

हरियाणा सरकार ने जन्म के समय लिंगानुपात सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। ग्रामीण और शहरी पंचायतों में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य विभाग की नियमित मॉनिटरिंग और अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण पर सख्त कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों को भी इस दिशा में सशक्त बनाया गया। किशोरियों के लिए पोषण अभियान, स्कूल स्तर पर स्वास्थ्य जांच तथा कौशल विकास कार्यक्रमों से बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने पर ज़ोर दिया गया। साथ ही कानून की सख्त निगरानी ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि लिंग चयन जैसे अपराध किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

हरियाणा के बढ़ते लिंगानुपात में सबसे बड़ा योगदान हरियाणा की बेटियों को जाता है, जिन्होंने कठिनाईयों के बीच में रहकर अपनी मंजिल को हासिल किया है। यहां बेटियों ने खेलों के क्षेत्र में भी राज्य का नाम रोशन किया है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, गीतिका जाखड़, कविता चहल, पूजा सिंह, रमिता जिंदल और भजन कौर जैसी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सफलता हासिल कर यह साबित किया है कि अवसर मिलने पर बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उनके संघर्ष और उपलब्धियों ने समाज में सकारात्मक सोच फैलाने में मदद की है।

लिंगानुपात में सुधार केवल सरकारी योजनाओं का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के विस्तार का संकेत है। जब परिवार बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर देने लगते हैं, तभी वास्तविक और स्थायी बदलाव संभव होता है। हरियाणा सरकार ने भी लगातार निगरानी, ज़मीनी स्तर पर जागरूकता और स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति ने लिंगानुपात सुधार को संभव बनाया, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

स्वामी-रुहेलखंड इंटरप्राइजेज के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक त्रिनाथ शुक्ला द्वारा 25/16-ए, जाप्लिंग रोड, लखनऊ-226001 (उ.प्र.) से प्रकाशित एवं प्लाट नं.-42, निकट बद्री नगर, इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज, लखनऊ-226008 (उ.प्र.) से मुद्रित। **संपादक- राजेश श्रीनेत, कार्यकारी संपादक- अनिल त्रिगुणायत***
0522-4008111 (कार्यालय), ईमेल-editorschoice@amritvichar.com, आर.एन.आई नं0-50986/1989 *इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी। (नोट-सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा)।

# दुनिया बहुत सुंदर है इसे बदसूरत न बनायें

प्रभात सिंह

आधी रात हो चुकी थी। अचानक बाहर कहीं से पटाख़ों के तेज़ धमाकों की गूंज सुनाई दी। एक के बाद एक, लगातार। नए साल के आगाज़ की ज़ोरदार मुनादी। शहर भर में जगह-जगह चल रहे जश्न में बुझा दी गई बत्तियां शायद अब जल उठी होंगी। शहर जाग रहा था, या कहें कि पूरा मुल्क ही। यों दुनिया भी कहां सो रही होगी! हमारा जागना, ये जश्न, मौज-मस्ती की ये महफ़िलें, मगर 'बहुत पहले अपने मुकद्दर से किया वायदा' पूरा करने का जोश थोड़े ही है। यह तो कैलेंडर बदलने का जश्न है।तोपों की सलामी जैसे धमाकों, शोर-संगीत के बीच उलझा उल्लास, कुछ पहचाने और कुछ अनजाने चेहरों की मुबारकबाद वाले विज्ञापनों से भरे हुए अख़बार, इनबॉक्स संदेशों की भरमार, शुभकामनाओं के बेशुमार नोटिफ़िकेशन, सोशल मीडिया में छा जाने की होड़, यह सब जज़्बात से कहीं ज़्यादा एक ख़ास तरह की मशीनी पाबंदी जैसे मालूम होने लगते हैं। सोचता हूं कि कैलेंडर बदलने से सचमुच क्या तारीख़ भी बदलती है! दिलो-दिमाग़ और हमारे ग़ौर-ओ-फ़िक्र के दायरे पर भी इसकी कोई छाप पड़ती है क्या! इस सोच को उम्र का तक़ाज़ा मान सकते हैं, अख़बारनवीस का दिमाग़ी फ़ितूर या कि अभी हाल के कुछ वाक़ये, जिनसे हमारा शहर गुज़रा है और जिनकी नौइयत शहर के मिज़ाज, समाजी जज़्बात और ज़िंदगी में ख़लल डालने वाली लगती है। ख़बरों के मामले में इंटरनेट की दुनिया 'जंगल की आग की तरह' वाले मुहावरे का पर्यायवाची है। सो 24 दिसंबर की शाम की यह ख़बर तेज़ी से आम हुई कि बरेली के सेंट अल्फ़ोंसस कैथेड्रल के बाहर बजरंग दल के सदस्यों ने धरना दिया और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। बजरंग दल के लोगों की दलील थी कि क्रिसमस के जलसे में स्कूली बच्चों के ज़रिये ऐसी नाटिका का मंचन हुआ, जिसमें कथित तौर पर हिन्दू धर्म और समाज को ग़लत रौशनी में पेश किया गया था। इसकी वजह से बच्चों और उनके मां-बाप को ठेस पहुंची। क़रीब आधा घंटे तक धरने और नारेबाज़ी के बाद पुलिस को शिकायत देकर वे लोग लौट गए।यह कैथेड्रल सिविल लाइंस से सटे कैन्टोमेंट के इलाक़े में बिशप कोनरॉड स्कूल कैंपस के भीतर बना हुआ है। क्रिसमस के मौक़े पर तीन दिन का मेला यहां की पुरानी रवायत है। चर्च के साथ ही पूरा कैंपस रंगीन रौशनी में नहा

उठता है, खाने-पीने के स्टॉल बाहर दूर तक लग जाते हैं, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं और इतनी भीड़ जुटती है कि पैदल चलना भी आसान नहीं होता, गाड़ियों की गुंजाइश तो ख़ैर होती ही नहीं। स्कूली बच्चों और उनके घर वालों के साथ ही यह शहरियों का मेला भी होता है, ख़ासकर नौजवानों का। मेला यानी कि मिलना-जुलना, खाना-पीना, मौज-मस्ती। याद नहीं पड़ता कि इस बार की तरह के ऐतराज की नौबत पहले कभी आई हो। बाद में ईसाइयों के सामुदायिक पोर्टल 'कैथोलिक कनेक्ट' ने बरेली के बिशप इग्नेशियस डिसूजा के हवाले से लिखा कि इस वाक़ये की वजह शायद कोई ग़लतफ़हमी थी, क्योंकि स्कूल के कार्यक्रम में तो समकालीन सामाजिक मुद्दों पर बात की गई थी। बक़ौल बिशप, स्कूल मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ एफ़आईआर लिखाने के लिए पुलिस से शिकायत की गई, मगर शिकायत करने वालों ने अपने आरोप की पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं पेश किया गया। चर्च पर विरोध-प्रदर्शन के बारे में पुलिस ने चर्च को पहले ही आगाह कर दिया था, हिफ़ाज़त के लिहाज़ से पुलिस भी तैनात कर दी थी।वैसे धर्म और रीति-रिवाज के जानकार तो यह भी बताते हैं कि हनुमान चालीसा का भाव शांति, श्रद्धा और समर्पण है, इसलिए ग़ुस्से या जल्दबाज़ी में, सूर्यास्त के तुरंत बाद और नहा-धोकर शुद्ध हुए बिना इसका पाठ नहीं किया जाना चाहिए। मुमकिन है कि नाराज़ लोग भी यह बात जानते रहे होंगे। हमारे शहर के ताने-बाने पर ग़ौर करें तो कैथेड्रल का मेला तो जुटा ही, बड़े दिन पर क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च पर लगने वाले मेले में हमेशा की तरह मज़े की भीड़ जुटी। अयूब ख़ां चौराहे से चौकी चौराहे की तरफ़ आने वाली चर्च की तरफ़ की सड़क पर गाड़ियां चलने पर पाबंदी थी, उस रोज़ वह सिर्फ़ पैदल वालों की रहगुज़र थी।सवेरे की प्रार्थना के बाद चर्च के दरवाज़े बंद थे, पर कैंपस गुलज़ार था। यीशु के जन्म की झांकी सजी थी, कैंपस में तीन-चार चौड़ी मेज़ें जोड़कर लगा दी गई थीं, अक़ीदतमंद जहां जाकर मोमबत्तियां रौशन करते, बंद दरवाज़े के सामने जाकर सिर झुकाते और फिर बच्चों को लेकर खिलौनों, खाने-पीने के ठिकानों की तरफ़ आ जाते जो पूरी सड़क पर आबाद थे। अपनी पत्नी, पोती और भतीजों को लेकर पहुंचे गवर्नमेंट कॉलेज के सहपाठी राजेश बाबू मौर्य इसी भीड़ में मिले। बताया कि अपने बच्चों की पढ़ाई के दिनों से ही वह हर साल मेले में आते ही हैं, और वजह इतनी ही कि यहां आकर अच्छा लगता है। प्रसंगवश इतना और कि शहरी इलाक़े में कुल 0.78 फ़ीसद ईसाई (2011 की जनगणना के मुताबिक़ 0.33 फ़ीसद ही) आबादी है, और कैन्टोमेंट के इलाक़े में 2.03 फ़ीसद।यह ख़बर अभी खलबली मचा ही रही थी कि 27 दिसंबर को राजेंद्रनगर के डेन कैफ़े में एक और हादसा गुज़रा। नर्सिंग स्कूल की एक छात्रा शिवांगी अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए अपने स्कूल के दोस्तों के साथ कैफ़े में गई थी। कुछ देर बाद नारे लगाते हुए वहां पहुंची भीड़ ने हंगामा खड़ा कर दिया। ख़ुद को बजरंग दल का सदस्य बताने वाली इस भीड़ ने शिवांगी के दोस्तों में शामिल वाक़िफ़ और शान को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उन्हें बचाने की कोशिश करने वालों के साथ भी हाथापाई की और प्रेमनगर पुलिस के आने के थोड़ी देर बाद बाइकों पर सवार होकर बड़ी शान से रुख़सत हुए।पुलिस ने चोटें खाए वाक़िफ़ और शान के साथ ही कैफ़े चलाने वाले शैलेंद्र गंगवार को हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर शांति भंग करने के आरोप में उनका चालान कर दिया। इंस्पेक्टर राजबली सिंह की दलील यह थी कि उन दोनों लड़कों की मौजूदगी ही हंगामे की वजह बनी थी।इसे लेकर जब पुलिस की ख़ासी लानत-मलानत हुई तो कुछ को नामज़द करके 24-25 लोगों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखी गई, एक नाबालिग समेत छह लोग गिरफ़्तार भी हुए। रिपोर्ट में नामज़द और भीड़ के अगुवा ऋषभ ठाकुर के बारे में बजरंग दल के महानगर संयोजक केवलानंद गौड़ ने यह कहकर किनारा किया कि ऋषभ को 14 दिसंबर को ही संगठन से निकाला जा चुका है और इस घटना से बजरंग दल का कोई लेना-देना नहीं है।इस क़िस्म के तर्ज-ए-अमल से हालांकि ज़माना भी अब नावाक़िफ़ नहीं है। मगर जिस रोज़ ऋषभ ठाकुर ने अपनी बेगुनाही जताते हुए 'लव जेहाद' के ख़िलाफ़ हंगामे को जायज़ बताने वाला अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसी रोज़ सुभाषनगर पुलिस ने अफ़सरों को बताया कि उसे ज़िला बदर करने का ऑर्डर तो अगस्त में ही हो गया था और चोरी के मामले में जुलाई में वह जेल जा चुका है। उस पर जानलेवा हमले का मुक़दमा भी चल रहा है।कैफ़े में हुए हादसे के बाद से शिवांगी सदमे के हाल में हैं। उस रोज़ की पार्टी में शरीक़ दस लोगों में वे छह लड़कियां और चार लड़के थे। नाम-निहाद 'लव जेहाद' के हल्ले के बारे में अपनी तक़लीफ़ बयान करते हुए उसने मीडिया को बताया कि साथ पढ़ने वाले से दोस्ती का ऐसा कोई पैमाना नहीं होता।शिवांगी की बातें सुनते हुए जो ख़्याल सबसे पहले आया, वह यह कि किसी जश्न में शामिल दस लोगों में कौन किस मज़हब को मानने वाला है, इस बारे में आख़िर ऋषभ और उसकी टोली को ख़बर कैसी हुई? और फिर नेहा दीक्षित की किताब 'मैनी लाइव्ज़ ऑफ़ सईदा' में तथाकथित 'लव जेहाद' के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वालों के काम करने के तरीक़े और उनके तंत्र की याद आई। याद आया कि एक बार मिजवां में बातचीत के दौरान किसी प्रसंग पर कैफ़ी आज़मी ने कहा था कि इस मुल्क में कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा, जिसके दस-पंद्रह हिन्दू दोस्त नहीं हों और न ही ऐसा कोई हिन्दू, जिसके दस-पंद्रह मुसलमान दोस्त न हों। अपने जन्मदिन की ख़ुशी में शिवांगी का अपने दोस्तों को शामिल करना समाज के किसी ख़ुदाई-ख़िदमतगार को भला क्यों खटकने लगा होगा!और फिर प्रो. कृपानंदन भी याद आए। इसलिए कि ज़माना भी उन्हें नज़ीर के तौर पर देखता था। जंग-ए-आज़ादी के सिपाही, बरेली कॉलेज में अंग्रेज़ी के शिक्षक, दानिश्वर, सर्वोदयी, शहर की रौशन ख़्याल जमात के चमकते सितारे और मुअज़्ज़िज़ शहरी। ज़किया ख़ातून उनकी विद्यार्थी थीं, और बाद में उनकी शरीक़-ए-हयात। दोनों ने एक छत के नीचे ज़िंदगी गुज़ार दी। ज़किया ख़ातून मज़हब की पाबंद और प्रो. कृपानंदन कुछ हद तक काफ़िर। उनके दो बेटे अशोक और एंजिल। सोचता हूं कि तब कहीं ज़्यादा मज़हबपरस्ती के बावजूद ऐसे ख़ुदाई-ख़िदमतगारों के बग़ैर वह दुनिया कितनी ख़ूबसूरत थी।हंगामे के मुल्ज़िम देर-सबेर पकड़ लिए जाएंगे, हो सकता है कि अपने किए की सज़ा भी पाएं, मगर शिवांगी के दिमाग़ पर जो छाप रह जाएगी उसका क्या, उनके दोस्त शान और वाक़िफ़ की चोटें ठीक हो जाने के बाद भी वे उम्र भर क्या यह हादसा भूल पाएंगे। दुआ कीजिए, जतन कीजिए कि हादसा मानकर भूल ही जाएं, नहीं तो वही मंसूबा पूरा होगा, जो ऐसे हादसे रचने का मानस तैयार करता है। फ़ैज़ लुधियानवी याद आते हैं,

तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई
वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई।।

## संपादकीय

### इंदौर में जानलेवा पानी तमगों पर धब्बा

वह अपने आप में विचित्र और अफसोसनाक है कि जिस शहर को पिछले कई वर्षों से देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिल रहा हो, वहां दूषित पेयजल के सेवन से लोगों के मरने की खबरें आती हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई और करीब दो सौ लोगों को अस्पताल भर्ती होना पड़ा। खबरों के मुताबिक, भागीरथपुरा में नर्मदा नदी की पाइपलाइन में गंदा पानी मिल गया, जिससे पानी दूषित हो गया। लोगों ने इस पानी का सेवन शायद इसलिए भी कर लिया कि साफ और गंदे पानी में फर्क करना मुश्किल हो गया था। सवाल है कि अगर आम लोग पेयजल के लिए पानी की आपूर्ति पर निर्भर हों, तो उनके पास गंदा और दूषित पानी पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी है। लोगों की मौत के मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने गलती मानते हुए आनन-फानन में कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन यह साफ है कि संबंधित महकमों की नींद तभी खुलती है, जब कोई बड़ा नुकसान हो चुका होता है।यों, देश भर में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, लेकिन ऐसा लगता है कि आम लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और इस क्रम में उनकी सेहत के साथ क्या होता है, इसकी परवाह शायद किसी को नहीं है। खबरों के मुताबिक, दूषित पेयजल की मार से प्रभावित इलाके में स्थानीय लोगों ने पिछले डेढ़ वर्ष से इससे होने वाली परेशानी और शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने की बात कही। मगर सरकार के कामकाज की शैली का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पेयजल में दूषित पानी मिलने के बाद जब लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, तब भी अगले कई दिन तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा, पीने के पानी के पाइप लाइन से अलग गंदे पानी के निकासी की लाइन को सुरक्षित मानकों तक दूर रखने की व्यवस्था नहीं की गई, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या यह सिर्फ अक्षम अधिकारियों की अदूरदर्शिता का मामला है या फिर जानबूझ कर की गई अनदेखी का? इस तरह की लापरवाही का इलाज सिर्फ कुछ औपचारिक कदम नहीं हैं, बल्कि इसके लिए सभी स्तर पर सजगता और जिम्मेदारी की जरूरत है।विडंबना यह है कि सरकार का मकसद प्रचार के लिए किसी शहर की स्वच्छता के तमगे हासिल करना रह गया लगता है। सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में अगर कुछ लोगों को जहरीला पानी पीने पर मजबूर होना पड़ा, तो इस विरोधाभासी हकीकत की पड़ताल करने की जरूरत है कि ऐसे तमगे जारी किए जाने के पैमाने क्या हैं? पीने का पानी सबसे बुनियादी जरूरत है, जिसके बिना ज्यादा वक्त तक नहीं रहा जा सकता।सरकार देश भर में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना के तहत सबको स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का दावा करती है। मगर इस दावे की हकीकत अक्सर सामने आती रहती है, जब किसी इलाके में भूजल सूख जाने तो कहीं पीने के पानी के लिए लोगों के जद्दोजहद करने की खबरें आती हैं। जहां पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था है भी, अगर वहां यह सेहत पर जोखिम से लेकर जानलेवा होने तक के खतरे से बची नहीं है, तो इसे कैसे देखा जाएगा।

# राजनीतिक इच्छाशक्ति की दुनिया में कमी

अशोक स्वैन

वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मौत के साल के तौर पर याद रखा जाएगा। युद्ध कई गुना तेज हो गए। लोगों का पलायन ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। मानवीय एजेंसियों को बढ़ती जरूरतों और घटते संसाधनों के विरोधाभास का सामना करना पड़ा। बहुपक्षीय संस्थाएं कमजोर हुईं और सैन्य खर्च ने सामाजिक सुरक्षा को पीछे छोड़ दिया। अब जब 2025 खत्म हो गया है, वैश्विक समुदाय इस असहज सच्चाई को सामने खड़ा पा रहा है कि 2026 और भी ज्यादा अस्थिर होने वाला है। संघर्षों पर नजर रखने वाले संगठनों ने शीत युद्ध खत्म होने के बाद से संगठित हिंसा में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की है। गृह युद्ध गहरे हो गए हैं। इलाकाई युद्ध फैल गए हैं। कमजोर और मध्यम आय वाले देशों में राजनीतिक हिंसा की पकड़ मजबूत हो गई है। इस बीच, दक्षिणपंथी राजनीति के उदय के साथ मानवीय सहायता फंडिंग में तेज गिरावट आई है। घरेलू राजनीतिक दबाव, दानदाताओं की उदासीनता और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं को कमजोर कर दिया है। इस पृष्ठभूमि में 2026 में दुनिया को क्या कुछ झेलना पड़ सकता है, इसपर नजर डालना चाहिए। निश्चित ही, यहां पेश संघर्ष व्यापक नहीं और ऐसे तमाम अन्य टकराव भी होंगे, लेकिन ये मोटे तौर पर यह अंदाजा लगाने के लिहाज से काफी है कि आने वाला समय कैसा रह सकता है।सूडान में शुरू हुआ प्रतिद्वंद्वी सैन्य गुटों के बीच सत्ता संघर्ष दुनिया की सबसे गंभीर मानवीय आपदाओं में से एक बन गया है। बाहरी ताकतों ने इसे और भी बदतर बना दिया है, जिन्होंने युद्धरत पक्षों को हथियार, पैसे और राजनीतिक सुरक्षा दी। इस तरह सूडान प्रॉक्सी युद्ध का मैदान बन गया है।मध्यस्थता के प्रयास बिखरे हुए और प्रतिस्पर्धा में हुए हैं। प्रतिबंध चुनिंदा रहे हैं और मानवीय सहायता को भू-राजनीतिक हितों के हवाले कर दिया गया है। इसका नतीजा है: बड़े पैमाने पर हत्याएं, जातीय सफाए, यौन हिंसा, बढ़ता अकाल और लाखों लोगों का पलायन। प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने बातचीत की गुंजाइश को कम किया है, युद्ध को लंबा खींचा है और राजनीतिक समाधान की संभावना को और

भी दूर धकेल दिया है।गाजा और पश्चिमी तट में बमबारी और हवाई हमले बेशक रुक गए हों, लेकिन बुलडोजर अब भी चल रहे हैं और हिंसा बढ़ गई है। इजरायल संघर्षविराम का बेखौफ उल्लंघन कर रहा है, गाजा के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण बना रखा है और फिलिस्तीनियों और मदद की आवाजाही को सख्ती से नियंत्रित कर रहा है। ज्यादातर इलाका मलबे में बदल गया है, शासन व्यवस्था चरमरा गई है और खाने की कमी हर जगह है। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन को सामान्य मान लिया गया है और लोगों की तकलीफ को सैन्य रणनीति की एक स्वीकार्य कीमत माना जा रहा है। साथ ही, ट्रंप प्रशासन अंतरराष्ट्रीय सेना के लिए एक भरोसेमंद और राजनीतिक रूप से संभव सहमति बनाने में विफल रहा है, जिससे सैनिकों की भूमिका में रुकावट आ रही है और गाजा बिना किसी सार्थक नागरिक सुरक्षा के रह गया है। संघर्षविराम के उल्लंघन, बसने वालों के विस्तार और कूटनीतिक गतिरोध को खत्म किए बिना, गाजा को जान-बूझकर तबाही में बदला जा रहा है।डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में स्थानीय सशस्त्र समूह, क्षेत्रीय ताकतों और प्रॉक्सी सेनाओं के बीच लगातार चल रहे संघर्ष ने आम लोगों को खतरनाक दर से विस्थापित किया है। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाले और सबसे घातक संघर्षों में से एक है और 1996 से अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं जिससे भूख, बीमारी और मानवाधिकारों के उल्लंघन की वजह से मानवीय आपात स्थिति पैदा हो गई है। पूर्वी डीआरसी की विशाल खनिज संपदा- कोबाल्ट, तांबा, सोना- हिंसा को बढ़ावा देती है, क्योंकि सशस्त्र समूह और विदेशी ताकतें अवैध खनन और तस्करी से मुनाफा कमाते हैं, जिससे एक 'संघर्ष अर्थव्यवस्था' आकार लेती है जो लड़ाई को जारी रखती है।वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट और राजनीतिक गतिरोध के साथ 2026 में प्रवेश करेगा। इसके साथ ही उस पर ट्रंप प्रशासन का बाहरी दबाव भी होगा, जो सत्ता परिवर्तन करवाने के लिए हालात को भड़का रहा है। वेनेजुएला के लाखों लोग लैटिन अमेरिका में पलायन कर गए हैं, बुनियादी सेवाएं खस्ताहाल हैं और मानवीय संकट गंभीर। जबरदस्ती सत्ता परिवर्तन से यह इलाका और भी अस्थिर हो सकता है, विस्थापन की एक बड़ी लहर शुरू हो सकती है और पहले से ही नाजुक इस गोलार्ध में संकट गहरा सकता है।पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कमजोरी और जलवायु संकट से जूझ रहा है। उसके सीमाई इलाकों में सशस्त्र हमले तेज हो गए हैं, और सीमा पार आतंकवाद और विद्रोही समूहों को पनाह देने के आपसी आरोपों के बीच अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्ते खराब हो गए हैं। भारत के साथ तनाव तो है ही। पहलगाम की हालिया उकसावे वाली घटना और उसके बाद चार दिन के युद्ध के अलावा, दोनों के आपसी विवाद अनसुलझे हैं और बातचीत के लिए बनी व्यवस्थाओं के टूटने से हालात खराब ही हैं। पाकिस्तान में सैन्य प्रतिष्ठान के लिए ये बाहरी टकराव देश की शासन की नाकामियों और सामाजिक ध्रुवीकरण से ध्यान भटकाने का आसान तरीका हो सकते हैं, लेकिन लोगों के लिहाज से हालात गंभीर हैं- न सिर्फ घरेलू अस्थिरता बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ने की भी आशंका है।लाल सागर और आस-पास के समुद्री मार्ग एक और सुलगता क्षेत्र हैं। समुद्री मार्गों का सैन्यीकरण, जहाजों पर हमले और प्रॉक्सी टकराव ने दुनिया के सबसे जरूरी व्यापार मार्गों में से एक को संघर्ष क्षेत्र में बदल दिया है। यहां की अशांति का दुनिया भर में खाने की कीमतों, ऊर्जा बाजार और सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। खतरा यह है कि एक गलत अनुमान यहां के किसी भी सीमित संघर्ष को ऐसे बड़े टकराव में बदल सकता है जिसमें वैश्विक ताकतें कूद पड़ें। वैश्विक विस्थापन अपने आप में एक संकट है। आज जबरन विस्थापितों की संख्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा है और लगातार बढ़ रही है। संघर्ष, दमन और जलवायु आपदाएं लाखों लोगों को सीमाओं के पार धकेल रही हैं, जबकि शरण प्रणाली सख्त हो रही है और राजनीतिक नैरेटिव कहीं आक्रामक होते जा रहे हैं। शरणार्थियों को अब पीड़ितों के रूप में नहीं, बल्कि खतरों के रूप में देखा जाता है। 2026 में विस्थापन राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा सकता है, जेनोफोबिया को बढ़ावा दे सकता है और मेजबान समाजों पर दबाव डाल सकता है। चरम मौसमी घटनाएं अब असामान्य नहीं। सूखा, बाढ़ और तूफान नियमित रूप से उन देशों को तबाह कर रहे हैं जो पहले से ही संघर्ष या खराब शासन से कमजोर हो चुके हैं। जलवायु परिवर्तन खतरा बढ़ाने वाले एक कारक के रूप में काम करता है, जिससे खाद्य असुरक्षा बढ़ती है, पलायन होता है और राजनीतिक अशांति और बिगड़ती है। फिर भी, जलवायु अनुकूलन के लिए पैसे नाकाफी हैं और इसकी उपलब्धता असमान। अंदाजा है कि 2026 में जलवायु घटनाओं से और अधिक मानवीय आपात हालात पैदा होंगे।मानवीय सहायता के लिए मिलने वाला पैसा घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र 2026 में अपनी वैश्विक मदद को घटाकर करीब 23 अरब डॉलर कर देगा, जो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से आधा है। यह कमी दान देने वालों की घटती प्रतिबद्धता को दिखाती है, जिसमें बड़े दान देने वाले देश घरेलू राजनीतिक दबाव और बढ़ते सैन्य बजट के कारण समर्थन घटा रहे हैं।चूंकि सहायता एजेंसियां सभी संघर्षग्रस्त इलाकों से पीछे हट रही हैं, लाखों लोग जो भूख, विस्थापन और संघर्ष का सामना कर रहे हैं, उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। अपने मानवीय सहायता कर्मचारियों को निशाना बनाए जाने और पहुंच कम होने के कारण, संयुक्त राष्ट्र अब मानने लगा है कि उस पर बहुत ज्यादा बोझ है, उसके पास पैसे की कमी है और उसे सबसे ज्यादा जरूरत के समय जीवन बचाने वाले मिशन छोड़ने पड़ रहे हैं।

# रहमान पर पेटदर्द, हसीना पर मौन : देशद्रोही कौन ?

राकेश अचल

उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं. उनका देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं लेकिन वे अभिनेता शाहरुख़ खान के पीछे हाथ धोकर पडे हैं, क्योंकि शाहरुख़ आसान लक्ष्य है. वे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते क्योंकि जानते हैं कि प्रधानमंत्री उनकी दूकान बंद करा सकते हैं. मार्च 2026 में होने वाले आईपीएल से पहले देश का सियासी और मजहबी माहौल गर्म है. बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को खरीदने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स विवादों के को-ओनर और सुपरस्टार शाहरुख खान भी निशाने पर आ गए हैं. राजनीतिक नेता से लेकर धर्मगुरुओं तक, कई वर्गों की ओर से शाहरुख खान को निगल जाना चाहते हैं. शाहरुख को 'गद्दार' तक कह दिया गया.. गनीमत ये है कि शाहरुख़ अकेले नही हैं. शाहरुख के समर्थन में भी राजनेता उतर आए हैं. क्रिकेट का 'क' तक न जानने वाले कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सबसे पहले शाहरुख़ पर वाक प्रहार किया. बाद में जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने देवकीनंदन ठाकुर का समर्थन कर डाला.रामभद्राचार्य ने कहा, 'वह (शाहरुख खान) हीरो नहीं हैं. शाहरुख खान का कोई चरित्र नहीं है. उनके काम गद्दार जैसे रहे हैं.'अब जब गुरु बोले तो चेला पीछे कैसे रहता सो

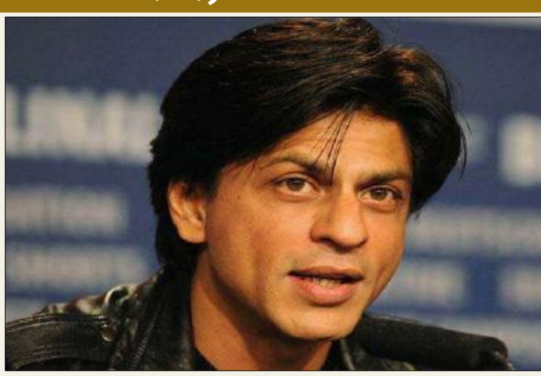

, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, 'कहीं न कहीं वहां (बांग्लादेश) ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हिंदुत्व के खिलाफ हैं. वहां के खिलाड़ियों को आवाज उठानी चाहिए, ताकि हिंदुओं की रक्षा हो सके और वहां के लोग तथा बीसीसीआई इस मुद्दे को समझें.' सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम भी अभिनेता शाहरुख खान को आडे हाथ ले चुके हैं.उन्होंने कहा, 'वो रहमान (मुस्ताफिजुर) यहां कैसे आ सकता है. शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीद कर साढ़े नौ करोड़ रुपए देने का काम करेंगे वो बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी.'दरअसल कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने ये मोर्चा खोला था. उन्होंने कहा था, 'जिस देश ने शाहरुख़ को हीरो बनाया, सुपर स्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया की तुम एक क्रिकेट टीम खरीद सको. देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया. तो क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पर खिलाकर उसका ऋण चुकाओगे.?देवकीनंदन ठाकुर के बयान का महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने भी समर्थन किया. लेकिन भाजपा के उपेक्षित नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब भी दिया. उन्होंने कहा, 'किसी को भी राष्ट्र भक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार नहीं है और किसी को भी राष्ट्र भक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का ठेकेदार बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए.धर्म के नाम पर धंधा करने वाले प्रवाचक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण देने के सरकार के फैसले पर एक शब्द नहीं बोलते जबकि सारे फसाद की जड तो वे ही हैं. इन कथावाचकों को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शाहरुख़ के फैसले पर उदरशूल हो रहा है.भारत-बांग्लादेश के बीच बिगड़ते राजनयिक हालात के बावजूद तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान के इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने की संभावना पर इन गाल बजाने वालों के बयानों का कोई असर होने वाला नहीं है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर किसी भी तरह के प्रतिबंध से इनकार किया है.आपको बता दूं कि मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में बिकने वाले इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी रहे. केकेआर ने उन्हें 9.20 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. शाहरुख़ को विवादों मैं घसीटकर सुर्खियों में आने की बीमारी नयी नही है. मुझे याद है कि 1993: माया मेमसाब फिल्म के इंटीमेट सीन पर पत्रकार से झड़प के बाद शाहरुख गिरफ्तार भी हुए.अमेरिकी एयरपोर्ट पर बार-बार डिटेन होने पर भी विवाद में आए थे शाहरुख़.2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ढ्रक्कमें शामिल करने की मांग का भी शिवसेना ने विरोध किया, आरोप – सरोगेसी बच्चे पर जांच हुई, लेकिन आरोप गलत साबित।2015 में भारत में बढ़ती असहिष्णुता पर बोलकर शाहरुख़ फंस चुके हैं.2023 में पठान फिल्म में भगवा बिकिनी सीन पर विवाद हुआ. उनके बहिष्कार का नारा दिया उन पर , धार्मिक भावनाएं आहत का आरोप लगा.

सम्पादकीय

# सियासी दलों के लिए चुनौतियों से भरा होगा नया साल

**नया साल सियासी दलों खासकर राष्ट्रीय जनतात्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए चुनौतियों का साल होगा। नए साल के पूर्वार्ध में केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी और चार राज्यों केरल, तमिलनाडु, असम व पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम देश की सियासत की भावी दशा और दिशा तय करेंगे। केरल में वामदल, तमिलनाडु में डीएमके, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, असम व पुदुचेरी में भाजपा की अगुवाई वाले राजग के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती होगी।**

नया साल सियासी दलों खासकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए चुनौतियों का साल होगा। नए साल के पूर्वार्ध में केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी और चार राज्यों केरल, तमिलनाडु, असम व पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम देश की सियासत की भावी दशा और दिशा तय करेंगे। केरल में वामदल, तमिलनाडु में डीएमके, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, असम व पुदुचेरी में भाजपा की अगुवाई वाले राजग के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती होगी। भाजपा के लिए विशेष रूप से नया साल चुनौतियों और अवसरों से भरपूर होगा। पार्टी के सामने दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में अपनी ताकत साबित करने का अवसर के साथ पश्चिम बंगाल में दशकों से कमल खिलाने की इच्छा को पूरा करने की चुनौती होगी। इसके अलावा असम में जीत की हैट्रिक लगाने और पुदुचेरी में राजग की अगुवाई वाली सरकार को बनाए रखने की भी चुनौती होगी। 2026 में विपक्षी गठबंधन के लिए चुनौती बड़ी है। दरअसल पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में असम, पश्चिम बंगाल और केरल में गठबंधन के घटक दल आमने-सामने होंगे। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ और वाम दलों की अगुवाई वाले एलडीएफ के बीच ही मुख्य मुकाबला होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी का वाम दलों और कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन के आसार नहीं दिख रहे। पुदुचेरी और तमिलनाडु में विपक्षी गठबंधन की पुरानी एकता बरकरार रहेगी। चुनावी राज्यों में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें रहेंगी। सत्तारूढ़ टीएमसी के सामने जीत का चौका लगाने की चुनौती होगी, तो मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा के लिए सत्ता हासिल करने की चुनौती रहेगी। बीते चुनाव में भाजपा सत्ता हासिल करने का सपना पूरा नहीं कर पाई थी। हालांकि इस बार टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखने, अलग पार्टी बना कर एआईएमआईएम से गठबंधन की संभावना के कारण टीएमसी को अपने मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव का भय सता रहा है। केरल में बीते चुनाव में अपनी सत्ता बरकरार रख वाम दलों के अगुवाई वाले गठबंधन एलडीएफ ने इतिहास रचा था। हालांकि इस बार कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ से एलडीएफ को कड़ी टक्कर के आसार हैं। पहले पश्चिम बंगाल और इसके बाद त्रिपुरा की सत्ता गंवा कर वाम दल गहरे संकट में है। केरल वाम दलों का अंतिम किला है। नतीजे केंद्र की राजनीति में राजग और विपक्षी गठबंधन की धमक साबित करेंगे। असम और पुदुचेरी में राजग की सत्ता में वापसी के साथ अगर भाजपा ने बंगाल में जीते, तो केंद्र में उसकी स्थिति और मजबूत होगी। इसी प्रकार केरल में जीत कांग्रेस के लिए सियासी टॉनिक का काम करेगी। उसके पास तब तेलंगाना, कर्नाटक के बाद एक और महत्वपूर्ण राज्य होगा। टीएमसी अगर बंगाल में जीत का चौका लगाती है तो ममता बनर्जी निर्विवाद चेहरा बन कर उभरेंगे।

# नए साल में कोड डायरेक्टरी से होगी सबसे बड़ी जनगणना

नए साल में देश अब तक के सबसे बड़े जनगणना अभियान का साक्षी बनेगा। साल 2026 में पहले मकानों का सूचीकरण व गणना होगी और दूसरे चरण में जनगणना कराई जाएगी। 135 करोड़ से ज्यादा लोगों की गिनती के लिए जनगणना कोड डायरेक्टरी तैयार की जा रही है। यह डायरेक्टरी तीस लाख प्रगणकों व पर्यवेक्षकों को दी जाएगी ताकि वह जनगणना करते वक्त सही से जवाब अंकित कर सकें। कोड डायरेक्टरी में घर के मुखिया से संबंध, मातृभाषा और अन्य भाषा का ज्ञान, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार या सेवा के प्रकार, जन्म स्थान या अंतिम निवास स्थान और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वगैरह के संबंध में कोड होंगे। आवास आवश्यकताओं पर व्यापक आंकड़े प्राप्त होने से आवास संबंधी प्रभावी नीतियां तैयार की जा सकेंगी। परिवारों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और संपत्तियों पर आंकड़े तमाम नीतियों को बनाने में उपयोगी होंगे। यह मकान सूचीकरण के तहत ब्लॉकों का जनसंख्या आकार जनसंख्या गणना के लिए आधार प्रदान करेगा। जनगणना के दूसरे चरण के दौरान, प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। उसके व्यक्ति्गत विवरण जैसे आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मातृभाषा, शिक्षा का स्तर, विकलांगता, आर्थिक गतिविधि, प्रवासन, प्रजनन (महिला के लिए) एकत्र होंगे। जनगणना पूरी हो जाने के बाद सभी भरे हुए जनगणना प्रपत्र सुरक्षित रखे जाएंगे। इसमें गणनाकर्ताओं द्वारा व स्वयं-गणना के माध्यम से भरे गए दोनो तरह के प्रपत्र शामिल हैं। यह सभी प्रपत्र राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के जनगणना संचालन निदेशक के कार्यालय में रखे जाएंगे। भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय सर्वर में डेटा केवल एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहीत किया जाएगा...डेटा को सुरक्षित रखने, सुरक्षित मोड में प्राप्त करने / संसाधित करने के लिए सभी सर्वर और स्टोरेज को भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय सर्वर में केवल एन्क्रिप्टेड रूप में रखा जाएगा। जनगणना से आने वाला डेटा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के सर्वर के अंदर संग्रहीत होगा। डेटा चक्र के हर स्तर पर डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। डेटा मोबाइल पर हो, ट्रांसमिशन में हो या बाद के स्तर में हो, तो बहुस्तरीय सुरक्षा होगी। एकत्र किए गए जनगणना के आंकड़ों को तारीख और समय के साथ अंकित करते हुए हुए मोबाइल में सहेजने से पहले उपयुक्त रूप से एन्क्रिप्ट किया जाएगा। एक बार जब डेटा भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय सर्वर को भेज दिया जाएगा तो नियत तारीख के बाद डेटा स्वत- ही मोबाइल से खत्म हो जाएगा। लॉग और सुरक्षा सुविधाओं के साथ एक्सेस किए गए सभी डेटा को सावधानीपूर्वक रख-रखाव किया जाएगा।

# भारतीय अर्थव्यवस्था का 'गोल्डिलॉक्स' दौर में प्रवेश

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2026 एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत एक ऐसे 'गोल्डिलॉक्स' चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां मजबूत वृद्धि दर और नरम महंगाई का दुर्लभ मेल दिख सकता है। हालांकि, घरेलू मोर्चे पर मजबूती के बावजूद वैश्विक व्यापार में तनाव और मुद्रा बाजार की अस्थिरता 2026 में नीति निर्माताओं के लिए मुख्य चुनौती बनी रहेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2026 एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत एक ऐसे 'गोल्डिलॉक्स' चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां मजबूत वृद्धि दर और नरम महंगाई का दुर्लभ मेल दिख सकता है। हालांकि, घरेलू मोर्चे पर मजबूती के बावजूद वैश्विक व्यापार में तनाव और मुद्रा बाजार की अस्थिरता 2026 में नीति निर्माताओं के लिए मुख्य चुनौती बनी रहेगी। आर्थिक शब्दावली में 'गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी' उस आदर्श स्थिति को कहते हैं जो न तो बहुत अधिक गर्म (बहुत ज्यादा महंगाई) होती है और न ही बहुत ठंडी (मंदी या सुस्ती)। यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक विकास की गति स्थिर बनी रहती है, बेरोजगारी कम होती है और महंगाई नियंत्रण में रहती है। साल 2026 के लिए जो अनुमान लगाए जा रहे हैं- जैसे कि 3.5 प्रतिशत की रिटेल महंगाई और स्थिर जीडीपी विकास दर- वे संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में इसी 'गोल्डीलॉक्स' जोन में है। यह मध्यम वर्ग के लिए सबसे सुखद स्थिति होती है क्योंकि यहां न तो ब्याज दरों के अचानक बढ़ने का डर होता है और न ही आय कम होने का जोखिम।

2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत तक पहुंच गई, इस आंकड़ने भारत को जापान से आगे निकालकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत अब अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़कर **तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अनुमान है कि 2030 तक भारत की जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।**

**भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने विकास अनुमान को 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और मूडीज जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी इस सकारात्मक दृष्टिकोण की पुष्टि की है।**

**फरवरी में पेश होने वाले आगामी केंद्रीय बजट से उद्योगों और आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। सरकार का ध्यान मुख्य रूप से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' पर केंद्रित रहने की उम्मीद है।**

**सरकार से नए साल में कई बड़े कदमों की उम्मीद रहेगी। जानकार मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार को पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स में निवेश और बढ़ाना चाहिए। सरकार से नई श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) का पूर्ण कार्यान्वयन और जीएसटी दरों में और अधिक तर्कसंगत सुधार की भी उम्मीद रहेगी। केंद्र ने राष्ट्रीय खातों के आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने की भी तैयारी कर ली है, इससे जीडीपी गणना की सटीकता बढ़ेगी।**

**भारत की विकास गाथा में वैश्विक कंपनियों का भरोसा बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट (2030 तक 17.5 बिलियन डॉलर), अमेजन (अगले 5 वर्षों में 35 बिलियन डॉलर) और गूगल (15 बिलियन डॉलर) जैसे दिग्गजों ने बड़े निवेश की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, एप्पल, सैमसंग और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील जैसी कंपनियां अपनी विस्तार योजनाओं को गति दे रही हैं।**

**आर्थिक मजबूती के बीच, भारतीय रुपया 2026 में भी दबाव में रहने के संकेत दे रहा है। वर्ष 2025 में रुपये ने डॉलर के मुकाबले 91 का ऐतिहासिक निचला स्तर देखा। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित पारस्परिक टैरिफ के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजार से बड़े पैमाने पर निकासी की है।**

**विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा मुद्रा संकट मुख्य रूप से गिरते पूंजी प्रवाह और अस्थिर पोर्टफोलियो प्रवाह के कारण है। कोटक सिक्योरिटीज और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौता निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन यह रुपए की गिरावट रोकने के लिए 'रामबाण' साबित नहीं होगा। अल्पकालिक अवधि में रुपया 92-93 के स्तर तक जा सकता है, लेकिन अप्रैल 2026 के बाद वैश्विक पूंजी के पुनर्गठन और डॉलर की संभावित कमजोरी से रुपया 83-84 के स्तर तक मजबूत हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है कि मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था और निर्यात विविधीकरण ने भारत को टैरिफ युद्ध के बावजूद लचीला बनाए रखा है। वहीं, इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2027 में विकास दर 6.5 से 7 प्रतिशत के बीच रहेगी, जबकि मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के आरामदायक स्तर पर बनी रह सकती है।**

**क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी ने चेतावनी दी है कि भारत पर वैश्विक चुनौतियों का असर कम है, लेकिन अमेरिका के मनमाने टैरिफ का असर विदेशी निवेशकों की धारणा पर असर डालना जारी रख सकता है। भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नितिन मेहता ने 2025 के सुधारों को बीएफएसआई क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया है। उनके अनुसार, 100 प्रतिशत एफडीआई और बीमा सुगम जैसी पहलों ने बीमा क्षेत्र में पूंजी और पहुंच की दोहरी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया है। मेहता का मानना है कि बैंकिंग कानूनों में संशोधन, विशेष रूप से नामांकित व्यक्तियों की लचीली व्यवस्था और जोखिम-आधारित जमा प्रीमियम, ग्राहक सुरक्षा और भरोसे को मजबूत करते हैं।**

# एआई की परीक्षा का साल हो सकता है 2026

**अगर 2025 एआई के शोर और उम्मीदों का साल था, तो 2026 शायद एआई के नतीजों का साल साबित होगा। 2026 में लगभग सभी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी एआई की दौड़ में आगे बढ़ना। लेकिन इसके लिए एआई से जुड़े उन विरोधाभासों की पहचान जरूरी है, जो तकनीक के बारे में कम, और इन्सानी खूबियों और कमजोरियों से ज्यादा जुड़ी हैं।**

अगर 2025 एआई के शोर और उम्मीदों का साल था, तो 2026 शायद एआई के नतीजों का साल साबित होगा। 2026 में लगभग सभी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी एआई की दौड़ में आगे बढ़ना। लेकिन इसके **लिए एआई से जुड़े उन विरोधाभासों की पहचान जरूरी है, जो तकनीक के बारे में कम, और इन्सानी खूबियों और कमजोरियों से ज्यादा जुड़ी हैं।**

**विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 रिपोर्ट बताती है कि आने वाले समय में नई नौकरियों की जरूरत बढ़ेगी। अगले पांच साल में करीब 17 करोड़ नौकरियां पैदा होने वाली हैं। यह बात सच है कि अलग-अलग क्षेत्रों में जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं और एआई का असर बढ़ रहा है, उससे कई नौकरियां स्वचालित होंगी, लेकिन इससे इंसान की भूमिका कम नहीं होगी। एआई आपकी राह आसान बना सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। एआई के नए-नए उत्साह में इंसान भले ही हर चीज में एआई का उपयोग करने की सोचे, लेकिन गंभीर योजनाओं के निर्माण और उनके क्रियान्वयन को मशीन के हाथों में तो नहीं छोड़ा जा सकता। मशीनों से रचनात्मकता की उम्मीद नहीं कर सकते।**

**एमआईटी स्लोन के शोध के अनुसार, एआई अपनाने की शुरुआत में प्रदर्शन थोड़ा घटता है, पर लंबे समय में नतीजे बेहतर होते हैं, क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण और कार्यप्रवाह बदलने में समय लगता है, जिससे तालमेल बिठाना मुश्किल होता है। यह पैटर्न 'एआई एडॉप्शन जे-कर्व' कहलाता है। इसीलिए यह पाया गया कि एआई अपनाने वाली कंपनियां दीर्घकाल में इसका इस्तेमाल न करने वाली कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन करने लगीं। कुछ कर्मचारी भले ही कहें कि कम गुणवत्ता वाले एआई-जनित काम की वजह से उन्हें उसे सुधारने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इतनी मेहनत तो करनी ही होगी।**

**बड़े लैंग्वेज मॉडल और जेनरेटिव एआई उपकरण भी अब इंसानों जैसे कन्टेंट बना सकते हैं। इसके अलावा, इंटरनेट पर इंसानों की तुलना में एआई द्वारा लिखे लेख ज्यादा हो चुके हैं, जिससे औसत, दोहराव या गलत सामग्री बढ़ने का जोखिम है। एक अध्ययन में पाया गया कि इंसान अब चार में से सिर्फ एक बार ही उच्च-गुणवत्ता वाले डीपफेक वीडियो पहचान पाते हैं। यही कारण है कि ऑनलाइन भरोसे को बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए इंसानी निगरानी जरूरी है। एआई का क्षेत्र जितना बढ़ेगा, उसके समांतर इंसानी हस्तक्षेप भी उसी मात्रा में बढ़ता जाएगा। एक अमेरिकी सर्वे के अनुसार, 47 फीसदी जेन-जी हर हफ्ते जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 41 प्रतिशत चिंतित हैं कि इससे उनकी सोचने की क्षमता कमजोर हो सकती है। एमआईटी के एक अध्ययन में भी पाया गया कि एआई पर ज्यादा निर्भरता दिमाग की सक्रियता, याददाश्त और मौलिक सोच को कम कर सकती है। किसी भी चीज की अति तो बुरी होती ही है। दोष एआई के इस्तेमाल में नहीं, बल्कि इस्तेमाल के तरीके में है। एआई को अपना सहायक मानें, तो कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर जेन-जी अपनी आंख बंद कर चलेगी, तो मैनहोल में गिरने से एआई थोड़े बचाएगा।**